संवाद

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। शनिवार, 29 जून 2024

अपवाद न बने बेल

सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश पर अमल हो

आखिर गिरफ्तारी के करीब 5 महीने बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और JMM नेता हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई। सोरेन को ईडी ने 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। ईडी द्वारा ही गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नियमित जमानत पाने में अभी तक सफल नहीं हुए हैं। इन दोनों मामलों से कई तरह के प्रशासनिक, राजनीतिक और कानूनी सवाल जुड़े नजर आते हैं।

हेमंत सोरेन को मिली ज़मानत

चुनाव से पहले गिरफ्तारी | दोनों न केवल अपनी-अपनी पार्टी के सबसे प्रमुख नेता माने जाते हैं बल्कि अपने-अपने राज्यों के मुख्यमंत्री पद पर रहे। इनके ऊपर लगाए गए आरोप बेशक गंभीर हैं, लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनावों से कुछ ही पहले इन्हें गिरफ्तार किया गया, उससे विपक्ष को यह कहने का मौका मिला कि इन गिरफ्तारियों के पीछे उसकी चुनावी संभावनाओं को प्रभावित करने की कोशिश हो सकती है।

सवाल-दर-सवाल | खासकर, केजरीवाल के मामले में जमानत पर रिहाई रोकने की जिस तरह की कोशिशें पिछले दिनों दिखीं वे भी सवाल खड़े करती हैं। निचली अदालत के जमानत दे देने के बाद ईडी का हाईकोर्ट पहुंचना अगर सामान्य था भी तो हाईकोर्ट ने जिस तरह से अपना आदेश सुरक्षित रख लिया उसे सुप्रीम कोर्ट ने भी असामान्य बताया। और फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से ठीक पहले जिस तरह से CBI ने केजरीवाल को उसी एक्साइज पॉलिसी केस में गिरफ्तार किया, वह कम से कम जांच एजेंसियों की कुशलता का उदाहरण तो नहीं माना जा सकता।

ज़मानत में देर | मंगलवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मंत्री और आप नेता सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी पर सुनवाई स्थगित करने के सवाल पर हाईकोर्ट को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट हजार बार कह चुका है कि जमानत से जुड़े मामले बेवजह टाले नहीं जाने चाहिए और यह भी कि बेल को नियम और जेल को अपवाद माना जाना चाहिए। फिर भी अलग-अलग मामलों में बार-बार जमानत की अर्जी को कानूनी प्रक्रिया में उलझाते हुए आरोपी को अधिक से अधिक समय तक जेल में रखने की प्रवृत्ति नजर आती है।

इंसाफ होते हुए दिखाई भी दे | इसमें दो राय नहीं कि कानून के सामने हर कोई समान है। लेकिन गिरफ्तार किया जाने वाला व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री है तो उस मामले के राजनीतिक, प्रशासनिक और चुनावी निहितार्थ दूर तक जाते हैं। निश्चित तौर पर सार्वजनिक जीवन में शुचिता को लेकर कोई समझौता नहीं हो सकता, हर मामले और हर व्यक्ति की पूरी जांच होनी ही चाहिए, लेकिन इस क्रम में इंसाफ न सिर्फ होना चाहिए बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए।

दो दूनी चार

फंड में जमा ट्रस्ट

रमेश तिवारी

म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एक बार फिर हिल गई है। इसके एक बड़े नाम Quant म्यूचुअल फंड के खिलाफ हाल ही में जो आरोप सामने आए हैं, वो चिंता पैदा करते हैं। जिस इंडस्ट्री को लोगों को जोड़ने की खातिर मोटा कमिशन खर्च करना पड़ता हो, वहां अविश्वास की स्थिति पैदा हो रही है। अगर Quant के निवेशकों ने इस घटनाक्रम से घबराकर पैसा निकालना शुरू कर दिया तो पूरी इंडस्ट्री पर बुरा असर पड़ेगा। हालांकि शुरुआती रपटों में बड़ी निकासी के संकेत नहीं मिले हैं।

फंड इंडस्ट्री जल्द ही 60 लाख करोड़ के असेट्स मैनेज करने जा रही है। पिछले सिर्फ पांच साल में ये असेट्स डबल हो गए। ये सफर इतना आसान नहीं रहा है। जब 1964 में इंडस्ट्री की शुरुआत हुई तो 10 लाख करोड़ के असेट्स मैनेज करने में पांच दशक लग गए थे। अब आज के दौर में लोगों का भरोसा देखिए। सबसे ताजातरीन 10 लाख करोड़ एक साल से भी कम समय में हासिल हो गए। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट बता रही है कि भारत में घरेलू बचत तेजी से कम हो रही है। फिर भी करीब एक साल से म्यूचुअल फंडों में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लगातार नई ऊंचाई छू रहा है।

Quant के खिलाफ जो आरोप लगे हैं, उन्हें इंडस्ट्री में फ्रंट-रनिंग के नाम से जाना जाता है। इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाले लोग इसके जरिये फायदा उठाते हैं। उसे पहले ही पता लग जाता है कि कि फंड हाउस किसी कंपनी के बहुत सारे शेयर खरीदने जा रहा है। वह लेन-देन होने से पहले अपने खाते में शेयर खरीद लेता है, ताकि बाद में उसे शेयरों के दाम बढ़ने का फायदा मिले। यह एक गंभीर अपराध है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने Quant के केस की जांच शुरू की है। हालांकि फंड हाउस ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है। इसकी कई स्कीमें हाल में जोरदार रिटर्न देने के लिए मशहूर हुई हैं। भरोसे को हिलाने वाले मौके पहले भी आए हैं। इससे पहले 2023 में एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस में ये मामला सामने आया था। मार्केट रेगुलेटर सेबी की जांच से पता चला कि फंड हाउस के तब के चीफ डीलर और 20 अन्य लोगों ने फ्रंट-रनिंग की थी। इस जरिये उन्होंने 30 करोड़ रुपये से अधिक का अवैध लाभ कमाया था। अप्रैल 2023 में सेबी ने LIC के फ्रंट-रनिंग के लिए पांच संस्थाओं और व्यक्तियों पर शिकंजा कसा था। उनमें LIC के एक कर्मचारी के भी शामिल होने की रिपोर्ट आई। इन लोगों ने 2.44 करोड़ रुपये का अवैध लाभ कमाया। 2007 में एचडीएफसी म्युचुअल फंड का भी नाम इस तरह के केस में आया था। इसके अलावा कई मौकों पर फ्रंट रनिंग के खिलाफ कदम उठाए गए।

सेबी के निदेशक मंडल ने हाल ही में नियमों में संशोधन करने का निर्णय लिया था। इसके तहत फंड हाउसों को एक सिस्टम बनाने के लिए कहा गया है, जो फ्रंट-रनिंग की पहचान और रोकथाम कर सके। पर प्रक्रिया जटिल है। इसमें छह महीने तक का वक्त लग सकता है। फंड इंडस्ट्री ने 2030 तक 100 लाख करोड़ के असेट्स मैनेज करने का लक्ष्य रखा है। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इसे कम और मध्यम आय वर्गों का विश्वास भी जीतना होगा। अगर इस विश्वास को फ्रंट रनिंग जैसी बातों से चोट पहुंचती है तो दो बातें होंगी। लोग खुद स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएंगे, जो ज्यादा रिस्की हो सकता है। या फिर पुराने फिक्स्ड डिपॉजिट की ओर लौट चलेंगे।

ऑफ दि ट्रैक

बिन खाए मिटे भूख

दिलीप लाल

जब शरीर को भोजन से कम कैलोरी ऊर्जा मिलती, तो वह अपने जमा वसा को ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करता है और इससे वजन घटता है। इसलिए मोटापा और बढ़ता वजन कंट्रोल करने के लिए calorie deficit की सलाह दी जाती है। मार्केट में Ozempic जैसी कुछ दवाएं हैं जिन्हें वजन कम करने वाली मैजिक पिल के रूप में जाना जाता है। इसे लेने के बाद मनपसंद खाना रखा हो तो भी खाने का मन नहीं करेगा। ऐसा क्यों होता है? इसे जानने के लिए वैज्ञानिकों ने मस्तिष्क के उस हिस्से की पहचान की है जो पेट भरा होने का अहसास दिलाता है। Science1 पत्रिका में प्रकाशित एक पेपर में वैज्ञानिकों ने दवाओं से मिलने वाली संतुष्टि के दो अलग-अलग न्यूरॉन समूहों की पहचान की है। ये न्यूरॉन समूह ही पेट भरने का मेसेज देते हैं। एक न्यूरॉन ग्रुप भोजन के पहले और दूसरा भोजन करने के बाद पेट भरने का संकेत देते हैं। अध्ययन से यह भी पता चलता है कि मोटापे को कम करने के लिए ये दवाएं दोनों ही हालात में काम करती हैं। ये दवाएं glucagon-like peptide 1 (GLP-1) नामक हॉर्मोन की नकल करती हैं, जो ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करता है और मस्तिष्क पर अपना असर डालकर भूख को मार देती है। सियोल नैशनल यूनिवर्सिटी के एक न्यूरोसाइंटिस्ट अपना अनुभव बताते हैं- जब मैंने यह दवा लेकर भोजन को देखा और उसकी गंध महसूस की, तो लगा पेट भरा हुआ है।

ऋषि सुनक ही नहीं, टीम इंडिया भी छीन रही अंग्रेजों की खुशियां

इंग्लैंड को कितना डराएगा भारत

शैलेंद्र पांडेय

आंखों की गुस्ताखियों की तरह होंठों की शरारत भी छुपती नहीं। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन और माइकल अर्थटन जब T-20 विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में टीम इंडिया की हार की भविष्यवाणी कर रहे थे, तब उनकी चेहरे पर आई मुस्कान को होंठों के कोरों पर धकेलने की असफल कोशिश साफ समझ आ रही थी।

इतिहास का हवाला | बड़े ही आत्मविश्वास के साथ क्रिकेट के दोनों महारथियों ने ऐलान कर दिया था कि फाइनल मुकालबा होगा इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच। उनके भरोसे की बुनियाद थी पिछले करीब एक दशक में ICC इवेंट्स के नॉकआउट मुकाबलों में भारत की हार का सिलसिला और पिछले T-20 विश्व कप के सेमीफाइनल में टीम इंडिया पर मिली 10 विकेटों की एकतरफा जीत।

कितना बड़ा दुख | भविष्यवाणी सच तो हुई, लेकिन आधी। मुस्कान गायब हो चुकी है पूरे इंग्लैंड की। अब उसकी जगह खिसियाई हंसी निकल रही है, जो कह रही है कि हम लोग बहुत खराब खेले, कि पिच भारतीयों के मुफीद थी, वगैरह। एक और पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने इंटरनैशनल क्रिकेट काउंसिल की ओर से भारत को मिलने वाली सहूलियतों की ओर ध्यान खींचा, तो जवाब में रविचंद्रन अश्विन ने X पर ऐसा फॉर्म्युला दिया है, जिसे सॉल्व करने के लिए ऑक्सफर्ड की मदद लेनी पड़ जाएगी। लेकिन, बात चिढ़ने की नहीं है। अंग्रेजों का दुख समझा जा सकता है, जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। जब भी बेचारे खुश होने की कोशिश करते हैं, कोई भारतीय आकर कान ऐंठ जाता है। क्या ऋषि सुनक का खौफ कम था उन पर, जो टीम इंडिया भी राशन-पानी लेकर चढ़ी हुई है।

AI Image

खौफ में क्यों है ब्रिटेन
- बैजबॉल फेल कर चुका है भारत
- सियासत में सुनक का जवाब नहीं
- ब्रिटिश इकॉनमी भी भारत से पीछे

सबसे बड़ा डर | इंग्लिश कमेंटेटर्स और क्रिकेट एक्सपर्ट्स की एनालिसिस देखकर इतना समझ आ जाता है कि उन्हें दुनिया में इससे बढ़कर दूसरा कोई डर नहीं लगता कि उनकी टीम खेल के मैदान पर भारत से हार जाए। उनके लिए यह पचाना बहुत मुश्किल है कि जिस देश को उनके पूर्वजों ने क्रिकेट खेलना सिखाया अब वही उन्हें पटखनी दे रहा है। कहां तो क्रिकेट की दुनिया चलती थी लॉर्ड्स से और कहां भारत उसे खींचकर BCCI ऑफिस ले आया। एडमिनिस्ट्रेशन हाथ से गया ही, खेल भी हाथ से जा रहा है।

भारत का बैजबॉल | इंग्लिश टीम जब भी अपना रुआब जमाने की कोशिश करती है तभी भारतीय टीम मॉनिटर की तरह आकर क्लास से बाहर निकाल देती है। इस साल की शुरुआत में बैजबॉल का परचम थामकर अंग्रेज भारत पहुंचे थे। तब यह चर्चा आम थी कि इंग्लैंड ने टेस्ट क्रिकेट खेलने का तरीका बदल दिया। लेकिन, भारतीय जमीन पर आते ही क्या हुआ? विशाखापट्टनम से लेकर धर्मशाला तक, बैजबॉल के सारे नट-बोल्ट खोलकर फैला दिए। गयाना में जो हुआ, उसकी तुलना भी उसी हश्र से कर सकते हैं। दोनों परिणामों के बाद इंग्लैंड में चर्चा चल रही है कि अब स्ट्रैटिजी बदलनी चाहिए।

सुनक पर चर्चा | इंग्लैंड के सामने लेकिन संकट है कि भारत को लेकर स्ट्रैटिजी बदले तो कहां-कहां? क्रिकेट के मैदान में, घरेलू राजनीति में, वर्ल्ड इकॉनमी में या कूटनीति में? क्रिकेट में फिर भी 2022 के एडिलेड को याद कर कुछ पल के लिए खुश होने की कोशिश कर सकते हैं, पर बाकियों का क्या करें?

ब्रिटेन की खबर | जिस तरह टीम इंडिया ने इंग्लैंड के अहं को चोट पहुंचाई है, कुछ वैसा ही काम किया है ऋषि सुनक ने भी। Winchester College, ऑक्सफर्ड और स्टैनफर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, महारानी से भी ज्यादा दौलत के मालिक और अक्षता मूर्ति जैसी शख्सियत के पति हैं सुनक। जब वह पीएम बनने वाले थे तो एक बहस यह भी थी कि वह तो पूरे ब्रिटिश भी नहीं। लेकिन, वही आधा-अधूरा ब्रिटिश करीब दो साल से ब्रिटेन की सबसे ज्यादा खबर ले रहा है।

गलत शॉट | गयाना में हुए सेमीफाइनल में अक्षर पटेल की पहली ही बॉल को अंग्रेज कप्तान जोस बटलर रिवर्स स्वीप करने चले गए और विकेट गंवा बैठे। ऋषि सुनक वहां पीएम हाउस में बैठकर रोज रिवर्स स्वीप खेल रहे हैं और उनकी कंजर्वेटिव पार्टी का विकेट गिरता जा रहा है। ऋषि सुनक यह सब जानबूझकर नहीं करते, उनसे बस हो जाता है।

नाकाम पीएम | अब इसमें उनकी क्या गलती कि उनके आने के बाद महंगाई दर 11% के पार चली गई और अगले सात महीनों तक दो अंकों के बीच टिकी रही। इसमें भी उनकी कोई गलती नहीं कि उनके आने के बाद ही ब्रिटेन को कास्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस से जूझना पड़ा, जिससे आम लोगों के living standards में गिरावट आई, साथ ही बिजली के बिल बढ़कर आने लगे। भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट न होने और रवांडा प्लान फेल होने के पीछे भी सुनक की क्या गलती? लेकिन, जनता उनके पीछे ऐसा हाथ धोकर पड़ी है कि उनके जूतों से लेकर घर में इस्तेमाल होने वाले टी सेट तक पर क्रिटिकल हुए जा रही है।

रहम की जरूरत | दुनिया की पिच रफ हो चुकी है और भारत की स्पिन का ब्रिटेन के पास जवाब नहीं। उसकी अर्थव्यवस्था को टॉप 5 से बाहर निकाल कर हम पहले ही वहां काबिज हो चुके हैं। उस पर इतने सारे झटके - रहम के लिए भी नहीं कह पा रहे अंग्रेज। वहां के मीडिया ने 4 जुलाई को होने वाली वोटिंग से पहले सुनक को नाम दिया है tetchy Rishi यानी चिड़चिड़े ऋषि। लेकिन लगता है कि भारत के खौफ ने चिड़चिड़ा ब्रिटेन को बना दिया है।

छोटे राज्य क्यों हों

भारत को अपना सबसे नया राज्य 2014 में मिला, जब आंध्र से अलग होकर तेलंगाना बना। कई और इलाकों में पृथक राज्य की मांग उठती रही है। देश में क्यों बनने चाहिए और भी राज्य, चलिए जानते हैं :

प्रशासनिक सहूलियत

बड़े सूबों को काटकर छोटे राज्य बनाए जाते हैं, तो प्रशासनिक आसानी होगी। योजनाओं की बेहतर निगरानी होगी। मशीनरी पर आबादी का प्रेशर कम होगा, तो सभी की समस्याएं सुनी जाएंगी और उसके हिसाब से पॉलिसी बन सकेंगी।

राजनीतिक प्रतिबद्धता

बड़े राज्य कई-कई इलाकों में बंटे हुए हैं, राज्य छोटे होने पर क्षेत्रीय जरूरतों पर फोकस हो सकेगा। मिसाल के तौर पर झारखंड जहां स्थानीय आदिवासी समाज ज्यादा मुखर हो चुका है।

AI image

विकास में तेजी

छोटे राज्य तेज गति से विकास करते हैं। हमारे सामने उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का उदाहरण है। अपने निर्माण के बाद अगले एक दशक तक उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ ने यूपी और एमपी के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन किया। इसी तरह तेलंगाना की GDP बाकी देश के मुकाबले बेहतर है। भारत की इकॉनमी में इसका योगदान बढ़कर 4.8% हो चुका है।

इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट

छोटे राज्य होंगे तो उनको चलाने के लिए इंफ्रा भी डिवेलप किया जाएगा। अब जैसे छत्तीसगढ़ ने रायपुर को बढ़ाया, संयुक्त आंध्र में हैदराबाद था, लेकिन अमरावती बनने के बाद वैसे दो होंगे। शहरीकरण में तेजी आएगी, तो इकॉनमी को भी रफ्तार मिलेगी।

बिजली-पानी-रोजगार

देश के तमाम इलाके आज भी बुनियादी जरूरतों की किल्लत से जूझ रहे हैं। छोटे राज्य इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। तेलंगाना ने एक दशक में ही बिजली उत्पादन को 7.8 गीगावॉट से 19.5 तक पहुंचा दिया।

उलझन : आगे कुआं और पीछे खाई!

ट्रंप भरोसेमंद लीडर नहीं तो बाइडन के लिए उम्र की अड़चन

मृत्युंजय राय

जो बाइडन डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से आगामी राष्ट्रपति चुनाव के प्रत्याशी के तौर पर अभी तक औपचारिक रूप से नॉमिनेट नहीं हुए हैं। इसमें दो महीने की देरी है। फिर भी अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के संभावित प्रत्याशी डॉनल्ड ट्रंप के साथ वह बहस के लिए तैयार हुए तो मन में एक आशा थी। आशा यह कि लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति चुने जाने के उनके अभियान में गति आएगी। बाइडन की मुश्किलः मजेदार बात यह है कि इस बहस से चुनावी अभियान में गति तो दूर, उलटा इसके बाद इस चर्चा ने जोर पकड़ लिया कि क्या डेमोक्रेट्स को बाइडन को अपना प्रत्याशी बनाना चाहिए या उन्हें बदल देना चाहिए। वजह यह है कि वह डॉनल्ड ट्रंप के सामने प्रभावशाली नहीं दिखे। उन्होंने समर्थकों को निराश किया और इससे पार्टी में घबराहट बढ़ गई है।

झूठे से बहस | वैसे, ट्रंप के साथ डिबेट के बाद उन्होंने मीडिया से कहा, 'मुझे लगता है, हमारा प्रदर्शन अच्छा रहा।' जर्नलिस्टों ने जब उनसे यह पूछा कि उनके परफॉरमेंस से उनकी पार्टी के लोग फिक्रमंद हैं और उनसे अपनी उम्मीदवारी वापस लेने की गुजारिश भी की जा रही है तो बाइडन ने कहा कि वह पीछे नहीं हटेंगे और 'एक झूठे (डॉनल्ड ट्रंप) व्यक्ति से डिबेट करना आसान नहीं था।'

ट्रंप के झूठ | दूसरी ओर, डिबेट में ट्रंप ने बाइडन को बेअसर लीडर बताया और बार-बार झूठे आरोप लगाए। ट्रंप की झूठ की इंतहा तब हो गई, जब उन्होंने कहा कि बाइडन 'मंचूरियन कैंडिडेट' हैं और चीन से उन्हें पैसा मिला है। इमिग्रेशन पर उन्होंने कहा, 'बाइडन के राज में बाहरी लोग आ रहे हैं और हमारे नागरिकों की हत्या कर रहे हैं।' यह भी सफेद झूठ था। ट्रंप ने यह भी आरोप लगाया कि बाइडन की शह पर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, जबकि सच यह है कि वह लगातार यूक्रेन की मदद करते रहे ताकि रूस की उसके इलाकों पर कब्जे की मंशा पूरी न हो।

उम्र की अड़चन | यहां कुछ सवाल उठते हैं। क्या बाइडन अपनी उम्मीदवारी वापस लेंगे? दूसरा, अगर एक झूठे से डिबेट करना उन्हें मुश्किल लगा तो चुनाव प्रचार में क्या वह ट्रंप की आक्रामकता का जवाब दे पाएंगे? तीसरा, अमेरिका के लोग क्या करें, जिनके सामने बाइडन और ट्रंप ही विकल्प हैं। इनमें से एक की सेहत को लेकर सवाल उठते रहते हैं तो दूसरा बात-बात में झूठ बोलता है।

AI Image

दोनों नेताओं के कमजोर पक्ष
- बाइडन की सेहत को लेकर उठते रहे हैं सवाल
- चीन का वर्चस्व बढ़ने से रोक न पाएंगे बाइडन
- ट्रंप से अमेरिकी लोकतंत्र के खतरे में पड़ने का डर

'आखिरी फ्री इलेक्शन' | Rebellion नाम की किताब में Robert Kagan ने लिखा है कि 2024 का चुनाव शायद अमेरिका का आखिरी 'फ्री इलेक्शन' हो। उनके मुताबिक, अगर ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव में हार जाते हैं तो वह अपनी हार मानने से इनकार कर सकते हैं। 2020 में उन्होंने ऐसा ही किया था। ट्रंप आज तक यही कहते हैं कि उन्हें उस चुनाव में धोखे से हराया गया। उनके समर्थकों ने तब कैपिटल हिल पर हमला भी किया था, जिसे ट्रंप की शह मिली हुई थी।

लीडरशिप छिन जाएगी | लेकिन अगर ट्रंप जीत जाते हैं, तब क्या होगा। इस बारे में मशहूर लेखक Joseph Nye की टिप्पणी दिलचस्प है। 'Is the American century over' नाम की किताब में वह लिखते हैं कि अगर 2024 राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप को जीत मिलती है तो अमेरिका अपनी ग्लोबल लीडरशिप गंवा देगा।

बाइडन का सपना | खैर, बाइडन के चुनाव से हटने की मांग पहले भी उठ चुकी है। वह 81 साल के हैं और जब वह राष्ट्रपति बने थे, तब भी उन्होंने अमेरिका के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति का रेकॉर्ड बनाया था। लेकिन पहले जब यह सवाल उठा तो बाइडन ने यह कहकर उसका जवाब दिया कि दूसरी बार में जो काम अधूरे रह गए हैं, वह उन्हें पूरा करना चाहते हैं।

इकॉनमी मजबूत | कुछ चीजें इस दौरान अच्छी भी हुई हैं। अमेरिका में चार दशकों के शीर्ष पर पहुंची महंगाई दर को काबू में लाने के लिए जब ब्याज दरों में बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू हुआ, तब कहा गया था कि इससे अमेरिकी इकॉनमी मंदी में फंस जाएगी। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। एक करिश्मा यह भी हुआ है कि इस बीच बाइडन सरकार बेरोजगारी को भी निचले स्तर पर रखने में कामयाब रही है। दुनिया भले ही अमेरिकी इकॉनमी पर रश्क कर रही हो, लेकिन वहां के मतदाता उससे खुश नहीं हैं। वे बाइडन और ट्रंप दोनों को इसका क्रेडिट देते हैं।

यूक्रेन को ट्रंप ने भुनाया | अब दूसरे सवाल पर आते हैं कि क्या बाइडन, चुनाव प्रचार के दौरान झूठे ट्रंप का मुकाबला कर पाएंगे? क्या वह अमेरिका के सामने कोई ऐसा विजन पेश कर पाएंगे, जिससे अधिकांश मतदाता उनके पीछे गोलबंद हो जाएं? अभी तक उन्होंने जिस तरह से सरकार चलाई है, उसमें चीन को लेकर वह ट्रंप सरकार की नीतियों पर ही चले हैं।

चीन का सवाल | अमेरिका में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वह दुनिया की महाशक्ति बना रहेगा या चीन उसका वर्चस्व खत्म कर देगा? यूक्रेन युद्ध में चीन रूस को ऐसे कल-पुर्जे भेज रहा है, जिससे उसे हथियार बनाने में मदद मिल रही है। अमेरिका इसे रुकवा नहीं पाया है। एडवांस्ड चिप पर पाबंदी और दूसरी सख्तियों के बावजूद ऐसा मानने वालों की कमी नहीं है कि टेक्नॉलजी वॉर में चीन को बढ़त हासिल है। वहीं, ताइवान पर जंग छिड़ती है तो क्या अमेरिका, चीन के खिलाफ सीधे युद्ध में कूदेगा? इस पर बाइडन के बयान को खुद उनके ही वाइट हाउस ने नकार दिया था। यानी यहां भी वह अपनी फजीहत करा चुके हैं।

www.nbt.in

पहली कमाई के वे सिक्के

खुद अपनी आंख से

अलका 'सोनी'

बात उस वक्त की है जब मैं कक्षा आठ में थी। बचपन से ही मुझे पढ़ने-पढ़ाने का शौक था। साथ ही मन में समाज के लिए कुछ करने की इच्छा भी घर कर गई थी। ऐसा क्यों हुआ, नहीं जानती लेकिन मन में एक धुन-सी लगी रहती थी। इसी धुन में अपने दिल की बात मैंने एक दिन मां को बताई। मन में एक शंका-सी थी कि कहीं वह इसे मेरी सनक समझ मना न कर दे। लेकिन मेरी बात सुन वह मुस्कुराई। फिर समझाते हुए बोली, 'यह विचार बहुत अच्छा है। लेकिन अच्छे कामों की शुरुआत घर से ही करनी चाहिए।' मैंने पूछा कि घर से मैं क्या कर सकती हूं? तब उन्होंने घर से थोड़ी ही दूर बसी एक छोटी-सी बस्ती की ओर संकेत करते हुए कहा, 'तुम इनके बच्चों को अक्षर ज्ञान दे सकती हो। ये बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। न ही घर पर कुछ पढ़ पाते हैं। वैसे तो तुम खुद छोटी हो पर इन्हें कम से कम अपना नाम लिखना तो सिखा ही सकती हो। वर्णमाला से परिचित भी करवा सकती हो। ये बच्चे फीस भले न दे पाएं लेकिन मानसिक सुकून और संतुष्टि तो तुम्हें जरूर मिलेगी।'

मां की बात मुझे जंच गई। मैंने बाहर खेलती और पानी लेने आती बच्चियों को अपने घर पढ़ने आने के लिए बोलना शुरू कर दिया। आखिर मेरी मेहनत रंग लाई। बस्ती की सात-आठ बच्चियां पढ़ने आने लगीं। उन्होंने कभी स्कूल का मुंह भी नहीं देखा था। वे लड़कियां अपने घरों के काम निपटाकर शाम को आती थीं। थकी होने के बाद भी गजब का उत्साह होता था उनमें। मुझे अगर पढ़ाने का जुनून था तो उन्हें पढ़ने का। क, ख, ग से शुरुआत करते हुए अब मैं उन्हें अपने नाम लिखना सिखाने लग गई थी। प्रतिदिन उनकी कक्षा लगती। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। मानो कोई तलाश पूरी हो गई हो। करीब एक महीने बाद उन बच्चियों ने एक दिन मेरे हाथों में कुछ सिक्के थमा दिए। मैं अचरज भरी नजरों से उन्हें देखती रही, फिर पूछा, 'क्या है यह?' उन्होंने बड़ी प्यारी-सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, 'दीदी, यह आपकी फीस है।'

मैं निःशब्द हो गई। जिन बच्चों के घर दो वक्त का खाना भी मुश्किल से जुट पाता था, उन्होंने मेरी फीस की चिंता की। यह बात मुझे अंदर तक भिगो गई। पर उनके ये सिक्के मैं कैसे स्वीकार कर सकती थी? फीस की तो कोई बात हुई नहीं थी। मैं उन्हें सिक्के लौटाने लगी। लेकिन उन्होंने नहीं लिए। हार कर मैंने उन सिक्कों को अपने जीवन की पहली कमाई मानकर माथे से लगा लिया। साथ ही बच्चों से यह प्रॉमिस भी लिया कि अगले महीने से वे इस फीस वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ेगी। बस पढ़ने आ जाया करें, वही मेरी फीस होगी। एक नन्ही शिक्षिका और छोटी-छोटी छात्राओं की यह कक्षा काफी समय तक लगती रही थी। उन्हें पढ़ाकर मुझे बहुत सुकून मिलता था।

उस दिन बच्चियों के जाने के बाद मैंने वे रुपये अपनी मां के हाथों में पकड़ा दिया। कुल आठ रुपये थे। वे सिक्के मां को समर्पित करते हुए खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही थी। आज भी जब कभी उन सिक्कों की याद आती है तो मन रोमांच से भर उठता है। आप चाहे कितने ही बड़े घर से क्यों ना हों, अपनी कमाई के चार पैसे भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं।

चलते-चलते...

फसलों को कीट-पतंगों, चूहों या गैरजरूरी पौधों (weeds) से बचाना किसानों की बड़ी चुनौती होती है। इस समस्या से निपटने के लिए Kansas State University के कृषि वैज्ञानिकों ने एक ऐसा सिंथेटिक जीन ड्राइव विकसित किया है जो इन्हें हटाने में मदद करेंगे। हालांकि इस तकनीक के साथ कई पर्यावरणीय चिंताएं भी जुड़ी हुई हैं। नेचर प्लांट्स में यह खोज हाल ही में प्रकाशित हुई है।

रीडर्स मेल

महाराष्ट्र की परीक्षा

28 जून का संपादकीय 'पार्टियों की बेचैनी' पढ़ा। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनावों की गहमागहमी शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र विधानसभा अब एक लोकतांत्रिक मंच के बजाय दलबदल का अखाड़ा बन गई है। वर्तमान सत्र में राजनीति के सबसे कुटिल रूप देखने को मिले हैं। चुनाव चिह्नों और पार्टियों हेराफेरी ने जनता को भी भ्रम में डाल दिया है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों से महाविकास अघाड़ी (MVA) के हौसले बुलंद हैं, लेकिन गठबंधन खुद ही आश्वस्त नहीं हो पा रहा कि विधानसभा चुनावों में वह अपने प्रदर्शन को दोहरा पाएगा। उधर, BJP भी लोकसभा चुनावों के बाद जमीनी हकीकत से रूबरू हो चुकी है। वह विधानसभा चुनावों में अपनी पूरी ताकत झोंक देगी। विभिन्न दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर भी घमासान होगा और भीतरघात की संभावना भी बनी रहेगी। महाराष्ट्र में इस बार सभी दलों के लिए परीक्षा कठिन होने वाली है।

मधु बुड़ावन वाला, ईमेल से

आत्ममंथन करे सरकार

यह पत्र 28 जून के लेख 'नाराज हों, मगर सरकार का काम भी देखें' पढ़ने के बाद लिखा है। लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखते हुए BJP को आत्ममंथन जरूर करना चाहिए। हिमाचल का उदाहरण हमारे सामने है। हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर अपने संसदीय क्षेत्र और पूरे राज्य का दौरा करते रहते हैं। शायद यही कारण है कि वहां की लोकसभा की चारों सीटों पर BJP बाजी मारती आई है। अनुराग ठाकुर भी 5वीं बार हमीरपुर से चुने गए हैं, जबकि राज्य में इस समय कांग्रेस की सरकार है। वहीं, यूपी को देखें तो वहां सरकार होने के बावजूद BJP को झटका लगा। पंजाब में खराब प्रदर्शन कहीं किसानों की नाराजगी की वजह से तो नहीं? मोदी सरकार और BJP को इस बारे में सोचना होगा। अगर पार्टी को भविष्य में बहुमत की जीत हासिल करनी है, तो उसके नेताओं को मोदी के नाम पर वोट मांगने के बजाय उनकी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के प्रयास करने होंगे। सरकार को महंगाई से राहत दिलाने के लिए भी काम करना चाहिए।

राजेश कुमार चौहान, ईमेल से

आर.एन.आई. नं. 510/57© सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। स्वत्वाधिकारी बैनेट, कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के लिए राजीव यादव द्वारा, 7 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित तथा **टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेस, साइट IV, औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद** और प्लॉट नंबर 7-8, सेक्टर M-11, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, मानेसर, हरियाणा से मुद्रित। फोन : 23302000 फैक्स: 23492047, पंजीकृत कार्यालय : दादाभाई नौरोजी रोड, मुंबई-400001। विमान सेवा शुल्क : 1 रु. प्रति कॉपी। नेपाल में कुल मूल्य : सेमवार से सनिवार : नेपाली 5 रु. ; रविवार : नेपाली 6 रु.
संपादक (दिल्ली मार्केट) : आशीष पांडे (इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी)

हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। **–वाल्तेयर**

राजस्थान पत्रिका
संस्थापक
कर्पूर चन्द्र कुलिश

हवाई अड्डों के रखरखाव में आपराधिक लापरवाही

देश में एक तरफ हवाई अड्डों की संख्या बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ हवाई अड्डों पर यात्रियों की सुरक्षा के मामले में गंभीर लापरवाही की घटनाएं सामने आ रही हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल वन पर छत का ऊपरी हिस्सा गिरने का हादसा सचमुच चिंतित करने वाला है। सरकार ने हादसे में मरने वाले के परिजनों और घायलों को मुआवजे का ऐलान किया है। सवाल यह कि क्या मुआवजा, इस हादसे से प्रभावित परिवारों की मुसीबत को कम कर पाएगा? हादसा, जांच के आदेश और मुआवजा, हर ऐसी घटनाओं में यह रटारटाया सरकारी सिस्टम है। पर इसे हवाई अड्डों के रखरखाव में बरती गई आपराधिक लापरवाही ही कहा जाएगा।

देश के सिरमौर कहे जाने वाले दिल्ली एयरपोर्ट पर बरसात के बीच हुए इस हादसे में एक जने की जान चली गई और कुछ लोग घायल हो गए। हादसे की चपेट में कई गाड़ियां भी आ गईं। यह एयरपोर्ट देश का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है और यहां दुनिया के विभिन्न हिस्सों से यात्री आते-जाते हैं। इस तरह का हादसा यह इंगित करता है कि एयरपोर्ट से जुड़ी इमारतों के रखरखाव पर समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा। यह तो तब है जब पिछले एक दशक में एयरपोर्ट की दुगनी संख्या होने को लेकर सरकार खुद की पीठ थपथपाने में लगी है। यात्रियों की सुविधाओं और सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगें तो इस उत्साह का कोई मतलब नहीं है। एक तथ्य यह भी है कि तमाम प्रयासों के बावजूद श्रेष्ठ एक सौ हवाईअड्डों की वैश्विक सूची में दिल्ली समेत हमारे सिर्फ पांच एयरपोर्ट ही जगह बना पाए हैं। इनमें भी शीर्ष 20 में एक भी नहीं है। देश के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर ही यात्री सुरक्षित नहीं हैं, तो दूसरे हवाई अड्डों की बात करना बेमानी लगता है। इसीलिए एक दिन पहले ही जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पर हुआ बड़ा हादसा भी चौंकाता नहीं है। दिल्ली के आइजीआइ एयरपोर्ट से प्रतिदिन करीब 1200 विमानों की आवाजाही होती है। जाहिर है यहां मामूली लापरवाही भी बड़े हादसे को जन्म दे सकती है। इस हादसे को लेकर भारी बरसात और पुराने निर्माण को दोष देने को लीपापोती ही कहा जाएगा। ऐसे स्थानों पर हर मौसम को ध्यान में रखकर निर्माण होते हैं। जहां तक पुराने निर्माण की बात है तो उसका भी रखरखाव होना चाहिए और यदि वह स्थान आवागमन के लिए खतरनाक होता है, तो वहां आवाजाही रोककर पुनर्निर्माण भी किया जा सकता है।

इस हादसे को लेकर सियासी बयानबाजी और आरोप-प्रत्यारोप भी शुरू हो गए हैं। जबकि इस सवाल पर फोकस किया जाना चाहिए एयरपोर्ट से जुड़ा जो हिस्सा हादसे की वजह बना क्या उसका समय-समय पर रखरखाव किया जा रहा था? जांच में रखरखाव के नाम पर खानापूर्ति सामने आए तो संबंधित अधिकारियों और एजेंसी के खिलाफ आपराधिक लापरवाही का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के साथ ही यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही भी सुनिश्चित होनी चाहिए।

भाव जीवन का सकारात्मक पहलू है। अभाव नकारात्मक होने से मृत्यु सूचक माना गया है। भाव का एक अर्थ है- ईश्वर में आस्था। जो कुछ ईश्वर ने दिया उसमें संतुष्टि। पिछले कर्मों के फलरूप यही था मिलना। जो नहीं मिला, उस पर मेरा अधिकार नहीं है।

अभाव की मानसिकता पतन है

गुलाब कोठारी
प्रधान संपादक
पत्रिका समूह
@patrika.com

शरीर ही ब्रह्माण्ड

इच्छापूर्ति का साधन प्राण है। मन के पीछे-पीछे ही चलता है। इच्छा का स्वरूप वर्ण और प्रकृति से तय होता है। जीवन के लक्ष्य से तय होता है। प्रारब्ध से तय होता है। प्राण स्वयं भी रजोगुणी होने से गतिमान तत्त्व है। मन-इच्छा-फल में गति नहीं होती। अत: इच्छापूर्ति के लिए प्राणों की शक्ति को बढ़ाना आवश्यक है।

विश्व में दो प्रकार की सृष्टि है- जड़ और चेतन। जड़ लक्ष्मी है, चेतन सरस्वती। जड़ सोम है, चेतन अग्नि। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन। किसी भी क्रिया के लिए पहले इच्छा आवश्यक है। क्रिया शरीर करता है- जड़ है। इच्छा पूरी करने के लिए इसकी पहले स्वीकृति आवश्यक है, जो बुद्धि से प्राप्त होती है। क्योंकि बिना ज्ञान के इच्छा पैदा ही नहीं होती। आज मानव सभ्यता मनमानी और बुद्धिमानी पर ही टिकी हुई है। दोनों ही निरंकुश हैं। अर्थ और काम की प्राथमिकता ने वर्तमान संस्कृति को लगभग निर्जीव कर दिया। दोनों ही आत्मा-चेतना के धर्म नहीं हैं। अनेक प्राणी शरीर-बुद्धि-मन के क्षेत्रों में मानव से श्रेष्ठ होते हैं। ये तीनों आत्मा के साधन कहे गए हैं। अभिव्यक्ति सदा ही भावना की होती है। इसका कारण व्यक्ति की प्रकृति-स्वभाव (सत्व-रज-तम) होता है। कुछ प्रभाव पूर्वजन्मों का भी रहता है।

व्यक्ति का जन्म सृष्टि के आदि स्वरूप में ईश्वर के अंश रूप में होता है। ईश्वर सूक्ष्म सृष्टि में रहता है, तो मैं- उसकी संतान सूक्ष्म ही हूं। स्वयं को दिखाई कहां देता हूं! दिखाई देने के लिए पहले मुझे एक स्वरूप ग्रहण करना होगा, जिस पर आवरण लपेटना पड़ेगा। ऋत पदार्थ (हवा जैसे) पर आवरण नहीं चढ़ाया जा सकता। चूंकि हमारा जन्म सूर्य से आगे होता है, वहां ऋत भाव में ही सृष्टि उत्पन्न होती है। वही मेरा मूल स्वरूप (ईश्वर अंश) है। वहां से षोडशकल आत्मा बिन्दुरूप में नीचे उतरता है। पर्जन्य में जलरूप बादल बनकर आकाश में विचरण करता है। वायु के माध्यम से बरसने का क्षेत्र तय होता है। ऋतभाव से चलकर बिन्दु (जल) बना। पृथ्वी की अग्नि में आहूत हुआ। पृथ्वी में पांचों महाभूत सम्मिलित रहते हैं। यहां अन्न पैदा होता है। मैं अन्न की देह में बसता हूं। अन्न के दाने में आने से पहले मैं अन्तरिक्ष से गुजरता हूं। वहां मेरे स्वरूप में चार प्रकार के गुण सम्मिलित हो जाते हैं- दधि-घृत-मधु और अमृत। इनसे ही अन्न का शरीर निर्मित होता है।

अन्न पार्थिव स्थूल पदार्थ है। मनुष्य अन्न का भोग करता है। अन्न जठराग्नि में जाता है और शरीर की सप्त धातुओं का निर्माण करता है। ये सारा पार्थिव क्रम है। अन्तिम धातु शुक्र बनता है। इसमें चेतना का भाग रहता है- शुक्राणु रूप में। पृथ्वी ने जड़ शरीर बनाया। आगे चेतना का विकास है। शुक्राणु के भी शरीर-मन-बुद्धि-आत्मा हैं। कौनसा शुक्राणु कब रूपान्तरित होगा, यह भी तय होता ही है।

शुक्र का एक भाग रज से संयुक्त होकर नई सृष्टि का निर्माण करता है, वहीं दूसरा भाग पुरुष का ओज और मन बढ़ाता है। शुक्र स्वयं में एक ब्रह्माण्ड है। शुक्राणु का शुक्र ब्रह्म है। उसमें प्रकृति, अहंकृति, आकृति, वर्ण, पितर प्राण, हृदयस्थ तीनों अक्षर प्राण एवं पंच तन्मात्रा- पंच महाभूत सम्मिलित रहते हैं। मेरा यह सम्पूर्ण रूप रज में प्रविष्ट होकर संतान रूप में मेरी प्रतिष्ठा बनता है। इस विकास क्रम में सूर्य से पृथ्वी तक के सभी देवताओं का सहयोग रहता है। गीता में कृष्ण कहते हैं कि हम यज्ञ से देवताओं को पुष्ट करें, वे हमारी इच्छाओं को पूर्ण करें। शास्त्र यह भी कहते हैं कि देवता भाव के भूखे हैं। क्योंकि भाव तो मन में उठते हैं। अच्छे-बुरे दोनों दिशाओं में उठते हैं। तीन शरीर हैं हमारे, तो मन भी तीन हैं। चौथा मन ईश्वर का मन (अव्यय मन/कृष्ण रूप) है। अत: मन के भी दो रूप हो जाते हैं- भाव और अभाव।

भाव जीवन का सकारात्मक पहलू है। अभाव नकारात्मक होने से मृत्यु सूचक माना गया है। भाव का एक अर्थ है- ईश्वर में आस्था। जो कुछ ईश्वर ने दिया उसमें संतुष्टि। पिछले कर्मों के फलरूप यही था मिलना। जो नहीं मिला, उस पर मेरा अधिकार नहीं है। जीवन का दूसरा पहलू है- लालसा-स्पृहा। यह भी चाहिए, वह भी चाहिए। चूंकि हम अविद्या के कारण पैदा होते हैं, अतः अभाव से ही जीवन शुरू होता है। गीता में कहा है-

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सत:।
उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभि:।।
(गीता 2.16)

असत् की सत्ता नहीं होती, सत् का अभाव नहीं होता। सत् की सत्ता तीनों कालों में रहती है। असत् बीच में खो जाता है। मूल में तो एक ही है- ईश्वर। उसका कभी अभाव नहीं है। अन्य सत्ताएं/अवस्थाएं असत् ही कही जाएंगी। सभी आभूषणों में स्वर्ण की सत्ता है, किन्तु गहनों का स्वरूप असत् है। 'नहीं है' कहने पर अभाव में भी अस्ति भाव रहता है। यह अस्तिबुद्धि ज्ञान से सिद्ध होती है। जब हम जानते हैं, तभी 'हैं' कहते हैं। अक्षर और क्षर अव्यय से प्रादुर्भूत होकर उसी में लीन हो जाते हैं। अव्यय का विनाश नहीं होता, सत् है। वेदान्त में अज्ञान से आवृत्त हो जाना ही विनाश है। वेद भी अभाव को ही सम्बोधित करते हैं। वैदिक यज्ञ फलों की वासना के विस्तार हैं। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी गुण (सत्व-रज-तम) की प्रधानता लिए रहता है। उसी के अनुरूप उसकी कामना होती है। रजोगुण वाले कामना प्रधान पुरुष संसार में बहुत हैं। उनकी पूर्ति के लिए विविध कर्म वेद में दिए गए हैं। कामना ही अभाव सूचक है तथा कर्म की प्रेरक शक्ति है। अत: कृष्ण कहते हैं-

त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन।
निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्।।
(गीता 2.45)

वेद तो तीनों गुणों वाले पुरुषों के लिए हैं। कामनाओं से तो कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। आत्मा निष्काम है, कर्म भी तटस्थ हैं। कामना में द्वन्द्व है, भाव-अभाव है, बन्धन है। संसार चारों ओर इन्द्रिय विषयों से भरा है। मन भी सदा नया चाहता है, चंचल है। त्रिगुणों से बाहर आकर ही व्यक्ति ऊंचा उठ सकता है। राग और द्वेष दोनों ही बांधकर रखने वाले हैं। अभाव का कारण राग भी है, तृष्णा है, परिग्रह है, स्पर्धा है। लेने का स्वभाव, स्वार्थ, संकुचन अथवा अल्प-प्राण अभाव का भाव उत्पन्न करते हैं। अभाव का स्वरूप इच्छा है-कुछ पाने की इच्छा। इच्छा ही प्रकृति है, माया है। यही अभाव पैदा करती है, यही पूर्ति भी करती है। दुर्गा सप्तशती में इसका विस्तृत विवरण प्राप्त होता है।

'या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता:'। ये क्षुधा (भूख) ही अभाव की सूचक है। कुछ चाहिए। और चाहिए। इसका पता नहीं कि क्यों चाहिए। व्यक्ति के मन का संकोच बढ़ता चला जाता है। वांछित वस्तु न मिले तो द्वेष-क्रोध आकर राग से जुड़ जाते हैं। मिल जाए, मिल जाए, फिर और मिल जाए तो मोह घेर लेता है। गीता में कृष्ण कहते हैं कि मोह से स्मृति विभ्रम, बुद्धि विनाश हो जाता है। तब व्यक्ति की शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। पतन ही मृत्यु है, उत्थान ही जीवन है।

इच्छापूर्ति का साधन प्राण है। मन के पीछे-पीछे ही चलता है। इच्छा का स्वरूप वर्ण और प्रकृति से तय होता है। जीवन के लक्ष्य से तय होता है। प्रारब्ध से तय होता है। प्राण स्वयं भी रजोगुणी होने से गतिमान तत्त्व है। मन-इच्छा-फल में गति नहीं होती। अत: इच्छापूर्ति के लिए प्राणों की शक्ति को बढ़ाना आवश्यक है। गति और लक्ष्य की दिशा का समन्वय होना आवश्यक है। यह कार्य अभाव की मानसिकता को अभ्यास द्वारा दूर करने पर ही संभव है। अभाव की क्रिया तो पतन का ही मार्ग है। खण्डित आत्मभाव दर्शाता है। हमें शास्त्र मार्ग देते हैं- इन्द्रिय संयम का। इसके लिए भी शुरू तो मन से करना पड़ेगा। मन को शान्त कर लेना ही विषयों के प्रति अनासक्त हो जाना है। अभाव से हटते-हटते व्यक्ति का बोध उसे भाव से भी मुक्त कर देता है। स्थितप्रज्ञ बना देता है।

क्रमश:

gulabkothari@epatrika.com

क्यूआर कोड को स्कैन कर आप आलेख सुन भी सकते हैं।

आर्ट एंड कल्चर

सभ्यता और संस्कृति की छाया रूप होती हैं कलाएं

कोई एक कला अपने आप में पूर्ण नहीं होती, दूसरी में घुलकर ही वह संपूर्णता को प्राप्त करती है। उदयशंकर ने कलाओं के अन्तर्संबंधों को साधा।

कलाएं सभ्यता और संस्कृति की छाया रूप हैं। कोई कलारूप ऐसे ही विकसित नहीं होता, वह समाज की किसी परंपरा में धीरे धीरे परिष्कृत होता बढ़त करता है। पता ही नहीं चलता कब कोई परंपरा कैसे कला का रूप ले संस्कृति की सिरमौर बन जाती है। ब्रज जनपद में कभी एक नृत्य होता था, हल्लिरास। श्री कृष्ण-राधा के रास का ही यह लोक रूप था। कब इसने आधुनिक 'गरबा' और 'डांडिया रास' का रूप ले लिया, पता ही नहीं चला। राजस्थान में 'घुड़लो घूमेला जी घूमेला...' बोल पर नृत्य होता है। सिर पर बहुत सारे छेद वाली मटकी और उसमें जलते हुए दीपकों को रखकर यह नृत्य महिलाएं करती रही हैं। इसी का एक रूप घड़े में आग जलाकर उसे सिर पर रख नाचने का हो गया। पर घुड़ले की कहानी इतर है।

डॉ. राजेश कुमार व्यास
संस्कृतिकर्मी, कवि और कला समीक्षक
@patrika.com

मुगल सूबेदार घुड़ले खां जब औरतों को अगवा कर ले जा रहा था तो जोधपुर के राव सातल ने युद्ध में उसे मारकर महिलाओं को मुक्त कराया। घुड़ले खान का कटा सिर रख तब मारवाड़ में महिलाओं ने विजयी नृत्य किया। इसमें उत्सव संग शोक भी था। छोटा घड़ा, इस पर घुड़ले खान के चेहरे पर हुए घाव के प्रतीक रूप में छिद्र और अंदर राव सातल की स्मृति में जलता हुआ दीपक। घर-घर नृत्य करते जाते गाया जाता 'म्हारो तेल बळै घी घाल घुड़लो घुमेला जी घुमेला।' दीप-दर्शन कर लोग उस पर चढ़ावा चढ़ाते। चैत्र नवरात्र की तीज पर गवर के साथ घुड़ले का भी विसर्जन होता है। यह परंपरा नृत्य-रंजन हो गई।

प्रख्यात नर्तक उदयशंकर ने बैले में भारतीय शास्त्रीय और लोक नृत्यों की परम्पराएं घोलीं। नृत्य शिल्पी के रूप में उन्होंने विश्वभर में भारतीय मंदिर वास्तुकला, मूर्तिकला और अजंता चित्रों संग राजपूत और मुगल लघु चित्रों के विरल नृत्य-रूप गढ़े। नृत्य संस्कृति का अनुष्ठान बन गया। उनकी कल्पित नृत्य-सरंचनाओं में शंकर-पार्वती, राधा-कृष्ण, कार्तिकेय आदि जगचावे हुए। मूलतः उदयशंकर राजस्थान के झालावाड़ से थे। रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में उन्होंने चित्रकला की पढ़ाई की। लंदन में उनका प्रख्यात बैले नर्तकी अन्ना पावालोवा से संपर्क हुआ और उसके बाद वह पूरी तरह से नृत्य में रम गए। यूरोप में सिमोन बारविए 'सिमकी' के साथ उनकी शंकर–पार्वती, राधा-कृष्ण नृत्य मुद्राएं बहुत लोकप्रिय हुईं। भारत आने पर बाद में पत्नी अमला शंकर के साथ नृत्य संयोजन में उन्होंने भारत की पहली नृत्य-केंद्रित फिल्म 'कल्पना' बनाई। इस फिल्म को पूरा करने का जुनून उदयशंकर को इस कदर था कि शूटिंग के दौरान उन्हें तेज बुखार रहता, फिर भी वह इसे पूरा करने में लगे रहे। यह फिल्म नृत्य की भारतीय दृष्टि ही नहीं है बल्कि कलाओं के आपसी संबंधों से जुड़ी परम्परा की भी साधना है।

कलाएं क्या हैं? मिथकों, धार्मिक विश्वासों और दैनिक कार्यकलापो में जीवन से जुड़ी सहज दृष्टि ही तो! कोई एक कला अपने आप में पूर्ण नहीं होती, दूसरी में घुलकर ही वह संपूर्णता को प्राप्त करती है। नृत्य, संगीत, नाट्य संग वास्तु और मंदिर स्थापत्य का मेल कर उदयशंकर ने कलाओं के अन्तर्संबंधों को साधा। इसी से वह भारतीय नृत्य के विश्वभर में अग्रदूत हुए। आनंद कुमार स्वामी चित्र और मूर्तिकला के जिस तरह से भारत-प्रवक्ता बने, मुझे लगता है कि पश्चिम में भारतीय नृत्य के वैसे ही अग्रदूत उदयशंकर हुए। यह विडम्बना ही है कि हमने उन्हें इस अवदान के लिए बहुत अधिक स्मरण नहीं किया है।

रियलमोंटे साल्ट माइन: इटली में नमक का भंडार

इटली के एग्रीजेंटो प्रांत में रियलमोंटे और पलेर्मो प्रांत में राकालमुटो और पेट्रालिया तीन नमक की खदानें हैं, जिनका प्रबंधन इटालकाली कंपनी करती है। रियलमोंटे क्षेत्र, सिसिली के दक्षिणी तट पर स्थित है, जो एग्रीजेंटो से लगभग चार किलोमीटर और इटली के पोर्टो एम्पेडोकल से एक किलोमीटर दूर है। रियलमोंटे प्रति वर्ष लगभग 500 हजार टन नमक का उत्पादन करने में सक्षम है। राकालमुटो, पिछली शताब्दी में एक महत्वपूर्ण खनन केंद्र बन गया और नमक उद्योग में भी कुछ वृद्धि हुई। स्थानीय अर्थव्यवस्था में नमक की इन खदानों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। आज अतीत की तुलना में, नमक की खदानें अधिक सुरक्षित हैं, क्योंकि खदानों के जोखिम वाले इलाकों में रिमोट से नियंत्रित इलेक्ट्रिक फावड़े लगाए जाते हैं।

सामयिक: धर्मतंत्र वाली व्यवस्था को सुधारवादी पेजेशकियान और मध्यम-मार्गी कालिबफ में से किसी से भी भयावह खतरा नहीं

ईरान: वैधता के दिखावे के लिए शासन चाहता है ज्यादा मतदान

जेसन रिजेअन
वर्ष 2012 से लेकर 2016 तक तेहरान में 'द पोस्ट' के संवाददाता रहे
द वाशिंगटन पोस्ट
से विशेष अनुबंध के तहत

मुख्य चुनावी मुकाबला पेजेशकियान और कालिबफ के बीच है। जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे, वही जीतेगा। पर यदि जीत कट्टरपंथी की होती है तो यह प्रदर्शित होगा कि अंधेरे से बाहर निकलने का अब कोई रास्ता नहीं बचा है।

पिछले माह हेलिकॉप्टर हादसे में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के बाद नए राष्ट्रपति को चुनने के लिए इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान में शुक्रवार को मतदान हुआ। नाम वापसी के बाद दौड़ में चार ही उम्मीदवार लोगों के चुनाव के लिए बचे। इनमें से भी जो सफल हो सकते हैं वे तीन उम्मीदवार हैं – पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मसूद पेजेशकियान (हार्ट सर्जन और एकमात्र सुधारवादी उम्मीदवार) जो लाखों ईरानियों के लिए बेहतर कल की उम्मीदों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं; कट्टरपंथी सईद जलीली, जो एक दशक से भी काफी पहले से ईरान के प्रमुख परमाणु वार्ताकार थे और अब भी बाहरी दबाव को लेकर प्रतिरोध के उन्हीं सिद्धांतों के लिए प्रतिबद्ध हैं; तथा संसद के मौजूदा स्पीकर और तेहरान के पूर्व मेयर मोहम्मद बखेर कालिबफ जो भ्रष्टाचार के कई मामलों में उलझे हैं और सत्तालोलुप व्यावहारिक टेक्नोक्रेट के तौर पर जाने जाते हैं।

तेहरान जैसी शासन-व्यवस्था में चुनाव न तो स्वतंत्र हैं और न ही निष्पक्ष, पर कोई भी इस चुनाव को लेकर भ्रम न पाले। इस मतदान के काफी निहितार्थ हैं। यह चुनाव गहरी आंतरिक और क्षेत्रीय उथल-पुथल के दौरान हो रहे हैं। ऐसे में इस्लामी गणतंत्र की दीर्घकालिक व्यवहार्यता पर इसका असर पड़ेगा। ईरान की धर्मतंत्र वाली व्यवस्था आज लोगों के व्यापक और बढ़ते असंतोष से जूझ रही है। इसकी वजह बहुत हद तक कमजोर अर्थव्यवस्था है। अगर अधिसंख्य ईरानी मतदाता चुनाव में भाग न लें तो देश की सर्वाधिक संकुचित विचारों वाली ताकतें और प्रतिगामी इरादों वाले लोग अपना शासन बिना रोक-टोक जारी रखेंगे। पर लोकप्रिय वैधता के दिखावे के बिना भी वे ऐसा ही करेंगे। दूसरी तरफ, यदि लोग बड़ी संख्या में मतदान करेंगे तो जरूर स्थिति पेचीदा हो जाएगी। कड़ी निगरानी में चुनाव कराए जाने के बावजूद, ऐतिहासिक रूप से राष्ट्रपति चुनाव ईरानियों के लिए वोट के जरिए शासन के बारे में कोई फैसला लेने का एकमात्र अवसर होता है। यही वजह है कि ईरान के चुनाव परिणाम अप्रत्याशित रहे हैं। ईरानियों ने राष्ट्रपति चुनावों में जब-जब भारी मतदान किया, उन्होंने तथाकथित सुधारवादी उम्मीदवारों को वोट दिया, जिन्होंने विदेशी निवेश के लिए देश के दरवाजे खोलने, बाकी दुनिया के साथ बेहतर संबंध और सामाजिक प्रतिबंधों में ढील देने का वाद किया था। यहां इस बात का स्मरण महत्त्वपूर्ण है कि इन सुधारवादियों की कोशिश इस्लामिक रिपब्लिक में भारी-भरकम बदलाव करना नहीं, बल्कि सुधार के जरिए इसकी उम्र बढ़ाने की रही है।

उदाहरण के लिए, 2013 में कई पर्यवेक्षक यह विश्वास करने लगे थे कि कट्टरपंथी जलीली- जो इस बार भी उम्मीदवार हैं, का जीतना तय है। पर बड़ी संख्या में लोग आश्वस्त नहीं थे। चुनाव के नजदीक आने पर हसन रूहानी को समर्थन मिला क्योंकि उन्होंने पश्चिम के साथ जुड़ाव का वादा किया था ताकि ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाए जा सकें। रूहानी ने शानदार जीत हासिल की, जबकि जलीली तीसरे स्थान पर रहे। इस वर्ष के एक दावेदार कालिबाफ 2013 में दूसरे स्थान पर रहे थे।

बड़ा सवाल, क्या पेजेशकियान को लेकर इतिहास फिर खुद को दोहरा सकता है? पेजेशकियान ने महिलाओं के लिए हिजाब को अनिवार्य बनाने के कठोर क्रियान्वयन की बुद्धिमत्ता पर विशेष रूप से सवाल उठाया है। वह अपना उद्देश्य कैसे हासिल करेंगे, यह साफ नहीं है। पर पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद खातमी समेत अन्य नेताओं ने उनका समर्थन किया है। जलीली के अलगाववादी विचारों बार-बार खारिज हुए हैं, जबकि कालिबफ बीच का रास्ता अपनाते हैं – समाज पर दृढ़ अधिनायकवादी पकड़ बनाए रखने के साथ लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए पश्चिम के साथ एक आवश्यक बुराई के रूप में बातचीत। ऐसे में, मुख्य चुनावी मुकाबला पेजेशकियान और कालिबफ के बीच है। जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे, वही जीतेगा। दोनों में से किसी से भी भयावह खतरा नहीं है।

आपकी बात

जरूरी है नियमित दिनचर्या

खराब जीवनशैली बीमारी को निमंत्रण देती है। जिस व्यक्ति की दिनचर्या नियमित है और जो दिन में भरपेट तथा रात को अल्प भोजन ग्रहण करता हो वह स्वस्थ रहता है। अधिक खट्टे, मीठे, तीखे, कसैले और नमकीन खान-पान से भी बचना चाहिए। योग करना चाहिए और घूमना चाहिए। जो जीवनशैली पर ध्यान नहीं देता और मनमानी करता है, वह बीमारी से बच नहीं सकता

-बी. एल. शर्मा, उज्जैन, मप्र

भविष्य से खिलवाड़

स्वस्थ जीवनशैली के मुख्य रूप से चार पायदान होते हैं। व्यायाम, सोचने समझने एवं प्रतिक्रिया व्यक्त करने का अंदाज, विश्राम एवं भोजन। उपरोक्त चार महत्त्वपूर्ण मामलों में जो भी अनुशासित होता है, वह ज्यादा स्वस्थ होता है। व्यायाम, सकारात्मक सोच, उम्र के अनुसार नींद एवं पौष्टिक आहार ही हमारे स्वास्थ्य की कुंजी है।

-डॉ. लोकमणि गुप्ता, कोटा

स्वाद है सेहत का दुश्मन

खाने-पीने की चीजों में सिर्फ स्वाद पर ध्यान देने और नशा करने से शारीरिक सेहत ही नहीं मानसिक सेहत भी खराब होती है। बीमारी होने पर आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाती है। इसलिए खान-पान के मामले में सावधान रहना चाहिए और नशे से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। सिर्फ स्वाद नहीं, स्वस्थ रहने के लिए खाना चाहिए।

-राजेंद्र पटेल, मांडावास, पाली

आज का सवाल

सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण कैसे रोका जा सकता है?

ईमेल करें: edit@epatrika.com

कल का सवाल था: खराब जीवनशैली सेहत को किस तरह से नुकसान पहुंचाती है?

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 115

सही रवैया

दूरसंचार स्पेक्ट्रम नीलामी का ताजा दौर केवल दो दिन में समाप्त हो गया और इस दौरान बोली से लगभग 11,000 करोड़ रुपये आए। इससे पता चलता है कि मांग में कमी है लेकिन स्पेक्ट्रम के लिए रुचि में कमी नहीं दिखी। स्पेक्ट्रम ऐसा दुर्लभ प्राकृतिक संसाधन है जो दूरसंचार सेवाओं के संचालन के लिए जरूरी है। आगे भी स्पेक्ट्रम नीलामी ऐसी ही होनी चाहिए। यानी संतुलित और जरूरत आधारित, न कि अतीत की तरह सार्वजनिक तमाशा जब कंपनियों को अपनी क्षमता से परे जाकर काम करना पड़ा। वर्ष 2012 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पेक्ट्रम की खुली और पारदर्शी नीलामी की प्रक्रिया का सिद्धांत तय किया था और कहा था कि बोली की प्रक्रिया को हर स्थिति में सरकार के लिए राजस्व बढ़ाने का माध्यम नहीं समझा जाना चाहिए। बुधवार को समाप्त हुई बोली इसी भावना के अनुरूप हुई। नीलामी के बाद केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि क्यों बोली कमजोर रही। उन्होंने कहा कि जरूरी स्पेक्ट्रम का बड़ा हिस्सा 2022 में ही नीलाम कर दिया गया था। दो वर्ष पहले जब दूरसंचार उद्योग 5जी सेवाओं की शुरुआत के लिए तैयार हो रहा था और जिसके कारण डाउनलोड गति में तेजी आनी थी और अगली पीढ़ी के मोबाइल नेटवर्क तैयार होने थे, उस समय उद्योग जगत ने इन तरंगों को खरीदने के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये की राशि व्यय की थी।

बातों को इस संदर्भ में रखते हुए देखें तो स्पेक्ट्रम की कम मांग शायद ही राजकोष पर बुरा असर डाले। सरकार ने अंतरिम बजट में वित्त वर्ष 25 के दौरान दूरसंचार संवाओं से 1.2 लाख करोड़ रुपये के गैर कर राजस्व संग्रह का लक्ष्य तय किया है। स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए कोई आधिकारिक लक्ष्य नहीं था लेकिन संकेत मिलते हैं कि सरकार को इस बिक्री से कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं थी यानी वित्त वर्ष 25 की पहली किस्त से करीब 500 करोड़ रुपये। वर्तमान 11,000 करोड़ रुपये की राशि अपेक्षाओं से काफी अधिक है।

दूरसंचार उद्योग जो बीते वर्षों में कई तरह के उतार-चढ़ाव से गुजरा है, उसने अपनी जरूरतों के मुताबिक बैंड और फ्रीक्वेंसी का चयन करने में सतर्कता बरती है। इस बार खरीदे गए स्पेक्ट्रम का एक बड़ा हिस्सा उन तरंगों के नवीनीकरण के लिए है जिनका परमिट समाप्त होने वाला है। भारती एयरटेल और वोडाफोन से तुलना करें तो अपेक्षाकृत नई कंपनी रिलायंस जियो ने कम बोली लगाई क्योंकि उसके किसी स्पेक्ट्रम की अवधि समाप्त नहीं हो रही है। अगर 2010 की 3जी स्पेक्ट्रम नीलामी से तुलना की जाए तो उस समय बोली की प्रक्रिया 34 दिन तक चली थी और इस बार यह दो दिन में समाप्त हो गई। इससे पता चलता है कि कंपनियों ने भी संतुलित रुख अपनाया है। इससे पहले 2022 में भी 5जी तरंगों की रिकॉर्ड बोली लगी थी और दूरसंचार कंपनियों को भी अगली बोली से पहले थोड़ा समय मिल गया था।

सरकार की इस बात के लिए सराहना की जानी चाहिए कि उसने उद्योग जगत को यह अवसर दिया कि वह अपनी सुविधा और समय के हिसाब से स्पेक्ट्रम खरीदे बजाय कि भविष्य की कोई जानकारी हुए बिना स्पेक्ट्रम की जमाखोरी करने के। सरकार ने सालाना स्पेक्ट्रम नीलामी को लक्ष्य के रूप में स्पष्ट करके दूरसंचार क्षेत्र के काम की सुगमता में योगदान किया है। इसके अलावा कंपनियों के पास भी यह विकल्प है कि वे सरकार को स्पेक्ट्रम के लिए सालाना राशि चुकाएं। इससे दूरसंचार उद्योग का वित्तीय दबाव कम होगा जो गत वर्ष 6.4 लाख करोड़ रुपये के कर्ज में फंसा था।

अब जबकि रिलायंस जियो और एयरटेल ने कदम उठा लिया है तो अन्य कंपनियां भी अपनी शुल्क दरों में इजाफा करेंगी ताकि बाजार कहीं दो कंपनियों में बंटकर नहीं रह जाए। इसके अलावा दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार होना चाहिए, 5जी का इस्तेमाल बढ़ना चाहिए और डाउनलोड की गति भी उपभोक्ताओं की अपेक्षाओं के अनुरूप होनी चाहिए।

अजय मोहंती

चीन से होने वाले आयात के विरुद्ध व्यापार अवरोध

भारत पड़ोसी देश चीन से आयात में सतर्कता बरते और शेष विश्व के साथ कारोबारी समायोजन बढ़ाए। सुझाव दे रहे हैं अजय शाह और इला पटनायक

ऑटार्की यानी आम जन की सीमा पार गतिविधियों में सरकारी हस्तक्षेप के विपरीत परिणामों की पूरी समझ अर्थशास्त्र में पेशेवर दक्षता की पहचान है। परंतु आज पूरी दुनिया असाधारण परिस्थितियों से दो चार हैः चीन की वृहद आर्थिक नीति की दिक्कतें दुनिया भर में विपरीत प्रभाव डाल रही हैं। हम मानते हैं कि भारत की सरकारी शक्ति का इस्तेमाल करके चीनी निर्यात के देश में पहुंचने के मार्ग में व्यापारिक गतिरोध खड़ा करने के फायदे हैं। ये कदम उस पूर्ण नीतिगत पैकेज का हिस्सा होने चाहिए जो भारतीय अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाता है।

शी चिनफिंग साल 2013 में सत्ता में आए। उनके अधीन 'चीन मॉडल' फला फूला। इसमें देश पर सरकार के नियंत्रण, सत्ता का केंद्रीकरण, आर्थिक राष्ट्रवाद, पश्चिम के विरुद्ध शत्रु भाव, हमेशा लोगों के खिलाफ कार्रवाई का खतरा, कुलीनों की व्यक्तिगत सुरक्षा की कमी जैसी बातें शामिल रहीं। ऐसे अधिनायकवादी शासन वृद्धि के कम ही अवसर बनाते हैं। यही वजह है कि शी चिनफिंग के 11 वर्ष के कार्यकाल में चीन की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी नहीं रही।

एक समय बेहतर स्थिति में रही निजी निवेश की प्रक्रिया का भी पतन हो चुका है। एक परिसंपत्ति वर्ग के रूप में अचल संपत्ति को लेकर अति उत्साह भी अब इसकी कीमतों में गिरावट में तब्दील हो गया है और अधिकांश संपत्तियां खाली पड़ी हैं। विदेशी कंपनियां, निवेशक और आम लोग चीन में अपनी गतिविधि कम कर रहे हैं। ब्याज का उच्च स्तर भी व्यवस्थित स्थिरता को चुनौती प्रदान कर रहा है।

आंतरिक आर्थिक कमजोरियों के बावजूद चीन की विदेश नीति में अहंकारपूर्ण रुख रहा है। सीमा पर भूटान और भारत के साथ सैन्य झड़प चीन में सक्रिय राष्ट्रवाद के उदाहरण हैं। आज दुनिया के सामने मौजूद विदेश नीति संबंधी सबसे बड़ मुद्दे की बात करें तो चीन ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण का समर्थन किया है। वहीं चीन द्वारा ताइवान पर आक्रमण की आशंका भी बनी हुई है।

2018 के बाद इन घटनाओं का असर वैश्वीकरण की प्रकृति पर नजर आने लगा जिसे तीसरा वैश्वीकरण नाम दिया गया। 1982 से 2018 तक दूसरे वैश्वीकरण में चीन तथा भारत जैसे देशों को बिना शर्त पहुंच मिली थी। तीसरे वैश्वीकरण में एक पंक्ति खींच दी गई। अब अगर कोई देश विदेश नीति या सैन्य मामलों में शत्रुतापूर्ण रुख रखता है तो उस देश को आर्थिक एकीकरण में सीमित अवसर मिलते हैं। अब विकसित देश तथा उनके सहयोगी एक दूसरे के साथ पूर्ण वैश्वीकरण आजमाते हैं लेकिन जो देश विदेश नीति या सैन्य नीति में उनके अनुकल नहीं हैं, उनकी बुनियादी संसाधनों तक पहुंच सीमित की गई। वर्ष 2018 के बाद से विकसित देशों की ओर से चीन के साथ सीमा पार व्यापार पर बड़ी संख्या में प्रतिबंध लगाए गए। चार अहम क्षेत्र जहां दिक्कत आ रही है वे हैं इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी, सोलर पैनल तथा माइक्रो चिप।

चीन की अर्थव्यवस्था की कमजोरी की वजह खराब घरेलू नीतियां और विकसित देशों द्वारा उठाए गए कदमों का मिश्रण भी है। वहां घरेलू मांग अधिक नहीं है। कई चीनी कंपनियों के सामने कीमत कम करने या बंदी की स्थिति है। आर्थिक मोर्चे पर नाकामी ने सत्ता तंत्र के लिए आर्थिक और राजनीतिक दिक्कत पैदा की। सरकार की चाह तो यही होती है कि कंपनियां अधिक से अधिक बेचें, ज्यादा निर्यात करें और रोजगार बढ़ाएं। चीन में समेकित खुदरा मूल्य सूचकांक बास्केट में अपस्फीति की स्थिति है। ऐसे में अमेरिकी डॉलर में चीनी निर्यात का मूल्य गिरा और उसमें और गिरावट आने की उम्मीद है।

समय के साथ और चीन में आर्थिक और राजनीतिक बदलाव आने पर ये समस्याएं हल हो जाएंगी। इस बीच चीन की ओर से सस्ती वस्तुओं का निर्यात उन देशों में कंपनियों या समूचे उद्योगों के खात्मे के खतरे के साथ आता है जो वास्तव में उन्हीं वस्तुओं का महंगा निर्माण करते हैं। विकसित देशों ने इन बातों को देखते हुए चीनी आयात पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। गत 12 जून को यूरोपीय आयोग ने चीन में बने इलेक्ट्रिक वाहनों पर 48 फीसदी शुल्क लगाने की घोषणा की। यह बहुत ही असाधारण दर है क्योंकि कई दशकों से ऐसे शुल्क की दरें एक अंक में रही हैं।

विकसित देशों को निर्यात करने में हो रही मुश्किलों को देखते हुए चीन की कंपनियों ने स्वाभाविक तौर पर शेष विश्व में निर्यात बढ़ाने पर जोर देना शुरू किया। 2018 में चीन के निर्यात में आसियान, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका की हिस्सेदारी क्रमशः 12.9 फीसदी, 5.8 फीसदी और 4.2 फीसदी थी जो अब बढ़कर 15.7 फीसदी, 7.8 फीसदी और 5.5 फीसदी रह गई है। यह वह वैश्विक परिदृश्य है जिसमें हमें भारत में चीन का आयात बढ़ता नजर आ रहा है। 2018 से 2023 के बीच अमेरिकी डॉलर में चीन के निर्यात की कुल वृद्धि 36 फीसदी थी। इस अवधि में भारत में उसका निर्यात 53 फीसदी बढ़ा। हमारा मानना है कि भारत के लिए अब बेहतर यही है कि वह चीनी निर्यात और चीनी कंपनियों के विदेशी उत्पादन केंद्रों के विरुद्ध गैर टैरिफ गतिरोध खड़े करे। हम यह भी मानते हैं कि यह संरक्षणवाद है और मजबूत विकास नीति के विरुद्ध है परंतु इस विशेष क्षण में हमारा मानना है कि एक खास कारोबारी साझेदार के साथ ऐसा किया जा सकता है।

इसके अलावा भी कई कदमों की आवश्यकता है ताकि अंतरराष्ट्रीय एकीकरण के लाभों को बरकरार रखा जा सके और भारतीय कंपनियों के कामकाज में भी सुधार किया जा सके। इनवर्टेड शुल्क ढांचे के कई मामले हैं जिन्हें दूर करना है। जीएसटी सुधार बहुत समय से लंबित हैं और इसकी दरों की तादाद कम करने की जरूरत है। दरों में भी कमी करने की जरूरत है। इसके अलावा ऊर्जा और रेलवे जैसे उद्योगों में व्यापक एकीकरण की आवश्यकता है।

भारत में चीन के आयात के खिलाफ गैर टैरिफ अवरोध के साथ उदारीकरण के अन्य तत्त्वों का समायोजन करना होगा। मसलन अन्य देशों के साथ संबद्धता में इजाफा करना होगा। ऐसा करके भारत को हर मायने में उदारीकरण का पूरा लाभ मिल सकेगा। वह एक देश को छोड़कर शेष पूरे विश्व के साथ वस्तु, सेवा, पूंजी और श्रम के क्षेत्र में रिश्ते कायम कर सकेगा।

केवल एक कारोबारी साझेदार के साथ संरक्षणवाद के तरीके अपनाते हुए कारोबार करने के लिए आर्थिक नीति में विशिष्ट क्षमताओं की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही ऐसे तमाम पूरक उपायों को भी अपनाना होगा जो शेष विश्व के साथ पारंपरिक भारतीय संरक्षणवादी रिश्ते नहीं बनने दें। 2024 में देश के नीति निर्माताओं के लिए ऐसी रणनीति बनाना एक बड़ी चुनौती होगी।

(शाह एक्सकेडीआर फोरम में शोधकर्ता और पटनायक आदित्य बिड़ला समूह में मुख्य अर्थशास्त्री हैं। लेख में विचार व्यक्तिगत हैं)

मोदी सरकार का हरित एजेंडा

ऊर्जा शक्ति

वंदना गोंबर

लोक सभा नतीजों की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पहले संबोधन में 'हरित युग' की शुरुआत का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि भारत किस तरह हरित औद्योगीकरण, हरित ऊर्जा और हरित वाहन खंडों में अग्रणी देश बनना चाहता है। प्रधानमंत्री द्वारा कही गई ये बातें संकेत देती हैं कि हरित विकास में सरकार किन प्राथमिकताओं के साथ आगे बढ़ेगी।

हरित ऊर्जा –विशेषकर सौर एवं पवन ऊर्जा- की बात करें तो भारत सालाना अपनी क्षमता बढ़ाने में दुनिया के शीर्ष देशों में शुमार है और वह इसे (हरित ऊर्जा) और बढ़ावा देने के लिए स्थानीय विनिर्माण क्षमता का और विस्तार कर रहा है। जो भी देश स्थानीय स्तर पर विनिर्माण बढ़ाने का प्रयास कर रहा है उसे एक अलग प्रकार की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।

उदाहरण के लिए अमेरिका में लगातार नीतिगत बदलाव किए जा रहे हैं ताकि प्रोत्साहित करने एवं हतोत्साहित करने का मिश्रण घरेलू विनिर्माताओं के लिए आकर्षक बना रहे और इसके साथ ही क्षमता विस्तार को भी अतिरिक्त विस्तार समर्थन मिलता रहे। भारत में लोक सभा चुनाव संपन्न होने और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद वेंकटेश जोशी के कमान संभालने के बाद अब तेजी से विभिन्न उद्देश्यों के बीच संतुलन स्थापित करने और विशेष लक्ष्य पूरे करने की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है।

भीषण गर्मी में बिजली की मांग ताबड़तोड़ बढ़ने के बीच अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ाने की जरूरत महसूस की जा रही है। अप्रैल 2024 के लिए केंद्रीय बिजली प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार अक्षय ऊर्जा (जल विद्युत सहित) की देश में कुल बिजली उत्पादन में 20 फीसदी हिस्सेदारी होती है। इस 20 फीसदी हिस्सेदारी में सौर ऊर्जा का योगदान लगभग आधा है और इसके बाद बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं और पवन ऊर्जा का सबसे अधिक योगदान रहा है।

दुनिया में इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर प्रगति थोड़ी धीमी हुई है। ब्लूमबर्गएनईएफ के आर्थिक बदलाव परिदृश्य (इकनॉमिक ट्रांजिशन सिनेरियो) में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री 2023 के 1.39 करोड़ से बढ़कर 2027 में 3 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। इस अवधि के दौरान इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री सालाना 21 फीसदी की दर से बढ़ने की उम्मीद है जबकि 2020 से 2023 के बीच इसकी दर 61 फीसदी रही थी। दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में भारत के सर्वाधिक तेजी से बढ़ने वाले बाजारों में शामिल रहने का अनुमान है। वियतनाम की विनफास्ट और टेस्ला के प्रवेश के बाद भारतीय बाजार को और मजबूती मिल सकती है। इस बीच, यूरोपीय संघ ने जुलाई से चीन से निर्यात होने वाली इलेक्ट्रिक कारों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का निर्णय लिया है। यूरोपीय संघ के इस निर्णय के कई मतलब निकाले जा सकते हैं। संघ ने कहा है कि वह 'अस्थायी तौर पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि चीन में बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक वाहन (बीईवी) मूल्य व्यवस्था अनुचित सब्सिडी से लाभान्वित होती है। इस अनुचित सब्सिडी प्रक्रिया से यूरोपीय संघ के बीईवी उत्पादों को आर्थिक नुकसान होने का खतरा पैदा हो गया है'। भारत में नई सरकार का आर्थिक नजरिया जुलाई में बजट पेश होने के बाद स्पष्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ दिनों पहले इटली में संपन्न जी-7 समूह की बैठक में 2070 तक कार्बन के नेट जीरो उत्सर्जन का भारत का संकल्प दोहराया है।

इलेक्ट्रिक वाहन और तेल

बीएनईएफ का अनुमान है कि सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहन और फ्यूल-सेल वाहन 2027 तक रोजाना लगभग 40 लाख बैरल तेल का विस्थापित कर सकते हैं। इसके अनुसार 2027 तक सड़कों पर चलने वाले वाहनों के लिए ईंधन की मांग शीर्ष स्तर पर पहुंच जाएगी और इसके बाद इसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) के अनुसार इस तिमाही में तेल की मांग लगभग 10.4 करोड़ बैरल प्रति दिन रहने की उम्मीद है। बीएनईएफ के आर्थिक बदलाव परिदृश्य के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहन खंड में प्रगति नहीं हुई होती तो तेल की मांग 2030 में प्रति दिन 66 लाख बैरल अधिक रहती।

कुछ वाहन निर्माता कंपनियों ने निकट भविष्य के इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर अपनी रफ्तार थोड़ी सुस्त कर दी है मगर दीर्घ अवधि में इन वाहनों के विकास एवं इनकी मांग बढ़ने के कई कारण मौजूद हैं। इनमें किफायती बैटरी, चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार और नए सस्ते वाहन ढांचे शामिल हैं। बीएनईएफ के अनुसार पेट्रोल-डीजल इंजन वाहनों की मांग वर्ष 2017 में सर्वोच्च स्तर पर पहुच गई। इस स्तर से वर्ष 2027 तक इसमें 29 फीसदी गिरावट आने का अनुमान है।

ऊर्जा भंडारण

लंबी अवधि तक ऊर्जा का भंडारण करने वाली नई तकनीकों का समूह ऊर्जा भंडारण में लीथियम-आयन बैटरियों के दबदबे को चुनौती दे सकता है। बीएनईएफ का पहला दीर्घकालिक ऊर्जा भंडारण (एलडीईएस) लागत सर्वेक्षण दर्शाता है कि ये सभी तकनीक फिलहाल शुरुआती चरण में हैं और महंगे भी हैं मगर इनमें कुछ ऊर्जा भंडारण में लिथियम से अधिक किफायती साबित हो रहे हैं। ताप बिजली भंडारण और संपीडित वायु भंडारण सबसे कम खर्चीली एलडीईएस तकनीक हैं। अन्य तकनीकों में फ्लो बैटरी, पंपयुक्त जलविद्युत भंडारण और गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा भंडारण शामिल हैं। एलडीईएस की अक्षय ऊर्जा आधारित बिजली प्रणाली में महत्त्वपूर्ण भूमिका है।

भारत दो घंटे तक ऊर्जा भंडारण के लिए तीन नीलामी कर चुका है जिनमें काफी बोलियां आई थीं। इन पर कोई सब्सिडी नहीं दी गई है मगर भारत अब 4 गीगावॉट-घंटा वाली बैटरी परियोजनाओं के लिए 9,400 करोड़ रुपये सब्सिडी देने की योजना पर काम कर रहा है। यह सब्सिडी विभिन्न नीलामी में बांटी जाएगी। बैटरी पर बीएनईएफ में लीड इंडिया विश्लेषक रोहित गाद्रे का कहना है, 'इस सब्सिडी योजना में बैटरी विनिर्माता काफी रुचि दिखाएंगे क्योंकि इन्हें लेकर दिशानिर्देश उनके अनुकूल हैं। उनके सामने बाजार के जोखिम भी नहीं होंगे और बैटरी परिचालन के तीन वर्ष पूरे होने पर उन्हें पूरी सब्सिडी का भुगतान किया जाएगा।'

(लेखिका ब्लूमबर्गएनईएफ में वरिष्ठ संपादक-वैश्विक नीति हैं)

आपका पक्ष

दवाओं के निर्यात में भारत के लिए बड़ी संभावनाएं

इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद फार्मा क्षेत्र का निर्यात प्रदर्शन लगातार बेहतर हो रहा है। पांच साल पहले वित्त वर्ष 2018-19 में फार्मा निर्यात 13 अरब डॉलर था जो वित्त वर्ष 2023-24 में 27.9 अरब डॉलर हो गया है। बीते वर्ष कुल वस्तु निर्यात में तीन प्रतिशत की गिरावट के बावजूद फार्मा निर्यात में 9.67 प्रतिशत का इजाफा रहा। वित्त वर्ष 2022-23 में भी फार्मा निर्यात में दहाई अंक में बढ़ोतरी हुई थी। सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स, रूस जैसे विकसित देश सबसे अधिक भारतीय दवा खरीद रहे हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में अकेले अमेरिका ने भारत से 7.83 अरब डॉलर की दवा का आयात किया। भारत मुख्य रूप से जेनेरिक दवाइयों का निर्यात करता है। वित्त वर्ष 2023-24 में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में 23 प्रतिशत की बढ़ोतरी रही है। इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन (इडमा) के मुताबिक

कोविड के दौरान भारत ने 200 से अधिक देशों को टीके और दवा मुहैया कराने का काम किया

अब भारतीय दवाओं की गुणवत्ता बढ़ती जा रही है और कोविड के दौरान भारत ने 200 से अधिक देशों को वैक्सीन और दवा मुहैया कराने का काम किया। इससे भारत के लिए निर्यात बाजार तैयार हो गया। अब हम सूडान, मिस्र, ब्रूनेई, लातविया, हैती, इथियोपिया जैसे देशों को फार्मा उत्पादों का निर्यात कर रहे हैं। हालांकि वैश्विक स्तर पर फार्मा का निर्यात बाजार 1.7 लाख करोड़ डॉलर का है और इस लिहाज से भारत की हिस्सेदारी मामूली है। लेकिन बढ़ोतरी दर को देखते हुए वर्ष 2030 तक फार्मा निर्यात 50 अरब डॉलर के स्तर को छू लेगा। हिमाचल ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के मुताबिक भारत की दवा सस्ती के साथ गुणवत्ता वाली भी है। यूरोप में बनने वाली दवा भारत की तुलना में 25-30 प्रतिशत अधिक महंगी होती है। हालांकि अब भी चीन की तरह हमारे यहां बहुत बड़ी मात्रा में एक साथ उत्पादन की क्षमता स्थापित नहीं हुई है और चीन के फार्मा उत्पाद भारत की तुलना में सस्ते होते हैं, परंतु गुणवत्ता के मामले में भारत बेजोड़ है।

सुधीर कुमार सोमानी, देवास

सौर ऊर्जा को बढ़ावा

एक जानकारी के मुताबिक अंतरिक्ष से सौर ऊर्जा का दोहन किया जाना अति आवश्यक है। पूर्व राष्ट्रपति डॉ अब्दुल कलाम ने कहा था कि आज दुनिया मे मनुष्य जितनी ऊर्जा की खपत करते हैं, उतनी ऊर्जा की तुलना में करीब दस ट्रिलियन गुना सूर्य अपनी किरणों के जरिये बिखेरता है। अगर ऊर्जा की इस मात्रा का छोटा-सा भाग हम निकाल सकें तो यह भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा। वाकई ऊर्जा संरक्षण की दिशा में यह बेहतर सुझाव है। बिजली (सौर ऊर्जा को मिलाकर) शत-प्रतिशत मिलने से शासकीय, घरेलू, व्यापार, कृषि आदि से जुड़े कार्यों की गति बढ़ेगी। ये सब सौर ऊर्जा के दोहन से ही संभव और सुलभ होगा। सौर ऊर्जा संयंत्र का उपयोग हर घर में किया जाना चाहिए। हालांकि सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए घरों में सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी भी दे रही है जिससे हर घर रोशन हो सके तथा बची हुई बिजली से आय भी हो सके।

संजय वर्मा, धार

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो – पीटीआई

ग्रीस की राजदूत अलिकी कोट्सोमिटोपोलू ने शुक्रवार को नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। एस जयशंकर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि पिछले साल से दोनों देशों के बीच संबंध प्रगाढ़ हुए हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

लोकसभा अध्यक्ष

नेतृत्व में निरंतरता

लोकसभा अध्यक्ष के रूप में ओम बिड़ला की पुन: नियुक्ति उनकी क्षमता तथा लोकतंत्र में उनका विश्वास प्रकट करती है। उनकी यह नियुक्ति संसदीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। बिड़ला का नेतृत्व उनकी निष्पक्षता, लोकतांत्रिक सिद्धान्तों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता तथा संसदीय कार्यवाहियों की जटिलता में मार्ग खोजने के लिए जाना जाता है। बिड़ला ने कहा था, 'संसद लोकतंत्र का मंदिर है। यह हमारा दायित्व है कि इसका समुचित संचालन सुनिश्चित कर जनता की आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति दें। मैं सभी सदस्यों के साथ यह सुनिश्चित करने हेतु काम करने के लिए प्रतिबद्ध हूं कि लोकसभा लोकतांत्रिक विमर्श का एक जीवन्त और प्रभावी मंच बन सके।' ओम बिड़ला राजस्थान के वरिष्ठ राजनेता तथा भारतीय जनता पार्टी-भाजपा के सदस्य हैं। उन्होंने पहले 2019 में लोकसभा अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी निभाई थी। उनकी पुन: नियुक्ति नेतृत्व की निरंतरता प्रदर्शित करती है जो निचले सदन का स्थायित्व व गरिमा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। यह देख कर बहुत खुशी होती है कि उनके चयन को न केवल उनकी पार्टी, बल्कि अनेक विपक्षी कतारों से भी व्यापक समर्थन मिला। सभी पार्टियों की ओर से मिला यह समर्थन इस बात की पुष्टि करता है कि बिड़ला निष्पक्षता के साथ संतुलित दृष्टिकोण अपनाने में सक्षम हैं और वे ऐसा परिवेश बनाते हैं जहां विविधतापूर्ण दृष्टिकोणों की अभिव्यक्ति तथा उन पर रचनात्मक बहस संभव हो।

ओम बिड़ला की राजनीतिक यात्रा 1990 के दशकारंभ में जनता की सेवा तथा जमीनी स्तर पर विकास के प्रति प्रतिबद्धता के साथ शुरू हुई।

राजस्थान में कोटा-बूंदी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले बिड़ला ने राज्य और केन्द्र में विभिन्न महत्वपूर्ण भूमिकायें निभाई हैं। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में बिड़ला ने संसदीय कार्यवाहियों में पारदर्शिता और क्षमता में सुधार करने की पहल की है। उन्होंने लोकसभा का कामकाज आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए डिजिटल टूल्स व प्रक्रियाओं को सहज बनाया ताकि विधायी गतिविधियां सरल हो सकें और जनता की उन तक पहुंच हो सके। हालांकि, लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर बिड़ला का कार्यकाल बिना चुनौतियों के नहीं था और वे अनेक विवादों में भी घिरे। ओम बिड़ला पर पूर्वाग्रह के आरोप लगे। आलोचकों का आरोप था कि वे संसदीय कार्यवाहियों में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी-भाजपा का समर्थन करते हैं तथा चयनित रूप से प्रमुख मुद्दों पर बहस की अनुमति देते हैं या नहीं। संसदीय कामकाज में बाधा डालने के लिए उन्होंने अनेक विपक्षी सांसदों का निष्कासन किया, जबकि आलोचकों का तर्क है कि यह 'विरोध को दबाने' का कठोर और चयनित तरीका था। इसके साथ ही बिड़ला पर विपक्षी नेताओं के साथ दुर्व्यवहार का आरोप भी लगा जिसके चलते वे अक्सर उनके बोलने का समय कम कर उनका दृष्टिकोण सामने नहीं आने देते थे। लेकिन बिड़ला ने महिलाओं और युवा सांसदों की ज्यादा प्रतिभागिता सुनिश्चित की तथा संसदीय प्रक्रियाओं को ज्यादा समावेशी व प्रतिनिधिक बनाया। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में ओम बिड़ला का पुन: चयन उनके नेतृत्व के प्रति लोकसभा सदस्यों का विश्वास प्रकट करता है। बिड़ला निष्पक्षता सुनिश्चित करने के साथ ही सदन की गरिमा और सम्मान सुनिश्चित करने में भी सफल हुए हैं। इसके लिए पार्टियों की दलगत सीमाओं से ऊपर उठ कर उनकी प्रशंसा अनेक दलों के सदस्यों ने की है। उम्मीद है कि उनकी अध्यक्षता में 18वीं लोकसभा भारत के संसदीय इतिहास में उल्लेखनीय योगदान कर भारत की प्रगति तेज करेगी।

सुनक को भारतीयों का समर्थन

ब्रिटेन में 4 जुलाई को होने वाले आम चुनाव में प्रमुख सवाल यह है कि क्या ब्रिटिश भारतीय वास्तव में वर्तमान प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और उनकी कंजरवेटिव पार्टी का समर्थन करेंगे?

विवेक शुक्ला
(लेखक, पूर्व सूचनाधिकारी हैं)

ब्रिटेन में 4 जुलाई को होने वाले आम चुनाव में प्रमुख सवाल यह है कि क्या ब्रिटिश भारतीय वास्तव में वर्तमान प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और उनकी कंजरवेटिव पार्टी का समर्थन करेंगे? क्या ब्रिटेन के पहले हिंदू प्रधानमंत्री ऋषि सुनक 4 जुलाई को होने वाले आम चुनाव के बाद अपने पद पर बने रहेंगे? क्या सुनक की कंजरवेटिव पार्टी को ब्रिटिश भारतीयों के वोट मिलेंगे? क्या लेबर पार्टी को भी अनिवासी भारतीयों के वोट मिलेंगे? ये सवाल वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि अनेक जनमत सर्वेक्षणों में ऋषि सुनक और उनकी कंजरवेटिव पार्टी को लेबर पार्टी की तुलना में बहुत पीछे बताया जा रहा है। वर्ष 2011 की ब्रिटिश जनगणना के अनुसार ब्रिटेन में भारतीय मूल के 1.5 मिलियन लोग निवास करते हैं जो देश की कुल जनसंख्या का 2.5 प्रतिशत हैं। भारतीय ब्रिटेन में सबसे बड़ा 'आप्रवासी समूह' हैं।

वे अन्य आप्रवासी समूहों की तुलना में ज्यादा पढ़े-लिखे हैं तथा उनका शुमार ब्रिटेन के सबसे अमीर लोगों में होता है। ब्रिटेन में सबसे अमीर लोगों की सूची में हिंदुजा, लक्ष्मी मित्तल तथा स्वराज पाल जैसे भारतीय मूल के लोग शामिल हैं। ऋषि सुनक तथा उनकी पत्नी व इन्फोसिस संस्थापक एन.आर. नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता मूर्ति ब्रिटेन के सबसे अमीर लोगों की सूची में 245 वें स्थान पर हैं। 'संडे टाइम्स' ने यह सूची मई में जारी की थी।

ऐतिहासिक रूप से ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय आप्रवासी लेबर पार्टी के पक्षधर माने जाते रहे हैं। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार के समय ही भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। इस कारण ब्रिटेन में पहले से रहने वाले भारतीय आप्रवासी स्वाभाविक रूप से लेबर पार्टी से प्रभावित थे। लेकिन हालिया सर्वेक्षणों से स्पष्ट है कि अनिवासी भारतीयों का झुकाव अब कंजरवेटिव पार्टी की ओर बढ़ रहा है जो लेबर पार्टी की प्रमुख प्रतिद्वंद्वी है।

1970 के दशक से लंदन में रहने वाले लेखक विनोद चह्वाण का विश्वास है कि ब्रिटेन में रहने वाले हिंदू आगामी चुनाव में पूरी तरह से कंजरवेटिव पार्टी को वोट देंगे। यह खबर ऋषि सुनक और उनकी कंजरवेटिव पार्टी को राहत देने वाली हो सकती है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि जब हम ब्रिटेन में रहने वाले हिंदुओं की बात करते हैं तो उनमें उस देश में पूर्वी अफ्रीका, कैरीबियन द्वीपों तथा अन्य स्थानों से आकर बसने वाले हिंदू भी शामिल हैं। ऋषि सुनक का परिवार भी 1960 के दशक में कीनिया से आकर ब्रिटेन में बसा था, हालांकि उनके पूर्वजों का संबंध मूलत: पंजाब से है।

यह विश्वास भी किया जाता है कि ब्रिटेन में रहने वाले अनिवासी भारतीयों का बड़ा हिस्सा 2014 में नरेन्द्र मोदी के भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद कंजरवेटिव पार्टी का समर्थक बना है। इन समर्थकों में हिंदुओं की संख्या सर्वाधिक है। ब्रिटेन में रहने वाले भारतीयों में हिंदुओं की संख्या एक मिलियन से अधिक है। इसके पीछे प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेन्द्र मोदी की राष्ट्रीय और विदेश नीति है जो आप्रवासी भारतीयों में भारी आकर्षण का कारण बनी है। प्रधानमंत्री मोदी 2014 के बाद से ही अपनी सभी विदेश यात्राओं में आप्रवासी भारतीयों को संबोधित करने तथा उनसे विचार-विमर्श करने को प्रमुख स्थान देते रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2015 में अपनी ब्रिटेन यात्रा के समय भारतीय मूल के 60,000 से अधिक लोगों को लंदन के खचाखच भरे विम्ब्ले स्टेडियम में संबोधित किया था। उस समय वहां गुजराती और पंजाबी लोगों की संख्या सर्वाधिक थी। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जानसन भी स्वयं को गर्व से 'भारत का दामाद' कहते थे। वे एक खास तरह से भारत के दामाद थे। उनकी दूसरी तलाकशुदा पत्नी मरीन व्हीलर की मां दीप सिंह कौर का विवाह पहले नई दिल्ली के प्रख्यात ठेकेदार सर शोभा सिंह के बेटे सरदार दलजीत सिंह से हुआ था।

> पहली बार ब्रिटिश हिंदुओं ने अपना एक घोषणापत्र जारी कर अगली सरकार से अपनी महत्वाकांक्षाओं और उम्मीदों को स्पष्ट किया है। उनका कहना है कि ब्रिटेन में रहने वाले हिंदू केवल उन उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे जो उनकी मांगों पर सहमति प्रकट करेंगे। ब्रिटेन में हिंदू तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक समूह है। अब तक 29 हिंदू संगठनों ने इस घोषणापत्र से अपनी सहमति प्रकट की है।

हालांकि, यह महत्वपूर्ण तथ्य समझना भी जरूरी है कि ब्रिटेन में रहने वाले सभी आप्रवासी भारतीयों की सोच समान नहीं है। वे राजनीतिक रूप से न एक तरह सोचते हैं और न किसी खास नेता का समर्थन करते हैं। विश्वास किया जाता है कि ब्रिटेन में रहने वाले अधिकांश भारतीय मुसलमान और सिख लेबर पार्टी को वोट दे सकते हैं। ऐसे लोगों को कंजरवेटिव पार्टी तथा मोदी के बीच निकट संबंध पसंद नहीं हैं। 1960 से 1980 के दशक के बीच अधिकांश भारतीय आप्रवासी ब्रिटेन में युगांडा, कीनिया और कैरीबियन द्वीपों से आकर बसे थे। वे खासकर लेबर पार्टी की आप्रवासी अधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता से आकर्षित थे। लेबर प्रधानमंत्री हेरोल्ड विल्सन द्वारा 1965 में पास 'रेस रिलेशन्स एक्ट' से वे बहुत प्रभावित थे।

युगांडा के क्रूर तानाशाह ईदी अमीन द्वारा अगस्त, 1972 में सभी भारतीयों को 90 दिन के भीतर देश छोड़ देने के आदेश के बाद हजारों भारतीय आप्रवासी ब्रिटेन आ गए थे। गंभीर विश्लेषण से पता चलता है कि ब्रिटेन में रहने वाले हिंदुओं का आकर्षण कंजरवेटिव पार्टी के प्रति 2010 से बढ़ने लगा था। इस प्रवृत्ति में अमीर और पढ़े-लिखे दूसरी और तीसरी पीढ़ी के हिंदुओं का प्रमुख स्थान था। पिछले 25 वर्ष में भारत से ब्रिटेन आप्रवासियों की एक नई लहर आई है। इनमें डाक्टर, इंजीनियर, आईटी पेशेवर, आदि शामिल हैं।

ऐसे सभी अमीर व मुख्यत: हिंदू आप्रवासी भारतीय अपनी पहचान कंजरवेटिव पार्टी के मतदाताओं के रूप में करते हैं। अनिवासी भारतीयों का लेबर पार्टी से मोहभंग रातोंरात नहीं हुआ है। इसकी शुरुआत 2019 में लेबर पार्टी के प्रस्ताव से हुई थी जिसमें जम्मू कश्मीर की जनता के लिए 'आत्मनिर्णय के अधिकार' की मांग की गई थी। इस प्रस्ताव के कारण ब्रिटेन में रहने वाले आप्रवासी भारतीयों के बड़े हिस्से ने लेबर पार्टी से अपनी दूरी बना ली थी। उन्होंने इसे भारत के आंतरिक मामलों में सीधे हस्तक्षेप की तरह देखा था। इस बीच ऋषि सुनक 2022 में ब्रिटेन के पहले हिंदू प्रधानमंत्री बन गए।

इस घटना ने हिंदुओं और कंजरवेटिव पार्टी के बीच संबंध और गहरे कर दिए। हालांकि, अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि सभी हिंदू ब्रिटेन के आगामी आम चुनाव में कंजरवेटिव पार्टी को वोट देंगे। हालांकि, पहली बार ब्रिटिश हिंदुओं ने अपना एक घोषणापत्र जारी कर अगली सरकार से अपनी महत्वाकांक्षाओं और उम्मीदों को स्पष्ट किया है। उनका कहना है कि ब्रिटेन में रहने वाले हिंदू केवल उन उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे जो उनकी मांगों पर सहमति प्रकट करेंगे। ब्रिटेन में हिंदू समुदाय तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक समूह है। अब तक 29 हिंदू संगठनों ने इस घोषणापत्र से अपनी सहमति प्रकट की है।

घोषणापत्र के अनुसार, 'हिंदू ब्रिटिश अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। देश की अर्थव्यवस्था में हमारा योगदान तुलनात्मक रूप से बहुत अधिक है। हम एक सर्वाधिक कानून का पालन करने वाले समुदाय हैं। लेकिन इसके बावजूद देश में हिंदू-विरोधी घृणा बढ़ रही है।' ब्रिटेन में रहने वाले हिंदुओं की सबसे बड़ी मांग अपनी सुरक्षा है। इन सभी चीजों को देखते हुए सवाल है कि क्या ब्रिटेन में रहने वाले लगभग सभी हिंदू कंजरवेटिव पार्टी को वोट देंगे? क्या लेबर और कंजरवेटिव पार्टियां हिंदू संगठनों द्वारा जारी घोषणापत्र पर विचार करेंगी?

बांग्लादेश के साथ बेहतर रिश्तों की ओर

> शेख हसीना की यात्रा ने भारत के लिए रणनीतिक साझेदार के रूप में बांग्लादेश की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर किया।

कुमारदीप बनर्जी
(लेखक, नीति विश्लेषक हैं)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई भारतीय सरकार अपनी विदेश नीति के एजेंडे पर वापस आ गई है, जिसे उसने पिछले एक दशक में सावधानीपूर्वक तैयार किया है। शपथ ग्रहण के कुछ दिनों के भीतर ही श्री मोदी विशेष आमंत्रित के रूप में जी7 बैठकों में भाग लेने के लिए इटली गए थे। उनका शपथ ग्रहण समारोह अपने आप में पड़ोसी प्रथम के घोषित नीतिगत फोकस का एक बयान था।

शपथ ग्रहण समारोह में लगभग सभी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों और कुछ हिंद महासागर क्षेत्र के नेताओं ने भाग लिया। गौरतलब है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के एक महीने के भीतर ही द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत वापस आ गई थीं। शेख हसीना के साथ संयुक्त ब्रीफिंग के दौरान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उजागर की गई बैठक का फोकस था आज हमने नए क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक भविष्य की दृष्टि तैयार की है। दोनों देशों के युवाओं को ग्रीन पार्टनरशिप, डिजिटल पार्टनरशिप, ब्लू इकोनॉमी, स्पेस जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग पर हुए समझौते से लाभ होगा। भारत बांग्लादेश मैत्री सैटेलाइट हमारी साझेदारी को नई ऊंचाइयां देगा। हमने अपना फोकस- कनेक्टिविटी, वाणिज्य और सहयोग पर रखा है।

बांग्लादेश भारत के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है, न केवल अंतरंग भौगोलिक सीमाओं और साझा संस्कृति और भाषा के कारण, बल्कि भारत के पूर्वोत्तर को बंगाल की खाड़ी से जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण गलियारे के रूप में भी। दोनों देशों के प्रधान मंत्री शेख हसीना और नरेंद्र मोदी एक दशक से अधिक समय से शीर्ष पद पर हैं। उन्होंने एक ऐसा कामकाजी रिश्ता विकसित किया है, जिसकी बराबरी करना मुश्किल है, जो पिछले पांच वर्षों में इन नेताओं की दस बैठकों से रेखांकित होता है। दोनों प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त रूप से 18 मार्च को वर्चुअल प्रारूप में भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया। पीएम शेख हसीना ने 11 जनवरी 2023 को वॉयस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट के उद्घाटन सत्र और 17 नवंबर 2023 को दूसरे वर्चुअल वॉयस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट में भी भाग लिया। नशीली दवाओं के व्यापार, तस्करी, नकली मुद्रा, मानव तस्करी और अपराधियों या आतंकवादियों की आवाजाही पर नज़र रखने के लिए संबंध।

सुरक्षा साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए, भारत और बांग्लादेश ने पिछले कुछ वर्षों में रक्षा सहयोग ढांचे पर काम किया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की हालिया यात्रा में दोनों देशों ने रक्षा साझेदारी को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया। अपने बयान में पीएम मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि रक्षा उत्पादन से लेकर सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण तक हमारे रक्षा सहयोग को और मजबूत किया जा रहा है। हिंद महासागर क्षेत्र में, हमारा दृष्टिकोण समान है। हम इंडो-पैसिफिक महासागर पहल में शामिल होने के बांग्लादेश के फैसले का स्वागत करते हैं। हम बिम्सटेक सहित अन्य क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपना सहयोग जारी रखेंगे।

भारत-बांग्लादेश संबंधों का सबसे मजबूत स्तंभ अर्थव्यवस्था है। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है और भारत एशिया में बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 16 बिलियन डॉलर का है। पद्मा नदी से बहुप्रतीक्षित इलिश मछली के अलावा, बांग्लादेश भारत को लगभग 2 बिलियन डॉलर का सामान निर्यात करता है, जो एशिया में सबसे अधिक है।

पिछले कुछ वर्षों में, आक्रामक चीन ने अपने अपारदर्शी बुनियादी ढाँचे की परियोजनाओं के माध्यम से द्विपक्षीय संबंधों में भारत के लिए आरक्षित कुछ पारंपरिक स्थान पर कब्ज़ा करने की कोशिश की है। भारत ने बुनियादी ढाँचे की साझेदारी को बढ़ाकर और बांग्लादेश को दक्षिण पूर्व एशियाई दृष्टिकोण की तुलना में इंडो-पैसिफिक भू-राजनीतिक विश्वदृष्टि के करीब लाकर इसका विरोध किया है।

यह बांग्लादेश को ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया और मध्य पूर्व में भारत के बहुपक्षीय भागीदारों के साथ संरेखित करने में मदद करता है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के तहत भारत के पहले राजकीय अतिथि के रूप में पीएम शेख हसीना की यात्रा दोनों पड़ोसियों के बीच मजबूत संबंधों का एक महत्वपूर्ण सुदृढ़ीकरण है।

आप की बात

राष्ट्रपति का अभिभाषण

देश की महामहिम राष्ट्रपति सुश्री द्रोपदी मुर्मू ने नवनिर्मित संसद में 18वीं लोकसभा के प्रथम सत्र को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार कामकाज के रोड मैप की जानकारी देश के समक्ष रखी है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में नीट परीक्षा की धांधली आदि महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए तथा 2036 में भारत भूमि पर ओलंपिक कराए जाने का संकल्प दोहराया है जिसका देश के प्रत्येक नागरिक को स्वागत करना चाहिए। यह भारत के लिए गर्व की बात होगी कि 2036 का ओलंपिक भारत में कराया जाए। इसके लिए खेल मंत्रालय भी तैयारी में लगा है। देश का युवा भी पूरी आशा के साथ केंद्र सरकार के इस कदम के साथ खड़ा है। 2010 में भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों का सफल आयोजन भी किया था और एशियन गेम्स 1982 में दिल्ली में आयोजित किया गया था। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में जनवरी 2023 में विश्व हॉकी कप का आयोजन किया गया था। इसी प्रकार 2018 में भी अंतरराष्ट्रीय हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत में सफलतापूर्वक किया जा चुका है। इस प्रकार 2036 ओलंपिक के प्रति प्रतिबद्धता अपने अभिभाषण में व्यक्त कर महामहिम सुश्री द्रोपदी मुर्मू ने भारत के इस दावे को और बल दिया है। सभी राजनेताओं को इसका समर्थन करना चाहिए।

– **वीरेंद्र कुमार जाटव,** दिल्ली

आपातकाल का पाप

लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन नेताओं के साथ स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर उनके द्वारा आसन से आपातकाल का जिक्र करने पर नाराजी जाहिर करते हुए इस कदम को राजनीतिक करार दिया। आज भी कांग्रेसी उस आपातकाल को इसलिए नहीं भूल पाते हैं क्योंकि इसके दौरान पार्टी को जैसी बदनामी झेलनी पड़ी वह आज भी उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। आपातकाल का पाप कांग्रेस को कभी नहीं छोड़ेगा। लोकसभा स्पीकर के साथ ही राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी आपातकाल का उल्लेख था। आपातकाल के दौरान विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, अखबारों पर सेंसर थोपा गया था तथा उसी दौरान चाले नसबंदी अभियान को याद कर आज भी लोग सहम जाते हैं। कांग्रेसी व कई विपक्षी नेता पिछले दस साल से जारी कथित आपातकाल की बात करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को जनता ने भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का जनादेश दे दिया है और मोदी इस पर तेजी से अमल कर रहे हैं। यदि भ्रष्टाचार के आरोपी बड़े से बड़े नेता को सुप्रीम कोर्ट तक से राहत नहीं मिलती है तो ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई को अघोषित आपातकाल नहीं कहा जा सकता है।

– **मनमोहन राजावत,** शाजापुर

विपक्ष की गलती

एनडीए ने लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए ओम बिड़ला का नाम सदन में पहले ही सर्वसम्मति से चुनने के लिए प्रस्तावित कर दिया था, किन्तु विपक्ष ने मांग की कि हमें उपाध्यक्ष का पद दिया जाए तभी हम ओम बिड़ला का समर्थन करेंगे। जब एनडीए इस शर्त पर नहीं हुआ तो उन्होंने के. सुरेश को उम्मीदवार घोषित करके चुनाव की स्थिति पैदा कर दी। भले ही कांग्रेस, टीएमसी व इंडी गठबंधन के अन्य सदस्यों ने इस मामले में काफी सफाई पेश की, किन्तु साफ़ था कि सत्ता-विपक्ष की सदस्य संख्या देखते हुए विपक्षी उम्मीदवार जीतना मुमकिन नहीं था। फिर भी उन्होंने अपनी अपरिपक्व राजनीतिक समझ का परिचय दे ही डाला। अगर वे सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद के लिए हामी भर लेते तो सत्ता पक्ष पर थोड़ा नैतिक दबाव बनता और जनता भी विपक्ष की सराहना करती। लेकिन विपक्ष ने ऐसा न कर भारी गलती की है। अब सत्ता पक्ष स्वाभाविक रूप से अपने गठबंधन सहयोगियों में से किसी को उपाध्यक्ष बना सकता है। इस पर सत्ता पक्ष के एक नेता का यह व्यंग बहुत मारक है कि जब हारने की नौबत आती है तो कांग्रेसी नेता किसी दलित को बलि का बकरा बनाना पसंद करते हैं और इस बार इसके लिए केरल के के. सुरेश को जानबूझ कर चुना गया था।

शकुंतला महेश नेनावा, इंदौर

आरक्षण पर विवाद

बिहार सरकार ने आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दी थी जिससे ईडब्ल्यूएस का आरक्षण जोड़ कर यह 75 प्रतिशत हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे निरस्त कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद पूरे देश में जातीय जनगणना की मांग हो रही है तथा कांग्रेस ने आरक्षण की सीमा बढ़ाने का वादा भी किया था। वोटों की राजनीति के चलते सभी दल बढ़-चढ़कर आरक्षण देना चाह रहे हैं ताकि उनका वोट बैंक मजबूत हो सके। लेकिन यह तथ्य अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए कि जातीय आरक्षण के चलते तीन पीढ़ियों से से फायदा उठाने वाले अब इसे अपने ही समाज के गरीबों तक नहीं पहुंचने देते हैं। इस निहित-स्वार्थके चलते अनेक प्रतिभाशाली छात्रों को अपनी योग्यता दिखाने का अवसर नहीं मिलता। रंगनाथ मिश्र कमेटी रिपोर्ट ने परिवार-केन्द्रित आरक्षण का सुझाव दिया था। अब आधार के सर्वव्यापी होने तथा डीबीटी सीधे खाते जाने के युग में इसे आसानी से लागू किया जा सकता है। इसका लाभ सभी जातियों के गरीब लोगों को मिलेगा और इससे वोटबैंक की राजनीति करने वाले नेताओं की असलियत भी उजागर हो जाएगी।

– **सुभाष बुड़ावन वाला,** रतलाम

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

संपादकीय

किसान खेती की बदलती हुई इकोनॉमी को समझें

कृषि विज्ञान के अनुसार एक-फसली खेती से उत्पादकता घटती है। मौसम विज्ञान बताता है कि तापमान वृद्धि से उत्पादन गिरता है। एनएसएसओ के घरेलू उपभोग व्यय सर्वे में सामने आया कि लोगों में भोजन के रूप में अनाज के प्रति कम, जबकि फल, सब्जी, अंडा, दूध और मांसाहार के प्रति ज्यादा रुझान है। 20 साल पहले एक व्यक्ति हर महीने औसतन 11.78 किलो खाद्यान्न खाता था जो 2022-23 में घटकर 8.97 किलो रह गया है। सर्वे के अनुसार साल 2022-23 में पहली बार भारत में खाद्यान्न से 15 हजार करोड़ रु. ज्यादा फल और सब्जी (4.34 लाख करोड़) की पैदावार हुई है। दूध, तीन साल पहले ही गेहूं-चावल के कुल उत्पादन मूल्य को पार कर चुका है। इन आंकड़ों से यह साफ है कि परंपरागत खेती करने वाले किसान अब घाटे में रहेंगे क्योंकि एक-फसली खेती के कारण उनके जमीन की उत्पादकता घट रही है और ज्यादा पानी का दोहन करने से मिट्टी की उर्वरता भी नीचे जा रही है। जहां यूपी सबसे ज्यादा मूल्य का अनाज पैदा कर रहा है, वहीं पश्चिम बंगाल यूपी के मात्र एक-तिहाई भू-भाग के बावजूद देश में सबसे ज्यादा फल और सब्जी पैदा कर रहा है। हालांकि आज भी देश की कृषि अर्थ-व्यवस्था में खेती की उपज का योगदान सर्वाधिक 54 प्रतिशत है लेकिन खाद्यान्न और खासकर चावल-गेहूं की जगह अन्य बहु-फसली खेती की जरूरत है।

प्रेरणा

अगर आपमें उत्साह की आग नहीं है, तो उसी उत्साह से आपको बाहर भी कर दिया जाएगा। - विन्स लोम्बार्डी

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता
ptvijayshankarmehta.com

अपनी गलतियों का भी ऑडिट करते रहें

एक होता है फाइनेंशियल ऑडिट, एक होता है मेंटल ऑडिट और एक है फॉरेंसिक ऑडिट। ऑडिट केवल आंकड़ों का ही नहीं है। जब आप ऑडिट करते हैं, तो गलतियां पकड़ में आ जाती हैं। चूक, छूट और भूल, ये तीन शब्द सबके जीवन में हैं और ऑडिट वाले इन ही को पकड़ते हैं। चूक का मतलब, जैसे निशाना चूक जाना। चलते हुए गिरे। क्यों? क्योंकि चूक हुई थी, तो चूक में एक विचलित होने का भाव रहता है। अनजाने में असावधानी से चूक होती है। फिर है छूट। कोई काम करते हुए बीच में जो बात रह गई, उसको छूट कहते हैं, जैसे सामान स्टेशन पर छूट गया, गिनती में ये संख्या छूट गई। ये भी साधारण त्रुटि है, लेकिन भूल का संबंध हमारी स्मरण शक्ति से है। अपने वचन को ठीक से न निभाना, ईमानदारी के विपरीत कार्य करना.. ये भूल है और ये दंडनीय है। तो हम अपने परिवार और कारोबार में लगातार इस बात का ऑडिट करते रहें कि हमसे कहां चूक हो रही है, कहां छूट रहे हैं, और कहां भूल कर रहे हैं। ये तीनों बातें अगर ठीक से समझ जाएं, तो जीवन में जरूरत और मजबूरी को भी ठीक से समझ कर जीवन जी सकेंगे। • Facebook:Pt. Vijayshankar Mehta

विश्लेषण • 18वीं लोकसभा लोकतंत्र में आदर्श है?

लोकसभा स्पीकर के लिए भी चुनाव होना चौंकाता है

संजय कुमार
प्रोफेसर व राजनीतिक टिप्पणीकार
sanjay@csds.in

अक्सर कहा जाता है कि लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल का पर्याप्त बहुमत के साथ निर्वाचित होना महत्वपूर्ण है, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण है एक मजबूत विपक्ष का होना, ताकि सरकार की शक्तियों पर अंकुश और संतुलन सुनिश्चित हो सके। 2024 के चुनावी मुकाबले ने जो 18वीं लोकसभा बनाई है, वह कमोबेश एक आदर्श लोकतंत्र के अनुरूप है। सत्तारूढ़ गठबंधन के पास बहुमत है, लेकिन उतना ही मजबूत विपक्ष भी है। एनडीए के पास 293 सीटें हैं, जिसमें भाजपा 240 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। वहीं इंडिया गठबंधन के पास लोकसभा में कुल 195 सदस्य हैं (टीएमसी और लेफ्ट को छोड़कर), जिसमें कांग्रेस 99 सीटों के साथ सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने 29 और वाम मोर्चे ने 6 लोकसभा सीटें जीती हैं, जबकि पंजाब में आम आदमी पार्टी के खाते में 3 लोकसभा सीटें आई हैं। इन आंकड़ों को मिलाकर नवनिर्वाचित लोकसभा में विपक्षी गठबंधन के सदस्यों की संख्या 233 हो जाती है, जो विधेयकों पर जरूरी बहस सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त है।

थ्योरिटिकली बात करें तो लोकतंत्र में निर्वाचित सरकार के संचालन के लिए इससे बेहतर संसद नहीं हो सकती। लेकिन थ्योरी और प्रैक्टिस में अंतर होता है, जिसकी झलक हाल में लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के मुद्दे पर देखने को मिली। जब सत्तारूढ़ गठबंधन ने विपक्ष को उपाध्यक्ष का पद देने के लिए अनिच्छा दिखाई, तो विपक्ष ने सदन के अध्यक्ष पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। ऐसी स्थिति पिछले कई दशकों के दौरान लोकसभा में शायद ही कभी उत्पन्न हुई हो। अतीत में केवल तीन बार ही ऐसे अवसर आए हैं, जब लोकसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ हो। पहली बार आजादी के बाद 1952 में हुए पहले लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने शांताराम मोरे को अपना उम्मीदवार बनाया था। कांग्रेस उम्मीदवार जी.वी. मावलंकर को 394 वोट मिले थे, जबकि मोरे को 55 वोट मिले थे। 1967 में कांग्रेस उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी का मुकाबला विपक्षी उम्मीदवार तेनेटी विश्वनाथम् से हुआ था। इस तरह का तीसरा उदाहरण आपातकाल (1976) का है, जब विपक्ष ने कांग्रेस उम्मीदवार बी.आर. भगत के खिलाफ जगन्नाथ राव को उतारा था।

स्वस्थ परंपरा को कायम रखते हुए ओम बिरला को ध्वनिमत से स्पीकर चुन लिया गया, जिससे कोई खींचतान नहीं हुई। लेकिन स्पीकर के चुनाव के मुद्दे पर पिछले कुछ दिनों से जो नूराकुश्ती चल रही थी, वह इस बात का संकेत मात्र है कि सत्तारूढ़ गठबंधन को लोकसभा में संगठित विपक्ष से कैसी चुनौती मिलने वाली है। विपक्षी दलों के कुछ सदस्यों और नवनिर्वाचित लोकसभा अध्यक्ष के बीच हुई नोकझोंक से यह संकेत मिलता है कि लोकतांत्रिक सरकार के बेहतर संचालन के लिए जो सबसे अच्छी लोकसभा दिखती है, वह सैद्धांतिक रूप से तो बनी रहेगी, लेकिन व्यवहार में नहीं। अपना उम्मीदवार उतारकर विपक्ष ने संकेत दिया है कि वे जनता के अधिकारों के लिए लड़ेंगे।

ये सच है कि भाजपा लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है और उसने अपने सहयोगियों के साथ सरकार बनाई है। लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी के लिए अब यह महसूस करने का समय है कि यह जनादेश 2014 और 2019 से अलग है। न केवल विपक्षी सांसद इस बार बड़ी संख्या में हैं, बल्कि पिछले कुछ वर्षों में आमजन के विचार भी बदले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी अन्य नेता की तुलना में कहीं अधिक लोकप्रिय बने हुए हैं। उनकी लोकप्रियता रेटिंग 41% है तो राहुल गांधी की भी 27% हो चुकी है। लेकिन लोकनीति-सीएसडीएस सर्वेक्षण में 28% भारतीयों ने उल्लेख किया कि नरेंद्र मोदी की छवि अब

विपक्षी दलों और नवनिर्वाचित लोकसभा अध्यक्ष के बीच हुई नोकझोंक से यह संकेत मिलता है कि विपक्ष इस बार संघर्ष करने के मूड में है। एनडीए को महसूस हो रहा होगा कि इस बार का जनादेश 2014 और 2019 से भिन्न है।

पहले जैसी नहीं रह गई है, वहीं 33% अन्य ने कहा कि भाजपा द्वारा विभिन्न राजनीतिक दलों से दागदार छवि वाले नेताओं को शामिल करने के कारण पार्टी की छवि खराब हुई है। सर्वेक्षण के निष्कर्षों ने पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी बदले की राजनीति की प्रकृति के बारे में लोगों की चिंता को भी दर्शाया। 44% लोग इस दृष्टिकोण से सहमत हैं कि विपक्षी दलों के नेताओं को राजनीतिक कारणों से गिरफ्तार किया गया था। वहीं 58% भारतीयों का मानना था कि विकास के लिए सरकार बदलना जरूरी है। 32% ने कहा सरकार में एक ही पार्टी का बने रहना विकास के लिए बेहतर है।

2024 के जनादेश ने दर्शाया कि राष्ट्रीय गौरव, पहचान और सुरक्षा के मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन बेरोजगारी, महंगाई आदि भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें कोई भी दल लंबे समय तक नजरअंदाज नहीं कर सकता।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

इस आलेख पर सुझाव एवं प्रतिक्रिया देने के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करें

दूरदृष्टि • मध्य-पूर्व के दोनों देशों में टकराव तय है

इजराइल और हिजबुल्ला के बीच पिस रहा है लेबनान

अभिजीत अय्यर मित्रा
सीनियर फेलो, आईपीसीएस
abhijit@ipcs.org

ऐसा लग रहा है कि लेबनान और इजराइल के बीच टकराव अब लगभग तय है। कई यूरोपीय देशों और अमेरिका ने अपने नागरिकों को लेबनान छोड़ने के लिए कहा है, जो एक बड़े इजराइली सैन्य अभियान का पूर्वाभास देता है। सवाल यह है कि हालात इस स्थिति तक क्यों पहुंचे और यहां से आगे क्या होगा। इसे समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा।

लेबनान को फ्रांस ने सीरिया से अलग करके एक ईसाई बहुसंख्यक देश के रूप में निर्मित किया था, ठीक उसी तरह जैसे पाकिस्तान को भारत से अलग करके मुस्लिम बहुसंख्यक देश बनाया गया था। यह 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद किया गया था, जिसके बाद 1921 में वहां जनगणना की गई थी। जनगणना के बाद वहां पर ईसाई बहुसंख्यक घोषित किए गए, लेकिन यह लेबनान में हुई एकमात्र जनगणना थी। वहां के तीन सबसे बड़े जनसंख्या-समूहों का प्रतिनिधित्व करने के लिए तीन भूमिकाएं परिभाषित की गईं। राजनीतिक शक्तियों के साथ कार्यकारी राष्ट्रपति पद ईसाइयों को दिया गया। कमजोर प्रधानमंत्री पद सुन्नियों को दिया गया, जो वहां का दूसरा सबसे बड़ा समूह था। संसद के अध्यक्ष का शक्तिहीन पद शियाओं को मिला।

तब से अब तक लेबनान में कई जनसांख्यिकीय परिवर्तन हुए हैं। सबसे पहले तो 1948 में इजराइल के निर्माण के बाद वहां पर बड़े पैमाने पर फिलिस्तीनियों की आमद हुई, जिनमें से अधिकांश सुन्नी मुसलमान थे। इन फिलिस्तीनियों को यहूदी बस्तियों में रखा गया था, ताकि नाजुक साम्प्रदायिक शक्ति-संतुलन न बिगड़े। हालांकि ऐसा हुआ नहीं और आखिरकार सुन्नी वहां पर बहुसंख्यक हो गए। सुन्नियों के पास राजनीतिक शक्ति की कमी थी, लेकिन उन्होंने दूसरे तरीके से इसकी भरपाई की। कई फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह उभरे और शक्तिहीन लेबनानी सेना देखती रही। सीरियाई लोग- एक विशाल सुन्नी बहुमत पर एक छोटे शिया-अलवी शासक-वर्ग के होने के कारण- सुन्नी राष्ट्रवाद को भड़काना नहीं चाहते थे, इसलिए फिलिस्तीनी उग्रवादी समूहों के माध्यम से सीरियाई सुन्नी भावनाओं को स्वर देने के लिए लेबनान को एक उपयोगी प्रॉक्सी पाया गया।

कुछ हद तक इन सुन्नी गुटों द्वारा लेबनानी सरकार की अवहेलना करने तथा इजराइल पर सीमा पार से आतंकी हमले करने की उनकी क्षमता के कारण 1975 में एक गृह युद्ध शुरू हुआ, जिसके कारण लेबनान की धनी ईसाई आबादी का एक बड़ा हिस्सा विदेश चला गया। आज यह आलम है कि ब्राजील में लेबनान (40 लाख) की तुलना में कहीं अधिक लेबनानी आबादी (70 लाख) है। इसका नतीजा यह हुआ कि जब 1990 में गृह युद्ध समाप्त हुआ, तो यह लगभग निश्चित था कि लेबनान में सुन्नी बहुमत में हो गए थे। परिणामस्वरूप, गृह युद्ध को समाप्त करने वाले ताइफ समझौते ने ईसाई राष्ट्रपति की अधिकांश शक्तियां सुन्नी प्रधानमंत्री को हस्तांतरित कर दीं। लेकिन तब से सुन्नी आबादी भी वहां पर स्थिर हो गई है और अब हम निश्चित हैं कि लेबनान में शिया बहुसंख्यक हो चुके हैं।

इस दौरान हिजबुल्ला वहां पर शक्तिशाली बनता चला गया। 1990 के ताइफ शांति समझौते में सभी सैन्य-संगठनों को निरस्त्र करने का उल्लेख किया गया था। उसमें एक शर्त यह थी कि वे केवल तभी निरस्त्र होंगे, जब दक्षिणी लेबनान पर इजराइल का कब्जा हो जाएगा। जब 2000 में वह कब्जा समाप्त हो गया तो हिजबुल्ला को हथियारबंद रहने के लिए एक बहाने भर की जरूरत थी, जो उसने तुरंत ही खोज निकाला।

नेतन्याहू गाजा के बाद हिजबुल्ला से निपटना चाहते हैं। पिछले 9 महीनों में इजराइल पर जारी हिजबुल्ला के हमलों ने नेतन्याहू को वही दिया है, जो वे चाहते हैं। और इस बार फिर लेबनान के लोगों को इसका खामियाजा भुगतना होगा।

इससे बेरूत में सुन्नी सरकार को बहुत परेशानी हुई। जब रफीक हरीरी जैसे सुन्नी प्रधानमंत्री ने सीरिया के प्रभाव को कम करने की कोशिश की तो उन्हें बम विस्फोट में मार दिया गया, ताकि संदेश दिया जा सके कि सीरिया से मुक्त होने की कोशिश नहीं की जा सकती। इस समय तक ईरान सीरिया और लेबनान दोनों का प्रमुख सहयोगी था, जो आवश्यकता पड़ने पर उन्हें हथियार और सेना की आपूर्ति करता था। सीरिया की ईरान पर निर्भरता के मद्देनजर लेबनान एक ईरानी-सीरियाई जागीरदार देश जैसा बन गया। सुन्नी सत्ता पर काबिज रहे, लेकिन हिजबुल्ला पर कोई बंदिशें नहीं लगाई गईं।

लेबनान के लिए यह कोई अच्छा सौदा नहीं रहा, क्योंकि इसका मतलब है कि हिजबुल्ला लेबनान नहीं, सीरिया और ईरान के हितों के लिए काम करता है। इसके अलावा, जब भी हिजबुल्ला इजराइल पर कोई बड़ा हमला करता है, तो लेबनान को कीमत चुकानी पड़ती है। 7 अक्टूबर 2023 से, हिजबुल्ला लगातार अपने हमलों को बढ़ा रहा है, लेकिन लेबनानी हित के लिए नहीं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

The Economist
29 जून के अंक से विशेष अनुबंध के तहत सिर्फ दैनिक भास्कर में
इकोनॉमिस्ट की मुख्य खबरें फ्रांसीसी संसद के चुनाव और कुछ एशियाई देशों में महिलाओं के खिलाफ असंतोष पर केंद्रित हैं।
दैनिक भास्कर
अब आप द इकोनॉमिस्ट के सभी आर्टिकल DB एप पर हर शनिवार पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें डीबी एप।

बिजनेस ब्रीफ

फॉक्सवैगन का ईवी पर 40 हजार करोड़ रु. का निवेश

फॉक्सवैगन ने इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनी रिवियन के साथ संयुक्त उपक्रम शुरू किया है। कंपनी प्रोजेक्ट पर 40 हजार करोड रुपए से अधिक निवेश करेगी। फॉक्सवैगन को यूरोप में सस्ती चीनी इलेक्ट्रिक कारों से बड़ी चुनौती मिल रही है। रिवियन अपनी टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर वीडब्लू को देगी। साल के पहले तीन महीनों में 11 हजार करोड़ रुपए का घाटा झेल चुकी रिवियन को करार से सहारा मिलेगा।

प्लेन यात्रियों को पर्यावरण सरचार्ज चुकाना पड़ेगा

लुफ्थांसा एयरलाइन उत्सर्जन के नए नियमों पर आने वाला खर्च यात्रियों से वसूल करेगी। जर्मन एयरलाइन यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन, नार्वे और स्विट्जरलैंड से रवाना होने वाली उड़ानों के लिए 31 दिसंबर के बाद 1 यूरो (89 रु.) से लेकर 72 यूरो तक पर्यावरण लागत सरचार्ज शुरू करेगी। इस बीच, एयरक्राफ्ट इंजिन की कमी के कारण एयरबस के मुनाफे में कमी के अनुमान से कंपनी के शेयर्स में 10% गिरावट आई है। एयरबस इस साल 800 विमानों के पूर्व अनुमान की बजाय अब 770 विमान डिलीवर करेगी।

सैन फ्रांसिस्को में सेल्फ ड्राइविंग एयर टैक्सी सेवा शुरू

कई झटके लगने के बाद अमेरिका में रोबोटैक्सी इंडस्ट्री ने बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। वायमो ने सीमित यात्रियों पर ट्रायल के बाद सैन फ्रांसिस्को में अपनी सेवा शुरू कर दी है। फीनिक्स के बाद अमेरिका में यह दूसरा शहर है जहां वायमो की सेल्फ ड्राइविंग टैक्सी हर किसी को मिलेगी। सैन फ्रांसिस्को में लगभग तीन लाख लोगों ने टैक्सी सेवा लेने का अनुबंध किया है।

बैंकों को 57 लाख करोड़ रु. का काल्पनिक नुकसान

अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने अपने सालाना जोखिम टेस्ट के नतीजे जारी किए हैं। इसके तहत दुनिया में भारी मंदी और प्रॉपर्टी मार्केट के ध्वस्त होने पर बैंकों की स्थिति का अनुमान लगाया जाता है। बैंक ऑफ अमेरिका, जेपी मॉर्गन चेज और वेल्स फार्गो सहित सभी 31 बैंक फेड के न्यूनतम पूंजी अनुपात के पैमाने पर खरे उतरते हैं। हालांकि नुकसान के खिलाफ बचाव के आसार 12.7% से कम होकर 9.9% रहेंगे। बैंकों को कुल काल्पनिक नुकसान 57.11 लाख करोड़ रुपए का होगा।

© 2024 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

राजनीति

मैक्रों ने 20 लाख जॉब्स और 60 लाख बिजनेस शुरू किए; पर जल्द चुनाव कराने से उनके लिए ही संकट

30 जून को फ्रांस में होंगे चुनाव नतीजों के बाद यहां का चुनावी समीकरण बदल सकता है

30 जून को फ्रांस में चुनाव होने हैं। यह चुनाव इसलिए भी खास हैं क्योंकि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने देश में समय से पहले चुनाव कराने का फैसला लिया है। एक माह के भीतर फ्रांस की राजधानी पेरिस में 33वें ओलिंपिक खेल होंगे। कुछ अच्छे संग्रहालयों, दीवारों पर पेंटिंग्स के लिए मशहूर पेरिस के किसी समय पिछड़ने का खतरा था लेकिन अब वह टैलेंट और निवेशकों को आकर्षित करता है। उसने फाइनेंस और टेक्नोलॉजी में लंदन को चुनौती देना शुरू कर दिया है। केवल पेरिस ही नहीं फ्रांस के लियोन, डिजोन शहरों का पुनर्जीवन हो चुका है। इसका श्रेय राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को जाता है। लोग सोचते होंगे कि वोटर इससे खुश होंगे पर मैक्रों का गठबंधन चुनाव में भारी पराजय की ओर बढ़ रहा है।

एक विश्लेषक ने मैक्रों के एनसेम्बल गठबंधन के बहुमत पाने के अवसर शून्य बताए हैं। मैक्रों के खिलाफ असंतोष का एक कारण उनका अचानक संसदीय चुनाव कराने का फैसला है। उन्हें तीन साल तक ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। मेरीन ली पेन की दक्षिणपंथी विपक्षी पार्टी नेशनल रैली के यूरोपीय यूनियन चुनाव में शानदार प्रदर्शन के केवल तीन सप्ताह बाद राष्ट्रपति ने चुनाव का जोखिम उठाया है। उनके फैसले ने फूट के शिकार वामपंथी विपक्ष को एकजुट कर दिया है। नेशनल रैली और न्यू पॉपुलर फ्रंट नामक वामपंथी गठजोड़ चुनाव सर्वेक्षणों में पहले और दूसरे स्थान पर हैं। दो दौर के चुनाव में मैक्रों की पार्टी के कई प्रत्याशी पहले दौर के बाद ही बाहर हो सकते हैं।

चुनाव का गलत समय ही अकेला कारण नहीं है। मैक्रों के आर्थिक सुधारों से फायदों के बावजूद फ्रांसीसी वोटर उन्हें खत्म करना चाहते हैं। नेशनल रैली ने पेंशन सुधारों का फैसला पलटने, संपत्ति कर फिर लगाने और पेट्रोल, डीजल, गैस, बिजली पर वैट कम करने के वादे किए हैं। उसने माइग्रेशन के खिलाफ सख्त कदम उठाने, दूसरे देशों से आए मुसलमानों को वापस भेजने, सार्वजनिक स्थानों में परदे पर पाबंदी लगाने का इरादा जताया है। अन्य यूरोपीय देशों से लगी सीमा पर कड़े नियंत्रण लागू होंगे। मैक्रों का वित्तीय मोर्चा कमजोर है। फ्रांस का सालाना बजट घाटा 5% है। सरकार पर जीडीपी का 110% कर्ज है।

चुनाव के बाद किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने की संभावना ज्यादा है। नियमों के अनुसार नए चुनाव एक साल में कराना होंगे। इस वक्त तक फ्रांस में कोई सरकार और संसद नहीं होगी। मैक्रों 2027 तक राष्ट्रपति रहेंगे। इसके बाद ली पेन राष्ट्रपति बन सकती हैं। मैक्रों के पास डिफेंस और विदेश नीति के मामले में व्यापक अधिकार होंगे लेकिन घरेलू नीतियों में उनके विकल्प सीमित हैं। यह संसद के प्रति जवाबदेह सरकार का क्षेत्र है। वे टेक्नोक्रेट्स की सरकार थोपने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन संसद उसे बाहर कर देगी। फ्रांस का असर अन्य यूरोपीय देशों पर होगा। जर्मनी का सत्ताधारी गठजोड़ टूटन की कगार पर है। उसकी सभी तीन पार्टियां यूरोपीय चुनावों में धुर दक्षिणपंथी पार्टी आल्टरनेटिव फॉर जर्मनी से पीछे रही हैं। चांसलर ओलफ स्कोल्ज अनुकूल समय में भी यूरोप का नेतृत्व करने में नाकाम साबित हो चुके हैं। यूरोप में फ्रांस और जर्मनी की जुगलबंदी के बिना कुछ काम नहीं करता है।

मैक्रों ने रोजगार और बिजनेस के अवसर बढ़ाए हैं

राष्ट्रपति के रूप में मैक्रों ने सात साल में फ्रांस को आधुनिक और बिजनेस के लिए अनुकूल अर्थव्यवस्था बनाने के लगातार प्रयास किए हैं। उनके सुधारों ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। 2017 में राष्ट्रपति बनने के बाद बीस लाख नए जॉब पैदा हुए। 60 लाख नए बिजनेस शुरू हुए हैं। उन्होंने कारोबार पर टैक्सों में कटौती की है। मैक्रों ने शिक्षा को बढ़ावा दिया और महंगा पेंशन सिस्टम लागू किया है। फ्रांस की विकास दर यूरोपीय देशों की औसत से अधिक है। वहां गरीबी की दर भी कम है।

मैक्रों के सुधारों से पेरिस जैसे बड़े शहरों को ज्यादा फायदा

मैक्रों के सुधारों से पेरिस और अन्य बड़े शहरों को ज्यादा फायदा हुआ है। फ्रांस के बाकी हिस्से पीछे रह गए हैं। कोविड-19 और महंगाई ने भी वोटरों को प्रभावित किया है। मैक्रों का ज्यादा ध्यान ओलिंपिक खेलों पर रहा इसलिए वे इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दे पाए। वे सोचते थे कि सत्ता की ताकत देश को एकजुट कर सकती है। उनकी इमेज अहंकारी और जनता से दूर राजनेता की बनी है।

© 2024 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.

चीन-जापान जैसे देशों के पुरुष मानते हैं महिलाओं को उनसे अधिक मौके मिल रहे

सोसायटी

महिलाओं के आगे निकलने से एशियाई देशों के पुरुषों में असंतोष

सिओल में 31 साल का शेफ किम वू सिओक हमेशा महिलाओं के प्रति समाज के व्यवहार पर सवाल उठाता था। वह स्वयं को नारीवादी समझता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उसकी राय बदल गई है। महिला एक्टिविस्ट द्वारा पुरुषों का ऑनलाइन मजाक उड़ाने से वह स्तब्ध है। अब वह यकीन करने लगा है कि कोरियाई समाज महिलाओं की तुलना में पुरुषों से ज्यादा भेदभाव बरतता है। किम अकेला नहीं है, जापान,दक्षिण कोरिया,ताइवान और पूर्व एशिया के कुछ अन्य देशों में कई सारे पुरुष ऐसा ही सोचने लगे हैं। पुरुष उस समाज में अधिक असहज महसूस करते हैं, जहां महिलाएं अधिक शिक्षित हैं और उनसे जॉब के मामले में मुकाबला करती हैं।

वर्कफोर्स में संख्या बढ़ी

दक्षिण कोरिया, चीन और ताइवान में लड़कों के मुकाबले अधिक लड़कियां कॉलेजों में पढ़ रही हैं। जापान में 2022 में 25-39 वर्ष की महिलाओं की संख्या पहली बार वर्कफोर्स में 80% से अधिक हो गई थी। दक्षिण कोरिया में 25-29 साल की 74% महिलाएं काम करती हैं।

2021 में एक सर्वे के अनुसार बीस से तीस वर्ष की आयु के 79% दक्षिण कोरियाई पुरुष सोचते हैं कि वे भेदभाव का शिकार हैं। जापान में 18 से 30 साल की आयु के 43 प्रतिशत पुरुष भी ऐसा मानकर चलते हैं। पूर्व एशिया के अधिकतर देशों में पितृ सत्ता का बोलबाला है। इस मामले में जापान, दक्षिण कोरिया की स्थिति सबसे ज्यादा बदतर है। इकोनॉमिस्ट इंडेक्स के अनुसार अमीर देशों के क्लब ओईसीडी में दक्षिण कोरिया में महिलाओं-पुरुषों के वेतन में अंतर सबसे अधिक है। महिलाएं पुरुषों से 31% कम कमाती हैं। जापान में अंतर 21 प्रतिशत है। सर्वे एजेंसी इप्सोस के 2023 के सर्वे में 72% दक्षिण कोरियाई इस बात से सहमत थे कि घर में रहकर बच्चों की देखभाल करने वाला पुरुष पूरी तरह मर्द नहीं है। 30 देशों में यह दर सबसे अधिक है। इस समय जापान में महंगाई चार दशक में सबसे अधिक है। वास्तविक वेतन कम हुआ है। दक्षिण कोरिया में शिक्षा, रोजगार और ट्रेनिंग में युवाओं की हिस्सेदारी घटी है।

इधर जापान में विवाह कम होने लगे हैं। 28-30 वर्ष की 60% से अधिक महिलाएं अविवाहित हैं।

40% पुरुष कभी डेट पर नहीं गए हैं। दक्षिण कोरिया और ताइवान में भी विवाहों की दर ऐसी ही है। इससे भी पुरुष असंतुष्ट हैं। महिलाओं के खिलाफ गुस्सा ऑनलाइन ज्यादा भड़कता है। यूट्यूब पर महिलाओं के खिलाफ ग्रुप बन गए हैं।

© 2024 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

फ्रांस-इटली के अमीर अब दुबई की प्रॉपर्टी में निवेश बढ़ा रहे

बिजनेस

यूरोपीय देशों के करोड़पतियों की दुबई में दिलचस्पी बढ़ रही है

दुबई दुनियाभर के करोड़पतियों का ठिकाना बन रहा है। उसकी सड़कें न्यूयॉर्क या लंदन के मुकाबले अधिक सुरक्षित हैं। वहां इनकम, प्रॉपर्टी या कैपिटल गेन्स पर कोई टैक्स नहीं हैं। वेल्थ कंसल्टेंसी हेनले एंड पार्टनर्स के अनुसार इस साल 6700 करोड़पति संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में प्रॉपर्टी खरीदेंगे या बिजनेस शुरू करेंगे। यह संख्या अमीरों के घर अमेरिका से दोगुनी अधिक है। अमीरात का दमकता बिजनेस सेंटर दुबई अमीर रूसियों, भारतीयों और अरबों को लंबे समय से आकर्षित करता रहा है। अब वह यूरोपीय देशों के अमीरों का ध्यान खींच रहा है।

अमीर फ्रांसीसी और इतालवी प्रॉपर्टी ब्रोकर्स और एजेंट्स के लगातार संपर्क में हैं। कुछ वहां अपनी संपत्ति और बिजनेस को मैनेज करने के लिए ऑफिस खोलना चाहते हैं। कई लोग प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। 2024 के पहले तीन महीनों में भारतीयों के अलावा सबसे ज्यादा मकान फ्रांसीसी और इतालवी अमीरों ने खरीदे हैं। फ्रांसीसियों को दक्षिणपंथी सरकार बनने से कठोर नीतियां लागू होने का डर सता रहा है। अभी हाल दक्षिण पंथी ताकतों के उदय से जर्मन करोड़पति भी चिंतित हैं।

यूरोपियनों के लिए दुबई के आकर्षण को फरवरी में सहारा मिला जब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने शहर को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया। मनी लांडरिंग और अन्य वित्तीय गड़बड़ियां करने वाले इलाके इस लिस्ट में शामिल किए जाते हैं। अमीरात के बैंक अब अपने क्लाइंट के बारे में अधिक सावधानी से छानबीन करते हैं।

© 2024 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.
From The Economist, translated by DB Corp, published under licence.
The original article, in English, can be found on www.economist.com

राष्ट्रीय
सहारा
नई दिल्ली • शनिवार • 29 जून • 2024
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

यदि मुस्कान आपके स्वभाव में नहीं हैं, तो दुकानदारी के चक्कर में न पड़ें।

-चीनी कहावत

अभिभाषण का सार

भारत के संसदीय लोकतंत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण की परंपरा वर्षों पुरानी है। संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक, लोक सभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद, पहले सत्र में सदस्यों के शपथ ग्रहण करने और सदन का अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। यह अभिभाषण सरकार का नीति वक्तव्य होता है। इसमें सरकार की नीतियों और कामकाज का उल्लेख रहता है। इसलिए सरकार के द्वारा ही इसके मसौदे को तैयार किया जाता है। परंपरा तो यह रही है कि इस सबसे गरिमापूर्ण औपचारिक कार्यवाही के दौरान विपक्ष शांतिपूर्ण ढंग से इसे सुनता है। अभिभाषण के बाद जब सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है तो विपक्षी सांसदों को अपनी आपत्तियों और असहमतियों को दर्ज कराने का

अवसर मिलता है लेकिन देखा जा रहा है कि कुछ वर्षों से राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान विपक्षी दलों के सांसद सदन में शोरगुल करते हैं और हंगामा बरपाते हैं। अठारहवीं लोक सभा में जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों को संबोधित करते हुए मोदी सरकार के पिछले दस वर्षों के कामकाज और उपलब्धियों का जिक्र किया तो विपक्षी दलों के सांसदों ने सदन में शोरगुल मचाना शुरू कर दिया। राष्ट्रपति को निवेदन करना पड़ा कि वे शांतिपूर्ण ढंग से उनके अभिभाषण को सुनें। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस समय के सबसे ज्वलंत राष्ट्रीय मुद्दे के रूप में पेपर लीक की घटनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेपर लीक की घटनाओं को बहुत गंभीरता से लिया है और इसे रोकने के लिए कड़े उपाय कर रही है। जाहिर है कि पेपर लीक का मामला सीधे-सीधे देश के छात्र-छात्राओं के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। निश्चित रूप से सरकार को ऐसे सख्त कदम उठाने चाहिए कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। राष्ट्रपति ने युवाओं की बात को आगे बढ़ाते हुए जब यह कहना शुरू किया कि सरकार की कोशिश है कि देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का अवसर मिले तो उनके इतना भर कहने पर विपक्ष के सदस्यों ने सदन के अंदर हंगामा करना शुरू कर दिया। उन्होंने पच्चीस जून, 1975 को देश की जनता पर आपातकाल थोपे जाने की घटना को संविधान और लोकतंत्र पर बड़ा हमला बताया। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय हासिल की क्योंकि भारत के मूल्यों में गणतंत्र की ही परंपराएं हैं।

गिरहबान में झांकें

भारत में धर्मांतरण विरोधी कानूनों, नफरत फैलाने वाले भाषणों और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के घरों और प्रार्थना स्थलों को ध्वस्त करने के मामलों में चिंताजनक वृद्धि हुई है। अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर विदेश विभाग की वार्षिक रिपोर्ट पेश करते हुए अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिकन ने ये बातें कहीं। उन्होंने दुनिया भर में लोगों की धार्मिक आजादी की रक्षा के लिए काफी जद्दोजहद करने की भी बात उठाई। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के 28 में से 10 राज्यों में धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून हैं, जिनमें से कुछ राज्य विवाह के उद्देश्य से जबरन धर्मांतरण के खिलाफ दंड भी लगाते हैं। इसमें दुनिया के तकरीबन दो सौ देशों की धार्मिक स्थिति का आकलन किया गया है। हालांकि भारत इसे पहले से ही खारिज करता रहा है और इसे

प्रकाशित करने वाले आयोग को पक्षपाती बताता है। सिखों, ईसाइयों, यहूदियों, मुसलमानों, दलितों और आदिवासियों के खिलाफ हिंसा से निपटने में मोदी सरकार की नाकामी की बात कर रही है यह रिपोर्ट। इसमें 2023 में गैर- सरकारी संगठनों ने ईसाइयों के खिलाफ हिंसा की 687 घटनाओं का जिक्र भी किया गया है। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने, मणिपुर हिंसा, ईसाइयों पर हमले, चर्च में तोड़-फोड़ और धर्मांतरण कानून के तहत हिरासत में रखे लोगों की चर्चा भी है। चीन, ईरान, रूस, सऊदी अरब, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और बर्मा के साथ भारत का नाम रखे जाने पर सरकार द्वारा जताई गई आपत्ति उचित है। कहना गलत नहीं है कि मोदी सरकार अपनी हिन्दुत्ववादी विचारधारा के चलते बहुसंख्यकों को प्रभावित करने में सफल है। इसलिए हर साल अमेरिका को इस पर पुनः विचार करने की बात करने की बात कर रस्मादायगी कर लेती है, जबकि सरकार को अंतरराष्ट्रीय पटल पर अपनी छवि सुधारने के प्रयास करने चाहिए। संविधान कहता है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है और धार्मिक आजादी मौलिक अधिकार है। इसलिए सभी धर्मावलंबियों की सुरक्षा का दायित्व सरकार का है। वहीं अमेरिका में अश्वेतों को लेकर जो पक्षपात होते हैं, उनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। दूसरों पर उंगली उठाते हुए, खुद की तरफ मुड़ी उंगलियां भी देखनी होंगी।

कटाक्ष/ कबीरदास

ये दुश्मनी वो नहीं छोड़ेंगे!

भई दुश्मनी हो तो मोदी जी जैसी हो, नहीं तो नहीं हो। पट्ठे केजरीवाल से दुश्मनी ठान ली तो ठान ली। अब लाख चुन ले दिल्ली की पब्लिक सीएम की कुर्सी पर बैठाने के लिए। हजार बार अड़ जाए अगला जान छूट जाए पर कुर्सी नहीं छोड़ूं की जिद पर; मोदी जी ने तिहाड़ की हवा खिलाने की ठान ली, तो तिहाड़ की हवा खिला कर ही माने। सॉरी! हवा खिला कर भी माने कहां हैं। अब भी तिहाड़ की हवा खिलाइंग एंड खिलाइंग एंड खिलाइंग!

विरोधियों ने क्या सोचा था? चुनाव में मोदी जी बासठ-तिरेसठ सीटें कम हो गई हैं, अपने बूते बहुमत से गैर-बहुमत में आ गए हैं, यूपी तक में अर्श से फर्श पर आ गए हैं, नायडू-नीतीश की बैसाखियों के सहारे ही पीएम की गद्दी पर चढ़ पा रहे हैं, तो क्या मोदी जी अपनी दुश्मनी छोड़ देंगे? नायडू-नीतीश के सहारे हैं तो क्या मोदी जी भागवत की बात मान कर, विरोधियों को दुश्मन तो छोड़ ही दो, विरोधी भी नहीं, सिर्फ प्रतिपक्षी मानने लग जाएंगे; दुश्मनी भूल कर गले लगाने लग जाएंगे! कभी नहीं। अपना बस चलते तो केजरीवाल को जेल से बाहर आने नहीं देंगे। कर ले बंदा बाहर आने की कितनी भी कोशिशें! देखा नहीं कैसे निचली अदालत ने अगले को जमानत दे दी, तो मोदी जी की ईडी नंगे पांव हाई कोर्ट में पहुंच गई, जमानत रोकी जाए, वर्ना बड़ा गजब हो जाएगा; भारतवर्ष खतरे में आ जाएगा।

हाई कोर्ट ने फौरन तो राष्ट्र को बचा दिया, पर सुप्रीम कोर्ट के दखल देकर जमानत बहाल करने का खतरा तो राष्ट्र पर अब भी मंडरा रहा था। सो, रिले रेस में शाह जी ने सीबीआई को आगे कर दिया और सीबीआई ने जेल से ही गिरफ्तारी कर के दूसरा ही राउंड शुरू कर दिया। अब ईडी के केस वाली जमानत किस काम की; बंदा तो जेल में ही रहेगा। और अगर सीबीआई वाले मामले में भी किसी तरह से जमानत मिल गई तो? तो क्या, मोदी जी ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। अदालत देख ले जमानत देकर। जरूरत पड़ी तो अरविंद नाम वालों के लिए विशेष अध्यादेश ले आएंगे, पर जेल के फाटक से बाहर अगले के कदम नहीं पड़ने दिए जाएंगे। इमरजेंसी का सबक-जब बिना इमरजेंसी के ही विरोधी मुख्यमंत्रियों को जेल में डाले रखा जा सकता हो, तो मोदी जी इमरजेंसी क्यों लगाएं!

प्रगाढ़ होते रिश्ते

भारत-बांग्लादेश

डॉ. लक्ष्मी शंकर यादव

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 21 एवं 22 जून की दो दिवसीय भारत यात्रा की। उनकी इस यात्रा का मकसद दोनों देशों के बीच पहले से ही बने घनिष्ठ संबंधों को और आगे बढ़ाना था। भारत में नई सरकार के गठन के बाद यह किसी विदेशी नेता की पहली द्विपक्षीय राजकीय यात्रा थी। प्रधानमंत्री हसीना की इसी माह में यह दूसरी भारत यात्रा थी। इससे पहले वे प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए भारत आई थीं। इसके बाद जुलाई महीने में चीन की यात्रा पर जाएंगी। चीन की यात्रा पर जाने से पहले उनका दो बार भारत आना दर्शाता है कि चीन यात्रा से उनके भारतीय संबंधों को कोई खतरा नहीं है। इधर भारत सरकार भी बांग्लादेश से अपने मधुर संबंधों को आगे जारी रखना चाहती है।

बांग्लादेश और भारत के प्रधानमंत्रियों ने 22 जून को बैठक करके व्यापक वार्ता की। इस वार्ता में नये क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए भविष्य की योजना पर सहमति जताई और समुद्री क्षेत्र सहित अनेक मुख्य क्षेत्रों में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए तकरीबन 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित प्रमुख समझौतों में डिजिटल, हरित और रक्षा क्षेत्रों में बढ़ावा देने के समझौते शामिल हैं। इनमें बांग्लादेश के रोगियों के लिए ई-वीजा प्रमुख है। उल्लेखनीय है कि बड़ी संख्या में बांग्लादेश के लोग इलाज कराने के लिए भारत आते हैं। वहां से भारत आने वाले ऐसे लोग 30 प्रतिशत के करीब हैं। ई-वीजा मिलने से ऐसे लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमने नये क्षेत्रों में सहयोग के लिए भविष्योन्मुखी विजन तैयार किया है, जिसमें हरित साझेदारी, डिजिटल साझेदारी, अंतरिक्ष एवं ब्लू इकॉनमी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भारत-बांग्लादेश की बनी सहमति से दोनों देशों के नवयुवकों को काफी लाभ मिलेगा। दोनों देशों की 'मैत्री उपग्रह' भारत-बांग्लादेश संबंधों को नई ऊंचाइयां प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि हम अपनी वरीयता में डिजिटल और ऊर्जा कनेक्टिविटी पर फोकस रखेंगे। हमने पिछले 10 वर्षों में कार्य करते हुए 1965 से पहले की कनेक्टिविटी को बहाल कर दिया है। इससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्था गतिशील होगी। उन्होंने दोहराया, 'मैं बंगबंधु के स्थिर, समृद्ध और प्रगतिशील बांगलादेश के विजन को साकार रूप प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हूं।' इन समझौतों में दूसरा समझौता बांग्लादेश के रंगपुर में भारत का नया सहायक उच्चायोग होगा। बांग्लादेश के उत्तर-पश्चिम क्षेत्र के लोगों के लिए रंगपुर में सहायक उच्चायोग

खोलने का निर्णय लिया गया है। ढाका और कोलकाता के बीच नई रेल सेवा चालू की जाएगी। इसी तरह, चटगांव और कोलकाता के बीच नई बस सेवा चालू हो जाएगी। पांचवां समझौता मेदे-दरसाना और हल्दीबाड़ी-चिलाहाटी के बीच दलगांव तक मालगाड़ी सेवाओं की शुरुआत किए जाने का है।

इसके अलावा, अनुदान सहायता के तहत सिराजगंज में अंतर्देशीय कंटेनर डिपो का निर्माण किया जाएगा। भारतीय ग्रिड के माध्यम से नेपाल से बांग्लादेश को 40 मेगावाट बिजली के निर्यात की शुरुआत की जाएगी। 1996 की गंगा जल संधि के नवीनीकरण के लिए भी एक समिति बनाई जाएगी। रक्षा संबंधों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मोदी और शेख हसीना के बीच चर्चा हुई। इसमें दोनों देशों ने लंबी अवधि के हितों को ध्यान में रख कर रक्षा सहयोग की एक नीति बनाने का निर्णय लिया है।

उल्लेखनीय है कि भारत-बांग्लादेश के बीच सैनिक और रक्षा सहयोग की गति अभी तक काफी धीमी रही है, लेकिन अब किए गए नये समझौते के बाद से भारत जो सहयोग करेगा उससे बांग्लादेश की आर्मी काफी अत्याधुनिक बनेगी। बांग्लादेश की रक्षा जरूरतों के मुताबिक रक्षा उपकरणों का उत्पादन शुरू होगा। यह कार्य इस प्रकार का होगा कि बांग्लादेश की रक्षा और यौद्धिक क्षमता काफी बढ़ सके। अभी तक भारत ने इस तरह का रक्षा समझौता किसी पड़ोसी देश के साथ नहीं किया है। प्रधानमंत्री मोदी और शेख हसीना ने आतंकवाद, कट्टरवाद और सीमा पर शांतिपूर्ण प्रबंधन अपनी सहभागिता को मजबूत करने का भी निर्णय लिया है।

इसके अतिरिक्त, दोनों देशों के मध्य हिन्द महासागर क्षेत्र के लिए समान दृष्टिकोण अपनाए जाने की बात निश्चित हुई। दोनों प्रधानमंत्रियों की मुलाकात में भारत ने बांग्लादेश की पुरानी मांग मान ली और बांग्लादेश को भूटान तथा नेपाल के साथ भारतीय रेलवे के जरिए कारोबार करने की स्वीकृति प्रदान कर दी। इस स्वीकृति से बांग्लादेश को निर्यात बढ़ाने का बेहतर अवसर प्राप्त होगा। इस कदम से उत्साहित दोनों देश शीघ्र ही एक विशेष समझौता भी करने वाले हैं। अब दोनों देशों का प्रयास है कि भूटान, नेपाल और बांग्लादेश के बीच एक साझा बाजार तैयार किया जा सके। यदि इस कार्य में सफलता मिल गई तो भविष्य में इस बाजार में अन्य पड़ोसी देशों जैसे श्रीलंका, म्यांमार आदि को शामिल किया जा सकेगा। इसीलिए दोनों देश रेल, सड़क, हवाई मार्ग और समुद्री मार्ग के जरिए आवागमन और माल ढुलाई के लिए कनेक्टिवटी को और ज्यादा मजबूत बनाएंगे।

प्रधानमंत्री मोदी और शेख हसीना के बीच बैठक में इस बात की भी सहमति बनी कि तीस्ता नदी जल प्रबंधन पर वार्ता के लिए भारत की एक तकनीकी टीम ढाका का दौरा करेगी। टीम तीस्ता नदी की गाद को साफ करने तथा नदी को पुराने स्वरूप में लौटाने के लिए एक रोडमैप तैयार करेगी। बांग्लादेश में तीस्ता नदी के संरक्षण पर बातचीत के लिए एक भारतीय दल भेजने का निर्णय इसलिए महत्त्वपूर्ण है क्योंकि भारत की आपत्तियों के बावजूद एक अरब अमेरिकी डॉलर की इस परियोजना पर चीन की नजर थी। यह मुद्दा भारत के लिए अत्यंत संवेदनशील है क्योंकि चीन की कंपनियों को ठेका मिलने का मतलब है कि उन्हें तीस्ता नदी से संबंधित सारा डाटा हासिल हो जाएगा। इसलिए भारत का प्रयास था कि चीन का इसमें प्रवेश न हो। इस आश्वासन के बाद अपने देश पहुंच कर शेख हसीना ने कहा कि उनकी भारत यात्रा सार्थक रही। निश्चित है कि उपर्युक्त समझौतों के बाद भारत तथा बांग्लादेश के आपसी संबंध और अधिक मधुरता की ओर बढ़ेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी और शेख हसीना के बीच बैठक में सहमति बनी कि तीस्ता नदी जल प्रबंधन पर वार्ता के लिए भारत की तकनीकी टीम ढाका का दौरा करेगी। टीम तीस्ता नदी की गाद साफ करने तथा नदी को पुराने स्वरूप में लौटाने के लिए रोडमैप तैयार करेगी। भारतीय दल भेजने का निर्णय इसलिए महत्त्वपूर्ण है क्योंकि भारत की आपत्तियों के बावजूद एक अरब अमेरिकी डॉलर की इस परियोजना पर चीन की नजर थी

शाम की कसरत मोटे लोगों के लिए फायदेमंद

- सिडनी यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया ने एक अध्ययन में पाया है कि दिन के अलग-अलग समय में की गईं शारीरिक गतिविधियों के मुकाबले शाम की कसरत मोटे लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद है
- शोध का निष्कर्ष है कि ग्लूकोज कंट्रोल करने और हृदय रोग के जोखिम को कम करने में भी शाम की कसरत लाभकारी है
- यह अध्ययन डायबिटीज केयर जर्नल में प्रकाशित हुआ है। अलबत्ता, यह भी सच है कि व्यायाम किसी भी तरह से मोटापे के संकट का एकमात्र समाधान नहीं है

(मीडिया इन्पुट्स)

अभी-अभी अमेरिकी राष्ट्रपति पद की डिबेट सुनीः क्या यही वास्तव में सबसे अच्छे दो विकल्प खुद को विश्व का महान लोकतंत्र कहकर नाज करने वाले देश को मुहैया कराने पड़ते हैं? ऐसा है तो बेहद दुखद बात।

राजदीप सरदेसाई, पत्रकार
@sardesairajdeep

अब भारत बनाए अपने सूचकांक

मुद्दा | प्रह्लाद सबनानी

वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों की भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में रेटिंग तय करने की दृष्टि से वित्तीय एवं विशिष्ट संस्थानों द्वारा सूचकांक तैयार किए जाते हैं। हाल के समय में इन विदेशी संस्थानों द्वारा जारी किए गए कई सूचकांकों में भारत की स्थिति को संभवतः जान बूझकर गलत दर्शाया गया है। इन सूचकांकों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं अफ्रीका के गरीब देशों की स्थिति को भारत से बेहतर बताया गया है। उदाहरण के लिए हाल में पश्चिमी देशों द्वारा जारी किए गए तीन सूचकांकों की स्थिति देखिए।

सबसे पहले उदार (लिबरल) लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंकिंग को 104 बताया गया है। इसी प्रकार, आनंद (हैपीनेस) सूचकांक में भी भारत का स्थान 126वां बताया गया है जबकि पाकिस्तान को 108वां स्थान मिला है, जहां अत्यधिक मुद्रास्फीति के चलते वहां के नागरिक अत्यधिक त्रस्त हैं। एक अन्य प्रेस की स्वतंत्रता नामक सूचकांक में भारत को 161वां स्थान मिला है जबकि इस सूचकांक में कुल मिलाकर 180 देशों को शामिल किया गया और अफगानिस्तान को 152वां स्थान दिया गया है अर्थात इस सर्वे के अनुसार, अफगानिस्तान में प्रेस की स्वतंत्रता भारत की तुलना में अच्छी पाई गई है। पश्चिमी देशों में स्थित इन संस्थानों द्वारा इस प्रकार के सूचकांक तैयार करके पूरे विश्व को भ्रमित किए जाने का प्रयास हो रहा है।

इसी प्रकार, भारत में हाल में संपन्न हुए लोक सभा चुनाव पर भी पश्चिमी देशों ने कई प्रकार के सवाल खड़े करने के प्रयास किए थे। जैसे, भीषण गर्मी के मौसम में चुनाव क्यों कराए गए, जिससे सामान्यजन वोट डालने के लिए घरों से बाहर ही नहीं निकले, ईवीएम मशीन में कोई खराबी तो नहीं है आदि, परंतु भारतीय मतदाताओं ने चुनाव में भारी संख्या में भाग लेकर पश्चिमी देशों को करारा जवाब दिया है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव सामान्यतः शांति के साथ संपन्न हो गए। इस सबके बावजूद पश्चिमी देशों ने पश्चिमी लोकतंत्र सूचकांक में 2014 में भारत को 27वां स्थान दिया था और 2023 में भारत की रैंकिंग नीचे गिराकर 41वें स्थान पर बताई गई है, जबकि वास्तव में तो इस बीच देश में लोकतंत्र अधिक मजबूत ही हुआ है।

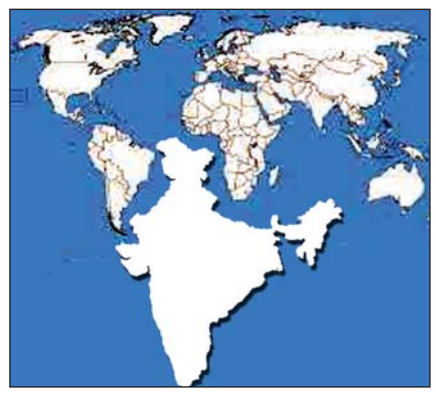

दरअसल, पश्चिमी देशों में कुछ शक्तियां भारत के हितों के विरुद्ध कार्य कर रही हैं एवं ये ताकतें विभिन्न सूचकांक तैयार करने वाली संस्थाओं को प्रभावित करने में कोर कसर नहीं छोड़ती हैं। कुछ समय पूर्व एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान ने वैश्विक भुखमरी सूचकांक जारी किया था। इस सूचकांक में बताया गया था कि भारत की तुलना में श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, इथियोपिया, नेपाल, भूटान आदि देशों में भुखमरी की स्थिति बेहतर है अर्थात सर्वे में शामिल किए गए 121 देशों की सूची में श्रीलंका का स्थान 64वां, म्यांमार का 71वां, बांग्लादेश का 84वां, पाकिस्तान का 99वां, एथीयोपिया का 104वां एवं भारत का 107वां स्थान बताया गया था जबकि पूरा विश्व जानता है कि श्रीलंका, पाकिस्तान एवं म्यांमार जैसे देशों में खाद्य पदार्थों की भारी कमी है। फिर किस प्रकार ऐसे सूचकांक बनाकर वैश्विक स्तर पर जारी किए जा रहे हैं। आभास हो रहा है कि भारत की आर्थिक तरक्की को विश्व के कई देश अब सहन नहीं कर पा रहे हैं एवं भारत के बारे में ऐसे सूचकांक जारी कर भारत की साख को वैश्विक स्तर पर प्रभावित किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। सवाल पैदा होता है कि अब कौन इस प्रकार के सूचकांकों पर विश्वास करेगा।

यह भी बताया जा रहा है कि इस सूचकांक को आंकने के लिए भारत के 140 करोड़ नागरिकों में से 3000 नागरिकों को ही इस सर्वे में शामिल किया गया था। इस प्रकार सर्वे का सैम्पल बनाते समय भारत जैसे विशाल देश के लिए अपर्याप्त संख्या का उपयोग किया गया। वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों की सावरेन क्रेडिट रेटिंग पर कार्य कर रही संस्था 'स्टैंडर्ड एंड पूअर' ने हाल में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकलन करते हुए भारत के संबंध में अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक करते हुए कहा है कि वह भारत की सावरेन क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड करने के उद्देश्य से भारत के आर्थिक विकास संबंधी विभिन्न पैमानों आधारभूत ढांचे को विकसित करने एवं राजकोषीय घाटे को कम करने से संबंधित आंकड़ों एवं प्रयासों का गंभीरता से लगातार अध्ययन एवं विश्लेषण कर रही है। वैश्विक पटल पर पश्चिमी देशों की विभिन्न संस्थानों द्वारा भारत के प्रति ईर्ष्या का भाव रखने के चलते समय आ गया है कि भारत विभिन्न पैमानों पर अपनी रेटिंग तय करने के लिए अपने सूचकांक विकसित करने पर विचार करे क्योंकि वैश्विक स्तर पर पश्चिमी देशों द्वारा जितने भी सूचकांक तैयार किए जा रहे हैं, उनमें भारत के संदर्भ में वस्तुस्थिति का सही वर्णन नहीं किया जा रहा है।

शुकराना का भाव | संत राजिन्दर

हम लोग सोचते हैं कि परमात्मा हमसे बहुत दूर हैं क्योंकि हमें लगता है कि पिता-परमेश्वर किसी दूर स्थान पर मौजूद हैं, जो पृथ्वी पर हमारे

जीवन के बारे में पूरी तरह से बेपरवाह हैं। हमें आश्चर्य होता है कि वे तो इतने व्यस्त हैं, उन्हें हमारे बारे में सोचने का समय कैसे होगा? पृथ्वी पर करोड़ों लोग रहते हैं, क्या वे हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देंगे? परंतु हम जैसा सोचते हैं असलियत बिल्कुल इसके विपरीत है। हम जो कुछ भी करते हैं उसके बारे में परमात्मा सब जानते हैं और हमारे माता-पिता से भी ज्यादा हमारी परवाह करते हैं। पिता-परमेश्वर का दरवाजा हमेशा-हमेशा के लिए खुला है। यदि हम दुनिया भर के लोगों की सभी प्रार्थनाएं सुनें तो हम उनमें समानता ही पाएंगे। हमने कई लोगों को पिता-परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए सुना-देखा होगा। हम यह भी देखते हैं कि वे उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर भी देते हैं, लेकिन यह इंसान का स्वभाव है कि जिस क्षण हमें जवाब नहीं मिलता या उस समय नहीं मिलता जब हम चाहते हैं, या वैसा नहीं मिलता जैसा हम चाहते हैं, तो हम निराश या दुःखी हो जाते हैं। यह किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं है, बल्कि ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। शुकराना एक विशेष गुण है, जिसकी कमी बहुत से लोगों में है। हम किसी के लिए सौ काम कर लें, लेकिन वह व्यक्ति उस एक चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करता है जो हमने नहीं किया या उसकी पसंद के अनुसार नहीं किया। ऐसे ही यदि हम अपने बच्चों को सैकड़ों खिलौने खरीद कर दें, लेकिन अगर हम एक भी खिलौना उनसे वापस ले लेते हैं तो वे हमसे शिकायत करते हैं। हम किसी के लिए अनेक स्वादिष्ट भोजन बना सकते हैं, लेकिन वह व्यक्ति सिर्फ उस भोजन पर ध्यान केंद्रित करता है जो पकवान हमसे जल गया था। ऐसे ही यदि हम किसी के जन्मदिन पर हर साल सुंदर ग्रीटिंग कार्ड भेजते हैं, लेकिन अगर हम किसी एक साल कार्ड भेजना भूल गए तो वह उस एक साल की शिकायत करता है। जहां हम काम करते हैं वहां यदि हम हजारों पेज टाईप कर लें, लेकिन हम कभी भी प्रशंसा का एक शब्द भी नहीं सुनते, लेकिन यदि अगर हमसे टाइपिंग में कोई गलती हो जाए तो उस पर हमें टोका जाता है।

रीडर्स मेल

झूठ बोलने से बचे विपक्ष

दिल्ली टर्मिनल में भारी बारिश की वजह से एक कार चालक की मौत दुखद है। विपक्ष ने जनता को भ्रमित करने के लिए झूठ परोसना शुरू कर दिया। कांग्रेस की महिला प्रवक्ता ने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित किया कि प्रधानमंत्री ने टर्मिनल एक का उद्घाटन 2024 में किया था, जबकि 2009 में कांग्रेस सरकार के अंतर्गत निर्मित हिस्सा टूटा और दुर्घटना हुई। इसी प्रकार अटल टनल के बारे में भी झूठी खबर फैलाई गई, सर्विस रोड को मुख्य मार्ग बता कर छायाचित्र प्रचारित किए गए, राममंदिर को लेकर भी झूठी खबरें फैलाई गईं कि पहली बारिश में ही राममंदिर की छत टपकने लगी। चुनाव से पहले और दौरान भी अनगिनत झूठ प्रचारित-प्रसारित किए गए और उसका खमियाजा सत्ता पक्ष को भुगतना पड़ा। इस पर अंकुश नहीं लगा तो भविष्य में मुश्किल होना तय है।

योगेश जोशी, बड़वाह, मप्र

कोहली की 'विराट' पारी बने

विश्व कप के अंतिम पड़ाव पर शनिवार को क्रिकेट का रोमांच चरम पर होगा जब पहली बार फाइनल में पहुंची नई नवेली टीम दक्षिण अफ्रीका का तीन बार के विश्व विजेता से मुकाबला होगा। विश्व कप में अपने-अपने सभी मैच जीत कर फाइनल में पहुंची भारत और द. अफ्रीका की टीमें अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन दोहराना चाहेंगी। फिर भी भारतीय टीम का पलड़ा भारी लगता है। टीम में अनुभवी बल्लेबाज, श्रेष्ठ क्षेत्र रक्षक और विकेट टेकर गेंदबाज अफ्रीका के लिए बड़ी चुनौती हैं। अगर चिंता है तो केवल भारतीय ओपनर विराट कोहली की जो अपनी ख्याति के अनुरूप इस टूर्नामेंट में प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। क्रिकेट प्रेमी उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि कोहली अपना नैसर्गिक प्रदर्शन कर टीम इंडिया को विश्व कप जिताएं। भारतीय टीम को विश्व विजेता बनने की शुभकामनाएं।

अमृतलाल मारू 'रवि', इंदौर

अरुंधति को शुभकामनाएं

यह जानकार मन-मस्तिष्क प्रफुल्लित हो गया कि लेखिका अरुंधति रॉय को इस वर्ष का 'पेन पिंटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें सबसे ज्यादा पहचान इनके उपन्यास 'द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स' के कारण मिली। इसी कृति के वास्ते इन्हें 1997 में बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। पेन पिंटर पुरस्कार और पिंटर इंटरनेशनल राइटर ऑफ करेज पुरस्कार, दोनों ही वार्षिक साहित्यिक पुरस्कार हैं, जिन्हें 2009 में इंग्लिश पेन द्वारा नोबेल साहित्य पुरस्कार विजेता नाटककार हेरोल्ड पिंटर के सम्मान में शुरू किया गया था, जो इंग्लिश पेन के उपाध्यक्ष एवं इंटरनेशनल पेन राइटर्स इन प्रिजन कमेटी के सक्रिय सदस्य थे। यह घोषणा भारत में अधिकारियों द्वारा 14 साल पहले की गईं टिप्पणियों के लिए आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत रॉय के खिलाफ कार्रवाई को मंजूरी दिए जाने के कुछ हफ्ते बाद की गई है। उन्होंने भारत में मानवाधिकार मुद्दों के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर युद्ध और पूंजीवाद के बारे में भी जम कर एवं निडर होकर लिखा है। अब सवाल उठता है कि क्या अरुंधति रॉय को 14 साल पुरानी टिप्पणी के लिए जेल जाना पड़ेगा? मगर वे लड़ाकू प्रवृत्ति की हैं। इस पर भी जरूर विजय प्राप्त करेंगी।

जंगबहादुर सिंह, जमशेदपुर, झारखंड

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा • राष्ट्रीयता • कर्तव्य • समर्पण
वर्ष-33, अंक 267

सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सातवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित। । समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, फैक्स - 23352370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

बारिश का एक दुख

पहली बारिश में ही दिल्ली का जो हाल हुआ है, वह न केवल चिंताजनक, बल्कि दुखद भी है। जगह-जगह जाम, जल भराव, पेड़ों का गिरना अपनी जगह बहुत गंभीर है, पर सबसे सनसनीखेज घटना नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल-1 पर घटी है। शुक्रवार को भारी बारिश के बीच छत का एक हिस्सा वाहनों पर आ गिरा, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और छह लोग घायल हो गए। जब हादसा हुआ, तब बारिश हो रही थी, सुबह करीब 5.30 का समय था, हादसा अकल्पनीय था। बीते मार्च में ही नई दिल्ली के सबसे बड़े हवाई अड्डे के टर्मिनल-1 का विस्तार किया गया है। इसका विस्तार करने-कराने वालों ने सुंदरता का तो ध्यान रखा, मगर मजबूती सुनिश्चित करना शायद वे भूल गए। इस टर्मिनल से लाखों लोग यात्रा करते हैं, पर रखरखाव में ऐसी लापरवाही अक्षम्य मानी जाए, तो ही न्याय है। एक बार सोचकर जरूर देखना चाहिए कि दुनिया में क्या संदेश गया है? क्या भारत अपने एक सबसे महत्वपूर्ण हवाई अड्डे को भी ढंग से नहीं रख पा रहा है?

राजधानी दिल्ली में एयरपोर्ट पर जब यह हाल है, तो बाकी जगहों पर आम लोगों की सुरक्षा को लेकर न जाने कितने सवाल खड़े किए जा सकते हैं? न जाने कितने ऐसे रेलवे स्टेशन, बस अड्डे देश में होंगे, जिन्हें सिर्फ रंग-रोगन करके चमकाया गया होगा? जिम्मेदार अधिकारियों को शर्म आनी चाहिए, उनकी लापरवाही के चलते भ्रष्टाचार का मुद्दा फिर चर्चा में आ गया है? कहीं भवन ढह रहे हैं, तो कहीं पुल गिर रहे हैं, तो कहीं सड़कों पर दरारें पड़ रही हैं? खूब लंबे-चौड़े राष्ट्रीय राजमार्ग बनाना जरूरी है, पर शहरों के अंदर की सड़कों का रखरखाव कौन करेगा? दिल्ली में केवल दो घंटे की बारिश के बाद अंडरपास और अंडर ब्रिज में पानी भर जाना क्या हमारी अक्षम नौकरशाही की ओर इशारा नहीं है? नौकरशाहों को भला कैसे निर्दोष मान लिया जाए और अगर उन्हें निर्दोष मान लिया जाए, तो फिर दोषी कौन है? यह शर्मनाक बात है कि राष्ट्रीय राजधानी में स्थित मिंटो ब्रिज दशकों से लोगों को रुलाता आ रहा है, वहां से तमाम नेताओं, अफसरों, रसूखदारों की गाड़ियां गुजरती हैं, पर क्या मजाल कि मिंटो ब्रिज इलाके में पानी न भरे? देश में ऐसे न जाने कितने स्थान हैं, जिनके बारे में यह मान लिया गया है कि यहां तो जल भराव एक सालाना आयोजन है। साल में दस-पंद्रह दिन जल भराव होगा, तो इस समस्या के समाधान के लिए क्या जहमत उठाएं?

एक बार सोचकर जरूर देखना चाहिए कि दुनिया में क्या संदेश गया है? क्या भारत अपने एक सबसे महत्वपूर्ण हवाई अड्डे को भी ढंग से नहीं रख पा रहा है?

क्या हम अपने देश में नागरिक सुरक्षा से समझौता कर रहे हैं? क्या अपने देश में लोगों की जिंदगी को बहुमूल्य माना जाता है? इस बार भी उदारता से मुआवजा दे दिया जाएगा, पर पुख्ता समाधान व सुरक्षा के इंतजाम के प्रति लापरवाही बरती जाएगी? यह दोषारोपण करने या आंखें चुराने का नहीं, बल्कि कमियों से दो-दो हाथ करने का वक्त है। सुविधाओं का विस्तार जरूरी है, लेकिन उनकी गुणवत्ता भी काबिले-गौर होनी चाहिए। गुणवत्ता या कानून से समझौता करने की इजाजत किसी को भी नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था गतिवान है, वस्तुओं और सेवाओं का निरंतर विस्तार हो रहा है, पर अगर हम अपने नागरिकों की कद्र नहीं बढ़ाएंगे, तो वास्तव में विकास को ही अंगूठा दिखाएंगे। दुनिया के अच्छे देशों से सीखते हुए सुधार की जरूरत है, ताकि हमारा बेहद चमकदार होता बुनियादी ढांचा हमारे माथे पर ही न गिरने लगे और हम आश्वस्त होकर सिर उठाए चल सकें।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 29 जून, 1949

नरेशों की सम्पत्ति

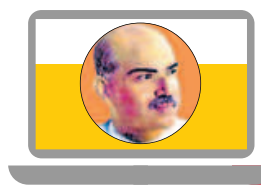

रियासतों के स्वतंत्र अस्तित्व का जब अन्त किया जा रहा है, तब नरेशों का महत्व भी पहले जैसा नहीं रह सकता। किन्तु रियासतें राजाओं की विरासत-सी रही हैं, इसलिए रियासत की कौन-सी सम्पत्ति राजा की मानी जाये और कौन-सी राज्य की, यह निश्चय करना सरल नहीं है। सभी रियासतों में यह समस्या रही है और प्रवृत्ति कुछ ऐसी पाई गई कि राजा अधिक-से-अधिक चीजें अपने पास रखने की कोशिश करते हैं और लोकपक्ष समझता है कि यह ठीक नहीं है। रियासती मंत्रालय के निर्णय द्वारा इस स्थिति का समाधान ही ऐसी हालत में विवाद को समाप्त कर सकता है। इस दृष्टि से रियासती मंत्रालय के इस विषयक निर्णय का हम स्वागत करते हैं।

जो निर्णय किया गया है, वह अभी अस्थायी है और तीन-चार रियासतों पर लागू नहीं होता, फिर भी एक अरब रुपये से अधिक सम्पत्ति का निश्चय उससे हो जाता है। आधार उसका यह रखा गया है कि (१) राजा जिस महल में रहता हो उसे वह अपने पास रख सकेगा, साथ ही समुद्रतटवर्ती या पहाड़ के एक मकान को भी वह रख सकता है, बाकी सब मकान राज्य के माने जायेंगे। (२) जमीन राजा के पास नहीं रहेगी और उसके पूर्वजों की सम्पत्ति साबित होने पर कोई जमीन राजा के पास रही भी, तो और लोगों की तरह उसे भी उस पर कर देना पड़ेगा। (३) सरकारी खजाने में जो रकम राजा की निजी सम्पत्ति के रूप में रहती आई है उनकी जांच कर उसका बहुत-सा भाग उन रियासतों से बने राज्यसंघों को दे दिया गया है और जो रकम सचमुच निजी मालूम पड़ी, वही राजा की निजी सम्पत्ति मानी गई है। (४) बाहर लगा रुपया या संकट के लिए सुरक्षित कोष कई राजाओं ने स्वयं राज्यों को दे दिया है। (५) जवाहरात को दो किस्मों में बांटा गया है और निजी उपयोग वाले निजी सम्पत्ति माने गये हैं तथा समारोहों पर काम आने वाले राज्य की। (६) पुरातत्व की चीजें भी सरकारी नियंत्रण में रहेंगी। (७) राजाओं द्वारा दी गई जागीरों (जमीन) के बारे में तय हुआ है कि विलीनीकरण के आसपास दी गई जागीरें मान्य नहीं की जायेंगी और उससे बहुत पहले दी गई जागीरें वहां की भूमि सम्बन्धी कानून के मातहत रहेंगी।

लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव शुरू से राजनीतिक खींचतान का विषय रहा है। यही कारण है, देश की पहली लोकसभा में भी अध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मति से नहीं हुआ था। विपक्ष के नेता चाहते थे कि लोकसभा अध्यक्ष कोई स्वतंत्र उम्मीदवार हो और आज भी कई लोग यही चाहते हैं।

आमने-सामने

दल छोड़कर लोकसभा अध्यक्ष बनना चाहिए

यहां स्कैन करें

श्यामा प्रसाद मुखर्जी | वरिष्ठ नेता व सांसद

- अध्यक्ष का निर्वाचन जिस ढंग से हुआ है, मैं उससे अधिक प्रसन्न नहीं हूं।
- विरोधी दल से परामर्श करते, तो शायद निर्वाचन सर्वसम्मति से हो जाता।
- बहुमत के बल पर अगर कानून बनाए गए, तो उन्हें भंग किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय (जीवी मावलंकर) पूर्व वक्ताओं के साथ-साथ मैं भी आपको लोकसभा अध्यक्ष बनने पर बधाई देता हूं तथा श्रद्धा अर्पित करता हूं। आप इस पद के लिए कोई नवागन्तुक तो नहीं हैं। आप भूतपूर्व केंद्रीय धारा सभा के अध्यक्ष तथा बाद में अस्थायी संसद के अध्यक्ष रह चुके हैं, जिस हैसियत में आपको उचित परंपराओं तथा प्रथाओं की स्थापना करनी पड़ी है। अतः स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद का अध्यक्ष निर्वाचित होने का भी आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वास्तव में, भारत के सांविधानिक इतिहास में आपका एक अपना विशिष्ट स्थान है।

मुझे तनिक भी संदेह नहीं कि आपके हाथ में माननीय सदस्यों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। हम सामान्यतः ब्रिटिश लोकसभा की प्रथाओं तथा परंपराओं का ही अनुसरण करते रहेंगे, किंतु ऐसी परिस्थितियों के उत्पन्न होने की संभावना है, जब हमें उन परंपराओं में परिवर्तन करके अपनी स्वयं की प्रथाएं स्थापित करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हमारा परम लक्ष्य जन-साधारण का कल्याण तथा देश की प्रगति है।

अध्यक्ष का निर्वाचन जिस ढंग से हुआ है, मैं उससे अधिक प्रसन्न नहीं हूं। यदि आप एक पार्टी के उम्मीदवार के रूप में खड़े न होकर एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में पुनर्निर्वाचन के लिए खड़े होते, तो हमें अधिक प्रसन्नता होती। सारे संसार की यह मानी हुई परंपरा है तथा अध्यक्ष का कोई विरोध नहीं करता है। यदि इस सदन के नेता निर्वाचन के लिए आपका नाम प्रस्तुत करने से पूर्व विरोधी दल से परामर्श कर लेते, तो शायद अध्यक्ष का निर्वाचन सर्वसम्मति से हो जाता। मुझे मालूम नहीं है कि ऐसा क्यों नहीं किया गया। कहने का आशय यह है कि परंपराओं तथा प्रथाओं की स्थापना तथा पालन करना हम सबका कर्तव्य होना चाहिए, चाहे हम सरकारी पक्ष में बैठे हों अथवा विरोधी पक्ष में।

स्वतंत्र भारत में यह पहला अवसर है, जब संसद में विरोधी दल के सदस्यों की संख्या काफी अधिक है, यद्यपि यह मानी हुई बात है कि सरकारी पक्ष के पास सदन में भारी बहुमत है। ऐसी दशा में श्रीमान, आप इस बात की ओर ध्यान देंगे कि सरकारी तथा विरोधी, दोनों पक्षों द्वारा परंपराओं तथा प्रथाओं का पालन किया जाए। लोकतंत्र के विकास के लिए यह आवश्यक है। ऐसे कठिन कार्य में, श्रीमान, यह आपका कार्य है कि आप सदन की कार्यवाही को ठीक ढंग से चलाएं, जिससे कि यद्यपि कुछ मामलों में हमारे पारस्परिक मतभेद हों, किंतु हमें अपने विचार सदन के समक्ष रखने का तथा सरकार की मनमानी कार्रवाइयों को किसी हद तक रोकने का मौका मिले। श्रीमान, मैं विरोधी दल के सदस्यों की ओर से आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि सदन की शान तथा इसके अधिकारों के लिए उचित परंपराएं तथा प्रथाएं स्थापित करने के आपके प्रयत्न में वे सदैव आपको सहयोग देते रहेंगे।...

यहां पर अनेक दलों के प्रतिनिधि मौजूद हैं। हमारे दृष्टिकोण भिन्न हैं, किंतु देशहित के लिए हमें ऐसा निश्चय करना चाहिए, जिससे हमारी सामान्य जनता को लाभ पहुंचे। यदि हम अपने मतभेदों को दूर न कर सके, तो अवश्य ही तानाशाही का इस देश में राज्य होगा। ...हमें कानून का सम्मान करना चाहिए और यह बात ठीक भी है। इस संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, किंतु यहां पर कानून इस प्रकार से बनाए जाने चाहिए, जिसमें उसे प्रत्येक दल का सहयोग प्राप्त रहे। यदि बहुमत के बल पर कानून बनाए गए- जिन्हें साधारण जनता पसंद नहीं करती- तो उन्हें अवश्य ही भंग किया जाएगा। कानूनों को हिंसक ढंग से नहीं, अहिंसक ढंग से भंग किया जाएगा, किंतु मैं आशा करता हूं, हम सब अपना-अपना कर्तव्य ठीक प्रकार से निभा सकेंगे। मतभेदों के होते हुए भी हम ऐसे निश्चय पर पहुंचेंगे, जिससे जन साधारण को लाभ होगा।

(लोकसभा में दिए गए दो उद्बोधनों के अंश)

मैं अपने दल से कतई अलग नहीं रह सकता

यहां स्कैन करें

जीवी मावलंकर | प्रथम लोकसभा अध्यक्ष

- हमारा लक्ष्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व प्राप्त करना है।
- हमारे देश में निर्दलीय का अध्यक्ष रहना संभव नहीं है।
- मेरा धर्म होगा कि मैं सदन के सभी पक्षों के साथ समान व्यवहार करूं।

संविधान के अंतर्गत निर्वाचित भारतीय गणतंत्र की पहली संसद का अध्यक्ष चुनकर माननीय सदस्यों ने जो मेरा सम्मान किया है, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। इस पद के कर्तव्यों, उत्तरदायित्वों तथा कठिनाइयों पर जब मैं दृष्टिपात करता हूं, तो मुझे एक प्रकार की घबराहट अथवा संभ्रांति हो जाती है, किंतु सदन की उदारता तथा आपके सहयोग की बात को ध्यान में रखते हुए मैं यह भार उठाने के लिए उत्साहित हूं।...

हमें ध्यान में रखना होगा कि हम यहां जनता के प्रतिनिधि होकर आए हैं तथा हमारा लक्ष्य उनके लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व प्राप्त करना है, जैसा कि संविधान की प्रस्तावना में दिया गया है। इसी पृष्ठभूमि में हमें अपनी संपूर्ण गतिविधियों को देखना है तथा यदि हम इसके बारे में सचेत रहें, तो संसदीय लोकतंत्र के लिए उचित वातावरण तैयार हो सकता है। लोकतंत्र का अर्थ चर्चा द्वारा शासन करना है। प्रत्येक सदस्य को अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का अधिकार है। इसी तरह उसे स्मरण रखना चाहिए कि दूसरे सदस्य को भी यही अधिकार प्राप्त है। इसलिए वाद-विवादों को उपयोगी, लाभकर तथा प्रभावी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि हम संयम, सद्भावना तथा उदारता से काम करें। इसका परिणाम एक अनुशासित मन होगा, जो असंख्य संसदीय नियमों का पालन करेगा, जितनी ही सदस्यों में सहिष्णुता होगी तथा एक-दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की इच्छा होगी, संसदीय शासन उतना ही सफल हो सकता है।

हमारे संविधान ने हमारी संसद का ढांचा अंग्रेजी नमूने के आधार पर बनाया है। हमारे विधानमंडल ऐतिहासिक कारणों के लिए उसी ढांचे के आधार पर बने हैं। ब्रिटिश लोकसभा की प्रक्रिया, नियम आदि उस संस्था के चिरकाल के अनुभव का परिणाम हैं। जहां तक उन प्रथाओं और परंपराओं का मानव प्रकृति से संबंध है, वे हमारे लिए लाभकर हो सकती हैं, किंतु ऐसी भी परंपराएं तथा प्रथाएं हैं, जिनका संबंध उनके स्वतंत्रता आंदोलन से है...।

हमारे देश में संसदीय जीवन हाल ही में शुरू हुआ है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम स्वस्थ परंपराएं स्थापित करें, उनका आदर तथा पालन करें, क्योंकि वे आने वाली संततियों के लिए पूर्व प्रथा का काम देंगी। देश में स्थिर सरकार बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है।

इंग्लैंड में अध्यक्ष एक निर्दलीय व्यक्ति होता है, किंतु यह परंपरा वर्षों के संघर्ष के पश्चात स्थापित की गई है तथा इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी है। जहां मैं इस आदर्श की स्थापना के लिए प्रयत्नशील रहूंगा, वहीं हमारे देश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति में इंग्लैंड के स्पीकर जैसा निर्दलीय व्यक्ति का अध्यक्ष रहना संभव नहीं है। भारत की लोकसभा का अध्यक्ष इस रूप में पूर्णतः निर्दलीय व्यक्ति रहता है कि वह पार्टी की कार्यवाहियों व झगड़ों से अलग-थलग रहता है, परंतु उसका राजनीतिक जीवन केवल इसी कारण से समाप्त नहीं हो जाता है कि उसे अध्यक्ष चुन लिया गया है।

अध्यक्ष पद के लिए अभी हमें अपनी परंपराएं स्थापित करनी हैं, जिसका सिद्धांत यह है कि अध्यक्ष जब तक अपने पद पर रहना चाहता हो, उसके चुनाव का न उसके निर्वाचन क्षेत्र में विरोध किया जाए और न ही सदन में। इस बात को दृष्टि में रखते हुए मैं उस महान संस्था अखिल भारतीय कांग्रेस से, जिसमें रहकर मैंने गत 40 वर्ष तक किसी न किसी रूप में काम किया है, अलग नहीं रह सकता हूं। मैं अब भी एक कांग्रेस जन हूं, जैसे कि कोई व्यक्ति भारतीय होते हुए भी हिंदू, मुसलमान, पारसी आदि रह सकता है। इसी तरह से यद्यपि मैं एक कांग्रेस जन हूं, मेरा यह कर्तव्य तथा धर्म होगा कि मैं सदन के सभी पक्षों के साथ न्याय तथा समानता के आधार पर व्यवहार करूं। निष्पक्ष रहूं, दलबंदी अथवा राजनीतिक अभिलाषाओं से ऊपर रहूं।

(लोकसभा में दिए गए उद्बोधन से)

सोशल मीडिया के शोर-शराबे में जिगरी दोस्तों का टोटा

यहां स्कैन करें

बीजू डोमिनिक | सीईओ, फाइनल माइल कंसल्टिंग

अमेरिकी सर्जन जनरल विवेक मूर्ति ने हाल ही में सभी सोशल मीडिया मंचों के लिए यह चेतावनी जारी किए जाने का प्रस्ताव रखा है कि 'यह किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है'। मूर्ति द्वारा सिगरेट को लेकर दिया गया इसी तरह का सुझाव कि 'धुम्रपान आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है', इसकी लत से निपटने के प्रयासों की शुरुआत थी। क्या सोशल मीडिया को लेकर उनका सुझाव सुखद अंजाम पा सकेगा?

दरअसल, सोशल मीडिया के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि यह सामाजिक नहीं है। मनुष्यों के सामाजिक संबंधों का पहला गहन अध्ययन ब्रिटिश मानव विज्ञानी रॉबिन डनबर ने किया था। उनका निष्कर्ष था कि एक इंसान की पांच से यारी, 15 से गहरी दोस्ती, 50 से मित्रता, 150 से सार्थक रिश्तेदारी और लगभग 500 से मामूली परिचय हो सकता है। यह अध्ययन सोशल मीडिया के आने से पहले किया गया था। अब जब ऑनलाइन मंचों ने हमारे रिश्ते बदल दिए हैं, तब डनबर ने पाया है कि सोशल मीडिया ने कमजोर संबंधों, मामूली परिचितों और जिनको आप पहचानते हैं, ऐसे लोगों की संख्या तो बढ़ाई है, लेकिन करीबी रिश्तों के लिए यहां जगह सिमट गई है। यह चिंतनीय आंकड़ा है कि आज के करीब 33 फीसदी नौजवान एक जिगरी दोस्त के लिए तरस रहे हैं। इस लिहाज से इसे अब तक के इतिहास की संभवतः सबसे अकेली पीढ़ी कह सकते हैं। मूर्ति ने अपनी रिपोर्ट में इस अकेलेपन को तंबाकू के सेवन जैसी महामारी बताया है। उनके मुताबिक, अकेलापन लोगों के लिए उतना ही बुरा है, जितना एक दिन में 15 सिगरेट पीना।

जैसे-जैसे सोशल मीडिया की लत से निपटने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, वैसे-वैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के दिग्गजों की तरफ से प्रतिरोध की आशंका बढ़ने लगी है। हालांकि, यह विडंबना ही है कि आज सोशल मीडिया विशेषकर युवा पीढ़ी में संदेशों के आदान-प्रदान का सबसे सशक्त माध्यम है, जिसका मतलब है कि इसकी लत के बारे में कोई भी संदेश हमें इसी माध्यम से प्रसारित करना होगा। यानी, किसी व्यक्ति को तभी इस तरह के चेतावनी भरे संदेश मिलें, जब वह सोशल मीडिया में डूबा हो। यह धूम्रपान का आनंद लेते हुए व्यक्ति से इसके खतरों के बारे में बात करने जैसा होगा। बहरहाल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की एल्गोरिद्म लिखने वालों को व्यसन संबंधी व्यवहार की अच्छी समझ होती होगी। चूहों पर किए गए एक अध्ययन से भी इसके संकेत मिले हैं।

स्मार्टफोन स्क्रीन को हम इसीलिए स्क्रॉल करते रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगली बार कुछ अप्रत्याशित दिखेगा। इसी मानसिक व्यवहार को ध्यान में रखकर सोशल मीडिया में सामग्रियां परोसी जाती हैं।

इस अध्ययन में चूहों के दो गुट बनाए गए थे, जिनमें एक गुट को लीवर दबाने पर हर बार मीठा पानी दिया जाता था, जबकि दूसरे को कई बार दबाने के बाद मीठा पानी मिलता था। यह अध्ययन बताता है कि पहले गुट के चूहों ने कुछ समय के बाद लीवर दबाना बंद कर दिया, जबकि दूसरे गुट के चूहों ने अपना काम जारी रखा। ऐसा इसलिए, क्योंकि अनिश्चित पुरस्कार मस्तिष्क को पुरस्कार को लेकर संवेदनशील बनाता है और इनाम पाने के लिए अनवरत कार्य करने को प्रेरित करता रहता है।

सोशल मीडिया पर परोसी जाने वाली सामग्रियां इसी मानसिक व्यवहार पर काम करती हैं। स्मार्टफोन स्क्रीन को हम इसीलिए लगातार स्क्रॉल करते रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगली बार कुछ अप्रत्याशित दिखेगा।

मस्तिष्क विज्ञान के अध्ययनों के अनुसार, किसी व्यसन में रासायनिक व मनोवैज्ञानिक रूप से दो अलग-अलग प्रकार के सुख मिलते हैं। मनोचिकित्सक डोनाल्ड क्लेन इसे 'शिकार का सुख' व 'दावत का सुख' बताते हैं। व्यसन के समय ज्यादातर ध्यान दावत के सुख, यानी किसी नशीले पदार्थ के सेवन के बाद की भावनाओं पर रहता है। शिकार का सुख इच्छा जनित उत्साह, शक्ति की भावना और नशा करने के बाद पैदा आत्मविश्वास पर आधारित होता है। स्मार्टफोन निर्माता व सोशल मीडिया मंच अपने उपयोगकर्ताओं में इसी प्रत्याशा को बढ़ाकर 'शिकार का सुख' बढ़ाते हैं। किसी संदेश के आने पर बजने वाली ध्वनि इस प्रत्याशा को बढ़ाने का काम करती है। बेशक वह संदेश क्रेडिट कार्ड कंपनी से आया हो, लेकिन इंसानी दिमाग अगले संदेश का बेसब्री से इंतजार करने लगता है। यही शिकार का आनंद है।

निस्संदेह, सोशल मीडिया की लत से निपटा जाना चाहिए, मगर करीब से देखने पर यही लगता है कि हम अलग ही तरह के दिमागी खेल से निपट रहे हैं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

प्रेम और वासना का फर्क

प्रेम में एक वस्तु भी जीवंत हो उठती है। पत्थर और वृक्ष तुमसे बातें करते हैं। समस्त सृष्टि सजीव और दिव्य हो जाती है। वासना में एक सजीव प्राणी भी केवल वस्तु बनकर रह जाता है। वासना तनाव लाती है, प्रेम विश्राम लाता है। वासना में कपट और छल है, प्रेम में विनोदिता, लीला है। वासना एक अंग पर केंद्रित होती है, प्रेम पूरे अस्तित्व पर। वासना में तुम झपटना चाहते हो, कब्जा करना चाहते हो; प्रेम में तुम देना चाहते हो, समर्पण करते हो।

वासना में प्रयत्न है, प्रेम प्रयत्नहीन है। वासना हिंसा लाती है, प्रेम बलिदान लाता है। वासना में मांग है, प्रेम में अधिकार है। वासना तुम्हें दुविधा देती है, प्रेम तुम्हें केंद्रित करता है। प्रेम के अनेक रूप और रंग हैं। वासना कहती है, 'जो मैं चाहूं, वही तुम्हें मिले'; प्रेम कहता है, 'जो तुम चाहो, वही तुम्हें मिले।' वासना जकड़ती है, विनाश करती है; प्रेम स्वतंत्रता लाता है, मुक्त करता है। वासना में बाधा होने पर व्यक्ति क्रोधित होता है और नफरत करने लगता है। आज संसार में फैली घृणा प्रेम के कारण नहीं, बल्कि वासना के कारण है।

भोलेपन और प्रेम के प्रतीक शिव एक बार ध्यान में बैठे थे। कामदेव ने फूलों के बाण से उनके ध्यान में खलल डाला। ध्यान से उठने पर शिव ने अपने तीसरे नेत्र को खोला और कामदेव (मन को मथने वाले, मनमथ) को भस्म कर दिया। वासना मन को जकड़ती है, शरीर को थकाती है और बुद्धि को क्षीण करती है। वासना कुछ और नहीं, केवल अनियंत्रित आदी ऊर्जा है। नियंत्रित होने पर यही ऊर्जा उत्साह, चमक, तीव्र बुद्धि और प्रेम के रूप में अभिव्यक्त होती है।

श्री श्री रविशंकर

उदय प्रकाश | हिंदी साहित्यकार

सन् 1968 के फ्रांसीसी छात्र आंदोलन ने जनरल देगाल की सत्ता को डिगा दिया था। 1974 में गुजरात के छात्र आंदोलन ने अंततः जेपी की अगुआई में इंदिरा गांधी को अपदस्थ किया। छात्र शक्ति को कम न आंकें!

अनुलोम-विलोम

अरविंद केजरीवाल

जांच एजेंसियां सिर्फ परेशान कर रहीं

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का यह आरोप सोलह आने सच है कि पूरा सिस्टम यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि उनके पति जेल से बाहर न आएं। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह सब 'तानाशाही' और 'आपातकाल' है। वाकई, दो दिन पहले हम सब 1975 में लगाए गए 21 महीनों के आपातकाल को कोस रहे थे। संसद तक में इसके खिलाफ आवाज बुलंद की गई थी और लोकतंत्र के प्रति गहरी आस्था जताई गई, लेकिन दावे और हकीकत में जमीन-आसमान का फर्क है। 1975 में सब कुछ घोषित था। सभी को पता था कि आपातकाल लगा हुआ है और लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार सीमित कर दिए गए हैं। लोगों को संभलने और सोच-समझकर कदम उठाने का मौका दिया गया था। मगर अब तो ऐसा लगता है कि लोकतंत्र प्रशासनिक नियमों तले दबा हुआ है। जब सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल को जमानत देने का इशारा कर चुकी थी, तब भी रात के अंधेरे में पहले मुख्यमंत्री से सीबीआई ने पूछताछ की और फिर अगले दिन रिमांड की मांग कर डाली। ऐसा इसलिए किया गया, ताकि उनका बाहर आना संभव न हो सके। ऐसा हुआ भी। आखिर क्या चल रहा है यह सब? निचली अदालत ने अरविंद केजरीवाल को इसलिए जमानत दे दी थी कि उनके खिलाफ ठोस सुबूत नहीं हैं। केवल गवाहों के आरोप को बतौर सुबूत पेश किया जाता रहा है। साफ है, इस मामले से जुड़ी जांच एजेंसियां अपने रसूख का फायदा उठा रही हैं, जो भारत जैसे लोकतंत्र में उचित नहीं जान पड़ता। इसका हर हाल में विरोध किया जाना चाहिए और अरविंद केजरीवाल के साथ इंसाफ होना चाहिए।

जंग बहादुर सिंह, टिप्पणीकार

अपराधियों जैसा व्यवहार

एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को किस हद तक परेशान किया जा सकता है, इसकी नजीर हैं केजरीवाल। उनके विरुद्ध ऐसा कोई सुबूत नहीं है कि उनके साथ दुर्दांत अपराधियों जैसा व्यवहार हो। फिर भी, जांच एजेंसियां उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रही हैं, जो बदले की कार्रवाई जान पड़ती हैं। जिस तरह से उन्हें कानूनी छिद्रों का फायदा उठाकर जेल में रखने की साजिश रची गई है, वह लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। उनको जैसे ही निचली अदालत से जमानत मिली, तुरंत ऊपरी अदालत में इसके खिलाफ अर्जी डाल दी गई। इतना ही नहीं, उस पर कोई फैसला आता कि तुरंत एक दूसरी जांच एजेंसी ने अपनी दबिश बढ़ा दी और उनको गिरफ्तार कर लिया। यह सही नहीं है।

सुनीत कुमार, टिप्पणीकार

कानून की निगाह में सभी आरोपी बराबर

दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जैसा कर्म किया है, वह उसी का फल भोग रहे हैं। शराब घोटाले को हल्के में कतई नहीं लिया जा सकता। यह विडंबना ही है कि इस घोटाले के दाग उस मुख्यमंत्री पर लगे हैं, जो खुद को कट्टर ईमानदार होने की बात कहते नहीं थकते थे। यहां तक कि अपने दल के लोगों को भी वह ईमानदार बताते थे और दावा करते थे कि राजनीति बदलने के लिए वह आए हैं, यानी देश में जरूरी वैकल्पिक राजनीति के वही मूलाधार हैं। मगर सत्ता मिलते ही आप संयोजक के रंग ऐसे बदले कि पहले उनके अपने संगी-साथी पीछे छूटते गए और फिर उन पर घोटाले के दाग लग गए। कोई सरकार शराब बिक्री पर ऐसी नीति लाती है, जिससे राजस्व की आनुपातिक रूप से भारी हानि हो और इस विषय पर कई राजनेताओं व व्यापारियों की बातचीत सामने आती हो, तो संदेह होता ही है। यह शक तब और बढ़ जाता है, जब पता चलता है कि मोबाइल फोन नष्ट किए गए हैं। साफ है, यह सब यूं ही नहीं किया गया होगा। कुछ न कुछ बात तो जरूर होगी? आम भाषा में कहें, तो बिना आग के यह धुआं तो नहीं फैला होगा?

कुछ लोग जांच एजेंसियों को कोस रहे हैं, लेकिन ऐसा करते हुए वे भूल जाते हैं कि ये एजेंसियां बिना सुबूत किसी पर हाथ नहीं डालतीं, वह भी उस शख्स पर, जो मुख्यमंत्री पद पर विराजमान हो। जाहिर है, कोई बड़ा सुबूत अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है, जिसे जुटाने में एजेंसियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी होगी। दरअसल, दिल्ली के मुख्यमंत्री कानून से अनजान जान पड़ते हैं। बेशक बौद्धिक रूप से वह काफी समृद्ध हैं, पर जांच एजेंसियां कानून से ही चलती हैं और भारतीय कानून इस तरह बनाए गए हैं कि कोई निर्दोष सजा पा ही नहीं सकता। ईडी, सीबीआई जैसी नामी एजेंसियां स्पष्ट तौर पर बता रही हैं कि उनके पास मुख्यमंत्री के खिलाफ पुख्ता सुबूत हैं, तो फिर हम उनकी बातों पर यकीन क्यों नहीं कर रहे?

यह कानूनी प्रावधान ही था, जिसके तहत मुख्यमंत्री ने चुनाव में जमकर प्रचार किया और यह भी कानूनी प्रावधान ही है, जिसके तहत उनको सीबीआई ने गिरफ्तार किया और रिमांड पर लिया, इसलिए जांच एजेंसियों को कोसने से कोई लाभ नहीं है। कानून अपना काम करेगा ही, क्योंकि उसकी नजर में सभी बराबर हैं। अगर कोई कानूनी छिद्रों से बेजा लाभ उठाने की कोशिश में है, तो उसको मात ही मिलेगी। अरविंद केजरीवाल की हालत देखकर यही कहा जा सकता है कि 'कानून से सबको कुछ न कुछ इसरार चाहिए/ मजलूम को इंसाफ तो मुलजिम को दरार चाहिए।'

दिनेश सिंह, चिकित्सक

दैनिक जागरण

विचार ही व्यवहार को आकार देते हैं

निर्माण कार्यों की गुणवत्ता

चंद दिनों पहले लू से झुलसती दिल्ली अब बारिश के कारण बेहाल है। यह स्थिति इसीलिए बनी, क्योंकि कम समय में कहीं अधिक बरसात हो गई। इसके चलते जगह-जगह जलभराव होने से जनजीवन तो अस्त-व्यस्त हुआ ही, दिल्ली एयरपोर्ट के एक हिस्से की छत गिर जाने से एक व्यक्ति की जान भी चली गई। इस घटना को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। आवश्यकता तो उन कारणों का निवारण करने की है, जिनके चलते जगह-जगह जलभराव के साथ एयरपोर्ट पर हादसा हुआ। अत्यधिक बरसात के कारण जो स्थिति दिल्ली में बनी, वैसी देश-दुनिया के अन्य शहरों में भी रह-रहकर बनती ही रहती है। कुछ समय पहले आधारभूत ढांचे की दृष्टि से कहीं अधिक उन्नत शहर दुबई सामान्य से अधिक बरसात के चलते पानी-पानी हो गया था। पिछले कुछ वर्षों में अपने देश में भी अत्यधिक बरसात के चलते बेहतर आधारभूत ढांचे वाले शहर भी गंभीर समस्याओं से घिरते रहे हैं। अब जब जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम में अप्रत्याशित बदलाव एक यथार्थ है, तब फिर यह समझा जाए कि इस बदलाव जनित समस्याओं पर राजनीतिक तू-तू मैं-मैं से किसी को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मौसम में अप्रत्याशित बदलाव के कारण भीषण गर्मी अथवा ठंड के चलते जो समस्याएं सामने आ रही हैं, उनका सामना आसान नहीं, लेकिन कम से कम ऐसे उपाय तो किए ही जा सकते हैं, जिससे अत्यधिक बरसात जनित समस्याओं से पार पाया जा सके। यह तभी संभव हो सकेगा, जब सरकारें दूरगामी उपायों पर ध्यान केंद्रित करेंगी और आम जनता भी अपने हिस्से की जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए तैयार रहेगी।

जब भी कहीं आवश्यकता से अधिक बरसात हो जाती है तो आधारभूत ढांचे की पोल खुल जाती है। स्थिति यह है कि एक-दो वर्ष पहले किए गए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं। इन सवालों को लेकर राजनीतिक दल एक-दूसरे को ऐसे घेरने लगते हैं, जैसे उनके दल द्वारा शासित राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों की ओर से कराए गए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि की साबित हो रही हो। इस सच से मुंह मोड़ने का कोई मतलब नहीं कि चाहे राज्य सरकार की एजेंसियों की ओर से किए गए निर्माण कार्य हों या फिर केंद्र सरकार की एजेंसियों के, उनकी गुणवत्ता कसौटी पर खरी नहीं उतरती। अपने देश में जैसे नई बनी सड़कें रह-रहकर धंसती रहती हैं, वैसे ही नए बने पुल भी गिरते रहते हैं। देश भर में सड़कों, पुलों, रेल-बस स्टेशनों, हवाई अड्डों आदि का निर्माण तो तेजी से हो रहा है, लेकिन क्या उनके निर्माण मानकों पर खतरे उतर पा रहे हैं? उचित यह होगा कि केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारें भी यह देखें कि उनकी ओर से जिस भी आधारभूत ढांचे का निर्माण कराया जा रहा है, उसकी गुणवत्ता से कोई समझौता तो नहीं हो रहा है?

लेवी पर लगे रोक

नक्सलवाद का दंश झेल रहे झारखंड में दशकों से आतंक के कारण विकास और जनजीवन प्रभावित रहा है। नक्सलियों को पनाह देने में उनके संरक्षकों की भी भूमिका रही है। वहीं इस बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि पूर्व के वर्षों में नक्सलियों से निबटने के हमारे प्रयास में कमियां रहीं। इसके पीछे संसाधनों की कमी से लेकर राजनीतिक संरक्षण और कई अन्य कारक भी जिम्मेदार रहे हैं। लंबे समय से नक्सली सिद्धांत की लड़ाई छोड़कर बंदूक के जोर पर लेवी वसूलने को ही अपना एकमात्र ध्येय मानते हैं। जब वह सिद्धांत की बात करते थे, तब भी इसके लिए चुना गया हिंसा का रास्ता कहीं से भी सही नहीं था। हाल के वर्षों में प्रभावी कार्रवाई कर झारखंड में नक्सलियों की नकेल कसी गई है, लेकिन इसे अनवरत जारी रखने की जरूरत है, ताकि नक्सली फिर से सिर नहीं उठा सकें। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों व कोयला क्षेत्र में ट्रांसपोर्टिंग कर रहे ट्रांसपोर्टर तथा ठेकेदार अक्सर इस कारण जांच एजेंसियों के निशाने पर आते रहे हैं। एनआइए ने गुरुवार को पश्चिम सिंहभूम के मनोहरपुर में एक ईंट भट्ठा कारोबारी के यहां टेरर फंडिंग मामले में छापेमारी की। उसके एक करोड़ के इनामी नक्सली मिसिर बेसरा तक लेवी पहुंचाने में भूमिका निभाने की बात सामने आ रही है। पूर्व में भी रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, लातेहार आदि स्थानों पर ऐसे मामले सामने आए हैं। नक्सलियों के मददगार सफेदपोश लोगों पर भी कड़ी कार्रवाई जरूरी है, क्योंकि वह नक्सलियों के अर्थतंत्र को मजबूत कर देशद्रोह का काम कर रहे हैं।

> नक्सलियों को मदद पहुंचाने वाले लोगों पर भी कड़ी कार्रवाई जरूरी है, ताकि आतंक फैलाने वालों को संरक्षण न मिल सके

भारतीय हितों के समक्ष नया संकट

कैप्टन आर. विक्रम सिंह

म्यांमार की कमजोर होती स्थिति भारत के साथ-साथ बांग्लादेश की मुश्किलें बढ़ाने का काम कर रही है

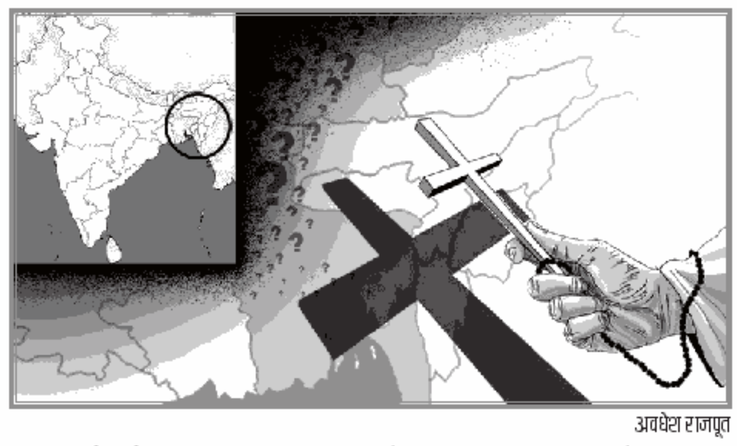

अवधेश राजपूत

संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने विघटनकारी शक्तियों से सावधान रहने की जो आवश्यकता जताई, उसमें भले ही इन शक्तियों की ओर संकेत न किया गया हो, लेकिन ऐसी शक्तियों की ओर गंभीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए। इन दिनों म्यांमार भीषण गृहयुद्ध से जूझ रहा है। बीते दिनों नई दिल्ली में म्यांमार के उपप्रधानमंत्री यू थान श्वे ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर से गंभीर चर्चा की। म्यांमार की सैन्य सरकार ने फरवरी 2021 में निर्वाचित चांसलर आंग सान सू की सरकार को बर्खास्त किया था। सैन्य सरकार के खिलाफ ताजा विद्रोह उसका ही परिणाम जान पड़ता है। सीमावर्ती क्षेत्रों के काचिन, सैगाइन, चिन और रखाइन राज्यों में विद्रोहियों से सेना लगातार पराजित हो रही है। पूर्वोत्तर भारत से व्यापार का नया व्यावसायिक समुद्री एवं सड़क मार्ग भी विद्रोहियों की गतिविधियों से प्रभावित हो रहा है। भारत को म्यांमार में सितवे का काउंसलेट बंद करना पड़ा है। राजनयिक वापस बुला लिए गए हैं। वहां के शरणार्थी जिनमें सरकारी सैनिक भी हैं, भाग कर मिजोरम आ रहे हैं।

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी बीते दिनों भारत यात्रा पर थीं। उन्होंने कुछ दिन पूर्व एक बड़ा बयान दिया था कि एक बड़ी शक्ति म्यांमार एवं बांग्लादेश के हिस्सों को लेकर एक ईसाई राज्य स्थापित करने की योजना बना रही है। उन्होंने यह भी कहा था कि उन पर सेंट मार्टिन द्वीप लीज पर देने का दबाव है। पश्चिमी देश के एक प्रतिनिधि ने उनसे कहा था कि यदि वह सहयोग करेंगी तो उनके चुनावों पर कोई आपत्ति नहीं होगी, अन्यथा उनके लिए बहुत सी समस्याएं खड़ी होंगी। ध्यान रहे कि बांग्लादेश के सेंट मार्टिन आइलैंड को लीज पर लेने के लिए अमेरिकी दबाव की बातें खूब सामने आई हैं। शेख हसीना ने किसी सभा में कहा भी था कि वह देश को किराये पर देने नहीं आई हैं। सेंट मार्टिन द्वीप बांग्लादेश एवं म्यांमार की सीमाओं के निकट बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यहां से बड़े इलाके की निगरानी की जा सकती है। शेख हसीना का बयान यही संकेत करता है कि इस क्षेत्र में एक ईसाई देश बनाने का प्रयास हो रहा है। यह प्रयास 1941-47 में भी ब्रिटिश क्राउन कालोनी संरक्षित राज्य के रूप में किया गया था, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों एवं अंग्रेजों के भारत से जल्द भागने के फेर में वह परियोजना सिरे नहीं चढ़ सकी।

म्यांमार के संकट में चीन द्वारा विद्रोहियों को अस्त्र-शस्त्र दिए जाने की सूचना है। यदि अमेरिका असल में भारत का रणनीतिक भागीदार है तो म्यांमार संकट के समाधान में उसे भारतीय हित का पक्षधर होना चाहिए, पर ऐसा नहीं दिख रहा है। यदि म्यांमार चीन के पाले में चला गया तो म्यांमार के बंदरगाहों से हिंद महासागर में चीन के प्रवेश के आसार बन जाएंगे और वह मलक्का स्ट्रेट की बाधा का विकल्प तलाश लेगा। साथ ही अपने पूंजी निवेश व दोहन के लिए पाकिस्तान के समान उसे म्यांमार जैसा देश भी मिल जाएगा।

तीन भारतीय राज्य नगालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम की सीमा म्यांमार से लगती हैं। म्यांमार का एक राज्य काचिन है, जो चीन की सीमा के दक्षिण में है। यह म्यांमार का उत्तरी राज्य है। एक सैगाइन राज्य है और उसके बाद चिन राज्य आता है। इनकी जनसांख्यिकी को देखें तो चिन राज्य मिजोरम एवं मणिपुर से मिलता है। वहां ईसाई आबादी 85 प्रतिशत है। काचिन राज्य की सीमा अरुणाचल और नगालैंड से मिलती है। वहां ईसाई आबादी तेजी से बढ़कर 80 प्रतिशत पहुंच रही है। हमारे यहां मणिपुर के मैतेयी एवं कुकियों के बीच विवाद का मूल यही चिन राज्य क्षेत्र है। कुकी चिन जाति की ही एक शाखा है। सीमावर्ती राज्यों नगालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम में ईसाई आबादी क्रमशः 80, 45 और 87 प्रतिशत हैं। इसी कारण अब इस क्षेत्र में म्यांमार की कमजोर डांवाडोल राजनीतिक स्थिति का लाभ उठाकर एक ईसाई देश स्थापित होने के आसार बनने लगे हैं। म्यांमार में 85 प्रतिशत ईसाई आबादी का चिन राज्य तो पहले से उपलब्ध है ही। उसे समुद्र तक पहुंच के लिए रखाइन राज्य और बांग्लादेश के चटगांव प्रायद्वीप की भूमि की भी आवश्यकता पड़ेगी। यहीं भारत का महत्वाकांक्षी सितवे कलादान प्रोजेक्ट भी पूर्ण होने के निकट है। यहां के एक बड़े शहर पलेटवा पर पिछले माह विद्रोही बलों का कब्जा हो चुका है। यहां भारत के हितों के विरुद्ध स्थितियां आकार ले रही हैं। जो लोग इस क्षेत्र में एक ईसाई राज्य के रणनीतिकार हैं, उनकी जानकारी में ब्रिटिश योजना निश्चय ही है। कमजोर होता म्यांमार गृहयुद्ध की स्थिति में अपनी मुख्यभूमि को सुरक्षित करने में ही अपने संसाधन लगाएगा। हमारी सीमा से जुड़े म्यांमार के ईसाई क्षेत्रों पर उनकी सत्ता का कमजोर होना हमारे लिए एक बहुत बड़ा संकट खड़ा कर रहा है। चिंता का सबसे बड़ा कारण यह है कि इस बिंदु पर आकर पश्चिमी लाबी और ईसाई मिशनरियों के हित तो सध रहे हैं, लेकिन इसकी तपिश हमें झेलनी पड़ेगी। मणिपुर में हिंदू-ईसाई विभेद पहले ही बढ़ा हुआ है।

भारत विभाजन के दौर का यह तथ्य ध्यान रहे कि भारत को दो नहीं, बल्कि तीन भागों में विभाजित करने की योजना थी। मिशनरियों की मांग पर पूर्वोत्तर एवं म्यांमार के ईसाई राज्यों को मिलाकर 'क्राउन कालोनी संरक्षित राज्य' बनाने की योजना असम के तत्कालीन गवर्नर रार्बट रीड एंड्रू ग्लो ने प्रस्तुत की थी। हालांकि कांग्रेस नेता गोपीनाथ बोरदोलोई के विरोध के कारण असम को पूर्वी बंगाल के समूह से अलग करना पड़ा। अंग्रेजों को कैबिनेट मिशन की तीसरी सूची संशोधित करनी पड़ी थी। यदि असम पूर्वी बंगाल के साथ पूर्वी पाकिस्तान के समूह में चला जाता तब पूर्वोत्तर में एक ईसाई राज्य की भूमिका बन जाती। अब 75 वर्ष बाद पुनः उसकी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं।

जार्ज सोरेस एवं भारत विरोधी शक्तियों की मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करने की योजना सफल हो जाती तो म्यांमार के विखंडन एवं बांग्लादेश में विद्रोही शक्तियों को उभार कर ऐसी स्थितियां बना दी जातीं, जिसमें 75 वर्ष पहले का ईसाई राज्य बनाने का ब्रिटिश साम्राज्यवादी एजेंडा अंततः सफल हो सकता था। अच्छी बात है कि उनकी इस साजिश पर पानी फिर गया, मगर भारत को कहीं अधिक सावधान रहने की जरूरत है।

(लेखक पूर्व सैन्य एवं प्रशासनिक अधिकारी हैं)

response@jagran.com

महामारी जैसा बनता अकेलापन

क्षमा शर्मा

आज की तकनीक भले हमें आकर्षित करती हो, लेकिन यह मानवीय संबंधों का रूप कभी नहीं ले सकती

युवा भी बनने लगे अकेलेपन का शिकार। फाइल

काफी समय से यह माना जाता रहा है कि बुजुर्गों में अकेलापन बढ़ गया है। इसका कारण संयुक्त परिवार का न होना, बच्चों का विदेश या बाहर के शहरों में बस जाना, रिटायरमेंट, जीवनसाथी का न रहना और दोस्तों से संपर्क टूटना आदि हैं, मगर अब नए शोध के अनुसार अकेलापन युवाओं को भी बहुत परेशान कर रहा है। यह असमय ही उन्हें मृत्यु की ओर धकेल रहा है। इसका एक कारण हमउम्र लोगों से कम संपर्क और परिवार से दूरी है। नौकरियां भी अब ऐसी हो चली हैं, जहां युवा 24 घंटे के नौकर हैं। उन्हें हर हाल में टारगेट पूरे करने होते हैं। भले ही इसके लिए कितने ही घंटे काम क्यों न करना पड़े। इस अतिरिक्त व्यस्तता के कारण वे अपने आसपास और दोस्तों से कट रहे हैं। आपको अमेरिका में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ गुप्ता का केस तो याद ही होगा। यह युवा बहुत तेजस्वी और मेधावी था। अमेरिका के एक बड़े संस्थान में काम करता था। वह दफ्तर में 16-18 घंटे काम करता था, फिर भी अधिकारी कहते थे कि और करो। न उसके पास घर जाने का समय था और न ही सोने का। तब परिवार और दोस्तों के लिए समय कहां से आता। एक दिन इस युवा ने जिंदगी से हार मान ली। जिनके लिए 16-18 घंटे काम किया, उन्हें क्या फर्क पड़ा। उसकी जगह कोई और आ गया।

विशेषज्ञ कहते हैं कि अपनों से कट जाने का मतलब एक तरह की असामयिक मृत्यु है। अकेलापन धूमपान करने से भी अधिक खतरनाक है। कुछ दिन पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बढ़ते अकेलेपन पर चिंता प्रकट की। उसके अनुसार अकेलापन दुनिया में महामारी की तरह फैल रहा है। डाक्टरों का कहना है कि अकेलेपन के कारण लोगों को नींद नहीं आती। उन्हें तरह-तरह की समस्याएं होती हैं। अवसाद बढ़ता है। प्रतिरोधक प्रणाली कमजोर हो जाती है। मानसिक स्वास्थ्य कमजोर हो जाता है। दिल की बीमारियों के खतरे बढ़ जाते हैं और तरह-तरह के रोग घेर लेते हैं।

अकेलापन किसी गंभीर बीमारी जैसा ही खतरनाक है। अकेलापन हमारी भावनाओं पर आघात करता है। यह हमें हमेशा दुखी रखता है। दुखी होने से चिंता और तनाव बढ़ता है। यह जीवन की कठिनाइयों को बढ़ाता है। रही-सही कसर इंटरनेट मीडिया ने पूरी कर दी है। युवाओं का दफ्तर के कामकाज से जो समय बचता है, उसे वे इंटरनेट मीडिया पर खर्च करते हैं। इंटरनेट मीडिया भी तरह-तरह की प्रतिस्पर्धा से भरा है। किसको कितनी रीच एवं लाइक्स मिले, यह एक चिंता का विषय बन जाता है।

अकेलेपन के जो कारण बताए जाते हैं, उनमें बेरोजगारी और कम आय भी महत्वपूर्ण है। जो लोग नौकरी या अन्य किसी कारण अकेले रहते हैं, उनका अकेलापन भी बढ़ता है। गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोग भी अकेलेपन का शिकार होते हैं। बहुत से सामाजिक दबाव भी इसे बढ़ाते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अकेलेपन की समस्या से समय रहते निपटा जाना चाहिए। इसके लिए ऐसी आदतें डाली जानी चाहिए, जो किसी को अकेला न रहने दें। अकेलेपन को दूर करने के लिए लोगों से मिलें-जुलें, दोस्ती बढ़ाएं। एक-दूसरे के सुख-दुख का हिस्सा बनें। सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने से भी जीवन सार्थक लगता है। इसलिए इनसे भी जुड़ना चाहिए। दोस्तों या परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बाजार जाएं। दूसरों के अनुभवों से सीखें। यदि समय हो तो किसी अभिरुचि को पूरा कर सकते हैं। बहुत से शौक अपनाए जा सकते हैं। बागवानी, पेंटिंग और संगीत भी अकेलेपन को दूर करने में बहुत मदद करते हैं। संगीत सुनना और संगीत सीखना, दोनों उपयोगी हैं। योग और व्यायाम से न केवल अकेलेपन को दूर किया जा सकता है, बल्कि स्वास्थ्य को भी अच्छा रखा जा सकता है।

इन दिनों कहा जाता है कि युवाओं में पढ़ने की आदत कम होती जा रही है, जबकि कोई अच्छी किताब हमारी सबसे अच्छी साथी होती है। मनपसंद किताबें कभी अकेला नहीं रहने देतीं। प्रकृति के साथ रहना भी हमारे अवसाद को कम करता है और हमें बहुत सी चिंताओं से मुक्ति दिलाता है। सबसे प्रमुख तो हमारा परिवार ही है। यदि परिवार के साथ रहते हैं तो स्वजनों के साथ समय बिताना एक अच्छा विकल्प है। दूर रहते हैं, तो मोबाइल ने यह सुविधा प्रदान की है कि हम कभी भी परिवार के सदस्यों से बात कर सकते हैं। आज की तकनीक भले ही हमें बहुत आकर्षित करती हो, लेकिन यह मानवीय संबंधों का रूप कभी नहीं ले सकती। वह पश्चिम जो तमाम तकनीकी उपकरणों और सुविधाओं से भरा पड़ा है, वहां न केवल युवा, बल्कि अधिकांश आबादी अकेलेपन की पीड़ा झेलने को मजबूर है। लंबे अर्से तक वहां अकेलेपन को आत्मनिर्भरता और ताकत के रूप में पेश किया गया। आज पश्चिम के लोग परिवार-परिवार चिल्ला रहे हैं। यह अफसोस की बात है कि भारत में अकेलेपन को किसी वरदान की तरह समझा जा रहा है। अकेलेपन की विशेषता के रूप में यह बताया जाता है कि हम जो चाहें, वह सब कर सकते हैं। पहले संयुक्त परिवार को तोड़कर एकल परिवार बने। अब बहुत से युवा जिनमें लड़के-लड़कियां दोनों शामिल हैं, परिवार नाम की संस्था से ही दूर भागते हैं। उन्हें लगता है कि अकेले हैं तो आजाद हैं। परिवार है तो जिम्मेदारियों का बोझ है और आजादी खतरे में है। थोड़े दिनों तक तो यह सोच बहुत अच्छा लग सकता है, मगर एक वक्त के बाद यह लगने लगता है कि हमारा कोई नहीं। जब तक यह बात समझ आती है कि शेयरिंग और केयरिंग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तब तक कई बार देर हो चुकी होती है।

(लेखिका साहित्यकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

सुख और दुख

सुख-दुख जीवन की अभिन्न अनुभूति हैं, जो व्यक्ति, वस्तु एवं समय के सापेक्ष होती हैं। कोई किसी घटना से सुखी होता है तो दूसरा उससे दुखी। वस्तुतः सुख या दुख की निरंतरता नहीं रहती। यह प्रतिपल बदलती है। हम कष्टों से पलायन कर स्वयं अपने सुखों से दूर होते चले जाते हैं। सुख व्यक्ति के अहंकार की परीक्षा लेता है जबकि दुख व्यक्ति के धैर्य की। इसलिए सदैव स्मरण रहे कि सुख में कभी अहंकार न घर करने पाए और दुख में जीवन से कभी मोहभंग न हो। सुख और दुख रूपी जीवन की दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण व्यक्ति का जीवन ही एक सार्थक जीवन है।

महात्मा गांधी ने कहा है, 'खुशी तब मिलती है जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं, जो करते हैं, उनमें समानता हो।' सुख हवा का वह झोंका है जिसके गुजर जाने का अहसास तक नहीं होता है। सुख में समय कब निकल गया, उसका आभास तक नहीं होता है। जबकि दुख में समय रुका, ठहरा सा लगता है। सुख का रंग-रूप व्यक्तिगत होता है और वह जहां भी मिलता है आनंद प्रदान करता प्रतीत होता है, जबकि दुख इसका विपरीत। दुख को शिक्षक समझें। उससे सीख लें। जीवन में जितना कष्ट आएगा, उतना ही आप कष्टों को सहते-सहते धैर्यवान होते जाएंगे। धैर्य की शक्ति से हम कितनी भी विकट परिस्थिति का सामना कर उससे उबरने में सक्षम हो जाते हैं। धैर्य एक ऐसा गुण है, जो व्यक्ति की कार्यक्षमता में वृद्धि करता है। उसे आगे ले जाता है।

तनाव एवं समस्याएं ही हमारे मन को जागृत रखते हैं। जीवन में विविध समस्याओं के समाधान खोजते समय ही हमारा वास्तविक क्षमताओं से परिचय होता है। इसी प्रक्रिया में ही हमारा व्यक्तित्व निखरता है। जैसे सोने में खोट मिलाए बिना आभूषण नहीं बनते, उसी प्रकार समस्याओं को सुलझाने की अग्निपरीक्षा के बिना हमारे व्यक्तित्व का आभूषण नहीं आकार ले पाता।

नृपेंद्र अभिषेक नृप

समाचार पत्र पढ़ने की अच्छी पहल

रेणु जैन

> नियमित रूप से अखबार पढ़ने वाले छात्रों का अन्य गतिविधियों में भी प्रदर्शन तुलनात्मक रूप से बेहतर देखा गया है

समाचार पत्र पढ़ना अच्छी आदतों में शामिल है। यह आदत इतनी सुलभ और सस्ती होती है कि कोई भी इसे आसानी से अपना सकता है। समाचार पत्र की यह खासियत है कि इसमें हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ जरूर होता है और आप जिस दिन से इसे पढ़ना शुरू कर देते हैं, उसी दिन से लाभ दिखने लगता है। परंतु दुखद यह है कि इस डिजिटल युग में खासकर बच्चों को पढ़ने की आदत कम हो गई है। इसी को देखते हुए केरल की स्टेट काउंसिंग आफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ने एक बेहतर पहल के तहत प्रदेश के सभी स्कूलों की हर क्लास में बच्चों को मुफ्त में समाचार पत्र उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इस पाठ्यक्रम में क्लास शुरू होने के पहले बच्चों को समाचार पत्र पढ़ना होगा। सप्ताह में एक बार छह दिन पढ़ी खबरों पर प्रतियोगिताएं होंगी। ड्राइंग, पेंटिंग, चित्र देखकर खबर लिखना, खबर पढ़कर चित्र बनाना, एक छोटा सा समाचार पत्र तैयार करना जैसी मजेदार गतिविधियों के साथ बच्चों को समाचार पत्र पढ़ने के प्रति जागृत करना इस पहल का उद्देश्य है।

रोजाना समाचार पत्र पढ़ने से बच्चों में पढ़ने की आदत भी विकसित होती है। आजकल लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में समसामयिक प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं और इन्हीं घटनाओं से अवगत रहने का सबसे विश्वसनीय स्रोत अखबार होते हैं।

स्काटलैंड में हुए एक शोध के मुताबिक जो नियमित रूप से समाचार पत्र पढ़ते हैं उनका स्वास्थ्य समाचार पत्र नहीं पढ़ने वालों की तुलना में 20 प्रतिशत बेहतर पाया गया। इसी शोध में यह बात सामने आई कि नियमित रूप से समाचार पत्र पढ़ने से तनाव के हार्मोंस का स्तर कम रहता है। नियमित अखबार पढ़ने से बच्चों का मस्तिष्क सक्रिय रहता है।

स्थानीय, देश-दुनिया, खेल, वित्त, जुर्म, पर्यटन, राजनीति आदि विविध क्षेत्रों की जानकारी का बड़ा स्रोत अखबार है। प्रत्येक अखबार में संपादकीय पृष्ठ पर विशेषज्ञ की राय होती है जो हर विषय के विभिन्न पहलू को उजागर करते हैं। बचपन में अखबार पढ़ने की आदत बच्चों के भाषा ज्ञान में भी बढ़ोतरी करता है। साथ ही समाचार पत्र पढ़ने वाले किसी भी विषय पर अपनी बात अधिक मजबूती से रख पाते हैं। अमेरिकी शिक्षाविदों और मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध के अनुसार समाचार पत्र नियमित पढ़ने वाले चाहे बच्चे, चाहे युवा कोई भी उम्र के हो इन लोगों के मित्र भी अधिक और अलग अलग क्षेत्रों से होते हैं, क्योंकि वे राजनीति, अर्थशास्त्र, सामान्य ज्ञान, खेल, फिल्म और धर्म के बारे में एक जीवंत संवाद स्थापित करते हैं। कहा भी गया है कि एक बात हमेशा याद रखी जानी चाहिए कि देखा हुआ या बोला हुआ तो इत्र की खुशबू की तरह थोड़ी देर में उड़ जाता है, लेकिन लिखा हुआ सदियों का दस्तावेज है। (लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

चीन को जवाब देना आवश्यक

'तिब्बत की आवाज बने भारत' शीर्षक से लिखे आलेख में शंकर शरण ने कूटनीतिक मोर्चे पर अतीत में कई गलतियों और उनके दुष्परिणामों को रेखांकित किया है। उन गलतियों का खामियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। समय आ गया कि अब हम चीन के साथ आक्रमक कूटनीति का परिचय दें। जैसा इस समय अमेरिका कर रहा है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का बीते दिनों धर्मशाला में दलाई लामा से मुलाकात इसी आक्रामक कूटनीति का हिस्सा है। यह बेहद सुखद है कि मौजूदा केंद्र सरकार ने अमेरिकी सांसदों के दल को दलाई लामा से मिलने की ही अनुमति नहीं दी, बल्कि इस दल से प्रधानमंत्री मोदी ने मिलकर चीन को जो संदेश दिया है उसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। इसके पहले चीन के साथ हमारे कूटनीतिक संबंध चार कदम आगे चलकर दो कदम पीछे हटने जैसे थे, जबकि चीन का नजरिया इस मामले में सदैव यथार्थवादी रहा। नतीजा यह हुआ कि जो तिब्बत 1951 तक स्वतंत्र देश था, आज उस पर चीन पूरी तरह अवैध कब्जा कर चुका है। इस तरह हमारी सीमा उससे प्रत्यक्ष रूप से जुड़ चुकी है। पिछली सदी के आठवें दशक तक अमेरिका के साथ चीन के रिश्ते सहज नहीं थे। बाद में ये रिश्ते इतने प्रगाढ़ हुए कि अमेरिकी पूंजी निवेश के बूते वह आर्थिक महाशक्ति बनकर आज अमेरिका को ही आंखें दिखाने की स्थिति में आ गया है। ऐसे में चीन की चुनौती का जवाब तलाशना आवश्यक हो गया है। साथ ही सतर्कता के साथ चीन पर नजर रखनी होगी।

मुकेश कुमार मनन, पटना

मेलबाक्स

विपक्ष का हंगामा गलत

नरेन्द्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पहले स्वतंत्रता के पश्चात लगातार तीन बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर जवाहरलाल नेहरू को ही मिला है। लोकसभा का गठन होने के बाद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने जो कुछ भी कहा, उससे मोदी सरकार के एजेंडे की झलक मिली, लेकिन विपक्ष द्वारा किया गया हंगामा ठीक नहीं है। जहां तक विपक्ष का सवाल है, 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में कानूनी रूप से किसी को विपक्ष का दर्जा भी हासिल नहीं हुआ। विपक्ष को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि संसद में देशहित के मसलों पर ही चर्चा होनी चाहिए।

मीना धानिया, सिरसपुर दिल्ली

तिब्बत नीति पर आक्रामक हो भारत

पिछले दिनों प्रकाशित लेख 'तिब्बत की आवाज बने भारत' और 'भारत भी बदले अपनी तिब्बत नीति' अमेरिकी संसद द्वारा तिब्बत-चीन विवाद को सुलझाने के लिए प्रोत्साहन संबंधी कानून (2024) के प्रभाव से तिब्बत की स्वतंत्रता के परिप्रेक्ष्य में चीन को ललकार है। यह न केवल अमेरिका, बल्कि यूरोप, भारत और उन सभी देशों को प्रभावित करेगा, जिनके भूभाग को चीन ने कब्जाया हुआ है। चीन ने तिब्बत पर अपने नियंत्रण की शुरुआत सितंबर 1949 में की, जब उसने पूर्वी तिब्बत के राज्यपाल के मुख्यालय पर अधिकार कर लिया। तिब्बत को बाहरी दुनिया से पूरी तरह काट दिया गया, लेकिन तिब्बतियों ने नवंबर 1950 में चीन के इस आक्रमण के विरोध में संयुक्त राष्ट्र में अर्जी लगाई। संयुक्त राष्ट्र महासभा की संचालन समिति ने इस मुद्दे को टाल दिया। चीन ने तिब्बत को अपना एक उपनिवेश बनाने की योजना को लागू करने के लिए तिब्बत से हुए किसी भी समझौते को नहीं माना और नौ सितंबर, 1951 को हजारों चीनी सैनिकों ने ल्हासा में मार्च किया। तिब्बत पर अधिग्रहण के बाद यहां के बौद्ध मठों का विनाश किया गया, लोगों की राजनीतिक स्वतंत्रता छीन ली गई, बड़े पैमाने पर लोगों को गिरफ्तार किया गया तथा निर्दोषों का नरसंहार किया गया। चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा भारत के लिए भी हानिकारक सिद्ध हुआ है। वर्ष 1962 में चीन ने हमारे एक बड़े भूभाग पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया। लिहाजा तिब्बत के लिए स्वतंत्रता की बात भारत को पहले करनी चाहिए थी। इससे चीन को वैश्विक स्तर पर तिब्बत के मुद्दे पर विरोध का सामना करना पड़ेगा।

विनोद जौहरी, दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए; नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

निर्माण कार्यों की गुणवत्ता

चंद दिनों पहले लू से झुलसती दिल्ली अब बारिश के कारण बेहाल है। यह स्थिति इसीलिए बनी, क्योंकि कम समय में कहीं अधिक बरसात हो गई। इसके चलते जगह-जगह जलभराव होने से जनजीवन तो अस्त-व्यस्त हुआ ही, दिल्ली एयरपोर्ट के एक हिस्से की छत गिर जाने से एक व्यक्ति की जान भी चली गई। इस घटना को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। आवश्यकता तो उन कारणों का निवारण करने की है, जिनके चलते जगह-जगह जलभराव के साथ एयरपोर्ट पर हादसा हुआ। अत्यधिक बरसात के कारण जो स्थिति दिल्ली में बनी, वैसी देश-दुनिया के अन्य शहरों में भी रह-रहकर बनती ही रहती है। कुछ समय पहले आधारभूत ढांचे की दृष्टि से कहीं अधिक उन्नत शहर दुबई सामान्य से अधिक बरसात के चलते पानी-पानी हो गया था। पिछले कुछ वर्षों में अपने देश में भी अत्यधिक बरसात के चलते बेहतर आधारभूत ढांचे वाले शहर भी गंभीर समस्याओं से घिरते रहे हैं। अब जब जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम में अप्रत्याशित बदलाव एक यथार्थ है, तब फिर यह समझा जाए कि इस बदलाव जनित समस्याओं पर राजनीतिक तू-तू मैं-मैं से किसी को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मौसम में अप्रत्याशित बदलाव के कारण भीषण गर्मी अथवा ठंड के चलते जो समस्याएं सामने आ रही हैं, उनका सामना आसान नहीं, लेकिन कम से कम ऐसे उपाय तो किए ही जा सकते हैं, जिससे अत्यधिक बरसात जनित समस्याओं से पार पाया जा सके। यह तभी संभव हो सकेगा, जब सरकारें दूरगामी उपायों पर ध्यान केंद्रित करेंगी और आम जनता भी अपने हिस्से की जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए तैयार रहेगी। जब भी कहीं आवश्यकता से अधिक बरसात हो जाती है तो आधारभूत ढांचे की पोल खुल जाती है। स्थिति यह है कि एक-दो वर्ष पहले किए गए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं। इन सवालों को लेकर राजनीतिक दल एक-दूसरे को ऐसे घेरने लगते हैं, जैसे उनके दल द्वारा शासित राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों की ओर से कराए गए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि की साबित हो रही हो। इस सच से मुंह मोड़ने का कोई मतलब नहीं कि चाहे राज्य सरकार की एजेंसियों की ओर से किए गए निर्माण कार्य हों या फिर केंद्र सरकार की एजेंसियों के, उनकी गुणवत्ता कसौटी पर खरी नहीं उतरती। अपने देश में जैसे नई बनी सड़कें रह-रहकर धंसती रहती हैं, वैसे ही नए बने पुल भी गिरते रहते हैं। देश भर में सड़कों, पुलों, रेल-बस स्टेशनों, हवाई अड्डों आदि का निर्माण तो तेजी से हो रहा है, लेकिन क्या उनके निर्माण मानकों पर खतरे उतर पा रहे हैं? उचित यह होगा कि केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारें भी यह देखें कि उनकी ओर से जिस भी आधारभूत ढांचे का निर्माण कराया जा रहा है, उसकी गुणवत्ता से कोई समझौता तो नहीं हो रहा है?

लापरवाही से जा रही जान

राज्य में मानसून सक्रिय है। धरती सूखी है। मगर, ठनका से प्रतिदिन अकाल मृत्यु की खबरें आ रही हैं। हाल के वर्षों में ठनका की चपेट में आकर होने वाली मौतों की संख्या बढ़ रही है। इस मौसम में शायद ही ऐसा कोई दिन गुजरता से जब ठनका से मौत की खबर नहीं है। राज्य सरकार का आपदा प्रबंधन विभाग ठनका की चेतावनी देता है। साफ-साफ बता देता है कि अमुक जिले में इस समय वर्षा होगी और ठनका गिरने की भी संभावना है। विभाग चेतावनी भी देता है कि लोग ठनका से बचने का उपाय करें। वर्षा के समय घर से बाहर नहीं निकलें। पेड़, ऊंची इमारत और बिजली खंभे के नीचे खड़े न हों। खुले में न जाएं। सुरक्षित और छतदार मकान के नीचे रहें। मोबाइल फोन का उपयोग न करें। लेकिन, चेतावनी से कोई डरता है, ऐसा नहीं लगता है। ठनका से होने वाली अधिसंख्य मौतें पेड़ के नीचे खड़े होने या खुले में ठनका गिरने से होती है। लोग मरते हैं और भगवान को दोष देकर रोने बैठ जाते हैं। गनीमत यह है कि अबतक किसी ने मौतों के लिए सरकार को जिम्मवार नहीं ठहराया है। सरकार अपने स्तर से पीड़ित परिवार की मदद भी करती है। मृतक के स्वजन को चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता देती है। ठनका को लेकर जारी होने वाली चेतावनी पर लोग अमल करें तो मौत की घटनाएं कम हो सकती हैं। क्योंकि ये मौतें उन्हीं जगहों पर होती हैं, जहां वर्षा के दौरान न जाने की चेतावनी दी जाती है। असल में किसी जरूरी चेतावनी की अनदेखी हमारी आदत में शामिल हो गई है। ट्रैफिक पुलिस मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट पहनने की सलाह देती है। लोगों को लगता है कि पुलिस अपना सिर बचाने के लिए सलाह देती है। नतीजा वही ठनका वाला निकलता है।

ठनका को लेकर जारी होने वाली चेतावनी पर लोग अमल करें तो मौत की घटनाएं कम हो सकती हैं।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या लोकसभा में आपातकाल पर लाए गए प्रस्ताव पर कांग्रेस की आपत्ति जायज है?

आज का सवाल
क्या दक्षिण अफ्रीका के मुकाबले भारतीय क्रिकेट टीम अधिक मजबूत है?

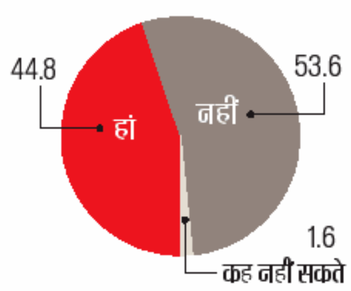

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

भारतीय हितों के समक्ष नया संकट

कैप्टन आर. विक्रम सिंह

म्यांमार की कमजोर होती स्थिति भारत के साथ-साथ बांग्लादेश की मुश्किलें बढ़ाने का काम कर रही है

संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने विघटनकारी शक्तियों से सावधान रहने की जो आवश्यकता जताई, उसमें भले ही इन शक्तियों की ओर संकेत न किया गया हो, लेकिन ऐसी शक्तियों की ओर गंभीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए। इन दिनों म्यांमार भीषण गृहयुद्ध से जूझ रहा है। बीते दिनों नई दिल्ली में म्यांमार के उपप्रधानमंत्री यू थान श्वे ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर से गंभीर चर्चा की। म्यांमार की सैन्य सरकार ने फरवरी 2021 में निर्वाचित चांसलर आंग सान सू की सरकार को बर्खास्त किया था। सैन्य सरकार के खिलाफ ताजा विद्रोह उसका ही परिणाम जान पड़ता है। सीमावर्ती क्षेत्रों के काचिन, सैगाइन, चिन और रखाइन राज्यों में विद्रोहियों से सेना लगातार पराजित हो रही है। पूर्वोत्तर भारत से व्यापार का नया व्यावसायिक समुद्री एवं सड़क मार्ग भी विद्रोहियों की गतिविधियों से प्रभावित हो रहा है। भारत को म्यांमार में सितवे का काउंसलेट बंद करना पड़ा है। राजनयिक वापस बुला लिए गए हैं। वहां के शरणार्थी जिनमें सरकारी सैनिक भी हैं, भाग कर मिजोरम आ रहे हैं।

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी बीते दिनों भारत यात्रा पर थीं। उन्होंने कुछ दिन पूर्व एक बड़ा बयान दिया था कि एक बड़ी शक्ति म्यांमार एवं बांग्लादेश के हिस्सों को लेकर एक ईसाई राज्य स्थापित करने की योजना बना रही है। उन्होंने यह भी कहा था कि उन पर सेंट मार्टिन द्वीप लीज पर देने का दबाव है। पश्चिमी देश के एक प्रतिनिधि ने उनसे कहा था कि यदि वह सहयोग करेंगी तो उनके चुनावों पर कोई आपत्ति नहीं होगी, अन्यथा उनके लिए बहुत सी समस्याएं खड़ी होंगी। ध्यान रहे कि बांग्लादेश के सेंट मार्टिन आइलैंड को लीज पर लेने के लिए अमेरिकी दबाव की बातें खूब सामने आई हैं। शेख हसीना ने किसी सभा में कहा भी था कि वह देश को किराये पर देने नहीं आई हैं। सेंट मार्टिन द्वीप बांग्लादेश एवं म्यांमार की सीमाओं के निकट बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यहां से बड़े इलाके की निगरानी की जा सकती है। शेख हसीना का बयान यही संकेत करता है कि इस क्षेत्र में एक ईसाई देश बनाने का प्रयास हो रहा है। यह प्रयास 1941-47 में भी ब्रिटिश क्राउन कालोनी संरक्षित राज्य के रूप में किया गया था, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों एवं अंग्रेजों के भारत से जल्द भागने के फेर में वह परियोजना सिरे नहीं चढ़ सकी।

म्यांमार के संकट में चीन द्वारा विद्रोहियों को अस्त्र-शस्त्र दिए जाने की सूचना है। यदि अमेरिका असल में भारत का रणनीतिक भागीदार है तो म्यांमार संकट के समाधान में उसे भारतीय हित का पक्षधर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा है। यदि म्यांमार चीन के पाले में चला गया तो म्यांमार के बंदरगाहों से हिंद महासागर

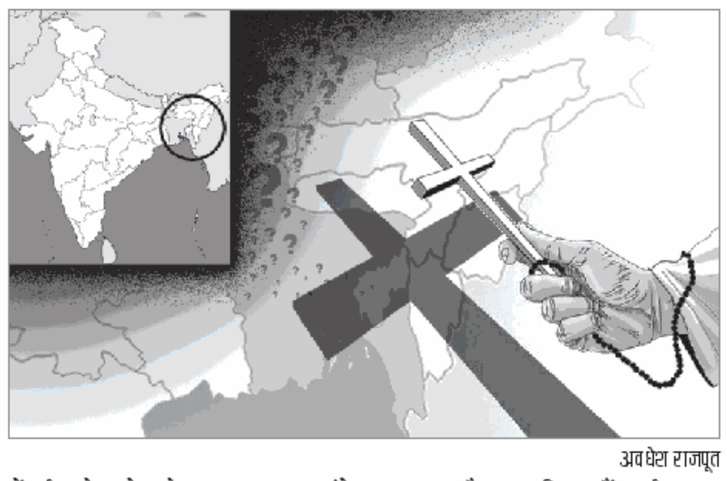

अवधेश राजपूत

में चीन के प्रवेश के आसार बन जाएंगे और इस तरह वह मलक्का स्ट्रेट की बाधा का विकल्प तलाश लेगा। इसके साथ ही अपने पूंजी निवेश एवं दोहन के लिए पाकिस्तान के समान उसे म्यांमार जैसा देश भी मिल जाएगा।

तीन भारतीय राज्य नगालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम की सीमा म्यांमार से लगती हैं। म्यामांर का एक राज्य काचिन है, जो चीन की सीमा के दक्षिण में है। यह म्यांमार का उत्तरी राज्य है। एक सैगाइन राज्य है और उसके बाद चिन राज्य आता है। इनकी जनसांख्यिकी को देखें तो चिन राज्य मिजोरम एवं मणिपुर से मिलता है। वहां ईसाई आबादी 85 प्रतिशत है। काचिन राज्य की सीमा अरुणाचल और नगालैंड से मिलती है। वहां ईसाई आबादी तेजी से बढ़कर 80 प्रतिशत पहुंच रही है। हमारे यहां मणिपुर के मैतेयी एवं कुकियों के बीच विवाद का मूल यही चिन राज्य क्षेत्र है। कुकी चिन जाति की ही एक शाखा है। सीमावर्ती राज्यों नगालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम में ईसाई आबादी क्रमशः 80, 45 और 87 प्रतिशत हैं। इसी कारण अब इस क्षेत्र में म्यांमार की कमजोर डांवाडोल राजनीतिक स्थिति का लाभ उठाकर एक ईसाई देश स्थापित होने के आसार बनने लगे हैं। म्यांमार में 85 प्रतिशत ईसाई आबादी का चिन राज्य तो पहले से उपलब्ध है ही। उसे समुद्र तक पहुंच के लिए रखाइन राज्य और बांग्लादेश के चटगांव प्रायद्वीप की भूमि की भी आवश्यकता पड़ेगी। यहीं भारत का महत्वाकांक्षी सितवे कलादान प्रोजेक्ट भी पूर्ण होने के निकट है। यहां के एक बड़े शहर पलेटवा पर पिछले माह विद्रोही बलों का कब्जा हो चुका है। यहां भारत के हितों के विरुद्ध स्थितियां आकार ले रही हैं। जो लोग इस क्षेत्र में एक ईसाई राज्य के रणनीतिकार हैं, उनकी जानकारी में ब्रिटिश योजना निश्चय ही है। कमजोर होता म्यांमार गृहयुद्ध की स्थिति में अपनी मुख्यभूमि को सुरक्षित करने में ही अपने संसाधन लगाएगा। हमारी सीमा से जुड़े म्यांमार के ईसाई क्षेत्रों पर उनकी सत्ता का कमजोर होना हमारे लिए एक बहुत बड़ा संकट खड़ा कर रहा है। चिंता का सबसे बड़ा कारण यह है कि इस बिंदु पर आकर पश्चिमी लाबी और ईसाई मिशनरियों के हित तो सध रहे हैं, लेकिन इसकी तपिश हमें झेलनी पड़ेगी। मणिपुर में हिंदू-ईसाई विभेद पहले ही बढ़ा हुआ है।

भारत विभाजन के दौर का यह तथ्य ध्यान रहे कि भारत को दो नहीं, बल्कि तीन भागों में विभाजित करने की योजना थी। मिशनरियों की मांग पर पूर्वोत्तर एवं म्यांमार के ईसाई राज्यों को मिलाकर 'क्राउन कालोनी संरक्षित राज्य' बनाने की योजना असम के तत्कालीन गवर्नर राबर्ट रीड एंड्रू ग्लो ने प्रस्तुत की थी। हालांकि कांग्रेस नेता गोपीनाथ बोरदोलोई के विरोध के कारण असम को पूर्वी बंगाल के समूह से अलग करना पड़ा। परिणामस्वरूप अंग्रेजों को कैबिनेट मिशन की तीसरी सूची संशोधित करनी पड़ी थी। यदि असम पूर्वी बंगाल के साथ पूर्वी पाकिस्तान के समूह में चला जाता तब पूर्वोत्तर में एक ईसाई राज्य की भूमिका बन जाती। अब 75 वर्ष बाद पुनः उसकी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं।

जार्ज सोरेस एवं भारत विरोधी शक्तियों की मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करने की योजना सफल हो जाती तो म्यांमार के विखंडन एवं बांग्लादेश में विद्रोही शक्तियों को उभार कर ऐसी स्थितियां बना दी जातीं, जिसमें 75 वर्ष पहले का ईसाई राज्य बनाने का ब्रिटिश साम्राज्यवादी एजेंडा अंततः सफल हो सकता था। अच्छी बात है कि उनकी इस साजिश पर पानी फिर गया, मगर भारत को कहीं अधिक सावधान रहने की जरूरत है।

(लेखक पूर्व सैन्य एवं प्रशासनिक अधिकारी हैं)

response@jagran.com

महामारी जैसा बनता अकेलापन

श्वेता शर्मा

आज की तकनीक भले ही हमें बहुत आकर्षित करती हो, लेकिन यह मानवीय संबंधों का रूप कभी नहीं ले सकती

युवा भी बनने लगे अकेलेपन का शिकार ● फाइल

काफी समय से यह माना जाता रहा है कि बुजुर्गों में अकेलापन बढ़ गया है। इसका कारण संयुक्त परिवार का न होना, बच्चों का विदेश या बाहर के शहरों में बस जाना, रिटायरमेंट, जीवनसाथी का न रहना और दोस्तों से संपर्क टूटना आदि हैं, मगर अब नए शोध के अनुसार अकेलापन युवाओं को भी बहुत परेशान कर रहा है। यह असमय ही उन्हें मृत्यु की ओर धकेल रहा है। इसका एक कारण हमउम्र लोगों से कम संपर्क और परिवार से दूरी है। नौकरियां भी अब ऐसी हो चली हैं, जहां युवा 24 घंटे के नौकर हैं। उन्हें हर हाल में टारगेट पूरे करने होते हैं। भले ही इसके लिए कितने ही घंटे काम क्यों न करना पड़े। इस अतिरिक्त व्यस्तता के कारण वे अपने आसपास और दोस्तों से कट रहे हैं। आपको अमेरिका में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ गुप्ता का केस तो याद ही होगा। यह युवा बहुत तेजस्वी और मेधावी था। अमेरिका के एक बड़े संस्थान में काम करता था। वह दफ्तर में 16-18 घंटे काम करता था, फिर भी अधिकारी कहते थे कि और करो। न उसके पास घर जाने का समय था और न ही सोने का। तब परिवार और दोस्तों के लिए समय कहां से आता। एक दिन इस युवा ने जिंदगी से हार मान ली। जिनके लिए 16-18 घंटे काम किया, उन्हें भला क्या फर्क पड़ा। उसकी जगह कोई और आ गया। कंपनियों का तो यह नियम ही है।

विशेषज्ञ कहते हैं कि अपनों से कट जाने का मतलब एक तरह की असामयिक मृत्यु है। अकेलापन धूमपान करने से भी अधिक खतरनाक है। कुछ दिन पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बढ़ते अकेलेपन पर चिंता प्रकट की। उसके अनुसार अकेलापन दुनिया में महामारी की तरह फैल रहा है। डाक्टरों का कहना है कि अकेलेपन के कारण लोगों को नींद नहीं आती। उन्हें तरह-तरह की समस्याएं होती हैं। अवसाद बढ़ता है। प्रतिरोधक प्रणाली कमजोर हो जाती है। मानसिक स्वास्थ्य कमजोर हो जाता है। दिल की बीमारियों के खतरे बढ़ जाते हैं और तरह-तरह के रोग घेर लेते हैं।

अकेलापन किसी गंभीर बीमारी जैसा ही खतरनाक है। अकेलापन हमारी भावनाओं पर आघात करता है। यह हमें हमेशा दुखी रखता है। दुखी होने से चिंता और तनाव बढ़ता है। यह जीवन की कठिनाइयों को बढ़ाता है। रही-सही कसर इंटरनेट मीडिया ने पूरी कर दी है। युवाओं का दफ्तर के कामकाज से जो समय बचता है, उसे वे इंटरनेट मीडिया पर खर्च करते हैं। इंटरनेट मीडिया भी तरह-तरह की प्रतिस्पर्धा से भरा है। किसको कितनी रीच एवं लाइक्स मिले, यह एक चिंता का विषय बन जाता है।

अकेलेपन के जो कारण बताए जाते हैं, उनमें बेरोजगारी और कम आय भी महत्वपूर्ण है। जो लोग नौकरी या अन्य किसी कारण अकेले रहते हैं, उनका अकेलापन भी बढ़ता है। गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोग भी अकेलेपन का शिकार होते हैं। बहुत से सामाजिक दबाव भी इसे बढ़ाते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अकेलेपन की समस्या से समय रहते निपटा जाना चाहिए। इसके लिए ऐसी आदतें डाली जानी चाहिए, जो किसी को अकेला न रहने दें। अकेलेपन को दूर करने के लिए लोगों से मिलें-जुलें, दोस्ती बढ़ाएं। एक-दूसरे के सुख-दुख का हिस्सा बनें। सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने से भी जीवन सार्थक लगता है। इसलिए इनसे भी जुड़ना चाहिए। दोस्तों या परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बाजार जाएं। दूसरों के अनुभवों से सीखें। यदि समय हो तो किसी अभिरुचि को पूरा कर सकते हैं। बहुत से शौक अपनाए जा सकते हैं। बागवानी, पेंटिंग और संगीत भी अकेलेपन को दूर करने में बहुत मदद करते हैं। संगीत सुनना और संगीत सीखना, दोनों उपयोगी हैं। योग और व्यायाम से न केवल अकेलेपन को दूर किया जा सकता है, बल्कि स्वास्थ्य को भी अच्छा रखा जा सकता है।

इन दिनों कहा जाता है कि युवाओं में पढ़ने की आदत कम होती जा रही है, जबकि कोई अच्छी किताब हमारी सबसे अच्छी साथी होती है। मनपसंद किताबें कभी अकेला नहीं रहने देतीं। प्रकृति के साथ रहना भी हमारे अवसाद को कम करता है और हमें बहुत सी चिंताओं से मुक्ति दिलाता है। सबसे प्रमुख तो हमारा परिवार ही है। यदि परिवार के साथ रहते हैं तो स्वजनों के साथ समय बिताना एक अच्छा विकल्प है। दूर रहते हैं, तो मोबाइल ने यह सुविधा प्रदान की है कि हम कभी भी परिवार के सदस्यों से बात कर सकते हैं। आज की तकनीक भले ही हमें बहुत आकर्षित करती हो, लेकिन यह मानवीय संबंधों का रूप कभी नहीं ले सकती। वह पश्चिम जो तमाम तकनीकी उपकरणों और सुविधाओं से भरा पड़ा है, वहां न केवल युवा, बल्कि अधिकांश आबादी अकेलेपन की पीड़ा झेलने को मजबूर है। लंबे अर्से तक वहां अकेलेपन को आत्मनिर्भरता और ताकत के रूप में पेश किया गया। आज पश्चिम के लोग परिवार-परिवार चिल्ला रहे हैं। यह अफसोस की बात है कि भारत में अकेलेपन को किसी वरदान की तरह समझा जा रहा है। अकेलेपन की विशेषता के रूप में यह बताया जाता है कि हम जो चाहें, वह सब कर सकते हैं। पहले संयुक्त परिवार को तोड़कर एकल परिवार बने। अब बहुत से युवा जिनमें लड़के-लड़कियां दोनों शामिल हैं, परिवार नाम की संस्था से ही दूर भागते हैं। उन्हें लगता है कि अकेले हैं तो आजाद हैं। परिवार है तो जिम्मेदारियों का बोझ है और आजादी खतरे में है। थोड़े दिनों तक तो यह सोच बहुत अच्छा लग सकता है, मगर एक वक्त के बाद यह लगने लगता है कि हमारा कोई नहीं। जब तक यह बात समझ आती है कि शेयरिंग और केयरिंग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तब तक कई बार देर हो चुकी होती है।

(लेखिका साहित्यकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

सुख और दुख

सुख-दुख जीवन की अभिन्न अनुभूति हैं, जो व्यक्ति, वस्तु एवं समय के सापेक्ष होती हैं। कोई किसी घटना से सुखी होता है तो दूसरा उससे दुखी। वस्तुतः सुख या दुख की निरंतरता नहीं रहती। यह प्रतिपल बदलती है। हम कष्टों से पलायन कर स्वयं अपने सुखों से दूर होते चले जाते हैं। सुख व्यक्ति के अहंकार की परीक्षा लेता है जबकि दुख व्यक्ति के धैर्य की। इसलिए सदैव स्मरण रहे कि सुख में कभी अहंकार न घर करने पाए और दुख में जीवन से कभी मोहभंग न हो। सुख और दुख रूपी जीवन की दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण व्यक्ति का जीवन ही वास्तव में एक सार्थक जीवन है।

महात्मा गांधी ने कहा है, 'खुशी तब मिलती है जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं, जो करते हैं, उनमें समानता हो।' सुख हवा का वह झोंका है जिसके गुजर जाने का अहसास तक नहीं होता है। सुख में समय कब निकल गया, उसका आभास तक नहीं होता है। जबकि दुख में समय रुका, ठहरा सा लगता है। सुख का रंग-रूप व्यक्तिगत होता है और वह जहां भी मिलता है आनंद प्रदान करता प्रतीत होता है, जबकि दुख इसका विपरीत। दुख को शिक्षक समझें। उससे सीख लें। जीवन में जितना कष्ट आएगा, उतना ही आप कष्टों को सहते-सहते धैर्यवान होते जाएंगे। धैर्य की शक्ति से हम कितनी भी विकट परिस्थिति का सामना कर उससे उबरने में सक्षम हो जाते हैं। धैर्य एक ऐसा गुण है, जो व्यक्ति की कार्यक्षमता में वृद्धि करता है। उसे आगे ले जाता है। उसे संपूर्णता प्रदान करता है।

तनाव एवं समस्याएं ही हमारे मन को जागृत रखते हैं। जीवन में विविध समस्याओं के समाधान खोजते समय ही हमारा अपनी वास्तविक क्षमताओं से परिचय होता है। इसी प्रक्रिया में ही हमारा व्यक्तित्व निखरता है। हम अपनी नियति से साक्षात्कार कर पाते हैं। जैसे सोने में खोट मिलाए बिना आभूषण नहीं बनते, उसी प्रकार समस्याओं को सुलझाने की अग्निपरीक्षा के बिना हमारे व्यक्तित्व का आभूषण नहीं आकार ले पाता।

नृपेंद्र अभिषेक नृप

पाठकनामा

pathaknama@pat.jagran.com

चीन को जवाब देना आवश्यक

'तिब्बत की आवाज बने भारत' शीर्षक से लिखे आलेख में शंकर शरण ने कूटनीतिक मोर्चे पर अतीत में कई गलतियों और उनके दुष्परिणामों को रेखांकित किया है। उन गलतियों का खामियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। समय आ गया कि अब हम चीन के साथ आक्रमक कूटनीति का परिचय दें। जैसा इस समय अमेरिका कर रहा है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का बीते दिनों धर्मशाला में दलाई लामा से मुलाकात इसी आक्रामक कूटनीति का हिस्सा है। यह बेहद सुखद है कि मौजूदा केंद्र सरकार ने अमेरिकी सांसदों के दल को दलाई लामा से मिलने की ही अनुमति नहीं दी, बल्कि इस दल से प्रधानमंत्री मोदी ने मिलकर चीन को जो संदेश दिया है उसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। इसके पहले चीन के साथ हमारे कूटनीतिक संबंध चार कदम आगे चलकर दो कदम पीछे हटने जैसे थे, जबकि चीन का नजरिया इस मामले में सदैव यथार्थवादी रहा। नतीजा यह हुआ कि जो तिब्बत 1951 तक स्वतंत्र देश था, आज उस पर चीन पूरी तरह अवैध कब्जा कर चुका है। इस तरह हमारी सीमा उससे प्रत्यक्ष रूप से जुड़ चुकी है। पिछली सदी के आठवें दशक तक अमेरिका के साथ चीन के रिश्ते सहज नहीं थे। बाद में ये रिश्ते इतने प्रगाढ़ हुए कि अमेरिकी पूंजी निवेश के बूते वह आर्थिक महाशक्ति बनकर आज अमेरिका को ही आंखें दिखाने की स्थिति में आ गया है। ऐसे में समय रहते चीन की चुनौती का जवाब तलाशना बहुत आवश्यक हो गया है, क्योंकि अमेरिका की तो चीन के साथ सीमा भी नहीं लगती, लेकिन वह हमारा पड़ोसी है। इसलिए हमें अतिरिक्त सतर्कता के साथ चीन पर नजर रखनी होगी।

मुकेश कुमार मनन, पटना

भूल स्वीकारे कांग्रेस

संपादकीय आलेख अनावश्यक आपत्ति (28 जून) पढ़ा। नई लोकसभा के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कांग्रेस की आपत्ति अनावश्यक है। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल का उल्लेख करना कांग्रेस को रास नहीं आया है। आपातकाल लोकतंत्र का एक काला अध्याय है, जिसे कभी नहीं भूला जा सकता है। कांग्रेस पार्टी को आपत्ति दर्ज करने की बजाय अपनी भूल को स्वीकार करना चाहिए। लोकतंत्र की मजबूती के लिए मजबूत विपक्ष अनिवार्य है। इस लोकसभा में कांग्रेस का संख्या बल बढ़ा है। कांग्रेस को सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करनी चाहिए एवं संवाद की गरिमा को बनाए रखना चाहिए।

ई हिमांशु शेखर, केसपा, गया

ऐसी सफारी नहीं चाहिए

इस वर्ष की भयंकर गर्मी ने जन जन को त्रस्त कर दिया। जम्मू एवं लद्दाख तक में तापमान ने रौद्र रूप दिखा दिया। पर्यावरणविदों ने इसका कारण वृहद स्तर पर पेड़ों की कटान को बताया है। कंक्रीट के जंगल के फैलाव के कारण भूमि में जल को प्रवेश नहीं मिल रहा है। लखनऊ से नौ किमी दूर कुकरैल वन के स्थान पर सफारी व डिज्नीलैंड बनाने के प्रकल्प पर विचार हो रहा है। जू को भी वहीं स्थानांतरित करने की योजना है। ऐसे होने पर पांच हजार एकड़ में फैले वन का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। यह एक तरह से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा।

धर्मेन्द्र नाथ रस्तोगी, दुर्गादेवी मंदिर मार्ग, पटना

यथार्थवादी कदम उठाए भारत

'तिब्बत की आवाज बने भारत' शीर्षक आलेख में शंकर शरण का मानना है कि भारत चीन से आपसी संबंधों में सुधार चाहता है तो यथार्थवादी कदम उठाने होंगे। तिब्बत ही एकमात्र देश है, जो भारत-चीन संबंधों के बीच सेतु है। भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव की स्थिति में भारत की तिब्बत नीति में बदलाव आया है। नीति में यह बदलाव, सार्वजनिक मंचों पर दलाई लामा के साथ सक्रिय रूप से प्रबंधन करने वाली भारत सरकार को चिह्नित करता है। भारत की तिब्बत नीति में बदलाव मुख्य रूप से प्रतीकात्मक पहलुओं पर केंद्रित है। तिब्बत नीति के प्रति भारत के दृष्टिकोण से संबंधित कई चुनौतियां हैं। कुछ दशकों में चीन अपनी मुख्य भूमि से लोगों को तिब्बत में प्रवास करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। चीन उस तिब्बती आबादी का दमन कर रहा है, जो दलाई लामा से संबंधित है या उसका समर्थन करती है। इसके लिए वह क्षेत्र में अपने निवेश, बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं को बढ़ा रहा है। चीन ने तिब्बती मिलिशिया समूहों को समर्थन देना शुरू कर दिया है। इसके विपरीत भारतीय सेना तिब्बती स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को प्रशिक्षित करती है। अब समय आ गया है कि भारत को चीन से निपटने में तिब्बत के मुद्दे पर अधिक मुखर होना होगा। भारत में तिब्बत की युवा व अशांत आबादी रहती है, जो दलाई लामा के गुजरने के बाद नेतृत्व के लिए भारत से बाहर देखती है। अतः भारत को ऐसी स्थिति से बचने की भी आवश्यकता है।

युगल किशोर राही, छपरा, बिहार

पोस्ट

पिछले दस साल में दिल्ली के हाल बहुत बुरे हो गए हैं। शीला दीक्षित जी ने जो दिल्ली बनाई थी, उसे बाद में ठीक से संभाला नहीं गया।

सत्या चौधरी@satyagodara

दिल्ली एयरपोर्ट पर बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है। इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों और इसके मेंटेनेंस के लिए जिम्मेदार कंपनी पर हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

अंकित@samastipurwala

जब तक भारत को जीत मिल रही है तब तक कोई ज्यादा नहीं बोलेगा, लेकिन जिस दिन हारे तो यह सवाल जरूर उठेगा कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ नंबर तीन बल्लेबाज विराट कोहली से ओपनिंग क्यों कराई जा रही है?

एक्स क्रिकेटर@old_cricketer

भारत जल्द ही कुछ बड़ी उपलब्धियां हासिल करेगा। वह जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिकी बन जाएगा। जापान को पछाड़कर पूंजीकरण के लिहाज से तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा। रूस से ज्यादा रक्षा बजट के साथ इस मोर्चे पर भी तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। भारत के पास स्विट्जरलैंड से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हो जाएगा। भारत का उदय ऐसे ही जारी रहेगा। हर्ष मधुसूदन@harshmadhusudan

जनपथ

जिम्मेदारी है मिली बनिए जिम्मेदार,
जरा सदन में बैठकर करिए सोच विचार।
करिए सोच विचार चलाएं तब फिर जिह्वा,
झूठ मूठ में किंतु खड़ा मत करिए हव्वा।
हे नेता प्रतिपक्ष दीजिए बेशक गारी,
पर होकर गंभीर निभाएं जिम्मेदारी!

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व.पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त

जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्र, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प. बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073

E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी.एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 25 अंक 78

****

प्रवाह

महोत्सव विश्वास का 75

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक

स्थापना वर्ष : 1948

पानी जिंदगी का सार है और इसके बगैर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। -अल्बर्ट जेंट ग्योर्गी

तमिलनाडु जहरीली शराब कांड से उबर भी नहीं सका है कि अब विश्व स्वास्थ्य संगठन की ताजा रिपोर्ट ने भारत समेत पूरी दुनिया में शराब से होने वाली मौतों की एक चिंताजनक तस्वीर पेश की है, जिसे पूरी गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है।

शराब और मौतें

तमिलनाडु में जहरीली शराब की आग अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की ताजा रिपोर्ट ने भारत समेत पूरी दुनिया में शराब से होने वाली मौतों की एक चिंताजनक तस्वीर पेश की है, जिसे पूरी गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है। रिपोर्ट के अनुसार, पूरी दुनिया में शराब से हर वर्ष छब्बीस लाख से ज्यादा लोग मर रहे हैं, तो इस वक्त दुनिया में करीब चालीस करोड़ लोग शराब व नशे की लत से होने वाली बीमारियों से पीड़ित हैं। भारत की स्थिति तो और भी ज्यादा खराब है, जहां प्रति एक लाख में 38.5 फीसदी मौतें शराब से हो रही हैं। मौतों के कारणों में यकृत रोग, हृदय संबंधी समस्याएं, सड़क दुर्घटनाएं और हिंसा शामिल हैं, जो शराब के अत्यधिक सेवन के दुष्प्रभावों के ही प्रमाण हैं। उल्लेखनीय है कि 1.4 अरब से अधिक की आबादी वाला भारत दशकों से शराब की लत से जूझ रहा है और नवीनतम आंकड़े समस्या की गंभीरता को ही दर्शाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक का यह कहना भी महत्वपूर्ण है कि नशीले पदार्थों के सेवन से पुरानी बीमारियों के उभरने और मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ने का खतरा रहता है, जिससे दुर्घटनाओं, चोटों और हिंसा का जोखिम तो बढ़ता ही है, परिवारों व समुदायों पर भी भारी बोझ पड़ता है। रिपोर्ट का यह कहना भी गंभीर है कि 15 से 19 वर्ष की आयु के भारतीय किशोरों में शराब पीने की प्रवृत्ति अधिक होती है। भारत में पंद्रह वर्ष या उससे अधिक के 41 फीसदी पुरुष शराब पीते हैं, जबकि महिलाओं की संख्या करीब 21 फीसदी है। रिपोर्ट के अनुसार, अकेले 2020 में भारत में शराब से तीन लाख से ज्यादा मौतें हुईं, जो चीन में होने वाली ऐसी मौतों के दोगुने से भी अधिक है। शराब की समस्या पर काबू पाने में चीन की तुलनात्मक कामयाबी भारत के लिए भी एक मॉडल का काम कर सकती है। शराब के विज्ञापन और उपलब्धता को विनियमित करने पर चीन का सक्रिय रुख और सार्वजनिक स्वास्थ्य के सशक्त

अभियानों ने वहां शराब से होने वाली मौतों पर काबू पाने में मदद की है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार ने भी शराब की बिक्री और खपत को विनियमित करने के कई उपाय लागू किए हैं। दरअसल, यह ध्यान रखने की जरूरत है कि शराब से होने वाली मौतें केवल स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक विकास को भी बाधा पहुंचाती हैं। ताजा रिपोर्ट के निष्कर्ष व्यक्तियों, परिवारों व समग्र रूप से समाज पर शराब के विनाशकारी प्रभाव का स्मरण कराते हैं। ऐसे में, सरकार, नागरिक समाज व जागरूक व्यक्तियों को मिलकर इस गंभीर मुद्दे के समाधान के लिए आगे आना होगा।

तो कोई भी विजेता नहीं होगा

सिंचाई तथा शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू जलापूर्ति के कारण भूजल की कमी ने भारत को खतरनाक स्थिति में डाल दिया है। जलवायु परिवर्तन के दौर में, अगर हम पानी का विवेकपूर्ण प्रबंधन नहीं करते और यदि भूजल का अंधाधुंध दोहन बंद नहीं करते, तो कोई भी विजेता नहीं होगा।

पत्रलेखा चटर्जी

वरिष्ठ पत्रकार

जो लोग पर्यावरण कार्यकर्ताओं को 'झोलावाला' या भारत के आर्थिक विकास को पटरी से उतारने वाला मानते हैं, और जो भारत में बढ़ते जल संकट के संबंध में दी जा रही चेतावनियों को नजर अंदाज करते हैं, उन्हें ध्यान देने की जरूरत है। जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न जल संकट, जो पानी के अंधाधुंध उपयोग के कारण और गहरा गया है, जिसके प्रति भारतीय पर्यावरणविद लगातार चेताते रहे हैं, सिर्फ पर्यावरण या स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है, बल्कि एक गंभीर आर्थिक मुद्दा भी है, जो 1.4 अरब की आबादी वाले इस देश की महत्वाकांक्षाओं को कुचल सकता है। अभी भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और 2024 में भी इसके तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन भारत की आकांक्षाएं कई कारकों पर निर्भर करती हैं, जिनमें पानी भी एक है।

मूडीज रेटिंग की एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि 'भारत में जल संकट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि तेज आर्थिक विकास और जलवायु परिवर्तन के कारण लगातार बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं के बीच पानी की खपत बढ़ रही है। यह सॉवरेन क्रेडिट के साथ-साथ कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्रों एवं इस्पात निर्माण जैसे पानी की भारी खपत वाले क्षेत्रों के लिए भी नुकसानदेह है।' 'सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग' किसी देश या संप्रभु इकाई की ऋण पाने की क्षमता का एक स्वतंत्र मूल्यांकन है, जो यह भी बताता है कि उस देश में निवेश करना कितना जोखिम भरा हो सकता है।

जलवायु परिवर्तन के समय में जल संकट जैसे कारक, इससे होने वाली भारी मानवीय पीड़ा के अलावा आर्थिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हैं। तीव्र औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण के साथ भारत का तेज आर्थिक विकास दुनिया की इस सबसे बड़ी आबादी वाले देश में पानी की उपलब्धता को कम कर रहा है। जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार, भारत में प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक जल उपलब्धता 2031 तक घटकर

1,367 क्यूबिक मीटर रह जाने की आशंका है, जो 2021 में पहले से ही कम 1,486 क्यूबिक मीटर थी। 1,700 क्यूबिक मीटर से कम का स्तर जल संकट को ही दर्शाता है, जिसमें पानी की कमी की सीमा 1,000 क्यूबिक मीटर है।

जलवायु परिवर्तन के कारण चरम जलवायु घटनाओं, जैसे सूखा, लू, बाढ़ की आवृत्ति, गंभीरता या अवधि में वृद्धि से स्थिति और भी बदतर हो जाएगी, क्योंकि भारत पानी के लिए मानसून पर ज्यादा निर्भर है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज का कहना है कि 'जलापूर्ति में कमी से कृषि उत्पादन और औद्योगिक संचालन में बाधा उत्पन्न हो सकती है, जिसके चलते खाद्य महंगाई बढ़ेगी और इससे प्रभावित व्यवसायों एवं समुदायों की आय में कमी होगी, जिससे सामाजिक अशांति भी फैल सकती है। यह भारत के विकास को अस्थिर और आर्थिक झटकों को झेलने की भारत की क्षमता को कमजोर कर सकता है।'

भारत में नदियों और भूजल के लगभग 70 प्रतिशत पानी का उपयोग कृषि कार्यों में किया जाता है। लेकिन कुछ उद्योग भी पानी की ज्यादा खपत करते हैं। मूडीज के अनुसार, औद्योगिक क्षेत्र में कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्र और स्टील निर्माता उत्पादन के लिए पानी पर बहुत ज्यादा निर्भर होते हैं। बढ़ता जल संकट उनके संचालन को बाधित कर सकता है और उनकी कमाई को कम कर सकता है, जिससे उनकी कर्ज चुकाने की क्षमता भी खत्म हो सकती है। ये चेतावनियां ऐसे समय आई हैं, जब देश के कई हिस्से पानी की भारी कमी से जूझ रहे हैं। दिल्ली और बंगलूरू जैसे महानगरों से पानी के लिए संघर्ष और सरकारी बोरवेल से पानी निकालने वाले टैंकर माफिया के बारे में जमीनी स्तर से कई खबरें आ रही हैं। भारत में भूजल रिचार्ज चालू वर्ष में 449 अरब क्यूबिक मीटर (बीएमसी) तक पहुंच गया है, जो 2004 के बाद से अधिकतम है और 2022 की तुलना में 11.5 बीएमसी ज्यादा है, जैसा कि केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा कराए गए भारत के गतिशील भूजल संसाधनों के राष्ट्रीय संकलन, 2023 में बताया गया है। लेकिन रिपोर्ट यह भी बताती है कि भूजल का दोहन कई जगहों पर चिंता का विषय बना हुआ है, जहां रिचार्ज किए जाने से ज्यादा पानी जमीन के अंदर से नलकूपों के जरिये निकाला जाता है।

सिंचाई तथा शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू जलापूर्ति के कारण भूजल की कमी ने भारत को खतरनाक स्थिति में डाल दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, 'देश में कुल 6,553 मूल्यांकन इकाइयों (ब्लॉक/ मंडल/ तालुका) में से, विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 736 इकाइयों (11.23 फीसदी) को 'अति-शोषित' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो दर्शाता है कि भूजल दोहन वार्षिक भूजल रिचार्ज से अधिक है।' रिपोर्ट में बताया गया है कि, 'अति-दोहन वाली मूल्यांकन इकाइयां ज्यादातर देश के उत्तर-पश्चिमी भाग में केंद्रित हैं, जिनमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल हैं, जहां भूजल का अंधाधुंध दोहन हो रहा है।' साथ ही, यह भी कहा गया है कि देश के कुछ क्षेत्रों में कुछ आशाजनक संकेत भी हैं -निरंतर अच्छी वर्षा और सरकारी व निजी पहलों के माध्यम से भूजल संवर्धन और संरक्षण उपायों के चलते भूजल की स्थिति में सुधार हुआ है।

मूडीज की रिपोर्ट में पानी से संबंधित आधारभूत संरचनाओं में सरकारी निवेश और नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के सरकारी प्रयासों को सकारात्मक बताया गया है। इन पहलों से पानी पर आधारित कोयला ऊर्जा पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी।

लेकिन सरकार और अन्य लोगों को अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मिलेट्स (मोटा अनाज) जैसी कम पानी की जरूरत वाली फसलों को प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण होगा। हमें यह समझना होगा कि पेड़ों को काटने और लगभग पूरे शहर में जमीन को सीमेंट-कंकरीट से ढकने से वर्षा जल जमीन के अंदर नहीं जा पाता है और जमीन में जमा नहीं हो पाता है। जलवायु परिवर्तन के दौर में, अगर हम पानी का विवेकपूर्ण प्रबंधन नहीं करते और यदि भूजल का अंधाधुंध दोहन बंद नहीं करते, तो कोई भी विजेता नहीं होगा।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

माता अमृतानंदमयी

दूसरों की तुलना में हमारी समस्याएं, प्राय: तुच्छ होती हैं, अत: हमें अपने वर्तमान को स्वीकार करते हुए खुशी-खुशी जीवन बिताना चाहिए और परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए।

हृदय में फूल खिला हो, तो दुनिया सुंदर लगती है

एक बार एक व्यक्ति काफी समय से बेरोजगार था। फिर एक दिन उसे नौकरी के लिए साक्षात्कार हेतु बुलावा आया। जब उसे वह नौकरी नहीं मिली, तो निराश होकर वह एकांत स्थान पर सोच में डूबा बैठा हुआ था। तभी किसी ने उसका कंधा थपथपाया। पलट कर देखा, तो उसे धूप का चश्मा पहने एक बच्चा अपने सामने खड़ा दिखा। हालांकि एकांत भंग होने पर वह उसे डांटने वाला था, परंतु छिपा गया। उसने इतना ही पूछा कि क्या बात है? बच्चे ने उसे एक मुरझाया फूल देते हुए कहा, 'इस सुंदर फूल को देखो।' उसने बेमन इतना ही कहा, 'हां, सुंदर है।' बच्चे ने कहा, 'यह सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं, इसकी सुगंध भी बहुत अच्छी है।' अब तो उसे सचमुच क्रोध आ गया। उसने सोचा, यह बच्चा पागल तो नहीं, इस बासी फूल को लेकर यह क्यों मेरे पीछे पड़ा है? उसने तंग आकर कहा, 'तुम ठीक कहते हो। यह सुंदर व सुगंधित फूल है।' अब उस व्यक्ति को थोड़ा बेहतर लगा, शांति का अनुभव हुआ। बच्चे का धन्यवाद करके वह क्षितिज में ताकने लगा। तभी उसने धरती पर कुछ थपथपाहट महसूस की। मुड़कर देखा, तो वही बच्चा छड़ी लेकर खड़ा था। अचानक उसे बोध हुआ कि बच्चा दृष्टिबाधित है। उस क्षण उसे अनुभव हुआ कि उसने हाथ में जो फूल पकड़ा था, वह वास्तव में विश्व का सबसे सुंदर और सुगंधमय फूल था। उसने बच्चे को जाकर गले से लगा लिया। भाव-विभोर होकर वह बोला, 'यह कोई सामान्य फूल नहीं। यह वह फूल है, जो तुम्हारे हृदय में खिला है।' अब जिस सौंदर्य व निर्मलता पर उस व्यक्ति की दृष्टि पड़ी थी, वह उस बच्चे की थी, जो फूल में प्रतिबिंबित हो रही थी। नौकरी न मिलने के कारण वह इतना निराश और हताश था कि उसके मन में जीवन का अंत करने का विचार भी आया। और यहां यह बच्चा दोनों आंखें खोकर भी, न केवल खुश था, अपितु दूसरों में भी खुशियां बांट रहा था।

दूसरों की समस्याओं की तुलना में हमारी समस्याएं प्रायः तुच्छ होती हैं, अतः हमें अपने वर्तमान को स्वीकारते हुए खुशी-खुशी जीवन बिताना चाहिए। वास्तव में, देखा जाए, तो हमारे विचार ही तो हमारी खुशी की राह में बाधा बनकर रोड़ा अटकाते हैं, हमें स्वयं को भुला कर दूसरों के सहायक होने से रोकते हैं। प्रत्येक वस्तु पर अपनी सत्ता जमाने की इच्छा से हम इतने अभिभूत हुए रहते हैं कि खुशी क्या है-हम जान ही नहीं पाते। हृदय में प्रेम हो, तो एक दृष्टिबाधित इन्सान भी मार्गदर्शक हो सकता है, परंतु जिसका हृदय ही अंधा हो चुका हो, उसे राह दिखलाना बहुत कठिन कार्य है। अहंकार का अंधत्व हमें एक तहखाने में कैद कर देता है। अज्ञान वश हम जागते हुए भी सोए हैं। इस अहंकार पर विजय पा लें, तो हम स्वाभाविक ही विश्व के लिए अर्पित हो जाएंगे।

अहं पर विजय...

सूत्र

विभिन्न परिवारों में जन्मे लोगों के विभिन्न अनुभव होते हैं, किंतु मृत्यु का अनुभव सबको होता है। जिस इन्सान ने अहम पर विजय प्राप्त कर ली, उसने मानो मृत्यु पर विजय पा ली। जब तक जगत है, तब तक ऐसा व्यक्ति अपने कर्मों के कारण स्मरणीय रहेगा। जिसने अहम को जीत लिया, जिसका हृदय प्रेम के रस से लबालब भरा है, उसका संपूर्ण जीवन विश्व-हिताय समर्पित होता है। उसके जाने के बाद बहुत समय तक उसके कर्मों को याद किया जाएगा।

दूसरा पहलू

कैरेबियाई द्वीप पिछले करीब पांच साल से पानी की कमी से जूझ रहे हैं, जिसकी मुख्य वजह शहरीकरण व औद्योगिकीकरण है।

पर्यटकों के स्वर्ग में पानी का संकट

आम तौर पर कैरेबियाई द्वीपों को स्वर्ग माना जाता है, जहां लोग छुट्टियां बिताने जाते हैं। लेकिन इसके शांतिपूर्ण समुद्र तटों और हरीतिमा के बीच बने होटलों में एक ऐसा संकट पैदा हो गया है, जिसके बारे में स्थानीय लोगों ने शायद ही कभी सोचा हो। दरअसल ज्यादातर कैरेबियाई द्वीप पिछले करीब पांच साल से पानी की कमी से जूझ रहे हैं। त्रिनिदाद अपने ज्ञात इतिहास के सबसे भीषण सूखे का सामना कर रहा है, और वहां के लोगों को पानी की कटौती का सामना करना पड़ेगा।

फराह निब्स

पर्यटन कैरेबियन द्वीप समूहों में प्रमुख आर्थिक गतिविधि है और वहां साल भर पर्यटक आते रहते हैं, ऐसे में, पानी की कमी से पर्यटन व्यवसाय को नुकसान हो सकता है।

अपने पहाड़ी वर्षा वनों के लिए कैरेबियन द्वीपों के बीच प्राकृतिक द्वीप के तौर पर चर्चित डोमिनिका तक में ताजा पानी की कमी हो गई है। ऐसे ही, मसालों के द्वीप के रूप में चर्चित ग्रेनेडा में सूखे के कारण जलस्रोत बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से जमैका में भी पानी की भारी कमी दिख रही है, जिस कारण वहां रोज कुछ ही घंटों के लिए पानी की आपूर्ति होती है। सेंट विंसेंट, सेंट किट्स और बारबडोस में भी जल संकट के कारण पानी की राशनिंग शुरू हुई है।

कैरेबियन द्वीपों में पानी की कमी के कई कारण हैं। एक कारण यह है कि पिछले कुछ वर्षों से कैरेबियन द्वीपों में शहरीकरण तेज रफ्तार से हो रहा है। इन द्वीप समूहों की तीन चौथाई आबादी शहरों में रहती है, और आने वाले वर्षों में यह अनुपात बढ़ने ही वाला है। इससे पिछले कुछ वर्षों में वहां पानी की मांग काफी बढ़ी है। साथ ही, औद्योगिकीकरण के बढ़ने और कृषि के व्यवसायीकरण से पानी की गुणवत्ता घटी है। बढ़ते शहरीकरण से बारिश से पानी के रिचार्ज होने का अनुपात भी घट रहा है। बारबडोस में सालाना बारिश का 15 से 20 फीसदी ही रीचार्ज होता है, जबकि उटिला द्वीप में वर्षा का मात्र 2.5 फीसदी ही रीचार्ज हो पाता है। कई जगह पर भूजल के अनियंत्रित दोहन से भी स्थिति खराब हुई है।

कैरेबियन द्वीपों के कई देश पूरी तरह भूमिगत जल पर ही निर्भर हैं। जैसे, बारबडोस में 90 फीसदी जलापूर्ति भूमिगत जल से होती है, जबकि जमैका में यह आंकड़ा 84 प्रतिशत है।

कैरेबियन द्वीपों के कई देश पूरी तरह भूमिगत जल पर ही निर्भर हैं। जैसे, बारबडोस में 90 फीसदी जलापूर्ति भूमिगत जल से होती है, जबकि जमैका में यह आंकड़ा 84 प्रतिशत है। पानी की बढ़ती मांग और बारिश के पैटर्न में आए बदलाव के कारण भी कैरेबियन द्वीपों में जल संकट बढ़ रहा है। चूंकि पर्यटन कैरेबियन द्वीप समूहों में प्रमुख आर्थिक गतिविधि है और वहां साल भर पर्यटक आते रहते हैं, ऐसे में, पानी की कमी के बीच भी होटलों आदि में जलापूर्ति की व्यवस्था करनी पड़ती है, ताकि पर्यटन व्यवसाय को नुकसान न हो। *(कन्वर्सेशन से)*

आंकड़े

नक्सलियों की मौत

पिछले कुछ वर्षों की तुलना में इस वर्ष बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए हैं, जाहिर है, सुरक्षा बलों ने अपने अभियान में तेजी लाई है।

2020	134
2021	128
2022	66
2023	56
2024	157

25 जून तक | स्रोत : South Asia Terrorism Portal

सुतीक्षण ने अपने गुरु महर्षि अगस्त्य से कहा कि गुरुदेव मैं आपको गुरुदक्षिणा में क्या दूं? महर्षि ने कहा कि देना ही चाहते हो, तो सीता-राम के दर्शन करा दो।

सुतीक्ष्ण ने दी गुरुदक्षिणा

अंतर्यात्रा

संकलित

महर्षि अगस्त्य ने एक दिन अपने शिष्य सुतीक्ष्ण से कहा कि तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई है। सुतीक्ष्ण ने कहा कि गुरुदेव! आज्ञा करें कि मैं आपको कौन-सी गुरुदक्षिणा दूं? गुरु ने कहा कि तुमने मेरी बहुत सेवा की है। सेवा से बढ़कर कोई भी गुरुदक्षिणा नहीं। अतः जाओ और सुखपूर्वक रहो।

सुतीक्ष्ण ने जिद की, तो गुरु ने कहा कि देना ही चाहते हो, तो सीता-राम को लाकर हमें दर्शन करा दो। सुतीक्ष्ण गुरु को प्रणाम कर चले गए और घोर तपस्या करने लगे। वह नित्य सीता-राम की छवि का ध्यान करते रहते। कई वर्ष बीतने के बाद एक दिन उन्हें समाचार मिला कि श्रीराम जी सीता व लक्ष्मण सहित आ रहे हैं। यह सुनते ही सुतीक्ष्ण नाचने लगे। वह इतने मग्न हो गए कि उनके आश्रम तक श्रीराम, सीता और लक्ष्मण, तीनों पहुंच गए, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चला। भगवान ने उन्हें हृदय में जब अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन दिए, तब वह चेतना में आए।

आंखें खोलकर सुतीक्ष्ण ने देखा कि सीता और लक्ष्मण सहित प्रभु श्रीराम उनके सामने थे। उन्होंने प्रणाम किया। भगवान ने सुतीक्ष्ण को सभी सिद्धियां प्रदान कर कहा कि अब हम महर्षि अगस्त्य के दर्शनों के लिए जा रहे हैं, यह सुनते ही सुतीक्ष्ण की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह उनको महर्षि अगस्त्य के आश्रम तक लेकर पहुंचे और भगवान के आगमन का समाचार दिया। महर्षि अगस्त्य ने श्रीराम, जानकी और लक्ष्मण का स्वागत किया। इस तरह सुतीक्ष्ण ने गुरुदेव को गुरुदक्षिणा दी।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 2 मई, 1953

डॉ. मुखर्जी और उनके साथियों पर मुकदमा शुरू

डा॰ मुकर्जी व उनके साथियों पर मुकदमा शुरू

जनसंघ के नेता डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी और उनके 11 साथियों के विरुद्ध जुलूस निकालने और सभा करने पर प्रतिबंध की आज्ञा भंग करने के मुकदमे की प्रारंभिक सुनवाई दिल्ली में अतिरिक्त जिलाधीश की अदालत में शुरू हुई।

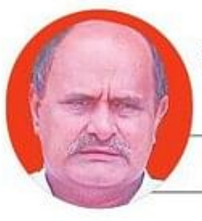

किसानों को दोषी न ठहराएं

खाद्य पदार्थों में मिलावट की घटनाएं देश की साख के लिए अच्छी नहीं हैं, लेकिन इसके जिम्मेदार किसान नहीं, कंपनियां हैं।

के. सी. त्यागी, पूर्व सांसद

मिलावट

खाद्य या आहार को किसी व्यक्ति के भरण-पोषण, विकास और वृद्धि के लिए मूलभूत आवश्यकता माना जाता है। हाल ही में राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत गुणवत्ता परीक्षणों में कई प्रमुख मसाला ब्रांड विफल रहे, जिसमें एमडीएच, एवरेस्ट, गजानंद, श्याम और शीबा ताजा जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों के नमूने उपभोग के लिए अनुपयुक्त पाए गए। इनमें कीटनाशक के अवशेष और अन्य हानिकारक रसायन मिले हैं। यह पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी मिलावट की घटनाएं पाई गई हैं। ऐसी घटनाएं खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता के प्रति गंभीर चिंताओं को उजागर करती हैं, जो उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और वैश्विक व्यापार में भारत की साख पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं।

ऐसी समस्या के लिए अब किसानों को जिम्मेदार ठहराया जाने लगा है, क्योंकि वे अपनी फसल सुरक्षा

और उत्पादन बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर रासायनिक का उपयोग करते हैं। लेकिन किसानों को दोषी ठहराना अनुचित है। यह एक जटिल और बहुआयामी समस्या है, जिसमें किसानों की भूमिका बहुत कम है। कई छोटे और सीमांत किसानों के पास आधुनिक कृषि पद्धतियों और सुरक्षित रसायनों के बारे में जानकारी की कमी होती है। ज्ञान और जागरूकता की कमी उन्हें अनजाने में हानिकारक रसायनों का उपयोग करने के लिए मजबूर करती है।

गंभीर आर्थिक दबाव में फंसे किसान अधिकतम उत्पादन के लिए तेजी से परिणाम देने वाले रसायनों का उपयोग करने के लिए मजबूर होते हैं। पर्याप्त निगरानी और प्रवर्तन की कमी के कारण, बाजार में हानिकारक और प्रतिबंधित रसायन आसानी से मिलते हैं। किसानों को अक्सर इन रसायनों की सुरक्षा और कानूनी स्थिति के बारे में नहीं बताया जाता है।

निस्संदेह आज कृषि क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है, जिसमें सरकार की नीतियों और संरचनात्मक बदलावों का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। किसानों को सुरक्षित कृषि पद्धतियों की ओर प्रोत्साहित करने के लिए नीतिगत समर्थन, वित्तीय सहायता और उचित बाजार पहुंच आवश्यक है। इसके बिना, किसानों को दोषी ठहराना समाधान की दिशा में सही कदम नहीं माना जा सकता।

एक मजबूत ट्रेसिबिलिटी सिस्टम की कमी खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में मिलावट, संदूषण और अनैतिक प्रथाओं के लिए गुंजाइश बनाती है। सब्जियों और फलों में कीटनाशक अवशेषों की अधिक मात्रा, दूध उत्पादों में हानिकारक रसायनों की मौजूदगी और मसालों में मिलावट की घटनाएं स्थिति की गंभीरता को उजागर करती हैं। हालांकि इन चिंताओं को दूर करने के लिए फूड सेफ्टी ऐंड स्टैंडर्ड रूल्स, 2011 के संशोधन से ट्रेसिबिलिटी को अनिवार्य कर आपूर्ति श्रृंखला में खाद्य की उत्पत्ति और आवाजाही को ट्रैक करने की क्षमता पर जोर दिया गया है। यदि यह प्रणाली प्रभावी ढंग से लागू की जाती है, तो हर हितधारक को जवाबदेह बनाया जाएगा और यह प्रणाली मिलावट की प्रथाओं को रोकेगी और अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत की साख बढ़ाएगी।

हालांकि, संभावित लाभों के बावजूद, 2011 का संशोधन काफी हद तक लागू नहीं हो पाया है, जिसके कारणों में बुनियादी ढांचे की कमी, लॉजिस्टिक चुनौतियां और छोटे व सीमांत किसानों को डिजिटल प्रणाली में एकीकृत करने की आवश्यकता शामिल है। खाद्य सुरक्षा मानकों के बारे में चिंताओं के कारण भारतीय कृषि निर्यात को खारिज कर दिया जाता है। इससे किसानों के लिए कम कीमतें और निर्यात के अवसर खत्म हो सकते हैं। यह विश्वसनीय उत्पादक और निर्यातक के रूप में भारत की छवि को कमजोर करती है।

इस समस्या के समाधान के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। किसानों को समर्थन और संसाधन प्रदान करना महत्वपूर्ण है, ताकि वे सुरक्षित और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाकर खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता को सुनिश्चित कर सकें। सरकार को बुनियादी ढांचे और क्षमता निर्माण में निवेश को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। उपभोक्ताओं को सुरक्षित भोजन की मांग करने के लिए सशक्त बनाया जाना चाहिए।

(साथ में बिशन नेहवाल)

कल्पमेधा

सफल व्यक्ति सकारात्मक ढंग से प्रशंसा करते हैं और हंसी-मजाक पर बुरा नहीं मानते। उनकी सकारात्मकता चारों तरफ फैलती है और उसकी खुशबू हर जगह बिखरती रहती है।

– विलियम आर्थर बार्ड

जोखिम की इमारतें

भवन, पुल, सड़कों आदि के निर्माण में तकनीकी उपयोग से तेजी तो आई है, ढांचे मनोहारी बनने लगे हैं, मगर उनकी मजबूती और टिकाऊपन को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। अब शायद ही कोई वर्ष बीतता हो, जब बरसात में पुलों, सड़कों, नवनिर्मित भवनों के धंसने, ढहने की खबरें न आती हों। ताजा घटना दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे के टर्मिनल-एक की है, जहां गाड़ियों के ठहराव वाली जगह की छत ढह गई, जिसमें कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से छत बैठ गई। यह तो इस मौसम की पहली बारिश थी, अभी पूरा मौसम बाकी है, इसलिए हवाई अड्डे की दूसरी छतों को लेकर भी लोगों में आशंका पैदा होना स्वाभाविक है। दरअसल, हवाई अड्डे की छत लोहे के खंभे खड़े कर सिंथेटिक और लोहे की पतली चादरों से बनाई गई है। इस तरह जगह तो काफी खुली हो गई है और सुंदर भी दिखती है, मगर इसके टिकाऊपन को लेकर कोई दावा करना मुश्किल है। यह कोई पहली इमारत नहीं है, जिसमें इस निर्माण कला का उपयोग किया गया है। अब बहुत सारी सार्वजनिक जगहों पर जल्दी काम पूरा करने के मकसद से यही तकनीक इस्तेमाल होने लगी है।

दरअसल, भवन निर्माण में कांच, लोहे, सिंथेटिक चादरों वगैरह का इस्तेमाल काफी तेजी से बढ़ा है। इस तरह इमारतें जल्दी तैयार हो जाती हैं, मगर न तो यह भारतीय प्रकृति के अनुकूल है और न इन्हें लंबे समय तक टिकाऊ माना जा सकता है। लोहे के खंभों को नट-बोल्ट से जोड़ कर बनाए गए ढांचे की समय-समय पर मरम्मत जरूरी होती है, जिसका प्रायः अभाव देखा जाता है। बहुत सारी इमारतें, सड़कें और पुल सरकार के दबाव में जल्दी तैयार कर दिए जाते हैं, इस वजह से भी इमारतें जोखिम भरी साबित होती हैं। दिल्ली हवाई अड्डे पर हुई घटना के कुछ घंटे पहले मध्यप्रदेश के जबलपुर में भी हवाई टर्मिनल की नई इमारत की छत का एक हिस्सा बारिश की वजह से एक गाड़ी पर गिर गया। बारिश शुरू होते ही बिहार में कई पुल ढह गए। पिछले कई वर्षों से मध्यप्रदेश, बिहार आदि में पुलों के बाढ़ में बह जाने, सड़कों के धंस या बह जाने की खबरें आती रही हैं।

ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जब इमारतें जल्दी तैयार करने की हड़बड़ी में उनकी जल निकासी, छतों की मजबूती आदि पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया और बरसात शुरू होते ही उनकी पोल खुल गई। यह समझना मुश्किल है कि तकनीकी इस्तेमाल से जहां निर्माण कार्यों में मजबूती आनी चाहिए, वे इतने भुरभुरे क्यों साबित हो रहे हैं कि बारिश का हल्का दबाव भी झेल नहीं पा रहे। इसकी एक वजह तो साफ है कि निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार के कारण निर्माण सामग्री की गुणवत्ता से समझौता किया जाता है। मगर यह सब ऐसी व्यवस्था में बढ़ रहा है, जो भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त न करने के दावे करती है। आमतौर पर हवाई अड्डा और वहां के समूचे परिसर को सबसे सुरक्षित जगहों में शुमार किया जाता है, जहां हुए निर्माण से लेकर सुरक्षा व्यवस्था तक के मोर्चे को पूरी तरह चाक-चौबंद माना जाता है। मगर बारिश ने इस बात की कलई खोल कर रख दी है। इस तरह इमारतों, पुलों, सड़कों के बारिश में ढह या बह जाने से न केवल बड़े पैमाने पर सार्वजनिक धन भी बह जाता है, आम लोगों की परेशानियां और बढ़ जाती हैं, इससे जान-माल का नुकसान होता है, सो अलग।

मुसीबत की बरसात

मानसून में बारिश एक स्वाभाविक चक्र है, लेकिन शहरों-महानगरों के लिए अब इसे एक तकलीफदेह दौर के रूप में जाना जाने लगा है। शुक्रवार को राजधानी दिल्ली में हुई बरसात के बाद जैसे हालात पैदा हुए, वह जितना बारिश का नतीजा है, उससे ज्यादा इसके लिए सरकार और समूची व्यवस्था की लापरवाही, अदूरदर्शिता और कुप्रबंधन जिम्मेवार है। कुछ घंटों की बारिश के बाद दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में जिस तरह व्यापक जलजमाव देखा गया, सड़कों पर पानी भर गया, बस और कार जैसे वाहन उसमें फंस गए, यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ, वह कोई नई घटना नहीं है। जब भी यहां कुछ घंटे ज्यादा बारिश होती है, तो उसके बाद समूचा जनजीवन लगभग ठप्प हो जाता है। हालत यह है कि दिल्ली के केंद्रीय इलाकों में भी पानी भर जाता है और लोगों के सामने कई तरह की मुश्किलें पैदा होती हैं। सवाल है कि क्या इससे उपजी अव्यवस्था के लिए केवल बरसात को बहाना बनाया जा सकता है। आखिर हर वर्ष ऐसी स्थिति पैदा होने के बावजूद इससे सबक क्यों नहीं लिया जाता और बरसात के पहले ही ऐसे इंतजाम क्यों नहीं किए जाते कि सड़कों या मुहल्लों में जलजमाव न हो?

यह उम्मीद की जाती है कि देश की राजधानी होने के नाते बाकी जगहों के मुकाबले दिल्ली में सरकारी तंत्र और प्रशासन के स्तर पर ऐसी चौकसी होगी कि मौसम या किसी भी वजह से उपजी अव्यवस्था से तत्काल निपटने के ठोस इंतजाम होंगे। मगर सामान्य बारिश में भी दिल्ली के कई इलाकों के सड़कों-मुहल्लों में नालियां और बड़े नाले जाम हो जाते हैं। नतीजतन, समूचा पानी सड़क पर बहता देखा जाता है। संबंधित सरकारी महकमे समय रहते पानी की निकासी के लिए एक बेहतर तंत्र को सक्रिय करने को लेकर शायद ही कभी गंभीर दिखते हैं। आम लोगों के स्तर पर भी लापरवाही बरती जाती है, जब लोग अपने घर से कचरा निकालते हैं और सड़क किनारे नालियों या नालों में डाल देते हैं। इसकी वजह से जाम होने वाली नालियां मुख्य सड़कों तक पर व्यापक जलजमाव का कारण बनती हैं। सिर्फ पानी की निकासी की व्यवस्था को ही पूरी तरह दुरुस्त बना कर इस समस्या पर लगभग काबू पाया जा सकता है। विडंबना यह है कि सरकारी तंत्र की नींद तब तक नहीं खुलती, जब तक घनघोर अव्यवस्था न फैल जाए!

विकट होती रोजगार चुनौतियां

सर्वेक्षण के अनुसार युवा बेरोजगारी का स्तर बढ़ा है और यह बीती तिमाही के 16.5 फीसद से बढ़कर चौथी तिमाही में 17 फीसद हो गया। यह आंकड़ा इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है कि इस आयु वर्ग के लोग पहली बार श्रम बाजार में प्रवेश करते हैं।

जयंतीलाल भंडारी

या कीनन इस समय बेरोजगारी देश की प्रमुख आर्थिक-सामाजिक चुनौती है। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी असंगठित क्षेत्र के उद्यमों से संबंधित आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2015 से जून 2016 की अवधि की तुलना में अक्तूबर 2022 से सितंबर 2023 की अवधि के दौरान विनिर्माण क्षेत्र के 18 लाख असंगठित उद्यम बंद हो गए हैं। इन उद्यमों में करीब 54 लाख लोग नौकरियों में थे। पिछले दस वर्षों में संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड और कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने जो भर्तियां की हैं, वे रिक्त पदों की तुलना में कम बहुत हैं। एनएसओ द्वारा जारी आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) आंकड़ों के अनुसार भारत के शहरी इलाकों में बेरोजगारी की दर वित्तवर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही (जनवरी से मार्च 2024) में बढ़ कर 6.7 फीसद हो गई है, जो इसके पहले की तिमाही में 6.5 फीसद थी। शहरी बेरोजगारी पिछली चार तिमाही के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। पंद्रह साल से अधिक उम्र में बेरोजगारी की दर जनवरी-मार्च 2023 की तिमाही के 6.8 फीसद के बाद सर्वाधिक है। सर्वेक्षण के अनुसार युवा बेरोजगारी का स्तर बढ़ा है और यह बीती तिमाही के 16.5 फीसद से बढ़कर चौथी तिमाही में 17 फीसद हो गया। यह आंकड़ा इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है कि इस आयु वर्ग के लोग पहली बार श्रम बाजार में प्रवेश करते हैं। इससे शहरी रोजगार के बाजार में गिरावट का पता चलता है।

पिछले दिनों फ्रांस के 'कारपोरेट एंड इन्वेस्टमेंट बैंक नेटिक्सि एसए' द्वारा प्रकाशित अध्ययन रपट के मुताबिक भारत में जिस तेजी से युवा रोजगार के लिए तैयार होकर श्रमशक्ति (वर्क फोर्स) में शामिल हो रहे हैं, उसे देखते हुए भारत को 2030 तक प्रति वर्ष 1.65 करोड़ नई नौकरियों की जरूरत होगी। इसमें से करीब 1.04 करोड़ नौकरियां संगठित क्षेत्र में पैदा करनी होगी। जबकि पिछले दशक में सालाना कुल 1.24 करोड़ नौकरियां ही पैदा हो सकी थीं। इस रपट में यह भी कहा गया है कि भारत को अपनी अर्थव्यवस्था में तेजी को बरकरार रखने के लिए सेवाओं से लेकर विनिर्माण तक सभी क्षेत्रों को नई रफ्तार से बढ़ावा देना होगा। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार वर्ष 2022 में भारत की कुल बेरोजगार आबादी में से 83 फीसद बेरोजगार युवा थे। विश्व बैंक के मुताबिक, भारत की कुल श्रमशक्ति की भागीदारी दर मात्र 58 फीसद है, जो भारत के एशियाई समकक्ष देशों की तुलना में बहुत कम है।

ऐसे में नई सरकारी नियुक्तियों और नए रोजगार के अवसर सृजित किए जाने की अहम जरूरत है। हाल में बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 तक पांच लाख 17 हजार सरकारी नियुक्तियां करने का सख्त निर्देश अन्य सभी सरकारों के लिए मिसाल की तरह है। नई केंद्र सरकार द्वारा न केवल सरकारी क्षेत्र में नए रोजगार सृजित करने होंगे, बल्कि देश में असंगठित क्षेत्र लघु एवं मध्यम उद्योगों और 'गिग वर्कर्स' की चिंताओं पर भी ध्यान देना होगा। इन क्षेत्रों में करोड़ों लोगों को रोजगार तो मिल रहा है, लेकिन भविष्य एकदम सुरक्षित नहीं है। जून 2022 में प्रस्तुत नीति आयोग की एक रपट बताती है कि भारत के 77 लाख लोग इस समय 'गिग इकोनामी' का हिस्सा हैं। अनुमान है कि 2029-30 तक इनकी संख्या 2.35 करोड़ हो जाएगी। 'गिग वर्कर्स' के लिए बड़ी समस्या नौकरी जाने का खतरा और प्रोविडेंट फंड, हेल्थ इंश्योरेंस और सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलना है। देश में रोजगार के मद्देनजर महिलाओं की स्थिति भी अच्छी नहीं है। 'नैसकाम' के मुताबिक भारत के प्रौद्योगिकी कार्यबल में केवल 36 फीसद महिलाएं हैं। विश्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक भारत में वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और प्रौद्योगिकीविदों में महिलाओं की भागीदारी केवल 14 फीसद है। भारत के बड़े अवसरों के लिए महिलाओं की कम भागीदारी चुनौतीपूर्ण है।

> **अब सरकार को देश में वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) की स्थापनाओं की रफ्तार बढ़ाकर नए तकनीकी कौशल वाले युवाओं के लिए रोजगार के अधिक मौके सृजित करने की डगर पर आगे बढ़ना होगा। उच्च कौशल, कम लागत, प्रतिभा और मूल्य निर्माण जैसी भारत की विशेषताएं दुनिया में अधिक प्रचारित-प्रसारित कर बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में और ज्यादा जीसीसी स्थापित करने के लिए प्रेरित करना होगा। 'नैसकाम-जिनोव' की ताजा रपट के मुताबिक वर्तमान में भारत तकरीबन 1600 जीसीसी की मेजबानी कर रहा है, जिसमें उच्च कौशल प्रशिक्षित 16.6 लाख लोग कार्यरत हैं।**

निश्चित रूप से सरकार को तेज रणनीति के साथ इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। पिछले दस वर्षों में जिस तरह नई पीढ़ी द्वारा स्वरोजगार के मौके मुट्ठी में लिए गए, उनकी रफ्तार बढ़ानी होगी। हाल ही में शोध संस्थान 'स्काच' ने 2014-24 की अवधि में ऋण आधारित हस्तक्षेपों और सरकार आधारित हस्तक्षेपों का अध्ययन किया है। जहां ऋण आधारित हस्तक्षेपों ने प्रतिवर्ष औसतन 3.16 करोड़ रोजगार जोड़े हैं, वहीं सरकार आधारित हस्तक्षेपों से प्रतिवर्ष 1.98 करोड़ रोजगार पैदा हुए हैं। सामान्यतया एक कर्ज पर औसतन 6.6 प्रत्यक्ष रोजगार पैदा हुए हैं। इस अध्ययन से यह भी पता चलता है कि सूक्ष्म कर्ज का इस्तेमाल स्थिर और टिकाऊ रोजगार सृजन के लिए किया जा रहा है। इस अध्ययन में रोजगार और स्वरोजगार से संबंधित बारह केंद्रीय योजनाओं को शामिल किया गया है। इनमें मनरेगा, पीएमजीएसवाई, पीएमईजीपी, पीएमए-जी, पीएलआइ, पीएमएवाई-यू, और पीएम स्वनिधि जैसी प्रमुख योजनाएं शामिल हैं। अध्ययन के मुताबिक पिछले दस वर्षों में ऋण अंतराल यानी जीडीपी के अनुपात में कर्ज के अंतर में 12.1 फीसद की गिरावट आई है।

विगत दस वर्षों में कृत्रिम बुद्धिमता (एआइ) जैसे नए कौशल से नई पीढ़ी के लिए रोजगार के मौके बढ़े हैं। अब सरकार को देश में वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) की स्थापनाओं की रफ्तार बढ़ाकर नए तकनीकी कौशल वाले युवाओं के लिए रोजगार के अधिक मौके सृजित करने की डगर पर आगे बढ़ना होगा। उच्च कौशल, कम लागत, प्रतिभा और मूल्य निर्माण जैसी भारत की विशेषताएं दुनिया में अधिक प्रचारित-प्रसारित कर बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में और ज्यादा जीसीसी स्थापित करने के लिए प्रेरित करना होगा। 'नैसकाम-जिनोव' की ताजा रपट के मुताबिक वर्तमान में भारत तकरीबन 1600 जीसीसी की मेजबानी कर रहा है, जिसमें उच्च कौशल प्रशिक्षित 16.6 लाख लोग कार्यरत हैं। भारत 2025 तक 1,900 से ज्यादा जीसीसी वाला देश बनने की ओर बढ़ रहा है, जिसमें बीस लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। चूंकि कई विकसित और विकासशील देशों में तेजी से बूढ़ी होती आबादी के कारण उद्योग-कारोबार और सेवा क्षेत्र के विभिन्न कामों के लिए युवा हाथों की कमी हो गई तथा श्रम लागत बढ़ने से ये देश कार्यबल संबंधी परेशानियों से जूझ रहे हैं। ऐसे में भारत को इस मौके को भुनाते हुए तेजी से आगे बढ़ना होगा। सरकार ने 2023 तक भारतीय श्रमिक उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न देशों के साथ तेरह समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ऐसे समझौतों को अब और बढ़ाना होगा। इससे देश की युवा श्रमशक्ति विदेशों में अधिक रोजगार के साथ अधिक विदेशी मुद्रा की कमाई भी कर सकेगी।

अब सरकार को बड़े स्तर पर रोजगार पैदा कर सकने वाली परियोजनाओं के बारे में सोचने की जरूरत है। इस समय रोजगार चुनौतियों के मद्देनजर राष्ट्रीय और स्थानीय दोनों ही स्तरों पर लोक निर्माण कार्यक्रम से रोजगार बढ़ाना जरूरी है। मनरेगा की तरह शहरी बेरोजगारों के लिए भी योजना बनाने की जरूरत है। सरकार को विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए रणनीतिक रूप से आगे बढ़ना होगा। साथ ही अप्रशिक्षित श्रमिकों को नई तकनीकों से प्रशिक्षित करना होगा।

आदतों के दायरे

एकता कानूनगो बक्षी

हम सभी का जीवन विभिन्न परिस्थितियों और भांति-भांति के लोगों के साथ बीतते हुए ही बनता है। यह जरूर हमें महसूस होता है कि हम रोजमर्रा के सामान्य दिनों में अपनी दिनचर्या की पुनरावृत्ति कर रहे हों, जबकि हमारा हर दिन अपने आप में अलग होता है। पत्र-पत्रिकाओं और सोशल मीडिया में अक्सर ऐसी पहेलियां आती रहती हैं, जिनमें बिल्कुल एक से दिखने वाले दो चित्र हमारे सामने रख दिए जाते हैं और हमें उनमें अंतर खोजना रहता है। बहुत गौर से देखने पर सूक्ष्म अंतर हमें नजर भी आते हैं। जैसे किसी एक में व्यक्ति का चेहरा बिना किसी भाव के है, तो दूसरे में वह मुस्करा रहा है। ऐसे ही हमारे जीवन के एक से दिखने वाले दिन भी एक दूसरे से काफी अलग होते हैं।

अक्सर सूक्ष्म भिन्नताओं को हम देख ही नहीं पाते और अपनी नियमित आदतों की धुन में बने रहते हैं। हम बस एक निश्चित जीवनशैली बना लेते हैं और उस पर लगातार बने रहने में संतुष्टि पाने लगते हैं। यह गलत भी नहीं है। अच्छी आदतों को दोहराते रहना बुरा भी नहीं है, पर अगर हम किसी मशीन की तरह रोज के कामों को करते ही रहते हैं, बाकी चीजों के प्रति हम सचेत नही हैं, कोल्हू के बैल या तांगे के घोड़े की तरह एक धुन में अपना रोज का काम निपटा रहे हैं तो हमें एक बार रुक कर थोड़ा विचार करने की जरूरत होगी।

अपनी दिनचर्या को पूरी तरह से नियमों से बंधा हुआ रखने की बजाय थोड़ा-सा लचीलापन रखना जिसमें बदलाव की थोड़ी बहुत गुंजाइश बनी रहे, अपने समय को सुखद बनाने के लिए शायद ठीक होगा। हर दिन अपने आप में नया होता है। थोड़े-बहुत बदलाव से हम उसका सही उपयोग, बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं। यह समझ हमें जीवन से जुड़ी अनिश्चितता को लेकर और अधिक सहज और स्वाभाविक भी बनाती है। अचानक से आई नई-नई परिस्थिति को लेकर भी हमारी प्रतिक्रिया सहज होने लगती है, हम अधिक संयम के साथ उसका सामना कर पाते हैं।

जब हम अपने ही बनाए ढांचे से समय-समय पर अपने को मुक्त करते हैं, खुद को सुरक्षा घेरे से थोड़ा बहुत बाहर निकालने की चुनौती देते रहते हैं, तब हम पहले से अधिक बेहतर, संतुलित और सक्षम भी होने लगते हैं। हम सिर्फ किसी यंत्र की तरह काम नहीं कर रहे होते, जिसे निर्धारित काम और परिस्थिति की जगह कुछ और काम या परिस्थियां हटकर दे दी जाए तो यंत्र काम करना बंद कर देता है। हम मशीन नहीं हैं। हम अपनी सारी इंद्रियों का उपयोग कर नई परिस्थिति को समझ रहे होते हैं, उसको बेहतर तरीके से करने की रणनीति बना रहे होते हैं, खुद को उस काम के लिए तैयार कर रहे होते हैं।

हमारे द्वारा स्वयं पर जबरन थोपे अस्वाभाविक नियम कभी-कभी हमें आत्मकेंद्रित बना सकते हैं। उन्हें पूरा करने को लेकर हमारी जिद हमारे आसपास के लोगों पर भी नकारात्मक प्रभाव डालने लगती है। किसी भी तरह का नियम बनाते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि उसके कारण किसी और को परेशानी तो नहीं हो रही। हमारी आदतें भी किसी के जीवन में दुख का कारण बन सकती हैं। अपनी दिनचर्या में हम पेड़-पौधों को रोज पानी पिलाते हैं। यह हमारी नियमित आदत है। इससे हमें संतुष्टि मिलती है। अब हम रोज ऐसा ही करेंगे, यह एक धुन है, जबकि मौसम के अनुरूप पौधे की आवश्यकता के अनुसार हम उसकी देखभाल करें, यह एक अच्छी समझ है, आदत में स्वाभाविक रूप से बदलाव करना होगा। मसलन, कल से मैं सुबह उठकर अपनी सेहत के लिए विशेष तरह के भोजन का सेवन करूंगा, थोड़ा जल्दी उठकर अपने लिए अपने अनुसार भोजन बनाऊंगा और इस बात का ध्यान रखूंगा कि मेरे कारण दूसरों की दिनचर्या में कोई व्यवधान न आए। ऐसी समझ और आदतों की शुरुआत से समग्र जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। यह हमारे व्यक्तित्व के हर पक्ष को छूता है। हमें दूसरों की जरूरतों के प्रति भी और संवेदनशील बनाता है। अपने लिए कुछ करते हुए हमारे मन में दूसरों की सुविधा-असुविधा का भी खयाल बना रहता है।

आदतों को बनाना और आदतों की कैद से खुद को समय-समय पर निकालना, दोनों ही बेहद महत्त्वपूर्ण है। फिर उसका संबंध हमारे द्वारा लंबे समय से बनाए विचारों से हो या हमारे द्वारा किए जा रहे व्यवहार से। किसी एक विचार से जुड़ी सामग्रियों से हटकर भी हमें अक्सर अलग-अलग विचारों को खुले दिमाग से सुनने का प्रयास करते रहना चाहिए। हो सकता है, इसके जरिए हम पुराने और प्रचलित विचारों की जगह अपनी नई बेहतर सोच विकसित कर सकें, जो और लोगों को प्रेरणा दे जाए। हमारे व्यवहार को भी हमें समय-समय पर व्यक्ति और परिस्थिति को देखते हुए संशोधित करते रहना चाहिए। हमारी हंसी-मजाक की सहज प्रवृत्ति हमेशा ही सबको सहज लगे जरूरी नहीं। अगर हम हमेशा अन्यों के साथ आदेशात्मक रवैया अपनाते हैं तो वह भी कड़वाहट और वैमनस्य का कारण बन सकता है। परिस्थिति और अन्यों की मनःस्थिति को समझते हुए उपयुक्त भाषा शिष्टाचार के साथ अपनी बात को रखना, अपने व्यवहार को सौम्य बनाना, व्यवहार में यह सकारात्मक लचीलापन हमारी अच्छी आदतों में शुमार किया जाना चाहिए।

जीवन का रोमांच सरल, सहज विवेकी रहकर आगे बढ़ते रहने में है। हमें नदी की तरह बहते रहना है... अलग-अलग रास्तों से गुजरते हुए कभी खुद को समेटते हुए तो कभी फैलाव की गुंजाइश का मान रखते हुए। प्राकृतिक रूप और रंगों के साथ अपने गंतव्य तक पहुंचने के प्रयास में यह भी जरूरी होगा कि भीतर की निर्मलता और तरलता हमेशा बनी रहे।

दुनिया मेरे आगे

> **जब हम अपने ही बनाए ढांचे से समय-समय पर अपने को मुक्त करते हैं, खुद को सुरक्षा घेरे से थोड़ा बहुत बाहर निकालने की चुनौती देते रहते हैं, तब हम पहले से अधिक बेहतर, संतुलित और सक्षम भी होने लगते हैं। हम सिर्फ किसी यंत्र की तरह काम नहीं कर रहे होते।**

सुविधा की असुविधा

दुनिया के आधुनिक होने के दावे के बीच स्मार्टफोन और इंटरनेट के दिनोंदिन बढ़ते हुए उपयोग ने बच्चों और युवाओं के साथ-साथ पचास वर्ष से ज्यादा उम्र वाले लोगों के बीच भी अपने पांव पसार लिए हैं। कोरोना काल से आनलाइन पढ़ाई के नाम पर कई बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन आ गए। बेशक स्मार्टफोन ने जीवन को सहज, सरल और आसान बनाया है और बैंक, रेलवे टिकट बुकिंग सहित कई कार्यों को घर बैठे निपटने का विकल्प दिया है, लेकिन कम उम्र के बच्चों और किशोरों के मामले में स्मार्टफोन ने फायदा कम और नुकसान ज्यादा किया है। वीडियो गेम, आनलाइन सट्टे, कई हानिकारक वस्तुओं के विज्ञापन से लेकर अश्लील फिल्में देखने, अपराध करने और महंगी जीवनशैली के ढेर सारे उपाय बच्चों के हाथ आ गए। निरंतर मोबाइल देखने से आंखों पर चश्मे के साथ-साथ अवसाद, मानसिक परेशानियां भी बड़े पैमाने पर पैदा हो रही हैं। अत्यधिक मोबाइल देखने से तनाव चिड़चिड़ापन और मनमानी करने के मामले सामने आ रहे हैं। फिर महंगे मोबाइल 'स्टेटस सिंबल' या रसूख के प्रतीक बन गए हैं। इससे उपजी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समस्याएं बढ़ती जा रही है।

– विभूति बुपक्या, खाचरोद, मप्र

मिलाप के मायने

ढाई दशक बाद अचानक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की उत्तर कोरिया की विदेश यात्रा ने पश्चिमी देशों के माथे पर पसीना ला दिया है। इस दौरान रूस द्वारा प्रदान की जाने वाली तकनीकी सहायता के पीछे का मंसूबा यूक्रेन युद्ध का समर्थन माना जा रहा है। इस मिलाप ने पश्चिमी देशों की बेचैनी इस डर ने भी बढ़ा दी है कि रूसी राष्ट्रपति द्वारा उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन को रूस द्वारा मिलने वाली तकनीकी सहायता का प्रयोग उत्तर कोरिया किस मंसूबे को पूरा करने के लिए करेगा। हाल ही में इटली में जी-7 की शिखर बैठक के बाद पश्चिम के अस्सी देशों ने स्विट्जरलैंड में यूक्रेन शांति प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। दुनिया में मात्र दो देश चीन और उत्तर कोरिया यूक्रेन युद्ध में रूस का समर्थन कर रहे हैं। इसीलिए यूक्रेन युद्ध से उपजी जरूरतों और पश्चिमी देशों से बढ़ती दूरियों के मद्देनजर वह उत्तर कोरिया से करीबी बढ़ा रहा है। राहत की बात है कि भारत ने इस मसले पर स्वतंत्र नीति अपनाई है।

– मामचंद सागर, रजोकरी, दिल्ली

साख पर सवाल

प्रत्येक अभ्यर्थियों के लिए परीक्षाओं को स्वच्छ तथा सुचारु रूप से कराने के लिए जिस एजंसी का गठन किया गया, हाल के दिनों में उसी पर प्रश्न चिह्न लग रहा है। लगातार हो रहे पर्चाफोड़ से न सिर्फ अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बल्कि एनटीए की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा हो रहा है। यह कोई नया मामला नहीं है। सरकारी महकमों के लिए भोजन बनाने से लेकर ड्राइवर तक की नियुक्तियों करने से पहले उनका अनुभव देखा जाता है तो परीक्षा को किसी अनुभवी संस्था के माध्यम से क्यों नहीं कराया जाता? अगर जनता सरकारी महकमे में किसी का समय बर्बाद करती है तो उस पर जुर्माना लगाया जाता है और जब विद्यार्थियों का कीमती समय और उनकी ऊर्जा बर्बाद होती है तो सब चुप हो जाते हैं। विद्यार्थियों का समय बर्बाद करने पर किस जुर्माने का प्रावधान है? क्या उन्हें अतिरिक्त समय दिया जाता है या उनके आर्थिक और मानसिक नुकसन की भरपाई की जाती है?

– स्वाति, प्रयागराज, उप्र

जल से कल

जल के बेलगाम दोहन से आज पूरी दुनिया के ऊपर जल संकट मंडराने लगा है। भूमिगत जल के दोहन में भारत दुनिया में प्रथम स्थान पर है। प्राकृतिक जलस्रोतों की अनदेखी की वजह से कई विलुप्त होने के कगार पर आ गए है, कई स्थानों पर नदियों, पोखर आदि का अतिक्रमण हो चुका है। देश के इक्कीस बड़े शहर 'जीरो भूजल स्तर' के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। जल संरक्षण की कमी और भूजल के अति दोहन के कारण देश की बारह फीसद जनता को अभी भी पानी सुलभ नहीं है। देश में अस्सी फीसद बारिश मानसून में होती है। आज के विकास के दौर में भी हम सिर्फ बारह फीसद बारिश के जल का उपयोग कर रहे हैं, शेष जल बर्बाद हो रहा है। अगर हम शेष जल को धरती के गर्भ तक पहुंचाने में सफल रहे, तो हमें सालों भर पानी की कमी महसूस नहीं होगी। भूमिगत जल का स्तर वर्षा की पानी से ही बढ़ता है।

– हिमांशु शेखर, केसपा, गया

www.readwhere.com

चिंतन

दिल्ली की जन समस्याएं मिलकर हल करें सरकारें

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली प्रशासनिक तौर पर देश के सामने कोई नजीर पेश नहीं कर पा रही है। रिकार्ड तोड़ गर्मी में बिजली आपूर्ति की बात हो, जल आपूर्ति संकट हो या अब भारी बारिश के चलते जलभराव की समस्या, सरकारें राजनीति करती नजर आईं। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, यहां शासकीय विभाजन है। कुछ चीजें दिल्ली सरकार के अधीन हैं, कुछ केंद्र सरकार के अधीन, तो कुछ नगर निगम और कुछेक एनडीएमसी के अधीन। इन सबका काम जनसेवा है, जनसमस्याओं को हल करना है, बेहतर जनसुविधा उपलब्ध कराना है, यह तभी संभव है, जब सभी शासकीय विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की जनता को आगे रखकर अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। शासकीय इकाइयों के बीच अहंकार, अविश्वास और दायित्व बोधहीनता से किसी भी जनसमस्या का समाधान नहीं होगा। दिल्ली में जबसे आम आदमी पार्टी की सरकार है और केंद्र में भाजपा की सरकार है, राष्ट्रीय राजधानी के शासकीय दायित्व के निर्वहन में टकराव है, हर मुद्दे पर राजनीति हावी है, भाजपा व आप एक दूसरे के खिलाफ हमेशा राजनीति करती रहती है, इसमें दिल्ली की जनता सफर कर रही है। दोनों दलों को मिलकर जन समस्याओं का समाधान करना चाहिए। भारत में जिस तरह की बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था है, जिस तरह नागरिकों के बीच भी भिन्न राजनीतिक अभिरुचि है, उसमें समूचे देश में सभी राज्यों व केंद्र में एक ही वक्त किसी भी एक दल या गठबंधन की सरकार आनी संभव ही नहीं है। अलग-अलग राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र में अलग-अलग दलों या गठबंधनों की सरकार रहेगी। इस सत्य को स्वीकारते हुए सत्ता में रहने वाले दलों को राजनीतिक मतभिन्नता से ऊपर उठकर जनकल्याण के लिए काम करना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि दल यह बात जानते नहीं हैं। सरकार में रहते हुए राजनीतिक व्यवहार करना निषेध होना चाहिए। चुनाव के समय राजनीतिक मतभेद और दलों के बीच स्पर्धा समझ में आती है, पर सत्ता में आने के बाद जनसमस्याओं के समाधान को लेकर सियासत करना राजनीति का निकृष्टतम रूप है। यह लोकतंत्र के मकसद के लिए भी खतरनाक है। जनता अपने विवेक से सरकार का चुनाव करती है, जनसमूह का विवेक एकसम नहीं हो सकता है, ऐसे में अलग-अलग दलों की सरकारें बननी लाजिमी है। सभी दल इस तथ्य को अच्छे से आत्मसात कर लें। सरकार गठन में पद की शपथ लेने व कार्यभार संभालने के बाद सभी पदेन लोग जनता के प्रति संवैधानिक रूप से जिम्मेदार हैं। कोई भी अपने दायित्वों के निर्वहन से बच नहीं सकता। सरकार में रहते हुए अपने-अपने दायित्वों को निभाने के बजाय जिम्मेदारी निभाने के लिए दूसरे को कसूरवार ठहराना बंद होना चाहिए। दिल्ली जलमग्न है, जनजीवन अस्तव्यस्त है, बिजली व पानी के संकट का सामना कर रही है और आप व भाजपा राजनीति में डूबी हुई हैं, यह शर्मनाक है। आरोप-प्रत्यारोप से समस्याओं के हल नहीं होंगे। सभी दल हमेशा राजनीतिक मोड में रहना बंद करें। केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम और एनडीएमसी को मिलकर दिल्ली की जनसमस्याओं को दूर करना चाहिए, बजाय एक-दूसरे पर ठीकरा फोड़ने के। संघीय व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए न कि कमजोर। भारी बारिश पर किसी का जोर नहीं, पर ड्रेनेज सिस्टम बेहतर बनाना, जलनिकासी की व्यवस्था करना सरकार के हाथ में है। पेयजल आपूर्ति सिस्टम ठीक करना हाथ में है।

कूटनीति
प्रभात कुमार राय

अलग-थलग पड़ता जा रहा इजराइल

गाजा पट्टी के बाद इजराइली सेना ने फिलिस्तीन के इलाके रफहा पर अपनी आक्रामक सैन्य कार्यवाही प्रारंभ कर दी है। रफहा में शुरू की गई इजराइल की सैन्य कार्रवाई का प्रबल विरोध अमेरिका द्वारा किया गया। इजराइल के समर्थक अमेरिका की कूटनीतिक सलाह की उपेक्षा करना इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को भविष्य में काफी भारी पड़ सकता है। अमेरिका ने इजराइली हुकूमत को हिजबुल्ला तंजीम से भी युद्ध नहीं करने की भी सलाह दी थी। अमेरिका की दोनों कूटनीतिक सलाहों को अस्वीकार करके इजराइल के प्रधानमंत्री ने इजराइल को दुनिया के पटल पर अलग-थलग करने की बाकायदा शुरूआत कर दी है।

इजराइली सेना द्वारा फिलिस्तीन तंजीम हमास के विरुद्ध प्रारंभ की गई सैन्य कार्रवाई को 7 महीने से अधिक वक्त बीत चुका है। अपनी समस्त सैन्य क्षमता के बावजूद इजराइल की सेना अभी तक हमास की ताकत को पूरी तरह से नेस्तनाबूद नहीं कर पाई है। गाजा पट्टी के बाद इजराइली सेना ने फिलिस्तीन के इलाके रफहा पर अपनी आक्रामक सैन्य कार्यवाही प्रारंभ कर दी है। रफहा में शुरू की गई इजराइल की सैन्य कार्रवाई का प्रबल विरोध अमेरिका द्वारा किया गया। इजराइल के समर्थक अमेरिका की कूटनीतिक सलाह की उपेक्षा करना इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को भविष्य में काफी भारी पड़ सकता है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका द्वारा ही इजराइल को आधुनिकतम अस्त्र-शस्त्र उपलब्ध कराए जाते रहे हैं। रफहा पर आक्रमण नहीं करने के अतिरिक्त अमेरिका ने इजराइली हुकूमत को लेबनान में सक्रिय हिजबुल्ला तंजीम से भी युद्ध नहीं करने की भी सलाह दी थी। अमेरिका द्वारा दी गई इन दोनों महत्वपूर्ण कूटनीतिक सलाहों को अस्वीकार करके इजराइल के प्रधानमंत्री ने इजराइल को दुनिया के पटल पर अलग-थलग करने की बाकायदा शुरूआत कर दी है। अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल सरकार से कहा है कि अमेरिका द्वारा इजराइली सेना को हथियारों की आपूर्ति तत्काल रोक दी जाएगी। यदि वास्तव में ही अमेरिका द्वारा इजराइल को आधुनिकतम हथियार नहीं प्रदान किए गए तो फिर इजराइल के लिए चौतरफा सैन्य दुश्मनों से अकेले मुकाबला करना बहुत दुश्वार हो जाएगा।

उल्लेखनीय है कि इजराइली सेना इन दिनों हमास तंजीम से जूझ रही है। लेबनान की ईरान द्वारा समर्थित हिजबुल्ला तंजीम से सैन्य मुकाबला कर रही है। यमन के हूती आक्रमणकारियों का सामना कर रही है। सीरिया और इराक़ में विद्यमान फिलिस्तीन समर्थक छापामारों के हमलों को भी झेल रही है। भविष्य में इजराइल को तालिबान के दुर्दांत लड़ाकू का भी मुकाबला करना है। हिजबुल्ला तंजीम के विरुद्ध युद्ध नहीं शुरू करने के लिए जो सलाह अमेरिका ने इजराइल को दी थी इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि अमेरिका की ताकत को बहुत अच्छी तरह से अनुमान लग रहा है। अमेरिका के सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि इजराइल का हिजबुल्ला के साथ युद्ध शुरू होने का मतलब यह होगा कि पूरा का पूरा उत्तरी इजराइल तबाह कर दिया जाएगा। 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इजराइल पर अचानक किए गए आक्रमण से प्रारंभ हुए इस युद्ध की व्यापकता का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। रूस बनाम यूक्रेन युद्ध में उलझा अमेरिका कदापि नहीं चाहता कि उसके लिए युद्ध का मध्य पूर्व में एक और बड़े युद्ध का मोर्चा खुल जाए। अमेरिकी कूटनीतिज्ञों का सटीक अंदाजा है कि रफहा में इजराइल द्वारा किया गया आक्रमण इस बर्बर युद्ध को वस्तुतः और अधिक विस्तार प्रदान कर देगा, इसीलिए बाइडेन ने इजराइली हुकूमत को यह सलाह दी थी कि उसको रफहा पर आक्रमण नहीं करना चाहिए और ना ही हिजबुल्ला के साथ युद्ध में कदाचित उलझना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि अमेरिका द्वारा इजराइल

हुकूमत को हथियार उपलब्ध नहीं कराए जाने की कूटनीतिक धमकी को वास्तव में अमेरिका द्वारा कोई अमलीजामा पहना दिया जाए। ऐसी स्थिति में इजराइल चौतरफा आक्रामक हालात में फंस जाएगा। वास्तव में अमेरिका स्वयं भी वियतनाम में और अफगानिस्तान में दीर्घकालीन गोरिल्ला युद्ध में परास्त होकर एक कटु अनुभव ले चुका है। अमेरिका नहीं चाहता कि उसका परम मित्र देश इजराइल उसकी तरह किसी दीर्घकालीन गोरिल्ला युद्ध में फंस बैठे। इजराइली हुकूमत अमेरिकन सलाह को निरंतर दरकिनार करती रही है। वर्ष 1948 में अपनी स्थापना से लेकर आज तक इजराइल किसी युद्ध पराजित नहीं हुआ है। इजराइल ने सन 1967 के युद्ध में अरब देशों को बुरी तरह पराजित किया था। इसके बाद 1973 में इजिप्ट के तत्कालीन राष्ट्रपति अनवर सादत ने इजराइल द्वारा हथियाई गई अपनी जमीन वापस लेने के लिए एक समझौता किया। जॉर्डन के शाह ने भी अपने घुटने इजराइल के सामने टेक दिए थे। यासर अराफत के नेतृत्व में एक दीर्घकालीन गोरिल्ला युद्ध इजराइल के विरुद्ध फिलिस्तीन लिबरेशन आर्मी -पीएलओ द्वारा लड़ा गया। पीएलओ के दीर्घकालीन संघर्ष का परिणाम निकला कि सन 1993 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जिमी कार्टर के नेतृत्व में इजराइली पीएम इजाकरॉबिन और पीएलओ लीडर यासर अराफत के मध्य ओस्लो समझौता हुआ, जिसके तहत वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में फिलिस्तीन को स्वायत्तता प्रदान कर दी गई थी, किंतु सार्वभौमिक राजसत्ता वाले देश का दर्जा फिलिस्तीन को प्रदान नहीं किया गया है जबकि सन 1948 में ही इजराइल को राष्ट्र घोषित करने के साथ ही संयुक्त राष्ट्र द्वारा दो स्वतंत्र राष्ट्रों के तौर पर फिलिस्तीन और इजराइल को क्रमशः 45 और 55 फीसदी भू-भाग दिया गया था। उल्लेखनीय है कि यूरोप में अमेरिका के मित्र नाटो देश एक के बाद एक फिलिस्तीन को राष्ट्र के तौर पर मान्यता दे रहे हैं। नार्वे, स्पेन और आयरलैंड द्वारा कुछ वक्त पहले ही फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दी गई है। इसके पहले नाटो सैन्य संगठन का नेतृत्व करने वाला नीदरलैंड भी फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में अपनी मान्यता प्रदान कर चुका है। दुनिया के 139 देश पहले से ही फिलिस्तीन को राष्ट्र का दर्जा दे चुके हैं।

उल्लेखनीय है कि गाजा में इजराइल सेना द्वारा वहशियाना सैन्य कार्यवाही अंजाम दी गई, जिसके तहत हजारों बच्चे, हजारों महिलाएं और हजारों बेगुनाह नागरिक हलाक़ कर दिए। गए। विगत 7 महीने में गाजा पर इजराइल द्वारा बरसाया गया बारूद जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका द्वारा गिराए गए 1500 टन बारूद के मुकाबले कई गुना अधिक है। आधुनिक इतिहास में दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका द्वारा वियतनाम, लाओस और कंबोडिया पर इससे कहीं अधिक बारूद गिराया गया था। इजराइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की सैन्य रणनीति के विरुद्ध पहली बार समस्त यूरोप का जनमत इजराइल के विरुद्ध खड़ा हो गया है।

इजराइली हुकूमत का यह दावा एकदम खोखला साबित हो चुका है कि वह गाजा में निर्दोष नागरिकों की हिफाजत कर रही है और केवल हमास के आतंकवादियों का सफाया कर रही है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इजराइल को बोको हरम सरीखे आतंकवादियों की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। इजरायली सेना के प्रवक्ता एडमिरल डेनियलहगरी का कहना है कि हमास को परास्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमास केवल एक तंजीम नहीं है बल्कि विचारधारा है जो हर फिलिस्तीनी के दिलों दिमाग में बस गई है। ऐसा प्रतीत होने लगा है कि इजराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का हमास को नेस्तनाबूद कर देने का सैन्य मिशन नाकाम हो चुका है। नेतन्याहू अपनी सैन्य रणनीति में खुद ही उलझ कर रह गए हैं, यहां तक कि उनके परम मित्र देश अमेरिका भी उनकी सैन्य रणनीति से नाराज होकर उनको भविष्य में हथियार प्रदान नहीं करने की धमकी दे रहा है।

(लेखक विदेश मामलों के जानकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया **edit@haribhoomi.com** पर दे सकते हैं।

मुद्दा
मनोज कुमार अग्रवाल

वो जो लौट कर घर ना आए...

अठारहवीं लोकसभा अस्तित्व में आ चुकी है। आम चुनाव को सम्पन्न कराने के लिए कुल दस लाख से अधिक केंद्र व राज्य कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी इन चुनावों को सम्पन्न कराने के लिए अपने घर परिवार बच्चों को छोड़कर मतदान केंद्रों पर ड्यूटी देने गए 123 कर्मचारी अपने घर जीवित वापस नहीं आए वरन वह अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ड्यूटी पर ही विभिन्न कारणों से जान गंवा गए। चुनाव आयोग को चुनाव कराने के लिए बड़ी संख्या में कर्मियों की जरूरत होती है और ये कर्मी विभिन्न सरकारी विभागों, सरकारी स्कूल के शिक्षकों, राष्ट्रीयकृत बैंकों और एलआईसी सहित विभिन्न उद्यमों जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से लिए जाते हैं, जो देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपने-अपने जिलों में चुनाव कराने में मदद करते हैं। चुनाव ड्यूटी के लिए नियुक्त लोगों के अनुपस्थित रहने की कोई गुंजाइश नहीं है। अनुपस्थिति पर आयोग की ओर से दंड दिया जाता है। चुनाव कार्य में केवल उन्हीं कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जा सकती है जो केंद्र या राज्य के स्थायी कर्मचारी हैं। इस बार का लोकसभा चुनाव 45 डिग्री वाले गर्म मौसम में सम्पन्न हुआ। यह गर्म मौसम की तपिश चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के लिए बेहद भारी साबित हुई। सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही 54 कर्मचारियों की ड्यूटी करते हुए मौत हो गई। 33 मौतें तो वोटिंग के आखिरी दिन 1 जून को हुईं। मरने वालों में ज्यादातर होमगार्ड्स थे, जिनके परिवारों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। कुछ परिवार ऐसे हैं, जिन्हें सहारा देने वाला कोई नहीं बचा। उनकी आखिरी उम्मीद 15 लाख रुपये का सरकारी मुआवजा है, जो अब तक नहीं मिला है। उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के दूसरे राज्यों में भी चुनाव ड्यूटी के दौरान कई कर्मचारियों की मौत हुई। चुनाव आयोग से इसकी जानकारी मांगी, लेकिन जवाब नहीं मिला। एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्यों में अधिकारियों से बात की, तो पता चला कि मध्यप्रदेश में 27, असम में 15, राजस्थान-छत्तीसगढ़ में 8-8, पंजाब में 7 और दिल्ली में 4 मौतें हुई हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान गर्मी काफी अधिक रही और चुनाव कर्मियों को सुविधाओं का अभाव था यही कारण है कि 54 पोलिंग स्टाफ की मौत हो गई। ड्यूटी पर जान गंवाने वाले इन कर्मचारियों में से अभी तक सिर्फ 27 के आश्रितों को सरकार की ओर से मदद मिली है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक, जान गंवाने वाले कर्मचारियों में ज्यादातर होमगार्ड, सफाईकर्मी और वोटिंग कराने वाले कर्मचारी थे। इन सभी की 500 रुपये रोज के हिसाब से ड्यूटी लगाई गई थी। सभी को वोटिंग से 3 से 4 दिन पहले तय लोकसभा क्षेत्रों में पहुंचना था। यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी नवदीप रिणवा के हवाले से बताया गया है कि यूपी में रिपोर्ट हुईं सभी मौतें नेचुरल डेथ की कैटेगरी में आती हैं, इसलिए सभी पीड़ित परिवारों को 15 लाख रुपये की मदद दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के अनुसार, चुनाव ड्यूटी के दौरान पोलिंग स्टाफ की मौत होने पर दो तरह से मदद दी जाती है। पहला- कर्मचारी की बीमारी से या फिर प्राकृतिक मौत होने पर 15 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाता है। दूसरा- किसी भी तरह के उपद्रव या आतंकी हमले में पोलिंग स्टाफ की मौत होने पर 20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी यह जानकारी नहीं दे रहे हैं कि देश में कितने पोलिंग कर्मचारियों की मौत हुई, कब तक पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिल जाएगा। सवाल सह है कि क्या तपती गर्मी को देखते हुए चुनाव टाला जा सकता था, वरिष्ठ पत्रकारों ने ऐसे 6 सवाल चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मेल के जरिये भेजे। 5 दिन बाद भी जवाब नहीं आया। यह शर्मनाक है कि देश का चुनाव आयोग ड्यूटी पर तैनात जान गंवाने वाले कर्मचारियों की सही संख्या तक नहीं बता रहा है। मध्यप्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी अनुपम रंजन के मुताबिक चुनाव ड्यूटी के दौरान 27 कर्मचारियों की मौत हुई है। इनमें से 21 के परिवारों को केंद्र सरकार की तरफ से 15 लाख रुपये की मदद दी गई है। छत्तीसगढ़ में 8 कर्मचारियों की मौत हुई। सभी के परिवारों को मुआवजा मिल गया है। राजस्थान के मुख्य चुनाव अधिकारी प्रवीण गुप्ता के मुताबिक, प्रदेश में 8 मौतें हुई हैं, जिनमें से 6 परिवारों को मुआवजा मिल गया है। एक ओर वह नेता हैं जो संविधान हाथ में लेकर संविधान में आस्था का प्रदर्शन करते हैं और मौका मिलने पर संविधान का दुरुपयोग करने से भी नहीं चूकते हैं वहीं दूसरी ओर वे हैं जो अपनी जान ड्यूटी देते गंवा गए। हमारे विचार में इन तमाम लोगों को कर्तव्य परायणता के लिए श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए और इनके आश्रितों को यथा शीघ्र आर्थिक मदद दी जानी चाहिए। इसमें देरी या अनावश्यक कागजी बाधाएं दूर करने की जरूरत है, ताकि लोकतंत्र के इन पहरूओं की आत्मा को शान्ति मिल सके।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

जीवन बना और बिगाड़ सकती है ये चीजें

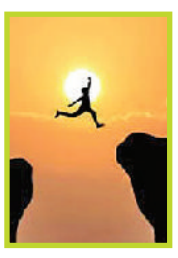

संकलित
दर्शन

आम आदमी अपने दिन का पूरा समय इन दो जगहों पर बिताता है वो है घर या फिर दफ्तर में। जैसी व्यक्ति की संगति होती है वैसी ही उसकी मति हो जाती है। इसलिए जरूरी होता है कि व्यक्ति हमेशा अपने लिए सही वातावरण चुनना चाहिए, जिससे वह सही पथ पर चले। आचार्य प्रशांत के अनुसार, एक व्यक्ति किस आधार पर विवाह करता है या फिर कैसी संगति चुनता है। यह महत्व की बात है कि वह व्यक्ति किसके साथ रह रहा है। आप चाहे विवाह करके रह रहे हो या फिर बिना विवाह करके अपना जीवन व्यय कर रहा हो। ऐसे में व्यक्ति को जरूर हमेशा याद रखना चाहिए कि वह अपने जीवनसाथी का चयन किस आधार पर कर रहा है। हर एक छोटी बात जैसे कि वह व्यक्ति अब से लगातार मेरे कमरे में रहेगा? किसके शब्द लगातार पड़ने लग गए हैं तुम्हारे कानों में? इन चीजों को याद करके ही निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि इसी बात पर तुम्हारी जिंदगी या तो बन जाएगी या बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। आचार्य प्रशांत आगे कहते हैं कि यहीं बात दफ्तर के लिए है कि दिन के आठ से दस घंटे आप किन लोगों की शक्लें देखते हैं या आर अपना बॉस बोलते हो, वो यूं ही है कोई सड़क का आदमी जो तुम्हारी जिंदगी पर अब अधिकार रखने लग गया है तो तुम बर्बाद हो जाओगे। यही बात दफ्तर के माहौल पर और धंधे की प्रकृति पर लागू होती है। तुम्हारी संस्था किस तरह का व्यवसाय करती है और तुम्हारे काम में किस तरह के लोग लगे हुए हैं?

गुरु अपने ज्ञान से किसी भी व्यक्ति की सोच बदल सकता है

संकलित
प्रेरणा

ऋषि वशिष्ठ श्रीराम कुलगुरु थे। इन्हीं की सलाह पर राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था। यज्ञ के फल से श्रीराम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। इन्होंने वशिष्ठ पुराण, वशिष्ठ श्राद्धकल्प, वशिष्ठ शिक्षा आदि ग्रंथों की रचना भी की। जब विश्वामित्र एक राजा थे, तब एक दिन वे शिकार खेलते-खेलते बहुत दूर निकल आए। आराम करने के लिए वे ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में रुक थे। आश्रम में विश्वामित्र ने कामधेनु नंदिनी गाय को देखा। नंदिनी गाय को देख विश्वामित्र ने वशिष्ठ से कहा कि ये गाय आप मुझे दे दीजिए, लेकिन ऋषि वशिष्ठ ने कामधेनु को देने से मना कर दिया। राजा विश्वामित्र कामधेनु को बलपूर्वक अपने साथ ले जाने लगे। विश्वामित्र कामधेनु के लिए युद्ध तक करने के लिए तैयार हो गए थे पर तब ऋषि वशिष्ठ के कहने पर नंदिनी गाय ने विश्वामित्र सहित उनकी पूरी सेना को भगा दिया। राजा विश्वामित्र को अपने सैनिकों सहित वापस राज्य में लौटना पड़ा। ऋषि वशिष्ठ का ऐसा प्रभाव देखकर विश्वामित्र बहुत हैरान हो गए। विश्वामित्र ने सोचा की तप में कितना बल है की एक व्यक्ति अपने तप से सभी को प्रभावित कर सकता है। इस घटना के बाद विश्वामित्र ने राज-पाठ छोड़ दिया और तप करने लगे। वशिष्ठ जी के ज्ञान और तप के प्रभाव से विश्वामित्र की सोच बदल गई और बाद में वे भी बह्मर्षि बन गए। गुरु अपने ज्ञान और तप से किसी भी व्यक्ति की सोच बदल सकते हैं।

अंतर्मन

आज की पाती

बढ़ती जनसंख्या कई समस्याओं की जड़

हमारा देश विकास और अन्य बहुत से अच्छे कामों में दुनिया भर में नंबर वन पर है और आगे भी बढ़ रहा है, लेकिन जनसंख्या के मामले में भी हमारा देश दुनिया भर में एक नंबर पर पहुंच चुका है। इस मामले में हमने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट में बताया गया है कि हमारे देश की जनसंख्या लगभग 144 करोड़ के आंकड़े तक पहुंच गई है और भारत की जनसंख्या 77 वर्षों में दोगुनी हो सकती है। अगर भारत सरकार और देश का आमजन बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए गंभीरता दिखाए तो भारत जनसंख्या वृद्धि के मामले में आगे नहीं बढ़ेगा। - **निरंजन विश्वकर्मा**, दुर्ग

ट्रेंड

सुधारों की सिफारिश

22 जून 2024 को इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ. के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों को शामिल करते हुए, समिति का उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया में सुधारों की सिफारिश करना, एनटीए की संरचना व संचालन की समीक्षा करना है।
-धर्मेन्द्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री

खाद्य सुरक्षा तेजी से बिगड़ी

सूडान में खाद्य सुरक्षा तेजी से बिगड़ रही है, 755,000 लोग विनाशकारी परिस्थितियों में हैं और 14 क्षेत्रों में अकाल का खतरा है। मानवतावादियों को जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए निर्बाध, निरंतर पहुंच की आवश्यकता है।
-एंटोनियो गुतरेस, यूएन महासचिव

छात्रों को सम्मान मिले

विपक्ष नीट परीक्षा और पेपर लीक मुद्दे पर सरकार के साथ रचनात्मक बहस करना चाहता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें आज संसद में ऐसा करने की अनुमति नहीं दी गई। यह एक गंभीर चिंता है। हम प्रधानमंत्री से छात्रों को वह सम्मान देने का आग्रह करते हैं जिसके वे हकदार हैं।
-राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष

कभी जबलपुर, कभी दिल्ली

बड़े जोर शोर के साथ प्रधानमंत्री जी ने टर्मिनल 1 के इसी हिस्से का उद्घाटन किया था आज धड़ाम हो गया 3 लोगों की जान चली गई कई लोग घायल हैं। कभी राम मंदिर, कभी अटल सेतु, कभी जबलपुर टर्मिनल, कभी दिल्ली टर्मिनल
-संजय सिंह, आप नेता

करंट अफेयर

चीन की धमकी, ताइवान ने नागरिको को किया सतर्क

ताइवान ने अपने नागरिकों से चीन और अर्ध-स्वायत्त चीनी क्षेत्रों हांगकांग और मकाऊ की यात्रा करने से बचने का आग्रह किया है। बीजिंग ने स्वशासित द्वीप ताइवान के लोकतंत्र की स्वतंत्रता के समर्थकों को मार डालने की धमकी दी थी, जिसके बाद ताइवान ने अपने नागरिकों से यह अपील की है। मुख्यभूमि मामलों की परिषद के प्रवक्ता और इसके उप प्रमुख लियांग वेन-चेह ने बृहस्पतिवार को एक संवाददाता सम्मेलन में यह सलाह जारी की। ताइवान की ओर से यह अपील चीन की ओर से बढ़ती धमकियों के बीच आई है। चीन दावा करता है कि ताइवान उसका अपना क्षेत्र है और यदि आवश्यक हुआ तो वह बलपूर्वक उस पर कब्जा कर सकता है। स्वतंत्रता समर्थक डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के लाई चिंग-ते के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद चीन ने ताइवान के स्वतंत्रता समर्थकों को खोज खोज कर मार डालने की धमकी दी है। चीन ने 2016 में डीपीपी की पूर्व राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन के चुनाव जीतने के बाद से ताइवान की सरकार के साथ सभी तरह के संपर्क से इनकार कर दिया है। लियांग ने कहा, चीन की ओर से मिल रही धमकी को देखते हुए नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह नागरिकों को सलाह दे।

ऑफ बीट

दुनिया का चौथा विशाल मूंगा विरंजन अभी जारी

दुनिया की मूंगा चट्टानें पानी के नीचे के शहरों की तरह हैं, जो सभी प्रकार की मछलियों और समुद्री जानवरों से भरी हुई हैं। मूंगा चट्टानें समुद्र के 1% से भी कम हिस्से को कवर करती हैं, लेकिन वे कई महत्वपूर्ण मछली प्रजातियों सहित सभी समुद्री प्रजातियों के अनुमानित 25% का समर्थन करती हैं। इन जटिल पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का आर्थिक मूल्य केवल अमेरिका में सालाना 3 .4 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। आज, समुद्र के बढ़ते तापमान से कई चट्टानों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है ।जब समुद्र का पानी बहुत लंबे समय तक गर्म हो जाता है, तो मूंगे अपने ऊतकों में रहने वाले रंगीन सहजीवी शैवाल, जिन्हें ज़ोक्सांथेला कहते हैं, को बाहर निकाल देते हैं - एक प्रक्रिया जिसे मूंगा ब्लीचिंग कहा जाता है। ये शैवाल मूंगों को भोजन प्रदान करते हैं, इसलिए प्रक्षालित मूंगे भुखमरी और बीमारी के प्रति संवेदनशील होते हैं और यदि पानी जल्दी से ठंडा नहीं हुआ तो वे मर सकते हैं। रिकॉर्ड स्तर पर वैश्विक महासागर की गर्मी के साथ, वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है कि वैश्विक मूंगा ब्लीचिंग चल रही है। 2023 की शुरुआत से, भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण, हिन्द, प्रशांत और अटलांटिक महासागरों में मूंगे मर रहे हैं।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-42422221 पर या सीधे मेल से **aapkepatra.haribhoomi@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

https://epaper.haribhoomi.com

अभिमत

रामगुलाम सिन्हा ने बताया कि प्रेरक संस्था ने इन महिलाओं की मदद के लिए चार स्तरों पर हस्तक्षेप किया है। सबसे पहले उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सब्जी बाड़ी (किचिन गार्डन) के लिए देसी सब्जियों के बीज वितरित किए हैं। जिससे उन्हें परिवार के लिए ताजी सब्जियां मिल सकें। और अतिरिक्त होने पर कुछ आमदनी भी हो सके। सुरक्षित व पौष्टिक भोजन मिल सके। मुर्गीपालन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो।

एकल महिलाओं की मदद की पहल

नवाचार

■ **बाबा मायाराम**

हमारी आधी दुनिया महिलाओं से बनी है। उनके लिए काफी योजनाएं और कार्यक्रम हैं, और नए बन रहे हैं। पंचायतों व स्थानीय निकायों में आरक्षण दिया जा रहा है। शिक्षा में भी वे आगे बढ़ी हैं। सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनकी उपस्थिति देखी जाती है। यानी पहले की स्थिति में काफी बदलाव आया है। लेकिन अभी भी कई स्तरों पर उनसे भेदभाव की खबरें आती रहती हैं। उनके साथ समानता का व्यवहार नहीं किया जाता है। इन सबमें विशेष तौर पर एकल महिलाएं सबसे ज्यादा उपेक्षित हैं। न्याय और समानता के लिए उनकी लड़ाई जारी है। छत्तीसगढ़ में उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की पहल की जा रही है। आज इस कॉलम में इस मुद्दे पर बातचीत करना चाहूंगा।

हम छुटपन से देखते आ रहे हैं कि महिलाओं के साथ कई स्तरों पर भेदभाव होता है। बचपन से लेकर बुजुर्ग होने तक उन्हें इसका शिकार होना पड़ता है। अगर मैं मेरे स्कूल के दिनों को याद करूं तो उस समय स्कूलों में बहुत कम लड़कियां पढ़ती थीं। महिलाओं का घरों से निकलना कम होता था। नौकरियों में उनकी संख्या बहुत कम थी। धीरे-धीरे इस स्थिति में बदलाव आया है। लेकिन एकल महिलाओं की स्थिति कई कारणों से अब भी बहुत अच्छी नहीं है।

हाल ही मुझे छत्तीसगढ़ में एकल महिलाओं से रूबरू होकर उनके दुख-दर्द जानने का मौका मिला। इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में प्रेरक संस्था काम कर रही है। महासमुंद, बस्तर और गरियाबंद जिले में एकल महिलाओं के लिए संस्था का डेयर टू ट्रस्ट कार्यक्रम चल रहा है। जिसके तहत इन महिलाओं के लिए कई स्तरों पर मदद की जा रही है।

संस्था के प्रमुख रामगुलाम सिन्हा ने बताया कि उनकी संस्था पिछले 35 सालों से समाज के सबसे वंचित तबकों के बीच काम कर रही है। कमार आदिवासियों के बीच काम की शुरूआत हुई थी। कमार, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह (पीवीटीजी) है। इस आदिवासी समुदाय का प्रकृति से गहरा जुड़ाव है। इनकी मुख्य आजीविका जंगल पर निर्भर है, लेकिन जंगलों में कमी व मौसम बदलाव के कारण कमारों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए उन्हें खेती की ओर मोड़ा। देसी बीजों की खेती-बाड़ी को बढ़ावा दिया और उनकी आजीविका व खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने का प्रयास किया।

इसी प्रकार, वन अधिकार कानून, 2006 के क्रियान्वयन में आदिवासियों की मदद की जा रही है। सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (सीएफआर) के दावा फार्म की औपचारिकताएं पूरी करवाने में मदद करना, और सामुदायिक वन अधिकार मिलने के बाद जंगल का संरक्षण व संवर्धन की योजना बनवाने में सहयोग करना इत्यादि, संस्था के कामों में शामिल है। इसके अलावा, संस्था का बुजुर्गो के लिए सियान सदन है, जहां 25 वृद्धजन रहते हैं, जिनमें निराश्रित शामिल हैं। दिव्यांग बच्चों के लिए भी आवासीय स्कूल संचालित किया जा रहा है।

एक साल से एकल महिलाओं के लिए भी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके माध्यम से ऐसी महिलाओं की पहचान की गई है। महासमुंद, बस्तर और गरियाबंद में ऐसी महिलाओं की संख्या 813 है। इनमें तलाकशुदा, विधवा, अलग रहने वाली, अविवाहित व अकेली वृद्ध महिलाएं शामिल हैं। इन महिलाओं के साथ सामाजिक स्तर पर भेदभाव तो होता ही है, साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है।

इसी कड़ी में पिछले एक साल से एकल महिलाओं के लिए भी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके माध्यम से ऐसी महिलाओं की पहचान की गई है। महासमुंद, बस्तर और गरियाबंद में ऐसी महिलाओं की संख्या 813 है। इनमें तलाकशुदा, विधवा, अलग रहने वाली, अविवाहित व अकेली वृद्ध महिलाएं शामिल हैं। इन महिलाओं के साथ सामाजिक स्तर पर भेदभाव तो होता ही है, साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है।

इनमें से सबमें विधवा महिलाओं की संख्या ज्यादा है। ये पूरी तरह अकेली पड़ जाती हैं। ऐसी महिलाओं को समाज व परिवार में तिरस्कार या अपमान झेलना पड़ता है। यह सब उन गरीबों परिवारों में और भी कष्टदायक हो जाता है, जहां बुनियादी जरूरतों का अभाव है। अत: अन्य समस्याओं के साथ उन्हें भोजन, दवा, वस्त्र, उचित आवास की कमी का सामना करना पड़ता है।

इसी प्रकार, इनमें से ऐसी महिलाएं भी हैं, जिनके पति गुजर जाने के बाद, उन पर बच्चों की या बुजुर्ग परिवारजनों की जिम्मेदारी आ गई है। लेकिन आर्थिक अभाव के कारण उन्हें जीविका चलाने में और बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

रामगुलाम सिन्हा बताते हैं कि 20 से 25 उम्र की आयु में किसी महिला का विधवा हो जाना, बहुत बड़ी त्रासदी है। उनके सामने पूरी जिंदगी होती है, और कदम-कदम पर कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पति की संपत्ति से बेदखल करने की कोशिश, घरेलू हिंसा और कई तरह सामाजिक तिरस्कार को झेलना पड़ता है। ऐसी महिलाओं को मदद की जरूरत होती है।

इसके अलावा, ऐसी कई बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनके गिरते स्वास्थ्य और थकान के कारण रोजाना के काम नहीं कर पाती हैं। संयुक्त परिवार टूटने से भी महिलाओं की समस्याएं बढ़ जाती हैं। कुछ ऐसी अकेली महिलाएं भी हैं, जिन्हें खुद के लिए घर की जरूरत हैं, लेकिन उन्हें न तो जगह मिल पा रही है और न ही उसे बनाने के लिए आवास योजनाओं से राशि।

रामगुलाम सिन्हा ने बताया कि प्रेरक संस्था ने इन महिलाओं की मदद के लिए चार स्तरों पर हस्तक्षेप किया है। सबसे पहले उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सब्जी बाड़ी (किचिन गार्डन) के लिए देसी सब्जियों के बीज वितरित किए हैं। जिससे उन्हें परिवार के लिए ताजी सब्जियां मिल सकें। और अतिरिक्त होने पर कुछ आमदनी भी हो सके। सुरक्षित व पौष्टिक भोजन मिल सके। मुर्गीपालन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो। इन सबसे उनकी टिकाऊ आजीविका की रक्षा के साथ देसी बीजों की विरासत, जैव विविधता व पर्यावरण का भी संरक्षण होगा। वे आत्मनिर्भर बनेंगी।

इसके अलावा, शासकीय कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता खुलवाने इत्यादि के काम किए जा रहे हैं। ऐसी पात्र महिलाओं को विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, महतारी वंदन योजना, मनरेगा जैसी योजनाओं से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। जिससे इन योजनाओं का उन्हें लाभ मिल सके।

महिला और पुरूषों की बराबरी के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाना, जिसमें महिला दिवस मनाना भी शामिल है। इसके अलावा, सामाजिक लिंग भेद पर कार्यशालाएं आयोजित करना। इसमें किशोरी लड़कियों व बच्चों को भी जोड़ना। पर्यावरण व स्वच्छता के प्रति भी लोगों को सजग बनाना। महिलाओं के घरेलू व अदृश्य अवैतनिक कामों का भी सम्मान करना।

साथ ही ऐसी महिलाओं के लिए ऐसा मंच उपलब्ध कराना जिसमें वे एक साथ आ सकें, उनका दुख-दर्द बांट सकें, एक दूसरे से जुड़ सकें, खुलकर बात कर सकें और आपस में अनुभव साझा कर सकें। कोई महिला सहज महसूस कर सके, चाहे वह अकेली हो।इसके अलावा, जिन महिलाओं को कानूनी सहायता की जरूरत है, उन्हें ये सुविधाएं उपलब्ध कराना। इसके लिए वरिष्ठ महिलाओं से परामर्श व कानूनी सहायता लेना और उनके अधिकारों के लिए लड़ना।

कुल मिलाकर, इन पहलों का असर यह हो रहा है कि ये महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। सब्जी बाड़ी लगाने से उन्हें ताजी हरी सब्जियां मिल रही हैं, कुछ आमदनी भी हो रही है। पेंशन, विधवा और वृद्धावस्था जैसी योजनाओं का लाभ मिलने लगा है। राशन कार्ड से अनाज मिल रहा है। महिलाओं के समूह में जुड़ने से उनकी एक साथ आवाज उठ रही है। लेकिन इस दिशा में अभी काफी कुछ करने की जरूरत है। यह तो अभी शुरूआत भर है।

उनके लिए बच्चों को निशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, आवास योजनाओं को लाभ, भूमिहीन महिलाओं को किचिन गार्डन के लिए भूमि के साथ ही विवाह संस्था से बाहर वाली महिलाओं को योजनाओं में प्राथमिकता मिलना चाहिए। इसके साथ ही समाज का भी उनके प्रति नजरिया बदलना जरूरी है। उनके साथ न्याय व समानता का व्यवहार होना चाहिए। लेकिन क्या हम अपनी सोच में बदलाव करने के लिए तैयार हैं?

बीता सप्ताह

22 जून

- इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति मोक्षदा ममता चंद्राकर को कुलपति पद से हटा दिया गया।
- रिटायर्ड आईएएस अजय सिंह छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाए गए।
- बिहार के जमुई विधायक श्रेयसी सिंह का निशानेबाजी के लिए पेरिस ओलंपिक के लिए चयन हुआ।
- सऊदी अरब में गर्मी के दौरान 98 भारतीयों की मौत हो गई।

23 जून

- नीट परीक्षा में घोटालों के बीच केंद्र सरकार ने परीक्षा प्रक्रिया में सुधार के लिए पूर्व 7 सदस्यीय समिति गठित की गई।
- भारत-बंगलादेश के बीच पीएम नरेन्द्र मोदी के मध्य 10 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। अब बंगलादेश के लोगों को मिलेगी मेडिकल ई वीजा की सुविधा।
- अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले मुख्य आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित का निधन हो गया।
- अमरनाथ यात्रा की प्रथम पूजा गुफा में सम्पन्न हुआ।

24 जून

- 18 वी लोकसभा चुनाव के बाद संसद का पहला सत्र शुरु हुआ जिसमें नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई गई।
- भाजपा नेता और ओडिशा के सात बार सांसद रह चुके भर्तृहरि मेहताब प्रोटेम स्पीकर बने।
- इसरो ने दो बार इस्तेमाल हो सकने वाले विमान की तकनीक की सफलतापूर्वक परीक्षण किया।
- बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को फिर से बनाया उत्तराधिकारी।

25 जून

- भाजपा के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा राज्यसभा में सदन के नेता बनाए गए।
- देश की 18वीं लोकसभा में चुने गए सांसदों को शपथ दिलाई गई।
- छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण के लिए ग्राम पंचायतों में बनाए जाएंगे महतारी सदन।
- तीसरे कार्यकाल में पीएम मोदी ने सदन में कहा कि वे अब पहले से तीन गुना ज्यादा काम करेंगे।

26 जून

- राहुल गांधी 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता चुने गए।
- मध्यप्रदेश सरकार ने एक फैसला लेते हुए कहा कि- मंत्री अब अपना इनकम टैक्स खुद भरेंगे। राज्य शासन वहन नहीं करेगा।
- अमेरिका से समझौते के बाद विकीलीक्स के संस्थागत जुलियन असांजे ब्रिटेन की जेल से रिहा हुए।
- अमेरिका ने अपने ग्लोबल म्यूजिक डिप्लोमेसी इलिरिएटिव के समर्थन को लेकर यूट्यूब के साथ साझेदारी की।

27 जून

- ओम बिरला ध्वनिमत से लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए।
- पूर्व विदेश सचिव मुचकुंद दुबे का निधन हो गया।
- जैन साध्वी शशिप्रथा का सड़ दुर्घना में निधन हो गया।
- सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को शराबनीति मामले में गिरफ्तार किया।

28 जून

- छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्व की भांति अपना जनदर्शन कार्यक्रम फिर शुरू किया।
- संसद की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आपातकाल को संविधान पर हमला बताया।
- दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया में तख्तापलट करने राष्ट्रपति भवन में घुसे विद्रोही सैन्य कमांडर जनरल जुआन जोस को गिरफ्तार कर लिया।
- अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने पूर्व चीन सागर में पहला संयुक्त मतरी डोमेन अभ्यास शुरू किया।

एनडीए के सामने बड़े सवाल

2024 के लोकसभा चुनाव में 240 सीटों पर सिमटने के बावजूद नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन से नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने में कामयाब हो गए हैं। लेकिन इस बार विपक्ष बेहद मजबूत है। विपक्ष के पास 230 से ज्यादा सांसद हैं। पिछले 10 साल नरेंद्र मोदी ने तानाशाहपूर्ण तरीके से सरकार चलाई। संसद में होने वाली बहसों और सड़कों पर होने वाले आंदोलनो पर भी नरेंद्र मोदी ने कभी जवाबदेही नही स्वीकार की। क्या अपने तीसरे कार्यकाल में नरेंद्र मोदी उत्तरदायी सरकार चलाएंगे? क्या विपक्ष एकजुट होकर सरकार को घेरेगा? क्या एनडीए सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी? आज भारतीय लोकतंत्र के सामने ऐसे तमाम सवाल खड़े हुए हैं?

24 जून को 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो चुका है। नरेंद्र मोदी ने पहले दिन से ही संकेत दिए हैं कि वह भले ही एनडीए की सरकार चला रहे हैं लेकिन उनके काम का तरीका और तेवर वही पुराने रहेंगे। अलबत्ता, अबकी बार नरेंद्र मोदी के लिए राह आसान नहीं है। भाजपा के भीतर भी मोदी विरोध में आवाजें उठने लगी हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी और योगी आदित्यनाथ जैसे गुजराती लॉबी के विरोधी नेता जी हुजूरी करने के लिए तैयार नहीं हैं। यही कारण है कि मोदी ने भाजपा संसदीय दल की बैठक के बजाय एनडीए की बैठक में नेता सदन का प्रस्ताव पास कराया। वे जानते हैं कि अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू काबू में रहे तो उन्हें कोई खतरा नहीं है। इसलिए जेडीयू और टीडीपी से अंदरूनी समझौते के बाद नरेंद्र मोदी ने उनकी पार्टियों को मंत्रिमंडल में झुनझुना पकड़ा दिए। गृह, विदेश, रक्षा, रेल और वित्त जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय मोदी ने भाजपा के ही पास रखे। इन मंत्रालयों में पिछले कार्यकाल के मंत्रियों की पुन: बहाली से मोदी ने संकेत दिया है कि वे कहीं से भी कमजोर नहीं हैं।

प्रो. रविकांत

पहले अपने सहयोगी घटक दलों के जरिए मोदी ने मजबूत होने का संदेश दिया, फिर प्रोटेम स्पीकर के मामले में विपक्ष को बेपरवाही से दरकिनार कर दिया। भाजपा ने प्रोटेम स्पीकर के लिए उड़ीसा से सातवीं बार के सांसद भर्तृहरि महताब को चुना जबकि विपक्ष का दावा था कि केरल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पिछली लोकसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक रहे आठवीं बार के सांसद अडूर सीट से जीतकर आने वाले दलित के.सुरेश सबसे वरिष्ठ हैं। इसलिए उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया जाना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इसे स्वीकार नहीं किया।

पहले अपने सहयोगी घटक दलों के जरिए मोदी ने मजबूत होने का संदेश दिया, फिर प्रोटेम स्पीकर के मामले में विपक्ष को बेपरवाही से दरकिनार कर दिया। भाजपा ने प्रोटेम स्पीकर के लिए उड़ीसा से सातवीं बार के सांसद भर्तृहरि महताब को चुना जबकि विपक्ष का दावा था कि केरल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पिछली लोकसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक रहे आठवीं बार के सांसद अडूर सीट से जीतकर आने वाले दलित के.सुरेश सबसे वरिष्ठ हैं। इसलिए उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया जाना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसके बाद स्पीकर के लिए तकरार शुरू हुई। राजनाथ सिंह के जरिए पहली बार स्पीकर पद के लिए आमराय बनाने का दिखावा किया गया। पहले एनडीए की बैठक में राजनाथ सिंह ने मोदी की राय बता दी कि स्पीकर उनकी ही पसंद का होगा। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष से संपर्क करके उनका समर्थन मांगा। विपक्ष ने संसद की परंपरा का हवाला देते हुए डिप्टी स्पीकर की मांग की। इस पर राजनाथ सिंह कोई आश्वासन नहीं दे सके। इसके बाद विपक्ष ने के. सुरेश को स्पीकर के लिए अपना प्रत्याशी बनाया। लेकिन 26 जून को ध्वनिमत से मोदी की पसंद ओम बिरला को फिर से लोकसभा का स्पीकर चुन लिया गया। अब लगता है कि डिप्टी स्पीकर भी एनडीए का होगा। नरेंद्र मोदी परंपराभंजक हैं। लोकतंत्र की मर्यादा और विपक्ष के प्रति कोई सम्मान नरेंद्र मोदी के मन में नहीं है। उनके लिए जनविश्वास भी नंबर गेम है। नरेन्द्र मोदी के लिए लोकतंत्र महज चुनाव है। चुनाव जीतने के लिए परंपराएं, मर्यादाएं, मूल्य और नीतियां कोई मायने नहीं रखतीं।

अब सवाल यह है कि इस बार भी क्या नरेंद्र मोदी क्या निरंकुश सरकार चलाएंगे? नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की ओर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार ने समर्पण कर दिया है। नीतीश कुमार की निगाह में केवल बिहार है। उनका एजेंडा बिहार को विशेष आर्थिक पैकेज हासिल करना और विधानसभा चुनाव जीतकर पुन: मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान रहना है। जबकि भाजपा की प्राथमिकता बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाना है। इसके लिए मोदी- शाह नीतीश कुमार की पार्टी तोड़ने में भी संकोच नहीं करेंगे। क्या इससे नीतीश कुमार अनजान हैं? इसी तरह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की प्राथमिकता विशेष आर्थिक पैकेज हासिल करना है। नई राजधानी अमरावती उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। 16 सांसदों वाली टीडीपी के बिना नरेंद्र मोदी सरकार नहीं चला सकते। फिर भी नायडू ना तो अपना स्पीकर बनवा सके और ना ही कोई ढंग का मंत्रालय उन्हें मिला। लोग हैरान हैं कि आखिर नीतीश और नायडू ने मोदी के सामने आत्म समर्पण क्यों कर दिया? मोदी सरकार में उन्हें ना तो उचित स्थान मिला है और ना ही समुचित सम्मान। क्या नीतीश और नायडू विशेष आर्थिक पैकेज के लिए ही चुप है?

नीतीश और नायडू की खामोशी के बावजूद नरेंद्र मोदी इस बार निरंकुश और अलोकतांत्रिक सरकार नहीं चला पाएंगे। इसके संकेत संसद सत्र के पहले दिन से ही मिलने लगे हैं। राहुल गांधी समेत विपक्ष के तमाम सांसदों ने संविधान की प्रति हाथ में लेकर 'जय संविधान' के नारे के साथ शपथ ली। यहां तक कि पहले दिन जब नरेंद्र मोदी बतौर सांसद शपथ ले रहे थे तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने संविधान की प्रति उन्हें दिखाते हुए संदेश दिया था कि देश संविधान से चलेगा सेंगोल से नहीं। सरकार पर नकेल कसने के लिए कांग्रेस ने अपने सबसे लोकप्रिय और जनप्रिय नेता राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनाया है। पिछले दो साल में राहुल गांधी ने अप्रतिम विश्वसनीयता हासिल की है। दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और अतिपिछड़ा समाज में आज राहुल गांधी सबसे लोकप्रिय नेता हैं। देश के नवनिर्माण और समावेशी विकास के उनके स्वप्न और संघर्ष से प्रभावित नौजवान, किसान, दस्तकार, कारीगर और मजदूर राहुल गांधी की ओर उम्मीद से देख रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में मोदी (32 प्रतिशत) से ज्यादा लोग (36 प्रतिशत) राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। राहुल गांधी के सवालों और उनकी जनपक्षधरिता के सामने नरेंद्र मोदी बौने नजर आते हैं। चुनाव खत्म होने के बावजूद राहुल गांधी देश के लोगों के मुद्दों पर लगातार सक्रिय हैं। नीट और यूजीसी पेपर लीक होने का मुद्दा हो या ट्रेन दुर्घटनाओं का मुद्दा; राहुल गांधी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद कश्मीर में आतंकवादी हमले बढे हैं। मणिपुर अभी भी शांत नहीं हुआ है। इन मुद्दों पर भी नरेंद्र मोदी घिरते हुए नजर आ रहे हैं।राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद राहुल गांधी ने सदन में नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाकर यह साबित कर दिया है कि शिक्षा और नौकरी जैसे सवाल उनकी प्राथमिकता हैं। राहुल गांधी की सक्रियता और आक्रामकता से स्पष्ट है कि इस बार नरेंद्र मोदी के दिन अच्छे नहीं हैं।

बदलती भू-राजनीति के बीच कुछ नाटकीय भारतीय बदलाव

भारत की भू-आर्थिक और भू-राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं और इसके साथ ही एक ऐसा बदलाव आया है जो नेहरूवादी युग के दौरान बनाए गए लंबे समय से चले आ रहे समय द्वारा परीक्षित पदों और गठबंधनों को चुनौती देता है और जो गणतंत्र के पहले 75 वर्षों में मजबूत हुआ है। भारत के पदों में यह बदलाव संभवत: बेंजामिन नेतन्याहू के इजरायली शासन के साथ बढ़ती निकटता में सबसे अच्छी तरह से देखा जा सकता है, जिस पर गाजा में निरंतर और अथक नरसंहार का आरोप लगाया गया है। भारत में आंतरिक रूप से इस गहरे नीतिगत बदलाव पर पूर्ण सहमति नहीं है।

विदेश नीति, भू-राजनीति और भू-अर्थशास्त्र के क्षेत्रों में आम सहमति की आवश्यकता शायद कम महसूस की जाती है, जिनमें से सब देश में चर्चा का विषय नहीं हैं। आम नागरिक या छात्र आम तौर पर विदेश नीति, व्यापार संबंधों या राजनीतिक झुकाव और अर्थशास्त्र के साथ उनके अंतर्संबंधों की बारीकियों में शामिल नहीं होते हैं। फिर भी, इस बदलाव के महत्व को रेखांकित करने की आवश्यकता है। साथ ही भारत में स्पष्ट रूप से चल रहे पुनर्रेखण पर बहस या आम सहमति की कमी भी है। यह वैश्विक मामलों में एक कठिन समय में आया है।

गौर करें कि पिछले महीने जारी की गई 2023-24 की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) की वार्षिक रिपोर्ट में भू-राजनीतिक तनाव, भू-आर्थिक विखंडन और इससे होने वाली अक्षमताओं पर जोर दिया गया है, जो एक ऐसी दुनिया में आती है जहां वैश्वीकरण पीछे हटता हुआ दिखाई देता है। 30 मई, 2024 की आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट (भाग 1: मूल्यांकन और संभावनाएं, पिछले वर्ष की तुलना में अधिक बार) में 'भू-राजनीतिज और 'भू-अर्थशास्त्र' शब्द 16 बार दिखाई देते हैं, जो इस बात का संकेत है कि भू-राजनीति की मांगों और आवश्यकताओं के संदर्भ में राजनीति द्वारा अर्थशास्त्र को कैसे बाधित किया जा रहा है। जोर (या कुछ लोग इसे बहुत जोर कह सकते हैं) हमें बताता है कि मुद्दों का एक पूरा दायरा, जैसे कि बाहरी क्षेत्र जिसमें व्यापार, पूंजी प्रवाह और मुद्रा की चाल, कच्चे तेल की कीमतें और उनकी चाल, वैश्विक वित्तीय बाजार, वैश्विक मुद्रास्फीति और विदेशी मुद्रा बाजार शामिल हैं, वैश्विक स्तर पर इतने गहराई से जुड़े हुए हैं कि वैश्वीकरण के सिद्धांतों से हटकर वैश्वीकरण के युग में जाने से बड़ी नई और गंभीर आर्थिक चुनौतियां आएंगी।

फिर भी, ये चुनौतियां एक ऐसे विश्व में आ रही हैं, जहां तनाव बढ़ रहा है और सीमाएं बंद होने का खतरा, राष्ट्रीय एजेंडा का सुदृढ़ीकरण और वैश्वीकरण तथा बहुपक्षवाद के विरुद्ध एक मज़बूत राष्ट्र-राज्य की प्राथमिकताएं बढ़ रही हैं। जैसा कि आरबीआई की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है- 'समकालिक मौद्रिक नीति में सख्ती के साथ-साथ भू-राजनीतिक संघर्षों के बढ़ने के कारण अस्थिरता बढ़ने के बीच वैश्विक वित्तीय स्थितियां कठिन हो गई हैं।'

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की प्रथम उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ के अनुसार, 'हम देखते हैं कि पहले से ही व्यापार और निवेश प्रवाह भू-राजनीतिक रेखाओं के साथ पुनर्निर्देशित किए जा रहे हैं।' स्टैनफोर्ड इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च में अपने मई 2024 के भाषण ('भू-राजनीति और वैश्विक व्यापार और डॉलर पर इसका प्रभाव') में उन्होंने कहा कि व्यापार तनाव बढ़ने के बाद 2017 और 2023 के बीच अमेरिकी आयात में चीन की हिस्सेदारी में आठ प्रतिशत अंकों की गिरावट आई है और चीन के निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी में लगभग चार प्रतिशत अंकों की गिरावट आई है। यूक्रेन के साथ संघर्ष और उसके बाद रूस पर प्रतिबंधों के बाद रूस और पश्चिम के बीच सीधा व्यापार ध्वस्त हो गया।

भू-राजनीतिक तनाव बेशक नए नहीं हैं; वे विश्व युद्धों के दौरान सामने आए।

इसका आर्थिक परिणाम विदेशी व्यापार, सीमा पार पूंजी प्रवाह, मुद्रा चाल और श्रम के प्रवास के पैटर्न और दिशाओं में प्रकट हुआ। सोवियत संघ (यूएसएसआर) का पतन, एक नई आर्थिक शक्ति के रूप में चीन का उदय, यूरोपीय संघ का गठन, एक आधिपत्य के रूप में यूएसए का उदय और सबसे हाल ही में, इजरायल-फिलिस्तीनी संघर्ष पर नए सवाल ने, जिन्हें नरसंहार के रूप में देखा जा रहा है, विश्व राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में एक प्रतिमान परिवर्तन किया है, जिससे बहुपक्षीय सहयोग और आर्थिक शासन की बहुपक्षीय प्रणालियों को खतरा पैदा हो गया है।

परिणामस्वरूप इन घटनाक्रमों ने अंतरराष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता के लिए खतरा पैदा कर दिया है। विश्व आर्थिक व्यवस्था विकास और कल्याण-उन्मुख कार्यक्रमों पर सार्वजनिक व्यय से रक्षा व्यय के उच्च स्तर पर परिवर्तन का सामना कर रही है।

'भू-अर्थशास्त्र' शब्द का पहली बार इस्तेमाल एडवर्ड लुटवाक ने 1990 में किया था। लुटवाक ने तर्क दिया कि शीत युद्ध की वैचारिक प्रतिद्वंद्विता की जगह दुनिया भर में आर्थिक प्रतिस्पर्धा ने ले ली है, जिसमें व्यापार और वित्त सैन्य शक्ति पर हावी हो जाते हैं। भू-अर्थशास्त्र ज्ञान की एक शाखा के रूप में भू-राजनीति से उभरा है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध राजनीतिक संबंधों द्वारा निर्देशित होते हैं। पुरानी अंग्रेज़ी कहावत को उद्धृत करते हुए, 'व्यापार झंडे का अनुसरण करता है और झंडा व्यापार का अनुसरण करता है', जिसका पहली बार उपनिवेशों के संदर्भ में उपयोग किया गया था जब इसे 1894 में ई. कोबहम ब्रेवर ने गढ़ा था, लेकिन अब इसका उपयोग राजनीति और अर्थशास्त्र के सह-आंदोलन को उजागर करने के लिए किया जाता है। फिर भी, जैसा कि कुछ लोग तर्क देंगे, उपनिवेशवाद का अंतर्निहित बोझ अपरिवर्तित है, वैश्विक व्यापार नई कब्ज़ाकारी शक्ति के रूप में है जिसमें भारत भी हिस्सा चाहता है!

ब्रिक्स देशों में चीन नई आर्थिक शक्ति और भू-राजनीतिक ताकत के रूप में उभरा है, जिससे हमें आईएमएफ द्वारा अमेरिकी झुकाव वाले देशों, चीन झुकाव वाले देशों और गुटनिरपेक्ष देशों के रूप में ब्लॉकों का वर्गीकरण मिला है। चीन ने भू-राजनीति में अपने लिए एक स्थान हासिल कर लिया है। इसे दर्शाते हुए, चीनी मुद्रा रेनमिनबी को आईएमएफ द्वारा मुद्राओं की टोकरी में शामिल किया गया है। इसके अलावा चीन का विदेशी मुद्रा भंडार 3.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर (अप्रैल 2024) था, जो वैश्विक व्यवस्था में इसकी बढ़ती वित्तीय ताकत का संकेत है। कच्चे तेल के भंडार (भू-आर्थिक उत्तोलन) और मजबूत सैन्य अड्डे (भू-राजनीतिक उत्तोलन) के साथ रूस भू-राजनीतिक रूप से संवेदनशील है। भू-राजनीति के संदर्भ में भारत की स्थिति संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस दोनों के साथ सामंजस्यपूर्ण आर्थिक और राजनीतिक संबंध बनाए रखने की उसकी प्रतिबद्धता है। अमेरिका के संबंध में 2022-23 के दौरान भारत का कुल विदेशी व्यापार समग्र का 24.44ल्ल था (निर्यात में 17.41प्रतिशत हिस्सा और आयात में 7.03 प्रतिशत हिस्सा)। चीन के साथ भारत का व्यापार कुल विदेशी व्यापार का 17.18प्रतिशत था (निर्यात में 3.39ल्ल हिस्सा और आयात में 6.47प्रतिशत हिस्सा)।

रंजीत के. पटनायक

'भू-अर्थशास्त्र' शब्द का पहली बार इस्तेमाल एडवर्ड लुटवाक ने 1990 में किया था। लुटवाक ने तर्क दिया कि शीत युद्ध की वैचारिक प्रतिद्वंद्विता की जगह दुनिया भर में आर्थिक प्रतिस्पर्धा ने ले ली है, जिसमें व्यापार और वित्त सैन्य शक्ति पर हावी हो जाते हैं। भू-अर्थशास्त्र ज्ञान की एक शाखा के रूप में भू-राजनीति से उभरा है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध राजनीतिक संबंधों द्वारा निर्देशित होते हैं।

मोटे तौर पर ऊपर बताए गए ब्लॉकों में भारत कहां खड़ा है? क्या यह अमेरिका की ओर झुकाव वाला है, चीन की ओर झुकाव वाला है, गुटनिरपेक्ष है या हर जगह साझेदारी के लिए तैयार है? आधिकारिक रुख यह है कि भारत की विदेश नीति का उद्देश्य पारंपरिक गुटनिरपेक्षता की ओर झुकाव से बहु-गठबंधन की ओर बढ़ना है।

आरबीआई द्वारा प्रकाशित 2022-2023 के दौरान भारत के विदेश व्यापार के आंकड़ों से इसकी पुष्टि होती है। अमेरिका और चीन को छोड़कर अन्य देशों के साथ भारत का विदेशी व्यापार 2022-23 के दौरान कुल विदेशी व्यापार का 58.38 प्रतिशत था, जिसमें से विदेशी व्यापार में यूरोपीय संघ की हिस्सेदारी 21.70प्रतिशत और ओपेक देशों की 33.4प्रतिशत थी। इसके विपरीत, एक दशक पहले (2013-14) अमेरिका और चीन को छोड़कर कुल विदेशी व्यापार का हिस्सा 83.3प्रतिशत था, जिसमें से विदेशी व्यापार में यूरोपीय संघ की हिस्सेदारी 13.24प्रतिशत और ओपेक देशों की 31.26प्रतिशत थी। जैसा कि देखा जा सकता है, दशक के दौरान अमेरिका और चीन के साथ भारत के व्यापार संबंध 2013-24 में 16.7 प्रतिशत की तुलना में 2022-23 में 41.62 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं, जो एक झुकाव का संकेत देता है।

संक्षेप में, व्यापार विशेषज्ञता और वैश्वीकरण से दक्षता लाभ पीछे हटने वाले वैश्वीकरण से खतरे में हैं। जैसा कि आईएमएफ ने कहा है, 'भले ही विश्वास को फिर से बनाना मुश्किल है और इसमें समय लग सकता है, लेकिन तेजी से विखंडित हो रही दुनिया में सबसे बुरे परिणामों से बचना महत्वपूर्ण है। आर्थिक एकीकरण से प्राप्त कुछ भारी लाभों को संरक्षित करना उचित है, जिसने दुनिया को अधिक समृद्ध और अधिक सुरक्षित बनाया है।'

भारत इस चरण में खुद को पुन: खोजने का प्रयास कर रहा है और हम जो बदलाव देख रहे हैं, वे नाटकीय से कम नहीं हैं।

(डॉ. आर.के. पटनायक पूर्व केंद्रीय बैंकर और गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकानॉमिक्स, पुणे में प्रोफेसर हैं। ये उनके निजी विचार हैं।

(लेखक सिंडिकेट : द बिलियन प्रेस)

https://t.me/AllNewsPaperPaid

प्रकाशक, मुद्रक : राजीव रंजन श्रीवास्तव द्वारा पत्रकार प्रकाशन प्रा. लि. के लिए 506, आई.एन.एस. बिल्डिंग, 9, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित एवं बीएफएल इंफोटेक लि., सी 9, सेक्टर-3, नोएडा से मुद्रित। सम्पादक : राजीव रंजन श्रीवास्तव, (पी.आर.बी. एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार)। आर.एन.आई. नं. DELHIN/2008/24216. दिल्ली कार्यालय :फोन: 011-23718195,23357784, फैक्स: 011-43581404, नोएडा कार्यालय: फोन: 0120-4114404 फैक्स: 0120-4273770
ई-मेल: deshbandhudelhi@gmail.com वेब: www.deshbandhu.co.in

लोकसभा उपाध्यक्ष का पद

भारत की संसदीय प्रणाली को पूरे विश्व में बहुत कौतूहल से देखा जाता है क्योंकि इसके माध्यम से जिस तरह शान्तिपूर्ण तरीके से देश में सत्ता बदल होता है उससे यह पता चलता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो विरासत छोड़ कर गये हैं वह भारत की असली तासीर है। संसद को सर्वोच्च विधायिका मानकर चलने वाले देश भारत का यह गुण भी है कि इसे चलाने के लिए जो नियम व परिपाठियां हैं वे सत्ता और विपक्ष के नजरिये से नहीं बल्कि देश के लोगों के प्रतिनिधियों के नजरिये से बनाई गई हैं और इन्हें बनाने वाले स्वयं संसद सदस्य ही हैं। सर्वसम्मति का यह भाव संसदीय प्रणाली के स्थायित्व की गारंटी देता है। संसद के भीतर हमारे जो पुरखे व्यवस्था करके गये हैं वह 'कालजयी' है। लोकसभा का अध्यक्ष बेशक चुने हुए सांसदों में से ही एक होता है परन्तु उसका रुतबा ऐसे 'पंच परमेश्वर' का होता है जो सभी के साथ बराबरी से न्याय करता है।

लोकसभा में बहुमत होने की वजह से यह पद सत्तारूढ़ दल के सांसद को ही दिया जाता रहा है मगर आसन पर विराजते ही वह 'न्यायप्रिय विक्रमादित्य' की भूमिका में आ जाता है। इसमें जब भी किसी प्रकार खामी आती है तो संसद का सन्तुलन बिगड़ने लगता है और यह एक अनुशासित सभा न रहकर सांसदों का जमघट बन जाती है। अफसोस की बात यह है कि पिछली लोकसभा में हमने ऐसे कई दृश्यों को देखा जब थोक के हिसाब से विपक्षी सांसदों का निष्कासन किया गया और हंगामे के बीच विधेयक भी थोक के हिसाब से पारित कराये गये। भारत की संसदीय प्रणाली की प्रतिष्ठा के अनुरूप पिछली 17वीं लोकसभा का कार्यकाल नहीं रहा। यह बिना किसी शक के कहा जा सकता है। सबसे दुखद यह रहा कि लोकसभा बिना उपाध्यक्ष का चुनाव किये ही पूरे पांच साल चलती रही और इसका कार्यकाल भी समाप्त हो गया। परन्तु ऐसा लगता है कि सत्तारूढ़ दल अतीत की गलतियों से सबक लेना चाहता है जिसकी वजह से यह खबर आ रही है कि वर्तमान लोकसभा में उपाध्यक्ष का भी चुनाव होगा। लोकसभा या राज्यसभा केवल नियमों से नहीं चलती बल्कि कुछ स्थापित गौरवशाली परंपराओं से भी चलती है। पिछले कई दशकों से यह परंपरा रही है कि अध्यक्ष पद अपने पास रखने के बाद सत्तारूढ़ दल उपाध्यक्ष पद विपक्ष को देता है जिससे सदन की कार्यवाही न केवल सुचारू रूप से चले बल्कि आपसी समझदारी व सामंजस्य से भी चले।

संविधान के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों ही होने चाहिए। उपाध्यक्ष का पद भी संवैधानिक होता है और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके पास सारे संसदीय अधिकार रहते हैं। मगर उपाध्यक्ष पद का चुनाव कब होगा। इस बारे में संविधान खामोश है। संविधान का 95वां अनुच्छेद कहता है कि लोकसभा का एक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष होगा। उपाध्यक्ष पद की अधिसूचना अध्यक्ष जारी करेंगे। मगर संविधान यह नहीं कहता कि कितनी अवधि के भीतर अध्यक्ष इस पद के लिए अधिसूचना जारी करेंगे। इसी खामी का लाभ पिछली लोकसभा में उठाया गया और पूरे पांच साल तक चुनाव नहीं कराया गया। मगर इस लोकसभा में उपाध्यक्ष का चुनाव कराने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है।

संविधान के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों ही होने चाहिए। उपाध्यक्ष का पद भी संवैधानिक होता है और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके पास सारे संसदीय अधिकार रहते हैं। मगर उपाध्यक्ष पद का चुनाव कब होगा। इस बारे में संविधान खामोश है। संविधान का 95वां अनुच्छेद कहता है कि लोकसभा का एक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष होगा। उपाध्यक्ष पद की अधिसूचना अध्यक्ष जारी करेंगे। मगर संविधान यह नहीं कहता कि कितनी अवधि के भीतर अध्यक्ष इस पद के लिए अधिसूचना जारी करेंगे। इसी खामी का लाभ पिछली लोकसभा में उठाया गया और पूरे पांच साल तक चुनाव नहीं कराया गया। मगर इस लोकसभा में उपाध्यक्ष का चुनाव कराने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है और समझा जा रहा है कि परंपरा के अनुसार यह पद विपक्षी पार्टी कांग्रेस या उसके गठबन्धन इंडिया के किसी घटक दल को दिया जायेगा। संसद में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के लिए आपसी सहमति बनानी इसलिए जरूरी होती है जिससे सदन का कामकाज बिना किसी अवरोध या टकराहट के चल सके।

हम अक्सर देखते हैं किसी मुद्दे पर सदन के भीतर सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच गतिरोध पैदा हो जाता है और दोनों ही अपनी-अपनी जिद पर अड़ जाते हैं। ऐसी स्थिति से उबरने में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उत्प्रेरक का काम करते हैं क्योंकि उनका चुनाव सर्वसम्मति से हुआ होता है। दोनों ही पक्ष उन्हें अपना प्रत्याशी समझते हैं। इसी वजह से लोकसभा में अध्यक्ष पद पर सर्वसम्मति बनाई जाती है जो कि इस बार 18वीं लोकसभा में नहीं हो सका और नौबत चुनाव तक आ गई। इसके बावजूद नये लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला का चुनाव ध्वनिमत से ही हो गया और विपक्ष ने मत विभाजन के लिए जोर नहीं दिया। विपक्ष के इस कदम की प्रशंसा की जानी चाहिए क्योंकि मत विभाजन से अनावश्यक कड़ुवाहट ही पैदा होती। सत्तारूढ़ भाजपा को अब विचार करना चाहिए कि उपाध्यक्ष का पद परंपरानुसार विपक्षी सांसद को दिया जाये क्योंकि ऐसा होने पर लोकसभा के भीतर सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के बीच आपसी सौहार्द बढ़ेगा और फिजूल की खींचतान नहीं होगी।

सत्तारूढ़ दल को यह याद रखना चाहिए कि जब 2004 से लेकर दस वर्ष तक देश में डा. मनमोहन सिंह की कांग्रेस नीत सरकार थी तो इसके पहले कार्यकाल में अध्यक्ष पद इस सरकार को बाहर से समर्थन दे रही मार्क्सवादी पार्टी के नेता स्वयं सोमनाथ चटर्जी को दिया गया था जिन्होंने लोकसभा टीवी की शुरूआत की थी। टीवी पर तब विपक्ष को भी सत्तापक्ष के समान ही बराबर की कवरेज दी जाती थी। तब उपाध्यक्ष पद विपक्षी पार्टी भाजपा के सहयोगी अकाली दल के सांसद चरणजीत सिंह अटवाल को दिया गया था। दूसरे मनमोहन कार्यकाल में कांग्रेस ने अपना अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार को बनाया था मगर उपाध्यक्ष पद भाजपा के श्री कारिया मुंडा को दिया गया था। भाजपा ने 2014 से शुरू हुए अपने पहले कार्यकाल में अपना अध्यक्ष बनाने के साथ उपाध्यक्ष पद अपने सहयोगी दल अन्ना द्रमुक के श्री थम्बीदुरै को देना गंवारा किया जबकि अगले कार्यकाल में किसी को उपाध्यक्ष बनाया ही नहीं। यह एक गलत परंपरा पड़ी जिसे भाजपा ही अब स्वयं सुधारना चाहती है। इसे लोकसभा के लिए शुभ लक्षण कहा जायेगा। क्योंकि ये दोनों पद आलोचना से परे माने जाते हैं मगर इसके लिए इन पदों पर बैठे व्यक्तियों को भी 'ऊंचा' उठना पड़ता है।

आदित्य नारायण चोपड़ा

Adityachopra@punjabkesari.com

पर मेरी गिनती गुमनाम....

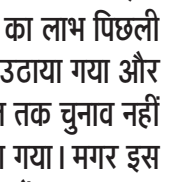

गीता पाढा

मैंने भी दुश्मन की गोली सीने पर खायी है,
पर मेरी गिनती गुमनाम सिपाही में आयी है,
चंद सत्ताधीशों ने वर्दी की कीमत लगायी है,
जो एक वीर की शहादत 'अग्निवीर" जैसी स्कीमों ने ठुकरायी है...!!

राहुल गांधी : विपक्षी नेता का रुतबा

राकेश कपूर

संसद से सड़क तक

kapurakesh@gmail.com

कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद ग्रहण करके पिछले दस साल से खाली चले आ रहे उस स्थान को भरा है जिसे संसदीय लोकतन्त्र में छाया प्रधानमन्त्री (शेडो प्राइम मिनिस्टर) कहा जाता है। 2012 में संसद के बारे में छपी एक आधिकारिक पुस्तिका में कहा गया है कि 'लोकसभा में विपक्ष का नेता छाया प्रधानमन्त्री के समान समझा जाता है जिसका अपना छाया मन्त्रिमंडल होता है जो सत्तारूढ़ सरकार के इस्तीफा देने या लोकसभा में हार जाने के बाद तुरन्त शासन की बागडोर अपने हाथ में लेने के लिए तैयार रहता है। संसदीय प्रणाली सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आपसी समझदारी और सामंजस्य से चलती है अत: विपक्ष का नेता प्रधानमन्त्री को सरकार चलाने देता है मगर उसे इसका विरोध करने की इजाजत भी होती है। सदन की कार्यवाही सुबोध तरीके से चलाने में उसकी भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी की सरकार या सत्ता पक्ष की।'

इससे स्पष्ट है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता का किरदार निभाना संसदीय परंपराओं व नियमों के तहत कितना मुश्किल भरा काम हो सकता है। श्री राहुल गांधी ने इस पद पर बैठ कर सिद्ध कर दिया है कि वह 24 घंटे के राजनीतिज्ञ हैं और उनका निजी जीवन एक खुली किताब है। अक्सर संसदीय लोकतन्त्र के बारे में यह भी कहा जाता है कि विपक्ष का काम सरकार के चेहरे से नकाब हटाना (एक्सपोज करना) होता है। सरकार का विरोध करना होता है और यदि संभव हो तो इसे सत्ता से बेदखल करना (डिपोज) होता है। मगर लोकतन्त्र में सरकार का गिरना या मजबूत होना लोकसभा के भीतर सदस्यों का अंकगणित होता है। जिसके पक्ष में अधिक सदस्य होंगे जीत उसी की होगी। वर्तमान 543 सदस्यों वाली लोकसभा में विपक्षी इंडिया गठबन्धन के मात्र 234 सदस्य हैं जबकि सत्तारूढ़ एनडीए के 293 सदस्य हैं। अत: मोदी सरकार मजबूत पाले में खड़ी हुई है मगर विपक्षी सांसदों की संख्या देखते हुए उसे मजबूत विपक्ष का सामना करना पड़ेगा।

राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वह किस प्रकार विपक्ष के एजेंडे को लोकसभा में मुखर रूप में लाते हैं। उनकी प्रमुख जिम्मेदारी सरकारी नीतियों को लेकर सरकार को एक्सपोज करने की ही रहेगी और संसद के माध्यम से अपने पक्ष में जन समर्थन जुटाने की रहेगी। संसद द्वारा 1977 में बनाये गये कानून के अनुसार उन्हें कैबिनेट स्तर के मन्त्री की सुविधाएं और रुतबा हासिल होगा तथा उनकी मौजूदगी हर उस उच्च स्तरीय चयन समिति में प्रधानमन्त्री के साथ होगी जो सीबीआई निदेशक, सतर्कता आयुक्त, केन्द्रीय सूचना आयुक्त, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों से लेकर इसके अध्यक्ष, चुनाव आयुक्तों व लोकपाल की नियुक्ति करेगी। इससे साफ है कि राहुल गांधी की जिम्मेदारियां इस कदर बढ़ जायेंगी कि उनके कार्यों पर देश की जनता की निगाह भी 24 घंटे रहेगी। मगर उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी विपक्ष के नेता पद की गरिमा को स्थापित करने की होगी क्योंकि पिछली लोकसभा में कांग्रेस के केवल 52 सदस्य होने की वजह से ही इसके नेता अधीर रंजन चौधरी को आधिकारिक तौर पर विपक्ष के नेता का रुतबा नहीं दिया गया था हालांकि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी होने की वजह से उन्हें विपक्ष के नेता के बराबर मान लिया गया था। इसके अलावा उनकी लोकसभा में छवि एक धीर-गंभीर नेता की न होकर विदूषक जैसी हो गई थी जिसकी बात को सत्तारूढ़ दल हंसी-मजाक में उड़ा देता था।

राहुल गांधी को विपक्ष के नेता की प्रतिष्ठा कायम करनी होगी और इस प्रकार करनी होगी कि वह नियमानुसार छाया प्रधानमन्त्री के रूप में दिखाई दे। पिछले दस साल से मोदी सरकार के रहते लोकसभा में कांग्रेस के कुल लोकसभा शक्ति के दस प्रतिशत सदस्य जीत न पाने की वजह से विपक्ष के नेता का रुतबा बहुत घटा है। राहुल गांधी

> **राहुल गांधी को विपक्ष के नेता की प्रतिष्ठा कायम करनी होगी और इस प्रकार करनी होगी कि वह नियमानुसार छाया प्रधानमन्त्री के रूप में दिखाई दे**

की पार्टी द्वारा इन चुनावों में 99 सीटें जीतने के बाद मनोवैज्ञानिक तौर पर सत्तारूढ़ दल दबाव में आया है क्योंकि भाजपा की सीटें 303 से घट कर 240 ही रह गई हैं। अत: राहुल गांधी का मनोबल इस तथ्य से बहुत ऊंचा नजर आयेगा और वह कोशिश करेंगे कि इस लोकसभा में सत्तारूढ़ पार्टी विधेयकों को पारित करते समय धींगा मस्तानी न करें। उनके सामने पहली चुनौती प्रतियोगिता परीक्षाओं के पेपर लीक होने की होगी जिसमें नीट आदि का मसला जुड़ा हुआ है।

इस मुद्दे पर विपक्ष शिक्षा मन्त्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है। इसके साथ ही नये तीन भारतीय फौजदारी कानून 1 जुलाई से लागू करने की घोषणा राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में भी कर दी है। ये वे कानून हैं जो संसद के दोनों सदनों में बिना किसी बहस-मुबाहिसे के ही भारी शोर- शराबे में तब पारित कराये गये थे जबकि 146 सांसदों को सदनों से निलम्बित कर दिया गया था।

इस मुद्दे पर राहुल गांधी लोकसभा में क्या रुख अपनाते हैं और किस प्रकार देशवासियों को सन्देश देते हैं यह देखने वाली बात होगी। क्योंकि संसद के दोनों सदनों में ही स्वयं संसद सदस्यों ने यह नियम बनाया था कि कोई भी विधेयक शोर-शराबे में पारित नहीं होना चाहिए। इस मामले में कांग्रेस पार्टी का रुख रहा है कि नये भारतीय न्याय संहिता के तीन कानूनों की देश को कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पुराने अंग्रेजों के बनाये कानूनों में समय- समय पर संशोधन होते रहे हैं और सैकड़ों कानूनों को निरस्त भी किया जा चुका है।

कांग्रेस के पूर्व गृहमन्त्री व इन कानूनों पर संसद में विचार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति के सदस्य पी. चिदम्बरम ने कुछ महीने पहले एक लेख लिख कर स्पष्ट किया था कि नई न्याय संहिता को लागू करने से पुलिस व वकीलों से लेकर निचली न्यायपालिका में अराजकता जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। राहुल गांधी इस मामले में अब कौन सा नया पैंतरा लोकसभा में चलते हैं इस तरफ सत्तारूढ़ दल का ध्यान रहेगा। राहुल गांधी ने हाल ही में सम्पन्न लोकसभा चुनावों में अपने राजनैतिक विमर्श को जिस प्रकार आम जनता में लोकप्रिय बनाया खास कर बेरोजगारी व अग्निवीर के मुद्दे पर जिस तरह उन्हें देश के युवा वर्ग का समर्थन मिला उससे उनकी छवि कांग्रेस पार्टी एक 'जन नायक' की मानने लगी है। अपनी इस छवि को राहुल गांधी तभी मजबूत बना सकते हैं जब विपक्ष के नेता के तौर पर वह लोकसभा में ऐसे कारनामें करें जिनसे सत्तारूढ़ सरकार को बगलें झांकने को मजबूर होना पड़ जाये।

इसके अलावा राहुल गांधी भाजपा के समक्ष विचारधारा की लड़ाई की चुनौती भी पेश करेंगे क्योंकि पूरे लोकसभा चुनावों में उन्होंने इस मुद्दे को कस कर पकड़े रखा और साफ कहा कि 'आइडिया आफ इंडिया' में साम्प्रदायिक दृष्टिकोण के लिए कोई जगह नहीं है। संसद के भीतर वह इस गंभीर लड़ाई को किस प्रकार प्रस्तुत करते हैं इसका इन्तजार भी सत्तारूढ़ भाजपा को बेताबी से रहेगा क्योंकि भाजपा का राष्ट्रवाद हिन्दुत्व से प्रेरित है। मगर यह तो मानना ही पड़ेगा और लोकसभा चुनावों से यह सिद्ध हो गया है कि राहुल गांधी ने जनता की नब्ज समझने की कला सीख ली है।

अपनी यात्राओं से जो उन्होंने अनुभव प्राप्त किये उनका इस्तेमाल उन्होंने लोकसभा चुनावों में बाखूबी किया। भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है। देश की जनता उन्हें नेहरू व इंन्दिरा गांधी की विरासत की राजनीति का सच्चा हकदार अब मानने लगी है और यहीं से कांग्रेस के पुनरुत्थान की कहानी भी शुरू हो सकती है। बेशक इमरजेंसी का मुद्दा भी राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में उठाया परन्तु कठोर तथ्य यह भी है कि केवल दो साल बाद ही देशवासी इमरजेंसी के जुल्मों को भूल गये थे और उन्होंने पुन: इन्दिरा गांधी के हाथ में लोकसभा की दो तिहाई सीटें दे दी थीं। इसके बाद बीस साल तक कांग्रेस के बूते पर दिल्ली की सरकारें गठित होती रहीं।

नवनिर्वाचित सांसदों को आवास दिलाना चुनौती से कम नहीं

ताक-झांक

आर.आर. जैरथ

मोदी सरकार के पास 18वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित सांसदों को आवास आवंटित करने का एक बड़ा काम है। लगभग 280 सांसद पहली बार सांसद बने हैं जिनके पास नई दिल्ली में आधिकारिक आवास नहीं है। इनके लिए आवास ढूंढने में लोकसभा आवास समिति को काफी माथापच्ची करनी होगी। इसका पहला काम हारे हुए 280 सांसदों से सरकारी आवास खाली कराना होगा। हालांकि भाजपा संभवत: अपने स्वयं के सांसदों पर कार्रवाई कर सकती है, किंतु समिति को अन्य दलों के सदस्यों के साथ खाली करवाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अतीत में, हमने सरकारी आवास से जबरन बेदखली के उदाहरण देखे हैं, जिनमें सबसे हाई प्रोफाइल दिवंगत रालोद प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह की बेदखली थी। उनकी संपत्ति सचमुच उनके तुगलक रोड बंगले के सामने फुटपाथ पर फेंक दी गई थी जिसे उन्होंने छोड़ने से इनकार कर दिया था। वह चाहते थे कि इसे उनके पिता और किसान नेता चरण सिंह के स्मारक में बदल दिया जाए।

नए सांसदों के अलावा, शहरी विकास मंत्रालय के तहत आने वाले संपदा निदेशालय को नवनियुक्त मंत्रियों के लिए उपयुक्त बंगले की तलाश करनी है। इस बार कम से कम 37 पूर्व मंत्रियों को केंद्रीय मंत्रिपरिषद से हटा दिया गया। कुछ को इसलिए क्योंकि वे स्मृति ईरानी, राजीव चन्द्रशेखर और अर्जुन मुंडा की तरह हार गए, अन्य को इसलिए क्योंकि उन्हें मंत्री के रूप में शामिल नहीं किया गया। हालांकि उन्होंने पुरूषोत्तम रूपाला की तरह चुनाव जीता था। मीनाक्षी लेखी को चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं दिया गया था। शिवराज सिंह चौहान और मनोहर खट्टर जैसे कुछ लोग न केवल पहली बार सांसद बने हैं, वे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी हैं और उनकी वरिष्ठता के कारण उनके लिए समुचित आवास की व्यवस्था करनी है।

निलंबित किए गए 58 सांसदों की नई संसद में वापसी

17वीं लोकसभा के पिछले शीतकालीन सत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा निलंबित किए गए लगभग 58 सांसद नई संसद में वापस आ गए हैं। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इनमें से तीन निलंबित सांसद अब एनडीए में हैं और उन्हें मोदी 3.0 सरकार में मंत्री नियुक्त किया गया है। हालांकि उनमें से एक लोकसभा चुनाव हार गए। लुधियाना से चुने गए कांग्रेस के तत्कालीन लोकसभा सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को उनकी पार्टी के बाकी सांसदों के साथ निलंबित कर दिया गया था। वह चुनाव से ठीक पहले भाजपा में शामिल हो गए थे, लेकिन लुधियाना सीट कांग्रेस उम्मीदवार से हार गए थे। वह पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते हैं। मोदी ने उन्हें खाद्य प्रसंस्करण और रेलवे राज्य मंत्री के रूप में शामिल किया।

राजीव रंजन सिंह जिन्हें लल्लन सिंह के नाम से भी जाना जाता है, को जद (यू) सांसद के रूप में लोकसभा से बाहर कर दिया गया था। उस समय जद (यू) विपक्ष का हिस्सा था। बाद में वह एनडीए में शामिल हो गये और अब हालिया चुनाव में ललन सिंह ने मुंगेर सीट जीत ली है। वह मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी के लिए मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। विपक्षी सांसदों के सामूहिक निलंबन के दौरान जद (यू) में सिंह के सहयोगी राम नाथ ठाकुर को भी बाहर कर दिया गया था। वह राज्यसभा सदस्य हैं और जदयू नेता नीतीश कुमार की 'चतुर' राजनीति के कारण, ठाकुर अब एनडीए में हैं और मोदी सरकार में कृषि राज्य मंत्री हैं।

नवीन पटनायक ने पाला बदलने का फैसला किया

हाल के चुनावों में मिले बड़े झटके के बाद बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक ने पाला बदलने का फैसला किया है। पिछले एक दशक से बीजेपी का समर्थन करने के बाद अब उन्होंने घोषणा की है कि राज्यसभा में उनके 9 सांसद विपक्ष के साथ मिलकर मोदी सरकार का विरोध करेंगे। पटनायक की बीजेडी ओडिशा में सभी 21 लोकसभा सीटें हार गई और राज्य विधानसभा चुनाव भी बीजेपी से हार गई। दस वर्षों तक, मोदी सरकार बीजेडी के समर्थन की बदौलत कई विवादास्पद विधेयकों को राज्यसभा में पारित कराने में सफल रही। उसे बीजद जैसी `मित्रवत' पार्टियों की मदद की ज़रूरत थी क्योंकि भाजपा के पास राज्यसभा में अपना बहुमत नहीं है। अब जब बीजेडी ने फैसला किया है कि वह सत्तारूढ़ शासन का समर्थन नहीं करेगी, तो मोदी सरकार को राज्यसभा में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, जहां उसके पास अभी भी बहुमत नहीं है।

पहली बार, सदन में ओबीसी का प्रतिनिधित्व उच्च जातियों के बराबर हुआ

यहां 18वीं लोकसभा के बारे में एक दिलचस्प तथ्य है। पहली बार, सदन में ओबीसी का प्रतिनिधित्व उच्च जातियों के बराबर हुआ। ओबीसी सांसद और उच्च जाति के सांसद प्रत्येक 26% हैं। दरअसल, इस बार लोकसभा में ऊंची जाति का प्रतिनिधित्व सबसे निचले स्तर पर है। आमतौर पर, उनकी संख्या अन्य जातियों से अधिक है। गौरतलब है कि ओबीसी सांसदों की सबसे ज्यादा संख्या इंडिया ब्लॉक से है, जिसमें कांग्रेस की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है।

चंद्रशेखर की जीत ने किया मजबूर

राहिल नोरा चोपड़ा

उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से भीम आर्मी प्रमुख चन्द्रशेखर आजाद की पहली चुनावी विजय ने राज्य में दलित राजनीति में नई जान

फूंक दी है। यह एक बड़ी वजह रही जिसके चलते मजबूर होकर बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती को अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक के रूप में बहाल करना पड़ा और उन्हें अपना एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित करना पड़ा। हाल ही में संपन्न चुनावों में हार के बाद पार्टी की पहली समीक्षा बैठक में यह कदम उठाया गया। इन चुनावों में बसपा का वोट शेयर गिरकर 9.39 प्रतिशत रह गया था। दरअसल, अब दलित वोट कांग्रेस, सपा और चन्द्रशेखर आजाद की ओर चला गए हैं। पूरी संभावना है कि आनंद की वापसी से बीजेपी को फायदा होगा।

कुशवाहा वोटों पर राजद की नजर

बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की आबादी में 4.2 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाले कुशवाहा समुदाय को लुभाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने अभय कुमार कुशवाहा को लोकसभा में संसदीय दल का नेता नियुक्त किया है जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रेमचंद्र गुप्ता को राज्यसभा में जिम्मेदारी सौंपी गई है। अभय कुमार कुशवाहा औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद हैं। लव-कुश जाति संयोजन के कुश, कुशवाहा समुदाय ने पिछले 20 वर्षों में पारंपरिक रूप से जद (यू) नेता नीतीश कुमार का समर्थन किया है। हालांकि, हाल के लोकसभा चुनावों में बदलाव देखने को मिला, जब विपक्षी गठबंधन ने नीतीश के इस वोट बैंक में सेंध लगा दी।

औरंगाबाद से अभय कुमार कुशवाहा के अलावा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) (लिबरेशन) के राजा राम सिंह ने भी काराकाट से जीत दर्ज की है।दरअसल, काराकाट में समुदाय के प्रभावशाली नेता उपेन्द्र कुशवाहा को एनडीए के समर्थन के बावजूद हार का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर, जद-यू ने अपने सुपौल सांसद दिलेश्वर कामैत को लोकसभा में पार्टी का नेतृत्व करने के लिए नामित किया है, जबकि संजय झा राज्यसभा में नेता होंगे। महादलित समुदाय से आने वाले कामैत दूसरी बार सुपौल से निर्वाचित हुए हैं। उनकी नियुक्ति की वकालत जद-यू अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री ने महादलित समुदाय के लिए एक संदेश के रूप में की है।

टूट के कगार पर अजीत गुट

जोरदार अटकलों के बीच कि अजीत पवार के नेतृत्व वाले राकांपा गुट के 15 से 20 विधायक पाला बदल सकते हैं, राकांपा (एसपी) नेता शरद पवार ने कहा कि उनकी पार्टी खुले हाथों से केवल उन विधायकों का स्वागत करेगी, जो समर्थन करेंगे और पार्टी को लाभ पहुंचाएंगे, जबकि उन लोगों को खारिज कर देंगे जो इसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। विभिन्न सूत्रों ने संकेत दिया है कि अजित पवार गुट के कई विधायक शरद पवार के संपर्क में हैं और फिर से पार्टी में शामिल होने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। इस बीच, अजीत पवार के नेतृत्व वाले राकांपा नेता कथित तौर पर मोदी 3.0 कैबिनेट में राज्य मंत्री (एमओएस) पद की पेशकश से नाराज थे। राकांपा नेता प्रफुल्ल पटेल को राज्य मंत्री की भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए इसे अस्वीकार कर दिया कि इसे स्वीकार करना कैबिनेट रैंक के साथ केंद्रीय मंत्री के रूप में उनकी पिछली स्थिति से गिरावट के रूप में देखा जाएगा।

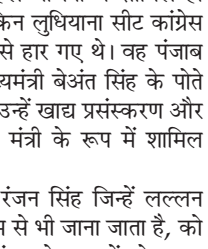

एमवीए पर दिखेगा नतीजों का असर

लोकसभा चुनाव के कारण महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के भीतर सत्ता समीकरण बदल गए हैं और इस साल अक्टूबर में होने वाले महाराष्ट्र राज्य विधानसभा चुनावों के लिए उनके सीट-बंटवारे के फॉर्मूले पर इसका असर पड़ सकता है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि चूंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस निस्संदेह 13 लोकसभा सांसदों और एक निर्दलीय सांसद के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है इसलिए कांग्रेस को राज्य विधानसभा चुनावों में अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने का वैध अधिकार है। हालाँकि, वे गठबंधन के व्यापक हित में कुछ सीटों को समायोजित करने के लिए तैयार हैं।

दूसरी ओर संजय राउत ने कहा कि एमवीए ने एकजुट होकर लोकसभा चुनाव लड़ा और दिखाया कि कैसे महाराष्ट्र ने भाजपा को पूर्ण बहुमत पाने से रोका। उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे पर अभी तक न तो एनसीपी (सपा) और न ही कांग्रेस के साथ चर्चा शुरू हुई है। इसलिए यह सवाल नहीं उठता कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। सभी समान हितधारक हैं। संजय राउत ने पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे को महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करने की भी वकालत की। राउत के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए, वरिष्ठ कांग्रेस नेता बालासाहेब थोराट ने कहा, 'ऐसे सभी निर्णय तीन दलों के शीर्ष नेताओं द्वारा चर्चा के माध्यम से लिए जाएंगे।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83

पंजाब केसरी

दिल्ली कार्यालय :

फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com

स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रैस, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।